मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा | अष्टम् सत्र

नवम्बर, 2015 सत्र

गुरुवार, दिनांक 5 नवम्बर, 2015

(14 कार्तिक, शक संवत् 1937)

[खण्ड-8] [अंक- 1]

मध्यप्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 5 वनम्बर, 2015

(14 कार्तिक, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.36 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

10.36 बजे राष्ट्रगीत

राष्ट्रगीत "वन्देमातरम्" का समूहगान

अध्यक्ष महोदय -- अब, राष्ट्रगीत "वन्देमातरम्" होगा. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं.

(सदन में राष्ट्रगीत "वन्देमातरम्" का समूहगान किया गया.)

10.37 बजे निधन उल्लेख

1. डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति,
2. श्री परसराम भारद्वाज, भूतपूर्व संसद सदस्य,
3. श्री जगन्नाथ सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य,
4. श्री सुखलाल कुशवाहा, भूतपूर्व संसद सदस्य,
5. श्री हीरालाल मालवीय, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
6. श्री कालूराम खटीक, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
7. महंत स्वामी श्री उमेश मुनि, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
8. श्री धीरज सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
9. श्री रतन पाटौदी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
10. श्री मुनीराम साहू, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
11. श्री रवीन्द्र जैन, सुप्रसिद्ध संगीतकार,
12. हरदा जिले में हुई रेल दुर्घटना में मृत व्यक्ति,
13. झाबुआ जिले के पेटलावद में हुए विस्फोट में मृत व्यक्ति.

अध्यक्ष महोदय मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यन्त दुख हो रहा है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का 27 जुलाई, पूर्व संसद सदस्यगण, श्री परसराम भारद्वाज का 19 अक्टूबर, श्री जगन्नाथ सिंह का 03 अगस्त, श्री सुखलाल कुशवाहा का 14 अगस्त, 2015 तथा मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यगण श्री हीरालाल मालवीय का 17 नवम्बर, 2014, श्री कालूराम खटीक का 07 अक्टूबर, महंत स्वामी श्री उमेश मुनि का 18 सितम्बर, श्री धीरज सिंह का 28 अक्टूबर, श्री रतन पाटौदी का 29 अक्टूबर, 2015 तथा श्री मुनीराम साहू का 15 दिसम्बर, 2014 सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री रवीन्द्र जैन का 09 अक्टूबर, 2015 को निधन हो गया है.

डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर, 1931 को रामेश्वरम्, तमिलनाडू में हुआ था. डॉ.कलाम 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान से जुड़े और विभिन्न पदों पर कार्य किया. जुलाई, 1980 में आपने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेव्लपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत 'अग्नि' एवं 'पृथ्वी' मिसाइलें विकसित कीं. वर्ष 1998 में आपने भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया. आप जुलाई 1992 से दिसम्बर, 1999 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार तथा डी.आर.डी.ओ. में सचिव के पद पर रहे. नवम्बर, 1999 से नवम्बर, 2001 तक आप भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे. भारत सरकार ने वर्ष 1981 में आपको पद्म भूषण, वर्ष 1990 में पद्म विभूषण तथा वर्ष 1997 में भारत रत्न से अलंकृत किया था. अनेक विश्वविद्यालयों ने आपको डाक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की थी. डॉ. कलाम ने वर्ष 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था.

आपके निधन से देश ने एक वैज्ञानिक, चिंतक, लेखक और श्रेष्ठ मार्गदर्शक खो दिया है. देश की उल्लेखनीय सेवा के लिए उन्हें हमेशा श्रद्धा के साथ स्मरण किया जायेगा.

श्री परसराम भारद्वाज का जन्म 01 अक्टूबर, 1948 को ग्राम तिवारी पाड़ा-खरोद जिला-बिलासपुर में हुआ था. श्री भारद्वाज अनेक शिक्षा और खेल संस्थानों से संबद्ध रहे. आप 1994-96 तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मध्यप्रदेश के अध्यक्ष रहे. आप सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं तथा वर्ष 1996 में ग्यारहवीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए.

आपके निधन से देश ने एक कर्मठ समाजसेवी एवं लोकप्रिय नेता खो दिया है.

श्री जगन्नाथ सिंह का जन्म 07 मार्च, 1946 को ग्राम चितरंगी, जिला सीधी में हुआ था. श्री सिंह जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष तथा भाजपा जिला सीधी के पांच बार अध्यक्ष और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय महामंत्री रहे. आप प्रदेश की छठवीं, आठवीं, बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभा के सदस्य रहे. आप छठी विधान सभा अवधि में संसदीय सचिव, बारहवीं विधान सभा में स्कूल शिक्षा तथा तेरहवीं विधान सभा अवधि में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण एवं श्रम मंत्री रहे. आप 1992 में राज्यसभा, 1989 तथा 1998 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए.

आपके निधन से प्रदेश ने एक कर्मठ समाजसेवी, आदिवासी नेता एवं कुशल प्रशासक खो दिया है.

श्री सुखलाल कुशवाहा का जन्म 05 जनवरी, 1964 को ग्राम बजवाही जिला सतना में हुआ था. श्री कुशवाहा समाज के कमजोर तथा दलित वर्गो के कल्याण और उत्थान के लिए सतत् सक्रिय रहे. आप राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियों के साथ ही एक कलाकार, खिलाड़ी और संगीतकार के रूप में भी सक्रिय रहे. श्री कुशवाहा ने 1996 में ग्यारहवीं लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी की ओर से सतना का प्रतिनिधित्व किया था.

आपके निधन से प्रदेश ने एक कर्मठ समाजसेवी एवं लोकप्रिय नेता खो दिया है.

श्री हीरालाल मालवीय का जन्म सन् 1918 में हुआ था. श्री मालवीय 1953 से 1961 तक शासकीय सेवा में रहे. आपने समाज के पिछड़े लोगों, गरीबों, अनाथों के कल्याण के लिए निरन्तर कार्य किया. श्री मालवीय ने प्रदेश की तीसरी विधान सभा (1962-67) में जनसंघ की ओर से गुलाना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था.

आपके निधन से प्रदेश ने एक कर्मठ समाजसेवी एवं लोकप्रिय नेता खो दिया है.

श्री कालूराम खटीक का जन्म 08 जनवरी, 1944 को ग्राम पथरिया, जिला दमोह में हुआ था. आप 1980 से 1985 तक ब्लॉक बीस सूत्रीय समिति के सक्रिय सदस्य तथा 1982-85 में अनुसूचित जाति-आदिवासी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रहे. श्री खटीक ने प्रदेश की दसवीं विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पथरिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था.

आपके निधन से प्रदेश ने एक कर्मठ समाजसेवी एवं लोकप्रिय नेता खो दिया है.

महंत स्वामी श्री उमेश मुनि का जन्म 04 फरवरी, 1944 को बुरहानपुर में हुआ था. श्री मुनि 1962 में सन्यास की दीक्षा लेकर धर्म प्रचार के कार्यो में संलग्न रहे. आप अखिल भारतीय संत समिति एवं केन्द्रीय मार्गदर्शक मण्डल के सदस्य और आध्यात्मिक उत्थान मण्डल के संयोजक रहे. श्री मुनि ने प्रदेश की दसवीं विधान सभा (1993-98) निर्दलीय सदस्य के रूप में बुरहानपुर का प्रतिनिधित्व किया था.

आपके निधन से प्रदेश ने एक कर्मठ समाजसेवी एवं धर्म प्रचारक खो दिया है.

श्री धीरज सिंह का जन्म 25 अप्रैल, 1925 को हुआ था. श्री सिंह 1957 में नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष चुने गए. आप 1967 में जिला ओलम्पिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी तथा 1966-67 में सहकारी उपभोक्ता भण्डार के अध्यक्ष रहे. श्री सिंह ने प्रदेश की पांचवीं विधान सभा (1972-77) में कांग्रेस की ओर से देवास का प्रतिनिधित्व किया था.

आपके निधन से प्रदेश ने एक कर्मठ समाजसेवी खो दिया है.

श्री रतन पाटौदी का जन्म 05 अगस्त, 1930 को हुआ था. श्री पाटौदी ने 1964 में राजनीति में प्रवेश किया. आप मीसा में 19 माह जेल में निरूद्ध रहे. आप कुश्ती के मशहूर पहलवान रहे तथा आपने कुश्ती पर पुस्तकें भी लिखी एवं कुश्ती पर केन्द्रित मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया. श्री पाटौदी ने प्रदेश की छठवीं विधान सभा (1977-80) में जनता (एस) की ओर से देपालपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था.

आपके निधन से प्रदेश ने एक प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी एवं लोकप्रिय नेता खो दिया है.

श्री मुनीराम साहू का जन्म 20 अगस्त, 1942 को गुरूवारण्डबरी, बिलासपुर में हुआ था. श्री साहू 1967 से राजनीति में आये. आप 1975 में मीसा में 19 माह जेल में निरद्ध रहे. श्री साहू ने प्रदेश की दसवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोरमी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था.

आपके निधन से प्रदेश ने एक कर्मठ समाजसेवी एवं लोकप्रिय नेता खो दिया है.

श्री रवीन्द्र जैन का जन्म 28 फरवरी, 1944 को अलीगढ़ (उ.प्र.) में हुआ था. श्री जैन ने कई फिल्मों तथा धारावाहिकों में मधुर संगीत दिया. संगीत के क्षेत्र में आपको फिल्म फेयर सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था. मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2003 में आपको लता मंगेशकर सम्मान से तथा भारत सरकार ने वर्ष 2015 में पदमश्री से अलंकृत किया था.

आपके निधन से देश ने एक प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार खो दिया है.

दिनांक 04 अगस्त, 2015 की रात्रि में हरदा जिले में खिरकिया और भिरंगी स्टेशन के निकट काली माचक नदी के पुल पर कामायनी एक्सप्रेस एवं जनता एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से अनेक यात्रियों की मृत्यु हो गयी तथा कई घायल हुए.

यह सदन इस हादसे में मृत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है.

दिनांक 12 सितम्बर, 2015 को झाबुआ जिले के पेटलावद में हुए विस्फोट से अनेक लोगों की मृत्यु हो गयी तथा कई घायल हुए.

यह सदन इस हादसे में मृत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है.

(अन्य दलों के नेताओं के भाषण के पश्चात)

अध्यक्ष महोदय :- मैं, सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। अब सदन दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेगा.

(मौन के पश्चात)

अध्यक्ष महोदय :- दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पांच मिनिट के लिए स्थगित.

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा कल एक पत्र दिया गया है.

अध्यक्ष महोदय – कृपया निधन उल्लेख के बीच में कुछ न बोलें.

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, निधन उल्लेख का पत्र ही मेरे द्वारा दिया गया है. पूरी विषयवस्तु तो सुन लें. किसानों के लिये सत्र बुलाया जा रहा है. प्रदेश में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या,हार्टअटैक से मृत होने वाले दिवंगत किसानों को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते.

अध्यक्ष महोदय – सारी मर्यादा खत्म कर रहे हैं आप.

एक माननीय सदस्य – किसानों के बहुत हितैषी हैं आप पता है बैठ जाईये. पहले श्रद्धांजलि हो जाने दो.

(..व्यवधान..)

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पत्र दिया है या आप इसे निरस्त कर दें. पत्र देने का मुझे अधिकार है.

अध्यक्ष महोदय – निरस्त कर दिया है उस पत्र को.

संसदीय कार्य मंत्री(डॉ.नरोत्तम मिश्र) – अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है.

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, क्या किसानों को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते.

अध्यक्ष महोदय – आप सारी मर्यादाएं सदन की खत्म कर रहे हैं. आप वरिष्ठ सदस्य हैं. आपको यह बिल्कुल शोभा नहीं देता. यह कोई भी बात रिकार्ड में नहीं आयेगी. यह आपका बिल्कुल अनुचित आचरण है. आप निधन के उल्लेख में भी राजनीति करेंगे.

श्री कैलाश विजयवर्गीय – अध्यक्ष महोदय, निधन उल्लेख का भी मजाक उड़ा रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत – xx xx

अध्यक्ष महोदय - आप कृपा करके बैठ जाएं. इसको रिकार्ड नहीं किया जायेगा.

श्री रामनिवास रावत - xx xx

अध्यक्ष महोदय – कार्य सूची अपने आप में एक सूचना है. बैठ जाईये कृपया. श्री रामनिवास रावत जी आप कृपया बैठ जाईये.

डॉ.नरोत्तम मिश्र – अध्यक्ष जी, यह इतना गंभीर विषय है.

एक माननीय सदस्य – आज की कार्यवाही भी किसानों के मुद्दे पर बुलाई गई है.सबको श्रद्धांजलि दे सकते हैं उनको नहीं दे सकते.

(..व्यवधान..)

श्री रामनिवास रावत - xx xx

अध्यक्ष महोदय – आप लोग इस तरह से निधन पर राजनीति कर रहे हैं. यह बहुत खराब बात है. आपको चर्चा में सारी बात बोलना था.

श्री रामनिवास रावत - xx xx

(..व्यवधान..)

डॉ.नरोत्तम मिश्र – अध्यक्ष जी, यह किसानों के लिये सत्र बुलाया गया है उसका भी राजनीतिकरण.

अध्यक्ष महोदय – रावत जी आपको 40-45 साल हो गये आपको बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं आप. निधन का उल्लेख हो रहा है. आप कृपा करके बैठ जायें. आप कुछ तो गंभीरता रखिये. कुछ तो मर्यादाएं समाज में रखिये या सारी ध्वस्त कर देंगे राजनीति के पीछे.

डॉ.नरोत्तम मिश्र – अध्यक्ष जी, आपसे मिलकर कह देते. यह इनको सामान्य ज्ञान नहीं है कि कार्यसूची में उल्लिखित विषय में इसका उल्लेख किया जाता है. अगर इन्होंने कार्यसूची पढ़ी होती तो आपसे व्यक्तिगत मिलकर कह देते.

श्री रामनिवास रावत - xx xx

एक माननीय सदस्य – अभी भी जोड़ सकते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय – कुछ नहीं जोड़ा जायेगा.

नेता प्रतिपक्ष(श्री सत्यदेव कटारे) - अध्यक्ष महोदय, जहां गरोठ उपचुनाव हो रहा है वहां आप श्रद्धांजलि दे रहे हो.आप पेटलावद में श्रद्धांजलि क्यों दे रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय – आप कृपा करके बैठ जाएं.

श्री मुकेश नायक – कृपा करके एक किसानों के लिये लाईन जोड़ दें कि इनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं. हम क्या ऐसी बात कर रहे हैं जो मर्यादा के विपरीत है.

अध्यक्ष महोदय – अरे,मेहरबानी करके एक स्थान तो छोड़ दीजिये राजनीति के लिये. बैठ जाईये आप. यह अलाऊ नहीं कर रहा हूं.

श्री बाला बच्चन – नेता प्रतिपक्ष जी क्यों नहीं हमारे साथ जुड़ेंगे. हम लोगों ने किसानों की मौत पर चर्चा के लिये जो मांग की उससे सरकार मुकर रही है.

डॉ.नरोत्तम मिश्र – अध्यक्ष जी, कभी किसी ने किसानों के लिये सत्र नहीं बुलाया गया आज तक के इतिहास में. किसानों की पीड़ा को समझकर.

श्री बाला बच्चन - तो फिर उनको क्यों नहीं जोड़ रहे हैं. सूखे पर किसानों की मौत से संबंधित और सूखे पर चर्चा के लिये आपने सत्र बुलाया है और उसके बाद जो किसान मृत हुए उनके प्रति संवेदना भी आप व्यक्त नहीं करना चाहते हैं.

डॉ.नरोत्तम मिश्र – अध्यक्ष जी, किसान विरोधी है कांग्रेस.

श्री बाला बच्चन – यह पब्लिक मेनडेट का मिसयूज कर रही है सरकार.

डॉ.नरोत्तम मिश्र – अध्यक्ष जी, श्रद्धांजलि में भी ऐसी (XXX) राजनीति, इसकी जितनी निंदा की जाये कम है.

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय – कृपया सभी बैठ जाएं. रावत जी क्या है. माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाएं.

डॉ.नरोत्तम मिश्र – (..व्यवधान..) करो चर्चा.

श्री बाला बच्चन – आप समय बढ़ाईये.

अध्यक्ष महोदय – आप कोई जबर्दस्ती नहीं कर सकते. आप निधन उल्लेख में राजनीति करते हैं यह बहुत खराब बात है. इस तरह से जबर्दस्ती नहीं कर सकते. मेरा विनम्रता से आपसे अनुरोध है. मर्यादा में रहें.

डॉ.नरोत्तम मिश्र – अध्यक्ष जी, यह इसके बाद उठा सकते थे. यही विषय अगर उठाना था.

अध्यक्ष महोदय – दोनों पक्षों से अनुरोध है कृपया बैठ जाएं.

श्री सत्यदेव कटारे - किसानों को क्यों श्रद्धांजलि नहीं दे रहे.

अध्यक्ष महोदय – प्रतिपक्ष के नेता जी से मेरा अनुरोध है कि कृपा करके बैठ जाएं. माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे.

श्री बाला बच्चन – अध्यक्ष महोदय, चर्चा का समय बढ़वाईये.

अध्यक्ष महोदय – माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं. कृपया सभी बैठ जाएं.

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान):- माननीय अध्यक्ष महोदय, डाक्टर कलाम साहब नहीं रहे वे सही अर्थों में निष्काम कर्मयोगी थे. प्रखर प्रज्ञा के धनी थे. वे हमारे देश के वैज्ञानिक तो थे ही,लेकिन मौलिक चिंतक थे,राष्ट्रवादी विचारक भी थे बहुत अच्छे लेखक भी थे और बच्चों से अद्‌भुत प्यार करते थे. मैंने निष्काम कर्मयोगी इसलिये कहा कि जीवन भर वे काम करते रहे और अंतिम सांस तक भी उन्होंने विश्राम नहीं किया.उनका अगर निधन हुआ तो एक सभा को संबोधित करते हुए हुआ. हमारे देश की सुरक्षा के लिये अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें विकसित की तो डाक्टर कलाम साहब ने कीं,जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ .भारत परमाणु सम्पन्न राष्ट्र बना, उस परमाणु परीक्षण में भी 1998 में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था. शायद उनके बिना हम उस परमाणु परीक्षण की कल्पना नहीं कर सकते थे. उन्होंने वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भारत की प्रतिरक्षा की क्षमता को विकसीत करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और सच में ऐसे राष्ट्रपति भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं हम सबका आदर करते हैं. सबकी अलग अलग क्षमता और विद्वता थी, लेकिन कलाम साहब जैसी लोकप्रियता राष्ट्रपति रहते हुये मैंने पहली बार देखी. अगर राजनेता भी मंच पर होते थे तो जनता और बच्चे उनको नहीं देखते, जनता देखती थी बच्चे देखते थे डाक्टर कलाम साहब की तरफ. सादा जीवन उच्च विचार अपनी सम्पूर्ण क्षमता, अपनी सम्पूर्ण प्रतिभा उन्होंने झोक कर देश की सेवा की. वह समाज के हर वर्ग में लोकप्रिय थे_सचमुच में ऐसा सर्वप्रिय व्यक्तित्व सदियों में कभी कभार जन्म लेता है. गये भी तो अचानक पता चला, भरोसा नहीं हुआ कि कलाम साहब नहीं है.इसी विधान सभा में कलाम आये थे. उन्होंने मध्यप्रदेश के विकास के रोड मैप को हमारे सामने प्रस्तुत किया था . पुराना जो उनका कन्सेप्ट था, गांवों में शहरों जैसी सुविधा देने का वे अपने आप में देश के और प्रदेशों के विकास के लिये महत्वपूर्ण था अभी उनकी हमें आवश्यकता थी.

बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना,
तुम्ही सो गये दास्तां कहते कहते.

अध्यक्ष महोदय, मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं भारत रत्न उनको मिला. अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्ट्रेट की उपाधियां दीं लेकिन उनकी योग्यता, उनकी विद्वता, उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता इतनी थी कि यह उपाधियां उनका सम्मान नहीं करती थीं बल्कि उनसे सम्मानित होती थीं.

अध्यक्ष महोदय, हम सब परिचित हैं स्वर्गीय परसराम भारद्वाज जी से वे कांग्रेस के प्रखर नेता थे, कुशल संगठक थे. कांग्रेस के संगठन को मध्यप्रदेश में बढ़ाने में उनका जबरदस्त योगदान था. वे न केवल संगठन के कुशल शिल्पी थे बल्कि संसदीय ज्ञान के भी अच्छे जानकार थे. उन्होंने लोकसभा के सदस्य के नाते

भी मध्यप्रदेश की अद्‌भुत सेवा की है. उनके निधन से केवल कांग्रेस ने अपना नेता नहीं खोया है बल्कि पूरे मध्यप्रदेश ने एक जनप्रिय नेता, समाजसेवी, जो विशेषकर गरीबों के हितार्थ काम करते रहे, को खोया है.

अध्यक्ष महोदय, जगन्नाथ सिंह जी पिछली विधान सभा में हमारे साथ मंत्री थे उसके पहले भी मंत्री थे आदिवासियों में हमारे ऐसे नेता, चार बार विधायक रहे, दो बार लोकसभा के सदस्य रहे, एक बार राज्यसभा के सदस्य रहे, मंत्री रहे. उन्होंने समाज के गरीब वर्ग की विशेषकर आदिवासी बहनों और भाइयों के कल्याण के लिये अपने आपको समर्पित किया था. वे जिस भी पद पर रहे पूरी गरिमा के साथ उन्होंने काम किया उनके व्यक्तित्व से शालीनता झलकती थी और मंत्रिमंडल के सदस्य के नाते भी उन्होंने प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया. वे भी अचानक हमारे बीच से चले गये. उनके निधन से प्रदेश ने एक लोकप्रिय, जनप्रिय नेता को, एक समाजसेवी को और भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक प्रखर कार्यकर्ता को खो दिया है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री सुखलाल कुशवाह जी का अपना एक व्यक्तित्व था उनके काम करने की अपनी शैली थी **एकला चालो रे** की तर्ज पर वे काम करते थे. उन्होंने अपने परिश्रम से अपनी मेहनत से मध्यप्रदेश की राजनीति में एक अलग स्थान बनाया था. उनके रहते हुए उनके महत्व से कोई इन्कार नहीं कर सकता है. वे राजनैतिक गतिविधियों के साथ-साथ सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय थे. वे कलाकार भी थे, खिलाड़ी भी थे, संगीतकार के रुप में भी सक्रिय रहे उनके निधन से भी हमने एक लोकप्रिय नेता और समाजसेवी को खोया है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री हीरालाल मालवीय जी पहले शासकीय सेवक रहे लेकिन शासकीय उनको रास नहीं आयी उनकी प्रतिबद्धता थी समाज के पिछड़े लोगों की सेवा व गरीबों की सेवा और उनके कल्याण के लिये वे आजीवन काम करते रहे. तीसरी विधान सभा में गुलाना क्षेत्र के लिये जनसंघ की ओर से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था. उनके निधन से भी हमने एक लोकप्रिय नेता और कर्मठ समाजसेवी को खोया है.

माननीय अध्यक्ष जी, कालूराम खटीक जी अनुसूचित जाति और जनजाति के बुंदेलखंड के एक वरिष्ठ नेता रहे. कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते बीस सूत्रीय कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता, कांग्रेस के संगठन को खड़ा करना और उस क्षेत्र की जनता की सेवा के परिणास्वरूप 10 वीं विधान सभा में उन्होंने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व यहाँ किया था, एक लोकप्रिय जनसेवी हमने खोया है.

अध्यक्ष महोदय, आत्मनो मोक्षार्थम् जगत् हिताय च की तर्ज पर सन्यास धारण करके जनता की सेवा में लगे रहने वाले और अपनी लोकप्रियता के बल पर निर्दलीय भी चुनाव जीतने वाले महन्त स्वामी उमेश मुनि जी हमारे बीच नहीं रहे. वे लोकप्रिय नेता थे लेकिन वे सन्यासी थे. उस नाते धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने जीवन भर प्रयास किया, उनके निधन से भी हमने न केवल एक सर्वस्व त्यागी सन्यासी को खोया है बल्कि एक लोकप्रिय नेता को भी खोया है.

अध्यक्ष महोदय, श्री धीरज सिंह जी सहकारिता के आँदोलन में सक्रिय रहे. सहकारी उपभोक्ता भंडार के अध्यक्ष भी रहे. खेलों में भी उनकी गहरी रुचि थी. देवास विधान सभा क्षेत्र की ओर से अपनी जनता का 5 वीं विधान सभा में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, वे कर्मठ समाजसेवी और लोकप्रिय नेता थे.

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रतन पाटौदी जी एक सुप्रसिद्ध पहलवान थे. वे खुद कुश्ती लड़ते भी थे और कुश्ती सिखाते भी थे और वे केवल पहलवान ही नहीं थे, लेखक भी थे. कुश्ती पर केन्द्रित मासिक पत्रिका का प्रकाशन वे वर्षों तक करते रहे. कुश्ती पर उन्होंने पुस्तकें भी लिखीं. जनता पार्टी की ओर से उन्होंने देपालपुर विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था. उनके निधन से एक योग्य खिलाड़ी, जो खेलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध थे, विशेषकर कुश्ती को, ऐसे एक लोकप्रिय नेता को हमने खोया है.

अध्यक्ष महोदय, श्री मुनिराम साहू जी लोकप्रिय जनसेवी थे. आपातकाल का विरोध करते हुए 1975 में 19 महीने जेल में निरुद्ध रहे थे. उन्होंने, जब छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश एक था तब संयुक्त मध्यप्रदेश से लोरमी विधान सभा क्षेत्र की ओर से जनता का यहाँ प्रतिनिधित्व किया था. उनके निधन से भी हमने एक कर्मठ समाजेसवी और लोकप्रिय नेता को खोया है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रविन्द्र जैन जी एक सुप्रसिद्ध संगीतकार थे. रामायण धारावाहिक जब जनता देखती थी तो उसमें उनकी रचनाएँ और उनकी आवाज भी थी, केवल संगीत ही नहीं था. रामायण धारावाहिक को लोकप्रिय करने में और महत्वपूर्ण योगदान दिया है. वे बहुत प्रतिभा संपन्न थे. अनेकों फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, धारावाहिकों में संगीत दिया. वे बैठे बैठे ही रचनाएँ कर देते थे और फिर उसी समय उसको संगीत से सजा कर सुना भी देते थे. वे मध्यप्रदेश से बड़ी गहराई से जुड़े थे, अंतर्आत्मा से, दिल से, जुड़े थे. फिल्म फेयर सहित कई पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया. मध्यप्रदेश सरकार ने भी, लता मंगेशकर जी के नाम पर जो हम पुरस्कार देते हैं, उनको पुरस्कार दिया था और अभी 2015 में ही भारत सरकार ने पद्मश्री से उनको अलंकृत किया था, उनके निधन से एक देशभक्त, लोकप्रिय, प्रसिद्ध गायक और संगीतकार, को हमने खोया है.

अध्यक्ष महोदय, 4 अगस्त 2015 की काल रात्रि में हरदा जिले में खिरकिया और भिरंगी स्टेशन के पास माचक नदी के पुल पर कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से भी अनेकों भाई और बहनों की मृत्यु हुई.कई घायल हुए थे उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं. पेटलावद के दुर्भाग्यपूर्ण विस्फोट की घटना में जो भाई बहन, बेटा-बेटियों ने अपनी जिंदगी खो दीं उनको भी हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय मैं अपनी ओर से, सदन की ओर से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें. उनके परिवार को,उनके मित्रों को, अनुयायियों को यह गहन दुख सहन करने की क्षमता दे. उनके चरणों में श्रद्धांजलि .ओम शांति.

श्री रामनिवास रावत(विजयपुर)--- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हुए हैं . डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जी ,जो इस देश का गौरव थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु कार्यक्रम चलाकर देश को गौरव दिलाया, देश की पहचान बनाई. उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाईलों का निर्माण किया. वह वैज्ञानिक सलाहकार रहते हुए डीआरडीओ के सचिव भी रहे और इन सबके साथ साथ उनका चिंतन सदैव देशहित में रहता था कि हम देश को किस तरह से आगे ले जाए. देश को विकास के पथ पर हम कैसे चलाये ,जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वह इस विधानसभा में भी आए थे उन्होंने विकास का एक रोडमैप तैयार भी किया था और बताया भी था कि किस तरह से हम देश,प्रदेश और युवाओं को आगे ले जा सकते हैं. उन्होंने हमारे देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति को भी सुशोभित किया. राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए सदैव बच्चों और देश की चिंता करते रहते थे. उन्हें पदमभूषण,पदम विभूषण और भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया. अनेक विश्वविद्यालय ने उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की थी. डा. कलाम साहब अंतिम क्षण में भी इस देश के लिए दिशा देने के लिए एक सम्मेलन में भाग लेने गये थे उसी समय उनका निधन हुआ इससे पूरे देश को अपूरणीय क्षति हुई है. डॉ. कलाम साहब के निधन से देश का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक,चिंतक,लेखक और देश का श्रेष्ठ मार्गदर्शक हमारे बीच से चला गया है हम हमेशा श्रद्धा से सदैव स्मरण करते रहेंगे, आनेवाली पीढ़ी भी उन्हें सदैव याद रखेगी.

माननीय अध्यक्ष महोदय, परसराम भारद्वाज जी जो ग्राम तिवारी पाड़ा-खरोद जिला बिलासपुर के थे. अनेक पदों पर रहते हुए उन्होंने प्रदेश की सेवा की . प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और पांच बार लोकसभा के सदस्य रहे और अनेक पदों को सुशोभित किया और प्रदेश के लिए कई कार्य उन्होंने किये उनके निधन से प्रदेश का एक कर्मठ समाजसेवी हमारे बीच से चला गया है. हम उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, जगन्नाथ सिंह जी सीधी में रहकर के छठवी, आठवीं,बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा के सदस्य रहे और संसदीय सचिव भी रहे, मंत्री पद को भी उन्होंने सुशोभित किया, आदिम जाति कल्याण मंत्री के पद पर वह रहे. उनके निधन से एक कर्मठ समाजसेवी और अनुसूचित जनजाति का नेता हमारे बीच से चला गया है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सुखलाल कुशवाहा जी का जन्म सतना में हुआ था उन्होंने सदैव कुशवाहा समाज एवं अन्य दलित वर्गों को साथ लेकर सदैव उनकी लड़ाई लड़ते रहे वह 1996 में ग्याहरवीं लोकसभा के बहुजन समाज पार्टी से सदस्य रहे और लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया. उनके निधन से भी कर्मठ समाजसेवी में नहीं रहा है.

हीरालाल मालवीय जी जो निरंतर पिछड़े,गरीबों और दलितों के लिए संघर्ष करते रहे. तीसरी विधानसभा के जनसंघ की ओर से सदस्य भी रहे उनके निधन से एक लोकप्रिय नेता हमारे बीच से चला गया है हम उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं.

कालूराम खटीक जी भी अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्र में सदैव कार्य करते रहे हैं. दसवीं विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विधायक रहे उन्होंने पथरिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया उनके निधन से भी एक कर्मठ समाजसेवी हमारे बीच में नहीं रहा है. महंत स्वामी श्री उमेश मुनि जी इस तरह के व्यक्ति थे कि दसवीं विधानसभा में राजनीति में रहने के बाद भी निर्दलीय रुप में चुनकर के आये और उसके बाद आध्यात्मिक उत्थान मंडल के संयोजक रहे और इन्होंने दीक्षा लेकर के धर्म के प्रचार के लिए निकल पड़े. ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो इस तरह से राजनैतिक सेवा में रहने के बाद,समाज में रहने के बाद पूर्णत: सन्यास की दीक्षा लेकर के निकल जाएं. इनके निधन से भी एक कर्मठ समाजसेवी हमारे बीच से चला गया है.

श्री धीरज सिंह जी,पांचवीं विधानसभा के कांग्रेस की ओर से देवास के सदस्य रहे. जिला ओलम्पिक एसोसिएशन के भी सेक्रेटरी रहे, नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष भी रहे. इनके निधन से भी अपूरणीय क्षति हमें हुई है.

श्री रतन पाटौदी जी जो एक मशहूर पहलवान रहे और कुश्ती के क्षेत्र में इन्होंने मध्यप्रदेश को काफी सम्मान दिलाया.पाटौदी जी छठवीं विधानसभा में जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं.इनके निधन से भी एक लोकप्रिय नेता हमारे बीच से चला गया है.

श्री मुनाराम साहू जी भी दसवीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदस्य रहे. इनके निधन से हमारा एक कर्मठ समाजसेवी प्रदेश से चला गया है.

श्री रवीन्द्र जैन, जिनके बारे में कहा गया कि इऩ्होंने रामायण और महाभारत जैसे सीरियलों में अपना संगीत दिया. जिस समय रामायण और महाभारत सीरियल चला करते थे उस समय टी.व्ही. बहुत कम हुआ करते थे. उस समय जब इनका सीरियल आता था तो पूरे नगरों में सनाटा सा पसर जाता था, ऐसी स्थिति इन्होंने रामायण और महाभारत में संगीत देकर अपनी पहचान दिलायी. मैं इन्हें अपने एक करौली केलादेवी एक जागरण कार्यक्रम में भी ले गया था. मैं बहुत अच्छे से उनसे परिचित था. उनसे पारिवारिक संबंध रहे. उनके निधन से एक महत्वपूर्ण संगीतकार हमारे बीच से चला गया है और इन्हें कई अवार्ड,फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ. मध्यप्रदेश सरकार ने भी इनको लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया. मैं समझता हूँ कि उनके चले जाने से संगीत के क्षेत्र में पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को अपूरणीय क्षति हुई है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. 4 अगस्त 2015 में हरदा जिले में हुए रेलवे हादसे में कई व्यक्ति मृत एवं कई घायल हुए. उसमें समस्त मृत व्यक्तियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 सितम्बर 2015 को झाबुआ जिले के पेटलावद में एक विस्फोट में अनेक लोगों की मृत्यु हो गयी. हम उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार को गहन दु:ख सहन करने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं.

इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा जो पत्र दिया गया था कि इस बार अवर्षा और भयंकर सूखे के कारण लगातार अगस्त,सितम्बर,अक्टूबर माह में जिन किसानों ने आत्म हत्या की हैं, हार्ट अटैक के कारण जिन किसानों की मृत्यु हुई है वे परिवार भी पूर्ण रुप से विपन्नता की स्थिति में पहुंच गये हैं.उनके बच्चों के ऊपर से एक मालिक का साया उठ गया है. मैं उन सब जितने भी किसान जो कर्ज के बोझ के तले दबे होने के कारण आत्महत्या या हार्ट अटैक से दिवंगत किसानों को भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ.मैंने भी एक पत्र दिया था उसमें 60 लोगों के लगभग नाम हैं. मैं चाहता हूँ कि पूरा सदन इससे सहमत होगा.

श्री सत्यप्रकाश सखवार(अम्बाह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपके द्वारा जिन महान विभूतियों के निधन का उल्लेख किया जा चुका है. उऩ्होंने वास्तव में ही इस समाज के लिए, देश के लिए अपनी पूरा जीवन लगा कर के बड़े परिश्रम से उन्होंने समाजसेवा के क्षेत्र में काम करके आगे बढ़ने का काम किया था. जिनके चले जाने से आज वास्तव में हम सबको बड़ी क्षति हुई है. पूरे राष्ट्र को क्षति हुई है.इनकी क्षतिपूर्ति करना सम्भव नहीं है. एक विद्वान ने लिखा था, कुछ लोग महान होते हैं, कुछ महानता प्राप्त कर लेते हैं, कुछेक के ऊपर महानता थोप दी जाती है, इन सभी विभूतियों ने अपने बलबूते पर ऐसी महानता प्राप्त की है. मैं अपनी ओर से,अपने दल की ओर से इन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. धन्यवाद.

..am

श्री कैलाश विजयवर्गीय – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, पर विशेष रूप से मैं रतनदादा के बारे में उल्लेख सदन में जरूर करना चाहूंगा. यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इन्दौर में जब छात्र राजनीति करता था तब रतनदादा अपनी बुलंदियों पर थे. इन्दौर समाजवादी आंदोलन का भी केन्द्र रहा, वहां जॉर्ज फर्नांडिस, लाड़ली मोहन निगम जी और मधु लिमये जी आदि जैसे बड़े-बड़े सब लोग आते थे. वहां एक चौगान है बजाज खाना चौक, वहां पर कल्याण जैन, रतनदादा आदि सब लोग बैठते थे. एक समय इन्दौर कुश्ती का भी बहुत बड़ा केन्द्र था और समाजवादी आंदोलन का केन्द्र भी था. उस समय मेहरूद्दीन पहलवान, चंगीराम पहलवान के वहां पर दंगल हुआ करते थे. उस समय रतनदादा एक बहुत अच्छे पहलवान माने जाते थे. वे समाजवादी आंदोलन के प्रवर्तक थे, युवा नेता थे और बहुत अच्छे वक्ता भी थे. अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में से हूँ जो उनका भाषण सुनने जाते थे. अगर कहीं समाजवादी पार्टी की सभा होती थी तो रतनदादा भी वहां होते थे और मैं कुश्ती प्रेमी भी हूँ तो मैं कुश्ती देखने जाता था कि रतनदादा लड़ेंगे क्या. देश ही नहीं वे दुनिया के सबसे खूबसूरत पहलवान थे. जब वे कपड़े उतार कर दंगल में खड़े होते थे तो पूरे कैरेना में उपस्थित लोग सिर्फ उनको देखते ही ताली बजाते थे, वे इतने खूबसूरत पहलवान थे. अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से वे बेदाग राजनीति की काजल की कोठरी में रहे. वे बहुत ही ओजस्वी वक्ता थे और साफ-साफ बोलने वाले नेता थे. उनके जाने से निश्चित रूप से इंदौर को भी क्षति हुई है, राजनीति के क्षेत्र में क्षति हुई है, समाजवादी आंदोलन से क्षति हुई है और कुश्ती जो उनका एक प्रिय विषय था, आखरी दम तक वे कुश्ती के पत्रकार की हैसियत से वे लिखते रहे और इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मैं अपनी ओर से और कुश्ती जगत की ओर से समाजवादी आंदोलन के प्रवर्तक रतन पाटौदी जी चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ.

अध्यक्ष महोदय – मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ. अब सदन दो मिनट खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेगा.

(सदन में दो मिनट का मौन रखा गया.)

अध्यक्ष महोदय – ऊँ शांति, दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित.

(11.18 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई.)

समय 11.37 बजे { अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए }

अध्यक्ष महोदय- आज सदन की दीर्घा में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी जी उपस्थित हैं ,सदन की ओर से उनका स्वागत है.

श्री कैलाश विजयवर्गीय- अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आधा मिनट का समय चाहता हूं. अध्यक्ष महोदय यह पूरे सदन के लिए और पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि FORBS मेगजीन ने देश के यशस्वी प्रधान मंत्री की दुनिया के सबसे पॉवरफुल व्यक्तियों का जो चयन किया है उसमें नवें नंबर पर देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का चयन किया गया है. (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ नरेन्द्र मोदी जी की बात नहीं है, देश के प्रधान मंत्री जी की बात नहीं है. यह देश की सवासौ करोड़ जनता का सम्मान है और न सिर्फ फोर्ब्स मेगजीन ने ,वर्ल्ड एकानामिक फोरम द्वारा भी पिछले 100 साल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तियों का चयन किया गया है उसमें दसवें नंबर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं. तो विश्व स्तर पर भारत को जो सम्मान देश के प्रधान मंत्री जी ने दिलवाया है यह न सिर्फ उनका सम्मान है, देश की सवा सौ करोड़ जनता का सम्मान है. मैं पूरे सदन से निवेदन करूंगा कि सर्वानुमति से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बधाई पत्र भेज कर बधाई दे.

अध्यक्ष महोदय- मैं समझता हूं कि सदन श्री विजयवर्गीय जी की भावनाओं से सहमत है. निश्चित रूप से प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्र का मान बढ़ाया है. यह सदन और राष्ट्र इससे गौरवान्वित महसूस करता है. सदन माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता है. (मेजों की थपथपाहट)

कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक गुरूवार दिनांक 5 नवंबर 2015 को संपन्न हुई , जिसमें वर्ष 2015-16 की द्वितीय अनुपूरक अनुमान (विशेष) की मांगो पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक के पुरःस्थापन,विचार एवं पारण पर चर्चा के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है.

श्री बाला बच्चन- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि माननीय विजयवर्गीय जी ने किस नियम के अन्तर्गत प्रधान मंत्री जो को ये सम्मान दिलाने की बात कहलायी है.

अध्यक्ष महोदय- पहले भी ऐसी परम्परा रही है.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ.नरोत्तम मिश्रा) –अध्यक्ष महोदय,point of information.

श्री बाला बच्चन – अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में लोग सूखे से मर रहे हैं , माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष पैकेज भी दें. जो पहले प्रदेश को राहत राशि मिलती थी वह राहत राशि दी नहीं जा रही है.

अध्यक्ष महोदय- पहले भी परम्परा रही है, आप आकर के रिकार्ड दे लीजिए. आप बहुत पुराने सदस्य हैं.

श्री बाला बच्चन- प्रधानमंत्री जी किसानो के लिए एक बड़ा पैकेज तो दें.

अध्यक्ष महोदय- जुलाई,2015 सत्र की दिनांक 23 जुलाई,2015 से 31 जुलाई ,2015 तक स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियां स्थायी आदेश 13-क की अपेक्षानुसार पटल पर रखी गयी.

अध्यक्ष महोदय :- चतुर्दश विधान सभा के विगत सत्रों में पारित निम्नलिखित सात विधेयकों को मान. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है :-

1. मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2015 (क्रमांक 8 सन् 2015) –(अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2015)

2. मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2015 (क्रमांक 9 सन् 2015) –(अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2015)

3. मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 12 सन् 2015)-(अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2015)

4. मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015) – (अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2015)

5. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015) –(अधिनियम क्रमांक 17सन् 2015)

6. मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015)-(अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2015) एवं

7. मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2015 (क्रमांक 6 सन्2015)-(अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2015)

इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे.

विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

अध्यक्ष महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 65 - मैहर से निर्वाचित सदस्य, श्री नारायण त्रिपाठी ने विधान सभा के अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया है, जिसे मेरे द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2015 को स्वीकृत किया गया है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी—अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का माईक काम नहीं कर रहा है.

अध्यक्ष महोदय—माईक काम कर रहा है. पहले आपके मुख्य सचेतक जी बोल रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 150 का निलंबन करके द्वितीय अनुपूरक अनुमान के पुरस्थापन और चर्चा करने की स्वीकृति तो प्रदान कर दी. अध्यक्ष महोदय, विधानसभा को जो सूचना दी जाना चाहिए थी, वह सूचना विधानसभा को कब प्राप्त हुई वह बता दें. नियमावली के नियम 60(3)में दिया गया है कि—**उस नियम के अधीन शासकीय विधेयकों को पुरःस्थापित करने, बजट प्रस्ताव की सूचना 7 दिन...**

श्री कैलाश विजयवर्गीय—अध्यक्ष महोदय, कभी भी विधानसभा सचिवालय के पत्राचार की चर्चा यहां पर कभी नहीं हुई है. इसलिए इस बारे में यदि उनको जानकारी चाहिए तो आपसे कक्ष में व्यक्तिगत रुप से ले सकते हैं. परन्तु इस सदन के अंदर कभी भी विधानसभा के सचिवालय के बारे में कोई चर्चा कभी भी नहीं हो सकती. यह परम्परा रही है.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, नियम 60(3) के अधीन यह स्पष्ट दिया है **इस नियम के अधीन शासकीय विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना की कालावधि 7 दिन पूर्व की होगी.** मैं यही जानकारी चाह रहा हूं कि सात दिन पूर्व विधानसभा सचिवालय को सूचना प्राप्त हो गई.

संसदीय कार्यमंत्री (डॉ नरोत्तम मिश्रा)—हां हो गई है. बता रहे हैं. आप सुनिये तो.

श्री बाला बच्चन—गलत परम्परा प्रारंभ कर रहे हैं.

डॉ नरोत्तम मिश्रा—कोई गलत परम्परा प्रारंभ नहीं की जा रही है.

श्री रामनिवास रावत—इस नियम को भी निलंबित कर सकते हैं जो नहीं किया गया. इसलिए मैंने उठाया.

श्री बाला बच्चन—अध्यक्ष महोदय, आप गलत परम्परा शुरु कर रहे हैं.

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता)—किसानों के लिए विशेष सत्र बुलाना क्या गलत परम्परा है. अगर किसानों के लिए सरकार चर्चा कर रही है. पैसे की व्यवस्था की जा रही है. किसानों के लिए तो सारे नियम शिथिल किये जा सकते हैं. पहली बार किसानों के लिए विशेष सत्र बुलाया. ऐसा आपने 50 सालों कभी नहीं किया.

डॉ नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष महोदय,यदि रामनिवास जी इसी पर आपत्ति कर देंगे कि यह विशेष सत्र बुलाने की परम्परा नहीं है.

श्री रामनिवास रावत—मैंने आपत्ति नहीं की.

डॉ नरोत्तम मिश्रा—कर सकते हैं. मेरी बात पूरी सुन लें. जब विशेष सत्र के लिए हमने नई परम्परा कायम की है तो वह भी नई परम्परा के तहत ही सूचना दी गई है. आप उसको समझने की कोशिश तो करें. यह विशेष सत्र भी नियम परम्पराओं को शिथिल करके बुलाया गया है. (व्यवधान)

श्री कैलाश विजयवर्गीय – अध्यक्ष महोदय यह आसंदी का अधिकार है.

डॉ नरोत्तम मिश्र – नई परम्परा डालकर नियम शिथिल करके यह सत्र बुलाया गया है. सिर्फ किसानों की समस्या पर चर्चा के लिए बुलाया गया है...(व्यवधान)—और उसी के तहत सूचना दी गई है.

श्री कैलाश विजयवर्गीय – यह आपका विवेक है..(व्यवधान)..

डॉ नरोत्तम मिश्र – माननीय अध्यक्ष महोदय यह सत्र अलग से नियम शिथिल करके किसानों के हित के लिए बुलाया गया है. अब उस पर चर्चा के लिए कौन मना कर रहा है, आखिर चर्चा करने के लिए किसने मना किया है. हम तो यह कह रहे हैं कि आप व्यवधान न करें. चर्चा को मना नहीं है व्यवधान करने को मना कर रहे हैं. आप श्रद्धांजलि कार्यक्रम से लेकर अभी तक लगातार व्यवधान किये जा रहे हैं. यह किसानों के बारे में आपका सोच बताता है.

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) – माननीय अध्यक्ष महोदय अगर आप अनुमति दें तो एक मिनट मैं बोलना चाहता हूं. मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से ए क अनुरोध करना चाहता हूं. आरोप

प्रत्यारोप के बहुत अवसर हैं, हम लोग लगाते रहेंगे, राजनीति में कई बार होता है ,होता रहेगा लेकिन मेरी विनम्र प्रर्थना है कि यह सत्र हम लोग होने दें. यह सत्र इसलिए बुलाया गया कि किसानों को फौरी राहत की राशि हमें बांटना है....(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हमें किसानों को राहत की राशि बांटना है उसकी तत्काल आवश्यकता है. इसलिए विधान सभा से अनुमति लेने के लिए यह सत्र बुलाया गया है मैं कांग्रेस के मित्रों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इसमें (XXX) राजनीति न करें कृपया.

अध्यक्ष महोदय – यह घटिया शब्द विलोपित करें.

श्री शिवराज सिंह चौहान – इस पर (XXX) राजनीति न करें यह ठीक नहीं है...(व्यवधान).. यह तरीका ठीक नहीं है, आप किसान को राजनीति की बलि न चढ़ायें, अध्यक्ष महोदय हर सत्र में कांग्रेस यह ही करती है, अरे एक सत्र तो ठीक है लेकिन अब तो चलने दें यह कोई तरीका होता है. सारा प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है. अब इसमें बात बात पर आरोप प्रत्यारोप बीच बीच में खड़े होना,..(व्यवधान)..हम किसानों को राहत की राशि देना चाहते हैं उ सके लिए सत्र बुलाया गया है उसके लिए यहां पर विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया गया है. इसलिए मैं यहां पर निवेदन करता हूं कि इसको अपनी (XXX) राजनीति की बलि मत चढ़ाइये, इसके पहले आपने कई सत्र (XXX) राजनीति की बलि पर चढ़ाये हैं. इस तरह की हरकत कांग्रेस करती है. यह अशोभनीय है, यह आपका किसान विरोधी दृष्टिकोण है. क्या आपको हर बात पर हंगामा खड़ा करना है. और कुछ नहीं है आपके पास..(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कांग्रेस के इस कृत्य की यहां पर निंदा करता हूं.

डॉ नरोत्तम मिश्र – हम घोर निंदा करते हैं ..चर्चा नहीं करना चाहते हैं..(व्यवधान) केवल हल्ला करना चाहते हैं.

श्री शिवराज सिंह चौहान – किसानों को राहत नहीं देना चाहते हैं केवल (XXX) राजनीति करना चाहते हैं. इसलिए प्रार्थना करता हूं कि इसको कम से कम सुचारू रूप से पारित हो जाने दें. यह मेरा निवेदन है आपसे...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – माननीय श्री रावत जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था. आपने यहां पर नियम 60 पढ़ा है. इसको जरा ध्यान से पढ़ लें. यह विधेयकों का प्रकाशन तथा पुर:स्थापन है. वित्तीय विधेयकों के नियम 149 से 159 में दिये गये हैं. कृपया करके इसको देख लें. उनका पालन करते हुए, वित्तीय विषयों में प्रक्रिया अध्याय 19 पेज 68 यह वित्तीय विधेयक है. इसका यहां पालन किया गया है. आपका व्यवस्था का प्रश्न निरस्त किया जाता है...(व्यवधान)..

श्री जयंत मलैया-- अध्यक्ष महोदय मैं राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2015-2016 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान (विशेष) का उपस्थापन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय-- मैं इस पर चर्चा और मतदान के लिये दिनांक 05 नवम्बर, 2015 को 2 घंटे का समय नियत करता हूं ।

सभापति तालिका

अध्यक्ष महोदय-- मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, मैं, निम्नलिखिल सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नाम निर्दिष्ट करता हूं ।

1. श्री मानवेन्द्र सिंह,
2. श्री कैलाश चावला,
3. श्रीमती अर्चना चिटनीस
4. श्री गिरीश गौतम,
5. श्री रामनिवास रावत, तथा
6. श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

वर्ष 2015-2016 की द्वितीय अनुपूरक अनुमान (विशेष) की मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय-- अब, अनुपूरक अनुमान (विशेष) की मांगों पर चर्चा होगी, सदन की परम्परा के अनुसार सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत मैं, वित्त मंत्री से कहूंगा कि वह सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत कर दें । मैं, समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

श्री जयंत मलैया-- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि-

श्री सुंदरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, मेरा ज्वाइंट ऑफ आर्डर है ।

अध्यक्ष महोदय-- माननीय मंत्री जी, इनका पाइंट ऑफ आर्डर हो जाने दीजिये । दो मिनट सुन लें ।

श्री सुंदरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के आदेशानुसार यह विशेष सत्र बुलाया गया है, मैं समझता हूं कि सदन के नेता सदन में उपस्थित हैं, इनके द्वारा कोई न कोई पत्र लिखा गया होगा, सरकार के द्वारा कि यह बैठक विशेष सत्र किस बात के लिये बुलाया गया है । जो कार्यसूची हम लोगों को भेजी गई, जो विधायकों को सूचना दी गई इस विशेष सत्र के बारे में उसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि सूखे पर चर्चा के लिये यह बैठक बुलाई गई है । हमारा यह मानना है कि इस विशेष सत्र बुलाने के लिये सदन के नेता ने भी यह सूचना सरकार के माध्यम से महामहिम को भेजा होगा कि सूखे पर चर्चा करने के

लिये । यहां पर मेरा यह कहना है कि जब कार्यसूची आई है तो कार्यसूची जो हम लोगों को आवंटित हुई उसमें सूखे पर चर्चा का उल्लेख कतई कहीं नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय-- ठीक है, बात आ गई आपकी ।

श्री सुंदरलाल तिवारी-- दूसरी बात कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय-- पाइंट ऑफ आर्डर में एक ही विषय उठाया जाता है, आप नियम पढ़ लीजिये ।

श्री सुंदरलाल तिवारी-- एक ही है, इससे जुड़ा हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय-- देखिये, एक बात है जब हम सुन रहे हैं तो आपको नियम से चलना पड़ेगा, पाइंट ऑफ आर्डर में एक ही विषय उठाया जाता है ।

श्री नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्ष जी, समस्या और समाधान दो तरह की बातें विनियोग में होती है ।

श्री गोपाल भार्गव-- अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, सूखे पर चर्चा के लिये विनियोग विधेयक पर आपने दो घंटे का समय निर्धारित किया है इस पर पर्याप्त चर्चा हो सकती है । सूखे की अलग चर्चा और विनियोग विधेयक पर अलग चर्चा मैं मानकर चलता हूं रिपीटेशन होगा इसमें, और जो महत्वपूर्ण विषय है कि पारित करना है हमें यह विनियोग, तो इस कारण से मैं मानकर चलता हूं कि सदस्य इसमें अवरोध पैदा न करें, इसके लिये सुचारू रूप से चलने दें ।

श्री सुंदरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय

अध्यक्ष महोदय-- तिवारी जी सुन लीजिये, आपकी बात पर ही चर्चा हो रही है । आपने जो विषय उठाया उसी पर माननीय मंत्री जी ने बोला ।

श्री नरोत्तम मिश्रा-- मैं भी यह निवेदन कर रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, सूखा एक समस्या है, आज जो विनियोग है ।

श्री सुंदरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय

अध्यक्ष महोदय-- बैठ तो जाइये आप, आप आपकी बात का उत्तर नहीं सुनना चाहते क्या ।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- मैं बोल तो लूं, निर्णय तो इनको देना है ।

अध्यक्ष महोदय-- आप ही की बात पर चर्चा हो रही है ।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- माननीय अध्यक्ष महोदय, सूखा एक समस्या है और यह विनियोग जो आया है वह समाधान है, सूखे का । हम समाधान और समस्या दोनों पर सामूहिक रूप से चर्चा करकर इसको पारित करना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारी विनम्र प्रार्थना है आपसे ।

अध्यक्ष महोदय-- आपका पाइंट ऑफ आर्डर अनुमानों पर आधारित है, आप जरा भाषा देख लें आपने क्या बोली, और अनुमानों पर आधारित कोई विषय उठाया नहीं जा सकता । माननीय जयंत मलैया जी...

श्री जयंत मलैया-- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि-

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 12, 13, 17, 22, 29, 36, 41, 57, 58, 64, तथा 74 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर आठ हजार चार सौ सात करोड़, चौबीस सलाख, इक्यासी हजार, आठ सौ चालीस रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये. (व्यवधान)

डॉ0 नरोत्तम मिश्रा-- विशेष सत्र सूखे पर ही बुलाया गया है, हम चाहते हैं कि आप चर्चा करो, व्यवधान मत करो, व्यवधान कर रहे हैं आप, आप चाहते नहीं हैं कि चर्चा हो । देखिये यह सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता देख रही है इस कृत्य को । आप चाहते नहीं है कि चर्चा हो, आप व्यवधान कर रहे हैं, यह सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता आपको देख रही है.

श्री बाला बच्चन – अध्यक्ष महोदय, मेरा पाईंट आफ आर्डर है.

अध्यक्ष महोदय—काफी चर्चा इस पर हो चुकी है. जब चर्चा हो तब आप इस पर बोल लीजियेगा.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा –अध्यक्ष महोदय, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष बनने की होड़ है और कुछ नहीं है. नेता प्रतिपक्ष बोल नहीं पा रहे हैं और यह लगातार कोशिश कर रहे हैं पाईंट आफ आर्डर..इसकी क्लिपिंग निकाल निकाल कर के दिल्ली भेजेंगे, अपनी प्रतिस्पर्धा में हाउस का उपयोग न करें . अध्यक्ष जी , कितने पाईंट आफ आर्डर आयेंगे 12 बज गये हैं एक पर भी चर्चा नहीं होने दी. श्रृद्धांजलि में व्यवधान उसके बाद लगातार व्यवधान. चर्चा चाहते ही नहीं है यह लोग.

अध्यक्ष महोदय—माननीय मुख्य सचेतक जी अब आपको जो कुछ कहना है वह आप चर्चा के समय कहिये. आपको मैं अवसर दूंगा. प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ. श्री रामनिवास रावत अपनी बात कहें.

श्री रामनिवास रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रथम वक्ता के रूप में..

(नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपनी बात कहने के लिये हाथ उठाने पर)

अध्यक्ष महोदय—नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाह रहे हैं.

श्री सुन्दरलाल तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मेरा माइक अपने हिसाब से काम करता है जब बोलता हूं बंद हो जाता है , अभी नहीं बोल रहा हूं तो चालू हो गया है.(हंसी)

अध्यक्ष महोदय—तिवारी जी आपका माइक बंद रहे तो सदन ठीक से चलेगा.(हंसी)

नेता प्रतिपक्ष(श्री सत्यदेव कटारे)—अध्यक्ष महोदय बोलने वाले वक्ताओं की लिस्ट आप तक पहुंची कि नहीं. लिस्ट में से आप नाम पुकार लें.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, प्रथम वक्ता के रूप में माननीय महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा जी को बोलने की अनुमति प्रदान की जाये.

अध्यक्ष महोदय—आप सहमत हैं.

श्री रामनिवास रावत- जी हां . मैं सहमत हूं.

श्री सत्यदेव कटारे – अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना थी कि हमें आप अनुमति दे दें. तीन बार हम हाथ उठा चुके हैं. मैं मर्यादा नहीं तोड़ रहा हूं तो आप बोलने नहीं दे रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—नहीं..नहीं. ऐसा नहीं है. नेता प्रतिपक्ष जी आप बोलिये. आपकी मर्यादा हम भी नहीं तोड़ेंगे. आप बोलिये.

श्री सत्यदेव कटारे – अध्यक्ष महोदय, मैं इतना भोला और सीधा नहीं हूं. यह बता रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय—(श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा के खड़े होने पर) माननीय महेन्द्र सिंह जी कृपया बैठ जायें. नेता प्रतिपक्ष की बात आ जाये. वे कह रहे हैं कि हम इतने भोले नहीं हैं (हंसी) नेता प्रतिपक्ष का माइक तो चालू करो.

श्री सत्यदेव कटारे – माइक बंद है.

अध्यक्ष महोदय—चालू हो गया है. आप बोलिये.

श्री सत्यदेव कटारे – अध्यक्ष महोदय, बीच में बंद तो नहीं होगा. हम बोल नहीं रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—आप बोलिये न. माइक चालू है.

श्री सत्यदेव कटारे – अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ यह पूछ रहे हैं कि आज की दैनिक कार्यसूची में तीन तरह के प्रस्ताव आये हैं . विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिये हमने डेढ़ महीने पहले चिट्ठी लिखी , जबाव नहीं आया मंत्री जी ने मना कर दिया था कि विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलायेंगे. अब यह किस मुंह से कह रहे हैं कि हमने बुलाया है. एक बात. दूसरी बात यह कि विधानसभा का विशेष सत्र किसानों की पीड़ा को लेकर के , सूखा को लेकर के, परेशानी को लेकर के बुलाया गया है. ठीक है. लेकिन इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है कि किसानों को, दूसरी चिट्ठी आती है कि सप्लीमेन्टरी बजट. सप्लीमेन्टरी बजट भी आ गया. अध्यक्ष महोदय पहले एक से तो निपट लो. पहले किसानों की ही चर्चा कर लो. और बजट और किसानों की समस्या दोनो करना चाहते हैं तो उसकी समय सीमा आप सीमित मत करो. यह हमारी प्रार्थना है. जो बोलने चाहता है आप बुलवायें. हम मना नहीं कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी, आप 165 लोग हैं न पर एक बात बताओ कि यहां पर कैलाश विजयवर्गीय जी बैठे हुये हैं , दूसरे की कुर्सी पर क्यों बैठे, अधिकार है उन्हें ? अध्यक्ष महोदय, क्या आपने उनको वहां बैठने की अनुमति दी है ?

डॉ. नरोत्तम मिश्रा – वे अपनी कुर्सी पर बैठे हुये हैं.

श्री सत्यदेव कटारे – अरे टीवी में आप देखें न नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय.. क्या आज की तारीख में वे मंत्रि-मंडल में मंत्री हैं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा – यह अलग विषय है. कुर्सी तो उनकी वही है. कुर्सी कब चेंज हो गई उनकी. अब वो महामंत्री हैं.

श्री बाला बच्चन – सदन में तो मंत्री, महामंत्री नहीं, सदस्य हैं.

श्री सत्यदेव कटारे- कुर्सी तो लकड़ी की है. लेकिन उनको यहां पर बैठने का अधिकार नहीं है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा – मैं कह रहा हूं कि इतना गंभीर विषय है .

अध्यक्ष महोदय—मंत्री जी बैठिये, नेता प्रतिपक्ष की बात भी आ गई है. माननीय महेन्द्र सिंह जी अपनी बात को प्रारंभ करें..

श्री गोपाल भार्गव – अध्यक्ष महोदय, क्या अनुपूरक की चर्चा में यह भी तय होगा कि किस सीट पर कौन बैठेगा.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (मुंगावली) -- अध्यक्ष महोदय, में 4 दिनों से मेरे विधान सभा क्षेत्र और अशोक नगर जिले के दौरे पर था. किसानों के संकट को लेकर आज हम बड़ी भारी जनाक्रोश रेली अशोक नगर में 4 बजे शाम को कर रहे हैं. इसलिये मैं जल्दी बोलकर जाना चाहता हूं. दो दिन पहले अशोक नगर जिले के बानोरा गांव में मुझे जाना पड़ा. जहां एक किसान अशोक अहिरवार ने फांसी लगाकर आत्महत्या की. मैं उसके घर में गया, वहां देखा कि क्या दुर्दशा थी, उस पर 80 हजार का कर्ज था. टूटी-फूटी झोपड़ी, उसमें उसने रस्सी से फांसी लगा ली.

अध्यक्ष महोदय-- आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं. अनुपूरक मांगों में जो विषय उसमें होते हैं, उन पर ही बात की जाती है. आपसे अनुरोध यह है, मैं आपको कोई टोक नहीं रहा हूं, किन्तु आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपा करके इसका ध्यान रखें कि जो नियमों में है...

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा -- अध्यक्ष महोदय, जरुर रखूंगा. मैं विषय पर ही बोलूंगा. विषय से नहीं हटूंगा.

श्री बाला बच्चन – संसदीय कार्य मंत्री जी, अब आप बोलें. मुख्यमंत्री जी इतने एक्साइटेड हो रहे थे. आसंदी से अब दिशा ही बदल रही है.

अध्यक्ष महोदय-- दिशा कहां बदल रही है. अनुपूरक में कृषि का ही तो विषय है. आप पढ़िये तो.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा -- मैं परसों आत्महत्या वाले किसान के घर गया था. उसकी पीड़ा मैं बता रहा हूं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा – प्रदेश के सूखे पर चर्चा हो रही है और इनमें से एक भी कांग्रेस का नेता ऐसा है, जो अपनी विधान सभा को छोड़कर कहीं दूसरे जिले में गया हो. एक भी बता दो. (श्री रामनिवास रावत द्वारा बैठे बैठे कहने पर कि हम गये थे).. और बता तो दो, हमारा विधायक जवाब देगा कि कौन सा जिला है बोलो. अभी हमारा विधायक जवाब देगा, उस जिले का कि कहां गये थे. यह भी बतायेंगे कि कहां पर गये थे. ..(व्यवधान).. बताओ ना. पूरे प्रदेश की जनता सुनेगी. बताओ कहां गये प्रदेश में. पूरे प्रदेश से कांग्रेस का एक विधायक नहीं गया. प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं. एक जना नहीं गया, हमारा विधयाक जवाब देगा, किस जिले में गये और कहां गये और कैसे गये थे, बोलो ना. अगर गये तो बोलो.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा -- अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरुआत ही अपने विधान सभा क्षेत्र से की है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- केवल अपने अपने विधान सभा में गये हैं. इसलिये मैं कह रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया माननीय सदस्य अपनी बात बोलें.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा -- अध्यक्ष महोदय, 5 दिनों से मैं अपने विधान सभा क्षेत्र और जिले का दौरा कर रहा था. कुछ दिन पहले वहां पर मणिमहीदपुर नाम का गांव है. वहां के किसान श्रीराम यादव ने जहर पी लिया और आत्महत्या कर ली. मेरे जिले की बात कर रहा हूं, जहां से मैं विधायक हूं. हमको रोना आया, हम उनके घर गये. महिलाएं और बच्चे रो रहे थे. उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता. आप अनुमान ही लगा सकते हैं. तो प्रदेश में अन्य जगह भी किसानों ने आत्महत्या की है. आंकड़ों में मतभेद हो सकता है. लेकिन आत्महत्याएं की हैं और मेरे ख्याल से सभी विधायकों को अपने अपने जिलों में जिन किसानों ने आत्हत्या की होगी, उनके प्रति सहानुभूति जरुर होगी. प्रदेश में हमारे गृह मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं, वह मैं आपको बता रहा हूं. 2004 में 1638, 2005 में 1248, 2006 में 1375, 2007 में 1263, 2008 में 1379 ,2009 में 1395, 2010 में 1237, 2011 में 1326 बाकी आंकड़े गृह मंत्री जी के पास होंगे. यह राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यरो के आंकड़े हैं. यह आत्महत्याएं किसान की हुई हैं. कोई नई बात नहीं है कि किसान ने आत्हत्या की है. कई सालों से ऐसा हो रहा है और हमारे अधिकारी कई बार उस आत्महत्या को या तो पागल हो गया था या उसने हार्ट अटैक हो गया या शराब पीकर मर गया. ऐसा करके उसको टालते रहते हैं. उसके बाद भी, ये गृह मंत्री, उमाशंकर गुप्ता जी के आंकड़े हैं. तो मैं कह रहा हूं कि हर साल हो रहे हैं, हमको जागृत हो जाना चाहिये. (डॉ नरोत्तम मिश्रा के बैठे बैठे कुछ कहने पर) उस समय भी हुए होंगे. मैं यह नहीं कह रहा हूं. इसको लेकर किसान आन्दोलन भी जबरदस्त हो रहे हैं. किसानों की पीड़ाओं के बारे में 2007 में 102 किसान आंदोलन हुए. 2008 में 112 हुए. 2009 में 206 हुए. 2010 में 363 हुए और 2011 में 588 हुए. उसके बाद के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं. यानी किसान आंदोलन भी बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में और किसानों ने आंदोलन किये हैं. अगर आप औसत लें, तो 4 व्यक्ति प्रति दिन आत्महत्या कर रहे हैं. तो इसलिये शासन को इस बात में जागृत होकर इसके लिये विचार करना चाहिये था, जो कि नहीं हुआ है. मैं सुझाव भी दूंगा कि हमको क्या क्या करना चाहिये ? मैं सिर्फ आलोचना नहीं करूंगा. मुझे सिर्फ इस बात की तकलीफ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध किया था कि सिर्फ किसानों का जोड़ दें, अभी भी जोड़ दें, अगर कार्य-सूची में नहीं आया हो कि उनके लिये भी हम श्रद्धांजलि देते हैं और जब हमारे तरफ से श्रद्धांजलि हुई महामंत्री जी ने कहा कि यह परम्परा के विरूद्ध है. सारे विधायक बी.जे.पी.एवं कांग्रेस के किसानों को श्रद्धांजलि देने में एतराज नहीं था, सिर्फ आपको एतराज हुआ, मुझे उसका दुःख है.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—अध्यक्ष महोदय, निधन का उल्लेख और आत्महत्या का विरोध करना दोनों अलग-अलग विषय हैं.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—आप निधन का उल्लेख कर दीजिये.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—आज भी आपसे कह रहा हूं कि किसी एक भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा कि इनके निधन का उल्लेख होना चाहिये आप तो केवल राजनीतिक रोटियां सेंक रहे थे और आत्म-हत्या कहकर सरकार का विरोध आप करना चाहते थे.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि कभी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप लोग घटिया राजनीति कर रहे हैं? डॉ.शेजवार जी कुछ शब्दों का उल्लेख कर रहे हैं, हम किसानों की समस्याओं के लिये एकत्रित हुए हैं, हम इन सब चीजों से बचें. हम बचेंगे और आप भी बचने का कष्ट करेंगे.

मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं थोड़े से सुझाव आपको दे देता हूं मुख्यमंत्री जी को मैंने टी.व्ही.पर सुना आपने कहा दो महीने के टेम्प्रेरी कनेक्शन किसान ले सकता है, बहुत अच्छी बात है मैं इसके लिये आपको बधाई देता हूं, लेकिन आपकी यह घोषणा चार दिन पहले की है, कल तक मैं पूछकर आया हूं कि इसका पालन नहीं हुआ है, आज के जमाने में ईमेल से आप आदेश भेज सकते हैं.

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—कल तक मेरे यहां पर आदेश नहीं पहुंचा है, अधिकारियों ने कहा है कि हमें आदेश लिखित में नहीं मिला है. मैं कल की बात कर रहा हूं मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं. आपके विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, आप मेरे यहां पर जांच करवा लो. मैं आपके विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं.

श्री रामेश्वर शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन पूरे मध्यप्रदेश के लिये आदेश निकालता है, इंडीविजुवल विधान सभा के लिये आदेश नहीं निकालता है.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—मेरे यहां पर अधिकारीगण बोल रहे हैं कि हमें आदेश लिखित में मिलेगा तब हम उस पर काम करेंगे. मेरे विधान सभा क्षेत्र में कल इन अधिकारियों ने कहा हमें लिखित में आदेश मिलेगा तभी हम काम करेंगे.

अध्यक्ष महोदय—आप चर्चा को आगे बढ़ाइये ?

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—अध्यक्ष महोदय आप सुनिये तो सही. दूसरा आपने यह भी कहा आपने एक अच्छी घोषणा की कि 10 प्रतिशत जो पैसा जमा करा देगा किसान की डी.पी.एवं ट्रांसफार्मर ठीक करवा देंगे, मैं आपके इस निर्णय की प्रशंसा करता हूं, लेकिन यह भी हमारे अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे पास में अभी लिखित में नहीं आया है, हम यह कार्य नहीं करेंगे. आप मेरे क्षेत्र में पुछवा लीजिये.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—कृपया आप लोग बैठ जाएं, उनको बोलने दें.

श्री गोपाल भार्गव—यह सारे आदेश आपके खाने में आपको मिल जाएंगे आप वहां से ले लीजिये. सभी माननीय सदस्यों के खानों में मिल जाएंगे.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—आपका धन्यवाद. आप उक्त आदेश को ईमेल से क्यों नहीं भेज सकते थे मेरा यह निवेदन है ? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप 10 प्रतिशत की रोक हटवा दें इसलिये हटा दीजिये, क्योंकि इनके पास में सिंचाई के लिये एक महीने बचा है, जिनके पास में अपना कुआं है, जिनके पास में पास में स्टॉफ डेम हैं अथवा नदी का पानी लेने के लिये उपलब्ध है उनके पास में सिर्फ एक महीना बचा है, उस एक महीने में वह सिंचाई कर लेंगे तो उनके यहां पर थोड़ा गेहूं, चना हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई है बाद में शुरू में भले ही थोड़ी बहुत हो गई हो. मेरा आपसे अनुरोध है कि 10 प्रतिशत की रोक भी आप हटवा लीजिये, डी.पी.तथा ट्रांसफार्मर ठीक करवा दीजिये, किसान सिंचाई कर लेगा, उसके पास थोड़ा गेहूं चना हो जाएगा तो आपको पैसे दे देंगे, यह मैं तो नहीं कह रहा हूं कि आप उनसे पैसे मत लीजिये, यह निर्देश दे दीजिये मेरा आपसे अनुरोध है.

बहुत किसान या तो चौपड़ खेल रहा है अथवा ताश खेल रहा है या इधर-उधर घूम रहा है, क्योंकि उनके पास में खेती का काम नहीं है. मेरा आपसे अनुरोध है कि तत्काल राहत कार्य जैसे पहले खुलते थे, वैसे खुलवाने का कष्ट करें और मनरेगा के अंतर्गत सारे कार्य खुलवाने का कष्ट करें, जो कि मजदूरमूलक काम हैं, क्योंकि किसानों की बहुत बड़ी दुर्दशा है, यह आप तत्काल आदेश कर दें, यह मेरा सुझाव है. मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई जगहों पर तीन साल से सूखा है, चने की फसल का अफलन हुआ है, अतिवृष्टि एवं औलावृष्टि हुई जिसके कारण उड़द की फसल खत्म हो गई हमारे लोगों ने बड़ा आंदोलन भी किया, कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया. चंदेरी के विधायक ने 3 हजार किसानों को लेकर के ज्ञापन दिया. मुख्य सचिव जब चंदेरी आये तो वहां भी उनको लोगों ने मिलकर आवेदन दिया. जब ये मुंगावली से गुजर रहे थे तो लोगों ने उनको रोककर आवेदन देना चाहा लेकिन वे रुके नहीं पहिये से एक आदमी को चोट भी लगी उनका आवेदन ले लेते तो अच्छा होता लेकिन वे गये थे तो उन्होंने भी अध्ययन किया होगा कि क्या दुर्दशा चंदेरी,मुंगावली क्षेत्र की है लेकिन मुझे अफसोस यह है कि 2 साल पहले जो नुकसान हुआ था उसमें पटवारियों ने बहुत मनमानी की. गये साल आपने एक काम ठीक किया था कि आपने एक टीम बनाई थी और टीम बनाकर लोग गये थे. थोड़ा बहुत आकलन ठीक हुआ लेकिन हम लोगों द्वारा इस साल इतने ज्ञापन और इतना निवेदन करने के बाद भी किसान ने उड़द की फसल इसलिये नहीं हांकी कि आकलन के लिये कोई आयेगी कोई व्यक्ति अशोकनगर जिले में नहीं पहुंचा अब आकलन जरूर हो रहा है लेकिन सवाल यह है कि जब उड़द की फसल हांक दी गई तब आकलन क्या करेंगे.सोयाबीन की भी यही हालत है. आपने अभी अब्दुल कलाम साहब को श्रद्धांजलि दी. अब्दुल कलाम साहब ने सोयाबीन मिशन बनाया है. उन्होंने सोयाबीन मिशन प्रस्तावित किया था और उन्होंने हार्टीकल्चर मिशन भी 35 पेज,45 पेज पर प्रस्तावित किया था. डेयरी डेव्लहपमेंट का भी उन्होंने 25 पेज पर प्रस्तावित किया था. किसानों की आप कितनी मदद करेंगे ओलावृष्टि से अतिवृष्टि से, किसानों के पास अगर अतिरिक्त आय का साधन होगा. डेयरी को आपको खूब प्रोत्साहित करना चाहिये ताकि ओला पड़े तो किसान आपसे याचना करने नहीं आये तो किसान डेयरी से दूध से जो इनकम होती है उससे अपना पालन कर सके. तीन साल से यह हो रहा है कितना आप बीमा

बांटेंगे. कितना आप मुआवजा बांटेंगे. अधिकारी आपके अन्याय करते हैं वहां पर पटवारी क्या न्याय कर देंगे तो मेरा अनुरोध है कि आप किसान को सशक्त बनाने के लिये डेयरी डेव्लहपमेंट पर जबर्दस्त जोर दीजिये और गाय,भैंसें पालने के लिये प्रोत्साहित कीजिये उनको. आपने अब्दुल कलाम साहब को श्रद्धांजलि दी लेकिन उन्होंने जो आपको मिशन दिया था वह टारगेट आपने पूरी नहीं किये. आपने मंथन किया. दो वर्ष पहले 2009 में भी आपने मंथन किया था. मेरे पास मंथन की रिकमंडेशंस हैं. आपने अब्दुल कलाम साहब के मिशन का पालन करते तो आज यह स्थिति नहीं होती थोड़ी बहुत बेहतर स्थिति किसानों की होती . आप मंथन कर लेते हैं लेकिन उस पर पालन नहीं करते हैं. यह तो वैसा ही हुआ जैसे कि सिटीजन चार्टर में व्यवस्था है कि किसान का नामांतरण हो जाये सीमांकन हो जाये उसको आप लागू न करके एक एक्ट लेकर आ जाते हैं उसका नाम देते हैं सुशासन की नई पहल, लोक सेवाओं की गारंटी, इस अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है. किसान इसलिये पीड़ित है कि कोई भी पटवारी 10-20 हजार रुपये लिये बिना काम नहीं करता है. मेरा आपसे यह सुझाव है अध्यक्ष महोदय, कि आप मनरेगा में जो भ्रष्टाचार हुआ है उन लोगों को दण्डित करिये. एक सीधा-सीधा सूखे का सवाल इस बात से भी जुड़ा है कि कितने लोगों को आपने बीपीएल कार्ड दिये. पूरे प्रदेश में बीपीएल कार्ड को लेकर भ्रष्टाचार हो रहा है. ट्रेक्टर बिल्डिंग वालों के पास है. हजारों अपात्रों के पास बीपीएल कार्ड नहीं है. पैसा लेकर बीपीएल कार्ड पैसे वालों के बन रहे हैं. मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक टारगेट फिक्स कर दीजिये. रोहाणी जी जब स्पीकर थे तो उन्होंने यह निर्णय दिया था कि जो बीपीएल कार्ड गलत है अपात्र ने लिया है उसके खिलाफ एफआईआर करो और जिसने बीपीएल कार्ड बनाया है उस पर भी एफआईआर करो. उसका भी पालन नहीं हुआ है. सीधी-सीधी बात है आप पटवारी और पंचायत के मंत्री को निर्देश दे दीजिये कि सभी अपात्र हट जायें. ट्रेक्टर वाले,मोटर वाले,पक्के मकानों वाले और एक भी अपात्र बचा तो आपकी खैर नहीं है. सिर्फ आप यह आदेश दे दें 15 दिन में तो सारे बीपीएल कार्ड गरीबों के पात्र लोगों के बन जायेंगे और अपात्र हट जायेंगे. यह बीपीएल से सीधा जुड़ा हुआ है. वाटर मेनेजमेंट, भारी जल संकट आने वाला है.मेरा आपसे अनुरोध है कि अब्दुल कलाम साहब ने वाटर शेड का जिक्र किया है, वाटर मेनेजमेंट का जिक्र किया हैवाटर मेनेजमेंट का जिक्र किया है। जल स्तर नीचे चला जा रहा है। हमारे पीएचई मंत्री नहीं है, उन्होंने जिक्र किया है कि पीएचई में बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा. मेरा निवेदन है कि जबरदस्त जल संकट आने वाला है, मेहरबानी करके आप पानी की व्यवस्था करें,लोगों को पानी मिले और पशुओं को पानी मिले, पुशओं के किचन शेड में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है, यह सब मनरेगा से जुड़ा हुआ है। इसकी जांच करकी जांच करके लोगों को दंडित करें।

श्रीमती अर्चना चिटनीस :- माननीय अध्यक्षीय महोदय, आज का यह विशेष सत्र प्रकृति की मार को सहता हुआ मार से संभलेते किसान के लिये बहुत ही महत्वूर्ण सत्र है। आज का यह सत्र सरकार की किसानों की परिस्थिती के प्रति वर्तमान गंभीरता बल्कि संवेदनशीलता का अपने आप में एक जीता जागता

प्रमाण है। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि आज हम सभी पक्ष और प्रतिपक्ष के विधायक अपने अपने सुझाव दें, सकारात्मक सुझाव दें, रचनात्मक विचार करें, जिससे माननीय मुख्यमंत्री, व उनकी केबिनेट निर्णय ले और देश व दुनिया के सामने हम एक मार्गदर्शक मिसाल बनें,कि हम अपने प्रदेश को इस विपत्ति से जुझते हुए भी आगे बढ़ाने की कैसे कार्ययोजना कर रहे हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज यह कहना आवश्यक समझती हूं कि हमारी सरकार आज इस सूखे पर विशेष सत्र को बुलाने के लिये,इसलिये बार करने की परिस्थिती हमारे लिये है, क्योंकि हम केवल कि आगे क्या किया जाये उस पर बात हम तब कर सकते थे जब पूर्व में भी हमने किसानों के लिये कुछ गंभीरता से निर्णय करने के लिये कुछ किया होता और माननीय शिवराज सिंह की सरकार ने सबसे बड़ा जो काम किया इसकी कल्पना हम करें तो 10 साल में सिंचाई क्षमता जितनी बढ़ी है, अगर उतनी सिंचाई की क्षमता मध्यप्रदेश की भूमि पर न बढ़ी होती तो इस सूखे की स्थिति में इतनी न केवल अल्प वर्षा बल्कि जो वर्षा हुई भी तो समय पर नहीं हुई अगर सिंचाई की परिस्थिती मध्यप्रदेश में साढ़े सात लाख से बढ़कर बत्तीस लाख हेक्टेयर न हुई होती तो मध्यप्रदेश में हा हाहाकार की स्थिति मची होती. मैं किसानों की ओर से बढ़ी हुई सिंचाई के लिये माननीय मुख्यमंत्री कीधन्यवाद देते हुए उनको अभिनन्दन करते हुए मैं अपनी बात करे आगे बढ़ाना चाहती हूं . अध्यक्ष महोदय, शून्य प्रतिशत ब्याज और रासायनिक खाद्य की समय पर उपलब्धता कस्टम हायरिंग सेन्टर्स सिस्टमस को खोलने का जो बड़ा महती निर्णय लिया गया और हमने जो देशानुकूल पद्धति के साथ साथ युगानूकुल यांत्रिकी खेती पर भी किसानों को प्रोत्साहित किया. लेकिन सूखे की परिस्थिती ने जो पिछले सालों से लगातार हमारी कृषि में जो आमदनी बढ़ी उसको इस साल एक बहुत बड़ा झटका लगा, मैं यह कहना चाहती हूं कि मुआवजे की स्थिती को अगर देखा जाये तो कई सारे विषयों में 1993 में जितना मुआवजा मिल रहा था कई बिन्दुओं पर पांच गुना मुआवजा बढ़ा और कई बिन्दुओं पर 10 गुना बढ़ा और कई बिन्दू पूर्व में थे ही नहीं आरबीसी 6(4)के अंतर्गत उन्हें भी शामिल किया गया जो अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने किया है. आज जैसा कि पूर्व में हमारे जो वक्ता थे कृषि मंत्री भी रह चुके हैं . मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं और जो अखबारों में पढ़ा और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा में सुना वह मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस दिशा में ठीक विचार कर रहे हैं , बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं और उस दिशा में न केवल विचार कर रहे हैं,उन्होंने उस पर गंभीरता से चर्चा कर कर उस दिशा में एप्लीकेशन की ओर भी वह आगे बढ़े हैं, मात्र खेती और किसानी के आधार पर हम गांव को किसान को समृद्ध नहीं बना सकेंगे और वह भारत के परम्परा में भी रहा है. हम केवल कृषि आधारित देश कभी नहीं रहे. अंग्रेजों ने हमारे उद्योग, कुटीर उद्योग, हुनर, प्रोडक्टिविटी को कमजोर करके, क्षीण करके हमारे यहां से रॉ-मटेरियल बाहर ले जाकर हमें मात्र कृषि पर आधारित देश बना दिया हम गुलामी के कारण कृषि आधारित देश बने

थे भारत परम्परा से केवल कृषि आधारित देश कभी भी नहीं था. आज यह सदन उस पर विचार करे न केवल परम्परा पर बल्कि आज की नई तकनीक आज की नई सारी परिस्थितियों पर अब हम केवल लोकल ही नहीं सोच सकते हैं हमको ग्लोबली कई चीजों पर निर्णय करना होगा. आज हम परम्परा और आधुनिकता दोनों को मिक्स एंड मैच करके मध्यप्रदेश की समृद्धि और किसानों की बेहतरी के लिये, निर्णय करने के लिये विचार करने के लिये यहां एकत्रित हुए हैं.

अध्यक्ष महोदय, मैं आज मुख्यमंत्रीजी को इस बात के लिये बधाई देना चाहती हूं कि दलहन और तिलहन के उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है लेकिन मात्र इससे बात नहीं बनेगी हमें दलहन और तिलहन की खेती को और आगे बढ़ाना होगा क्योंकि दलहन और तिलहन में आमदनी की सुनिश्चतता है और पानी की लागत कम है और देश को इस समय दलहन और तिलहन की आवश्यकता है इससे हम अपने किसान को भी समृद्ध करेंगे साथ ही साथ हम अपने देश का फॉरेन एक्सचेंज भी बचायेंगे क्योंकि आज महंगी होती दालों को अगर कोई प्रदेश रिलीफ दे सकता है तो वह हमारा मध्यप्रदेश है इसलिये दलहन की खेती को प्रोत्साहित करना निश्चित तौर पर सरकार के लिये एक बहुत महती कदम है और तिलहन की खेती को आगे बढ़ाना बहुत महती कदम है. मैंने अपने क्षेत्र में धारवाड़ पद्धति से तुअर की बुआई और सीरी पद्धति से सरसों की बुआई करने के लिये गांव-गांव में किसानों को प्रोत्साहित किया, प्रशिक्षित किया और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपको और माननीय मुख्यमंत्रीजी को बहुत हर्ष से बता रही हूँ कि जब हमारे किसानों ने सोयाबीन बो दिया और बारिश लेट हुई सोयाबीन की फसल विपत्ती में फंस गई तब कई किसानों ने, प्रशासन ने और हम जनप्रतिनिधियों ने मिलकर प्रयास किया कई किसानों ने एक महीने बाद अपनी सोयाबीन उखाड़कर तुअर लगाई और आज वे किसान इसको लेकर बहुत राहत में हैं अगर वे सोयाबीन ही लगाये रहते तो आज खेतों की परिस्थिति यह है कि सोयाबीन की फसल लगाने वाले किसान हारवेस्टर चलाने के बजाय रोटावेटर चलाकर अपनी खुद की बोयी हुई फसल को मिट्टी में मिला रहा है बारिश की परिस्थिति ने सोयाबीन के किसान को बहुत बुरी तरह मारा है. हमारा प्रदेश जो सोया स्टेट के तौर पर देश में जाना जाता है हमारे प्रदेश की अन्य फसलों को इतना नुकसान नहीं हुआ है जितना सोयाबीन की फसल को हुआ है. मैं माननीय द्वारा लिये जा रहे तमाम कदमों के साथ साथ इस बात के लिये आग्रह करूंगी कि कम पानी से लगने वाली फसलों के लिये हमें किसान को प्रोत्साहित करना होगा, किसान को मदद भी करना होगी और जो फसलें कम पानी लेती हैं वह परम्परागत फसलों के बीच उपलब्ध नहीं हैं तो उनकी उपलब्धि की ओर भी हमें निर्णायक कदम उठाने होंगे और देशी बीज मौसम की मार और बीमारियों की मार खाने की दृष्टि से ज्यादा रोबस्ट है, मजबूत है देशी बीजों को किसानों तक पहुंचाने के लिये सरकार की कार्ययोजना को आगे बढ़ाना चाहिये.

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हिस्टोरिकल फैक्ट है जब जब सूखा पड़ता है तब तब एनीमल इंडक्शन किसान अधिक करता है और इस समय शासन की जितनी भी योजनायें हैं उन समस्त योजनाओं को चाहे वह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो चाहे वे अन्य कृषि कल्याण की योजनायें हों चाहे वे

अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग की योजनायें हों उन योजनाओं के माध्यम से हमने पशुपालन को लेकर न केवल ट्रेनिंग बल्कि किसानों को प्रपोजल बनाकर बैंक के माध्यम से सहायता कराकर न केवल दुधारु पशुओं का बल्कि बकरी पालन, सूकर पालन और मधुमक्खी पालन में भी किसानों को ग्रामीणों को उस दिशा में बढ़ायें यह समय की मांग है और इससे आने वाले समय में मध्यप्रदेश की समृद्धि सुनिश्चित होगी. यह बात सही है कि मुआवजा जरुर बढ़ा है लेकिन मुआवजा तात्कालिक राहत है मुआवजा किसान को एक सांस लेने की थोड़ी सी सुविधा देता है लेकिन मुआवजा समृद्धि की ओर एक टोटल सॉल्यूशन बिलकुल भी नही हो सकता है. हमारे ग्रामीण विकास मंत्रीजी यहां विराजमान हैं मैं सदन के माध्यम से उन्हें भी यह कहना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्र में आपने पशुपालन के शेड देने का निर्णय किया है. एक शेड 1 लाख 3 हजार की कीमत का है. अगर हमारे जितने भी सरपंच और सेक्रेट्रीज़ हैं उनको आप ये यहाँ से संदेश दें कि प्रत्येक किसान को हम पशुपालन का शेड देने को राजी हैं बनिस्बत वह 1 लाख 3 हजार का पशुपालन का शेड लेने के लिए 60 हजार का कच्चा काम भी करे और हर खेत में बड़ी सिंचाई योजना, सिंचाई मंत्री जी ने इफ़रात दी है, बड़ी सिंचाई योजनाओं से जो राहत होगी वह अपनी जगह है, लेकिन मनरेगा के माध्यम से कच्चे काम बढ़ाने के लिए प्रत्येक किसान जिसके पास अगर 2 हैक्टेयर का रकबा है, हम उसको प्रोत्साहित करके, अनिवार्य तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रेरित करके, खेत खेत में अगर हम तालाब बनाएँगे तो न केवल पानी खेतों में रुकेगा, बल्कि जो मिट्टी बह कर चली जाती है, उसके क्षरण से भी हम बचेंगे. एक तालाब जो छोटा सा, 10 मीटर बाय 10 मीटर का बनता है. वह एक समय पर....

अध्यक्ष महोदय-- कृपया समाप्त करें.

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- मैं एक मिनट में अपनी बात खतम कर रही हूँ. वह 70 हजार गैलन पानी एक बार भरने पर उसमें इकट्ठा होता है. अध्यक्ष महोदय, खेत तालाब, खेत-खेत में बने, उससे मजदूरों को मजदूरी भी मिलेगी और जितना भी पानी आने वाले समय में आएगा, अभी भी आने वाले सालों के लिए, मौसम की अनिश्चितता आज भी बनी हुई है, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी समस्या है. ये खेत तालाब को हम अनिवार्य करें, किसान को प्रेरित करें, किसान से उसको बनाने के लिए आग्रह करें, खेत तालाब बहुत बड़ी समस्या का समाधान हम सबके लिए हो सकता है. मैं अंत में एक दो बात कह कर अपनी वाणी को विराम दूंगी.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री गोपाल भार्गव)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में शायद मैं उत्तर न दे सकूँ क्योंकि अवसर न मिले, मैं अवगत कराना चाहता हूँ माननीय सदस्या को कि पशु शेड के लिए भी और तालाब के लिए भी कोई सीमा नहीं है. जितनी आवश्यकता होगी, जितने किसानों को करना होगा, रोजगार गारंटी योजना में पर्याप्त राशि उपलब्ध है. इससे मैं सभी सदस्य को और सदन को अवगत कराना चाहता हूँ. (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- माननीय मंत्री जी, उसमें राशि तो उपलब्ध है लेकिन 60-40 का रेश्यो...

श्री बाला बच्चन-- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जैसा बोला ऐसा धरातल पर है नहीं. मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़वानी जिले.....

अध्यक्ष महोदय-- माननीय बाला बच्चन जी, यहाँ डिबेट नहीं हो रही है. बात हो जाने दीजिए. आपका नाम है तब आप बोल लेना. आप अपने समय में बोलिएगा. दूसरे का भी समय आप खराब कर रहे हैं. आपका समय है तब आप बोल लेना. 5-7 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते.

श्री सोहनलाल वाल्मीक-- अध्यक्ष महोदय, फिर मंत्री जी को जवाब नहीं देना था....(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- उनका मौका आएगा तब वे बोल लेंगे. अभी बीच में बोलने की क्या जरूरत है...(व्यवधान)..

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का कहना सही है राशि में कमी अदर वाइज़ नहीं है लेकिन राशि का उपयोग तभी हो सकेगा जब 60-40 परसेंट के बेसिस पर हम कच्चे और पक्के काम दोनों लेंगे और उसमें अगर हम खेत तालाब, ये भी स्ट्रक्चर्स, कुँए इत्यादि लेंगे तभी हम प्रत्येक किसान को पशुपालन देने की परिस्थिति बना पाएँगे. मैं अपनी बात को पूरा करते हुए इस बात के लिए पुनः आग्रह करूँगी कि पशुपालन एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यु है क्योंकि हमारी फर्टिलाइजर और पेस्टीसाइड्स की लागत, हम जितने रसायनिक पेस्टीसाइड और फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, उतनी अधिक पानी की रिक्वायरमेंट हो रही है, उतनी अधिक बिजली की रिक्वायरमेंट हो रही है इसलिए आगामी समय में हम पशुपालन की अगर अभिवृद्धि करते हैं तो हम उसको ऑर्गेनिक खाद भी उपलब्ध करा सकेंगे. मैं अंत में इतना कहते हुए अपनी बात को पूरा करूँगी कि गाँधीजी और दीनदयाल जी के बताए गए ग्रामीण विकास के रास्ते पर चलते हुए डॉक्टर कलाम के बताए हुए गाँव और शहर के बीच के ट्रेड बैलेंस को बनाने के संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, उसको पूर्ण करके मध्यप्रदेश उनके मार्गदर्शन में निश्चित तौर पर इस विपत्ति से भी निपट लेगा.

श्री रामनिवास रावत(विजयपुर)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में भयावह सूखे की स्थिति है और आज का जो विषय है, आज विनियोग विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है, वह सूखे की भयावह स्थिति के कारण जो प्रदेश में किसानों की स्थिति हो रही है, मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए विषय पर आज चर्चा हो रही है. अध्यक्ष महोदय, विगत वर्ष 2014-15 में भी रबी की फसल, खड़ी हुई फसल में,पकी हुई फसल में, भारी ओलावृष्टि के कारण अन्नदाता किसानों की फसलों में भारी तबाही हुई. प्रदेश के अन्नदाताओं के सामने इस वर्ष अवर्षा, अल्प वर्षा के कारण खरीफ की फसल सोयाबीन, तिल्ली, उड़द, ज्वार, मक्का, बाजरा, धान आदि पूर्णतः नष्ट हो जाने के कारण किसान अपने आपको असहाय पा रहा है. एक तरफ किसान बैंकों के कर्ज, साहूकारों के कर्ज, चुकाने में अपने आपको असमर्थ पा रहा है और दूसरी तरफ वहीं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों ,पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन करने में भी अपने आपको असमर्थ पाने के कारण प्रदेश में किसान पूर्णतः असहाय होकर किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया है और अपने आपको अकेला पाकर आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है और प्रदेश में लगातार किसान आत्महत्यायों की घटना बढ़ती जा रही हैं . लगभग 6 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं .

अध्यक्ष महोदय, हम सभी लोग किसानों के वोट से ,जनता के वोट से चुनकर आते हैं. हम सबका दायित्व होता है कि हम प्रदेश के किसानों की चिंता करें. निश्चित रूप से माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे सहृदयतापूर्वक स्वीकार करके सत्र बुलाया इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी को साधुवाद देता हूं. लेकिन जो मेरे पास परिपत्र पहुंचा ,सत्र बुलाने का आमंत्रण पहुंचा वह सूखे पर चर्चा का पहुंचा और जब कार्यसूची का विषय आया तो विनियोग विधेयक, केवल विनियोग विधेयक तक सीमित रहेंगे, यह विषय हमारे सामने आया. यह दुर्भाग्यपूर्ण है . अध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रियाओं की भी बात आई आपने भी बात कही पिछले समय में जब ओलावृष्टि हुई थी तब 24 मार्च 2015 को भी आपने एक दिवसीय सत्र बुलाया था. माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव पर ही बुलवाया था और उस एक दिवसीय सत्र की कार्यसूची निकाल लें, मेरे पास उसकी कार्यसूची है उसमें जयंत मलैया जी ने अनुपूरक अनुमान उपस्थापन किया है. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति हुई है फिर नियम 10 के तहत, जहाँ आदरणीय रामपाल सिंह जी ने....

श्री अनिल फिरोजिया—अध्यक्ष महोदय, सूखे पर चर्चा कर लें पहले.

श्री रामनिवास रावत-- आपसे सलाह की आवश्यकता नहीं है.

अध्यक्ष महोदय-- आप जो कह रहे हैं वह आ चुका है उसका उत्तर आप सुन लीजिये.

श्री रामनिवास रावत--- अध्य़क्ष महोदय, उसमें माननीय रामपाल सिंह जी ने प्रस्ताव दिया था कि आंधी-तूफान, वर्षा ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए विशेष सत्र बुलाया जाये.

अध्यक्ष महोदय--- हाँ तो उसका उत्तर सुन लीजिये आप . आज का और उसका फर्क सुन लीजिये आप.

श्री रामनिवास रावत--- वह मैंने सुन लिया है.

अध्यक्ष महोदय--- जब आपने सुन लिया फिर क्यों उठा रहे हो उस विषय को .

श्री उमाशंकर गुप्ता – क्या सुन लिया आपने, आप गलतबयानी करते हो, वही बातें आप रिपीट कर रहे हैं आपको किसानों की आत्महत्या पर चर्चा ही नहीं करना है. इधऱ उधर की बातें कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय--- आप रिपीटेशन मत करिये. रावत जी उस वक्त के सत्र में अनुपूरक में कोई स्पेसीफिक मांगें नहीं थी इस अनुपूरक में स्पेसीफिक मांगें कृषि के ही संबंध में हैं. कृपा कर के आप उसको पढ़ ले. इसलिए माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है कि समस्या और समाधान पर एक साथ चर्चा हो रही है आप उसी पर चर्चा करिये.

श्री रामनिवास रावत--- अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आपने मेरा ध्यानाकृष्ट किया है . मैं भी बहुत दुखी हूं.पीड़ा से भरा हुआ है लेकिन आपने कहा, माननीय संसदीय मंत्री भी देख लें, माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख लें. जो अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किये गये हैं उसमें विधानसभा उपचुनाव के लिए संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से संपादित करने के व्यय की भी व्यवस्था की गई है, कार्यालय भवन को आकस्मिकता निधि से 30 करोड़ , राज्य की आकस्मिकता निधि से राशि देने की बात कही है.

अध्य़क्ष महोदय--- समायोजन किया गया है आप उसको पढ़ तो लीजिये उसको .

श्री रामनिवास रावत--- अध्यक्ष महोदय, आखिर क्यों? किसानों की मौतों पर, सूखे की भयावह स्थिति पर क्या हम राजनीति करते रहेंगे. क्या सत्ता पक्ष का और विपक्ष का दायित्व नहीं है.

अध्यक्ष महोदय-- आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, समय कम मिला पढ़ने का.

डॉ. नरोत्तम मिश्र--- थोड़ा बहुत तो आप किसान पर बोलो .वह समायोजन है, उसको आप पढ़ भी लो, ऐसी क्या बुराई है, पढ़ने में क्या दिक्कत है.

अध्यक्ष महोदय--- आपने ठीक से पढ़ा नहीं कृपा करके आज रात को पढ़ लीजियेगा वह समायोजन किया है कोई नया प्रस्ताव नहीं लिया है.

श्री रामनिवास रावत-- अगली विधानसभा में समायोजन कर लेते.

अध्यक्ष महोदय--- वह पहले ही करना पड़ता है नियम है उसका.

श्री उमाशंकर गुप्ता--- रावत जी , यदि कुछ किसानों पर बोलने के लिए है तो वह बात आप बोले. जबसे विशेष सत्र पर सदन समवेत हुआ है किसानों पर चर्चा नहीं करने का आपका मकसद है क्या कांग्रेस विधायक दल का. कोई अच्छे सुझाव दीजिये जैसे कालूखेड़ा जी देकर गये हैं, अर्चना जी ने दिया है . मेरा कहना है कि आपके अऩुभव के आधार पर आप सुझाव दें ताकि सरकार निर्णय करे , जिस मकसद से यह सत्र बुलाया है वह पूरा करें. आप केवल इधर उधर की बातें कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय--- आप अच्छे सदस्य हैं, कृपया विषय पर आ जाएं.

श्री रामनिवास रावत--- आपने क्या गुप्ता जी को बोलने की अनुमति दी है? अगर उनको अनुमति दी है तो मैं बैठ जाता हूं.

अध्यक्ष महोदय--- आप बोलिये किन्तु विषय पर बोलिये.

श्री रामनिवास रावत-- मैं विषय पर बोल रहा हूं.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार--- माननीय अध्यक्ष महोदय, रावत जी थोड़े से विचलित हो रहे हैं क्योंकि उनका क्रम बदल दिया था. पहले उन्हें बोलना था उनके स्थान पर महेन्द्र सिंहजी को बुलवा दिया. वह ज्यादातर विषयों पर बोल गये हैं. अब इनके पास कोई विषय नहीं हैं और यह भ्रम में हैं, समायोजन को यह दूसरी बात कह रहे हैं . मेरा ऐसा कहना है कि इसमें जिन मांग संख्याओं में मांग की गई है वह सब सूखे से जुड़ी हुई हैं और सूखा राहत से जुड़ी हुई हैं. बिजली की उपलब्धता से जुड़ी हुई हैं तो अब सब कुछ इनके कहीं कहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यह इधर उधर की बातें कर रहे हैं इनके पास कुछ विषय बचा नहीं है.

श्री रामनिवास रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय,आज इतने संवेदनशील विषय पर लगातार हम देखते आ रहे हैं, क्या सत्तापक्ष क्या विपक्ष, ये होड़ लगी हुई है कि कौन किसान हितैषी है और कौन किसान विरोधी है. मैं किसानों की ही बात कर रहा हूँ.आज किसान बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है,लगातार किसान आत्महत्याएँ बढ़ती जा रही हैं और सत्तापक्ष हमेशा यह प्रयास करने की कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस किसान विरोधी है, कांग्रेस किसानों के साथ नहीं है. कैसे आपने कह दिया कि कांग्रेस किसानों के साथ नहीं है. आज तक जो किसानों का विकास हुआ,किसानों को आगे ले गये. हरित क्रांति क्या आप लाये,श्वेत क्रांति क्या आप लाये, क्या किया आपने? मेरा यह मानना है कि निश्चित रुप से जनप्रतिनिधि, हर जनप्रतिनिधि यह चाहता है, चाहे वह सत्तापक्ष का हो या विपक्ष का हो कि मेरे क्षेत्र का मेरे प्रदेश का किसान परेशान नहीं हो.आज प्रदेश की 43 जिलों की 141 तहसीलें सूखा प्रभावित घोषित कर दी हैं. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, यह भी जानना चाहूंगा कि आपके पास अभी कितनी तहसीलों के प्रस्ताव और पड़े हुए हैं, उन तहसीलों को भी तत्काल सूखाग्रस्त घोषित करें क्योंकि कल आपकी ही विधायक दल की बैठक में कई आपके ही विधायकों ने कहा था कि मेरी तहसील भी सूखा प्रभावित घोषित करो. आपने, आपका वक्तव्य पेपर में भी आया है कि अगर सभी को सूखा प्रभावित घोषित करेंगे तो केवल वेतन बांटना ही रह जाएगा, और कोई काम नहीं हो पायेंगे. माननीय मुख्यमंत्री जी आप किसान हितैषी हैं, आप किसान के बेटे हैं तो किसानों का दर्द समझिये. भले ही रोड रहे तो रह जाए, भले ही और कोई काम रहे तो रह जाए लेकिन किसान आत्महत्या न करे, किसान दु:खी नहीं हो. केवल कहने से काम नहीं चलता. आप बहुत अच्छा कहते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन समीक्षा नहीं करते. आप ओले पड़े तब भी जगह जगह गये, आपने ओलावृष्टि का सर्वेक्षण भी किया, खेतों में उतरे. उन खेतों में भी उतरे जिनमें ओले पड़े और खेत में हेलीपेड भी बना लेकिन आपने यह समीक्षा नहीं की कि जिस खेत में आपका हेलीकाप्टर उतरा, उस खेत के किसान को ओलावृष्टि का मुआवजा मिला है कि नहीं मिला.

अध्यक्ष महोदय—24 मार्च को उस चर्चा हो गयी. नियम 130 में चर्चा हुई.आपने खुद ने पढ़ा.अब फिर वही बात ले आये आप.

श्री रामनिवास रावत—अब मैं सूखे की बात कर रहा हूँ.

श्री उमाशंकर गुप्ता—ओले की बात? सूखे पर कुछ बोलना ही नहीं है. ओला हो गया, निपट गया, मुआवजा बंट गया. अब सूखे पर समीक्षा नहीं हो रही है,यह कह रहे हो.बोलो न कुछ है तो. है क्या तुम लोगों के पास. मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा कर रहे हैं. आप कह रहे हो समीक्षा नहीं हो रही है.आज का यह सत्र किसलिए बुलाया है

अध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्री जी कृपया बैठ जाएं. रावत जी अपनी बात जारी रखें.समय कम है.रावत जी को कृपया बोलने दें.

श्री रामनिवास रावत-- समय कम नहीं है. समय आपसे अनुमति ले ली है और विनम्रतापूर्वक निवेदन भी है.

अध्य़क्ष महोदय-- तो आप बात तो करिये.आप पुराने जमाने में चले गये. अभी पर आप आइये न.

श्री रामनिवास रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आपकी ही विधायक दल की मीटिंग हुई. आपने खूब कहा कांग्रेस विरोधी है. आज भी आप प्रदर्शित कर रहे हो. आप चाहते भी हो कि सत्र नहीं चले. सत्र चलाना चाहते हैं, कांग्रेस बैठी है. आप सुनिये. आप अगर किसान हितैषी हैं तो आपको यह शब्द विधायक दल की मीटिंग नहीं बोलना चाहिए कि और तहसीलों को मैं सूखा पीड़ित घोषित नहीं कर सकता. मेरे पास राशि नहीं बचेगी. आप ही का वर्जन है. यह पेपर है(अखबार को हाथ में ऊपर लेकर दिखाया)

अध्यक्ष महोदय—अखबार नहीं बता सकते. कृपया बैठ जाइये.

श्री जयंत मलैया—इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है.

मुख्यमंत्री(श्री शिवराजसिंह चौहान)—माननीय अध्यक्ष जी, मैं बीच में केवल यह निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ कि यह बात मैंने कभी नहीं कही कि कोई तहसील सूखाग्रस्त घोषित नहीं करेंगे, पता नहीं कहां से आपको जानकारी मिल गयी. जानकारी गलत है.पर मैं बीच में इसलिए टोक रहा हूँ कि मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि मेरा पूरा भाषण प्रतिपक्ष सुनेगा कि नहीं सुनेगा. मैं अनुरोध करता हूँ आपकी हर बात सुनूंगा लेकिन मेरी बात भी आप सुन के जाना. मैं आपकी बातों का उत्तर भी दे सकूंगा. अब तक के अनुभव बहुत खराब हैं तो मैंने सोचा कि इस बात खंडन मैं अभी कर दूं. (हंसी)

श्री रामनिवास रावत—बिलकुल. माननीय मुख्यमंत्री जी की बात पूरी तरह से सुनेंगे और बैठेंगे भी. आपका भाषण भी सुनेंगे लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी बात भी सुनें.

अध्यक्ष महोदय—कृपया आप दो तीन मिनट में समाप्त कर दें.

श्री रामनिवास रावत—फिर हम क्यों सुनेंगे. आप हमें बोलने ही नहीं देना चाहते.

अध्यक्ष महोदय—(हंसते हुए) अरे भाई बोलने के लिए मना कहां क्या है?

श्री रामनिवास रावत—हम कुछ भी सुनते रहें. मुख्यमंत्री,मंत्री कुछ भी बोलते रहें.

अध्यक्ष महोदय – बोलने के लिए मना कहां किया. आपको कहा जल्दी समाप्त कर दो, बोलने के लिए कहां रोका. आज क्या बात है, आप इतनी जल्दी-जल्दी गुस्सा क्यों हो रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं मन दु:खी हूँ, मैं आत्मा से दु:खी हूँ. इस शरीर की धमनियों में जो रक्त बह रहा है वह भी अन्न से बनता है आज प्रदेश का अन्नदाता संकट में है और हम लोग इस विधानसभा जो कि संवैधानिक संस्था है को भी अपना राजनीतिक प्लेटफार्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं यह बिल्कुल निंदनीय है. चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, निश्चित रूप से आगे आकर बात करना चाहिए. सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि वह विपक्ष का भी सहयोग ले कि हम प्रदेश के लिए क्या कर सकते हैं.

अध्यक्ष महोदय – चलिए आप अपनी बात करें.

श्री रामेश्वर शर्मा (हुजूर) – अध्यक्ष महोदय, अगर कांग्रेस के सदस्य किसानों के हित में हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक एक महीने का वेतन किसानों के लिए दे रहे हैं तो आप भी दें.

श्री रामनिवास रावत – मैं इसी विषय पर आ रहा हूँ. आप दु:खी न हों.

श्री सुन्दर लाल तिवारी (गुढ़) – अध्यक्ष महोदय, व्यापम का पैसा कहां गया.

अध्यक्ष महोदय – तिवारी जी जो कुछ बोलेंगे वह नहीं लिखा जाएगा.

श्री रामेश्वर शर्मा – फिर बकवास कर रहे हैं इस हाऊस में. अपने पूर्वजों का इतिहास देख लो, हम भी अतीत में जा सकते हैं.

अध्यक्ष महोदय – रावत जी अपनी बात रखें.

श्री रामनिवास रावत – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूँ और मैं मानता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम से भाषण देने में और दिखने में वाकई संवेनशील लगते हैं और हैं भी. अब हैं कि नहीं हैं ये तो मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा. पिछले कई वर्षों से प्रदेश को प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप झेलना पड़ रहा है और इसी विधान सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार संवेदनशील भाषण दिए हैं कि मैं रात में सो नहीं सका, मैं बैठ नहीं सका, मैं उठ नहीं सका, मैंने मीटिंग बुलाई, मैंने ये किया और इसी तरह से जब ओले पड़े थे तब भी कहा कि ये ओले किसान के खेत में नहीं मेरी छाती में पड़े हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब-जब उन्होंने भाषण दिया है ये 5.3.2014 का भाषण है उनका कि हमने ऋण वसूली तत्काल स्थगित करने का फैसला लिया, हम किसान को फिर से कर्ज देंगे, कर्ज किसान कहां से चुकाएगा. इतना ही नहीं इस साल किसानों से ब्याज नहीं लिया जाएगा, सरकार उनका कर्ज चुकाएगी. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके 24 मार्च का भाषण मेरे पास है इसमें भी आपने घोषणाएं की हैं, आप कृपया सुन लें. आपने जब-जब इस हाऊस में जो-जो घोषणाएं की हैं, उनके आदेश की कॉपी पहले सदन के पटल पर प्रस्तुत करें उसके बाद आप बोलें, हम पूरी तरह से सुनेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है.

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) – माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रिय मित्र का आप पूरा भाषण निकलवा लें, एक बात भी सूखे पर बोली हो तो या एक शब्द भी बोला हो तो.

अध्यक्ष महोदय – अब वे नहीं बोले तो हम क्या करें.

डॉ. नरोत्तम मिश्र – अब वे कंडिशन लगा रहे हैं कि पहले ऑर्डर की कॉपी
यहां रख दें.

श्री रामनिवास रावत – मैं सूखे पर ही बोल रहा हूँ.

अध्यक्ष महोदय – आप कृपया समाप्त करें, 15 मिनट हो गए आपको.

श्री रामनिवास रावत – माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चूँकि विषयांतर करना चाह रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय – मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूँ. आप विषय पर बोल ही नहीं रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, यह आपके शासन की योजना है, स्वयं के व्यय पर ट्रांसफार्मर रखे जाने की योजना पूरे प्रदेश में आज संचालित है और वर्तमान में चल रही है लेकिन आपके अधिकारियों के क्या हाल है. श्यापुर में स्वयं के व्यय पर ट्रांसफार्मर रखे जाने की योजना पूर्णत: बंद कर दी गई है. यहां कहीं श्योपुर के प्रभारी मंत्री हों तो वे आ जाएं, माननीय विधायक श्री दुर्गालाल जी भी बैठे हैं कि वहां पर यह योजना पूरी तरह से बंद है. क्या किसान चोर हैं, किसानों से 30 हजार रुपये अधिक बिल लेने का काम किया जा रहा है, 60-60 हजार में कनेक्शन दिए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम किसानों का भला कर रहे हैं. 60 हजार कैसे ले रहे हैं, 30 हजार क्यों ले रहे हैं और जब बात हुई, मैंने पूछा अभी कि क्या यह योजना बंद कर दी गई है तो बोले नहीं तो मैंने कहा कि अधिकारी बड़े हैं कि सरकार बड़ी है कि साहब हमें अधिकारियों के निर्देश नहीं मिले. आज भी यह योजना वहां चालू नहीं है और जिला योजना समिति की मीटिंग में यह निर्णय हुआ था वहां इनके सांसद थे, प्रभारी मंत्री भी थे और विधायक भी थे, वहां यह कहा गया कि आज के बाद सीधे फार्म लिए जाएंगे लेकिन फार्म लिये नहीं जा रहे हैं.

माननीय मुख्यमंत्री जी,आपकी घोषणाओं,आपके नियमों के ,आपके आदेशों के ,आपके निर्देशों की यह स्थिति है. प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता का माहोल है.

अध्यक्ष महोदय- कृपया समाप्त करें.

श्री राम निवास रावत- अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं. मुख्यमंत्री जी आपने कहा कि हमने सर्वे कराने के निर्देश दे दिये. निश्चित रूपसे आपने निर्देश दे दिये होंगे. आप भाषण देते हैं, घोषणा करते हैं.लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं भी गांव गांव घूमा हूं. सभी जिलों में घूमा हूं. कुछ पटवारियों ने जाकर कौन से किसान के खेत में कौन सी फसल खड़ी है, यह तो लिख लिया है. लेकिन आज तक नुकसान का प्रतिशत नहीं लिखा. अगर किसी एक के भी नुकसान का प्रतिशत लिखा हो तो मुझे बता दो,पटल पर रख दो तो मैं मान जाऊंगा.

अध्यक्ष महोदय-कृपया समाप्त करें.

श्री राम निवास रावत- क्या पूरे प्रदेश के किसानों को समाप्त करेंगे.?

अध्यक्ष महोदय- नहीं, आप आपना भाषण समाप्त करें.

श्री राम निवास रावत- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सुन तो लें.

अध्यक्ष महोदय- आपको 15-20 मिनट हो गये. This is not proper..दूसरों का भी समय है. यह बात ठीक नहीं है. आप बहुत देर बोल लिये. श्री कैदार नाथ शुक्ला...

श्री राम निवास रावत-इसी तरह से अगर सत्र बुलाना था तो क्यों नहीं सुनना चाहते. किसान विरोधी ये हैं कि हम है.

अध्यक्ष महोदय- अब आप समाप्त करें. आप अपना समय देख लीजिए. इस तरह से काम नहीं चलेगा. आपने करीब 20 मिनट बोल लिया. क्या सारे सदस्यों का समय आपको ही दे दें. आपके दल ने 30 सदस्यों के नाम दिये हैं, क्या सबके नाम काट दें.? सिर्फ आपको ही दिन भर दे दें. ? यह बात ठीक नहीं है. और इस तरह से आप बात नहीं कर सकते. आप बैठ जाईए.

श्री राम निवास रावत- आप अपनी बात से पलट रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय- जी नहीं, माननीय केदारनाथ शुक्लाजी...

श्री केदारनाथ शुक्ल (सीधी)- माननीय अध्यक्ष जी, मैं मध्यप्रदेश सरकार और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी को सूखा पर प्रभावी कदम उठाने के लिए ,त्वरित कार्यवाही के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. विधान सभा का विशेष सत्र बुला कर ,सूखा पर विनियोग विधेयक लाकर किसानों को लाभ पहुंचाने की स्पष्ट मंशा का प्रमाण है. (व्यवधान)

श्री राम निवास रावत- अध्यक्ष महोदय, दो मिनट तो सुन लीजिए.मैं अपनी बात पूरी तो कर लूं.

अध्यक्ष महोदय़- आपने पूरी की नहीं, 15-16 मिनट हो गए. एक मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें. सरकार सुन रही थी आप बोल नहीं रहे थे.

श्री केदारनाथ शुक्ल- मैं इस बात के लिए सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं. विपक्ष सूखे पर राजनीति करना चाहता है. निधन के उल्लेख के समय जिस तरह की बातें की गईं वह संसदीय परम्पराओं और गरिमा के विरूद्ध थीं. अध्यक्ष महोदय, हमारी सफल कृषि नीति के कारण हमें देश में दलहन और तिलहन के उत्पादन में मध्यप्रदश सबसे आगे रहा है..

(श्री राम निवास रावत जी उन्हें बोलने का पर्याप्त समय न दिये जाने के विरोध में गर्भगृह में आये और अध्यक्ष महोदय की समझाईश पर वापिस लौट गए.)

श्री केदारनाथ शुक्ल- सोयाबीन,चना में हम प्रथम रहे हैं. मसूर,सरसों में द्वितीय रहे हैं. विगत दस वर्षों में मक्का की फसल हमने दोगुना बढ़ाई है,गेहूं तीन गुना बढ़ा है. धान चार गुना बढ़ा है. इस तरह से लगातार हमने उत्पादन बढ़ाया है. जब दस वर्षों में नहरों से सिंचाई का रकबा 7.5 लाख हैक्टेयर से 32 लाख हैक्टेयर किया है. किसानों को शून्य प्रतिशत व्याज दर पर कर्ज देकर उत्पादन को बढ़ाया है. राज्य

सरकार के प्रयास से खरीफ में 30 प्रतिशत रासायनिक उर्वरक से वृद्धि हुई है. कस्टम हायरिंग सेन्टर 730 खोले गये, 510 और खोले जा रहे हैं. मध्यप्रदेश सर्वाधिक प्रमाणित बीज पैदा कर रहा है. आज प्रदेश इस मामले में देश में अग्रणी है. इन प्रयासों से हमने उच्च स्थान अर्जित किया है. विगत चार वर्षों में ओला,पाला,अतिवृष्टि,अनावृष्टि से फसलें प्रभावित हुई हैं. हमने पर्याप्त मुआवजा दिया है. आर.बी.सी. में जो प्रावधान है , वे इस बात के प्रमाण हैं ,अगर कहेंगे तो विषयवार उसको भी बता देंगे. इस वर्ष अवर्षा के कारण घोर अकाल की स्थिति है हमारे बुजुर्गों का कहना है कि इतना बढ़ा अकाल कभी नहीं पड़ा. प्रदेश में सोयाबीन,मूंग,उड़द की फसलों को अधिक नुकसान हुआ है. इसलिए पूरी संवेदनशीलता के साथ इनका सर्वेक्षण भी होना चाहिए, हो भी रहा है. अवर्षा से यलो मोजेक वायरस का प्रभाव भी हुआ है. इसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए. 366 में से 141 तहसीलें सूखग्रस्त घोषित की गईं हैं. अगर और भी रिपोर्ट आयेंगी तो हमारी सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगी. सर्वे में 32283 गांवों में 44.67 लाख हैक्टेयर भूमि में 25 प्रतिशत से अधिक फलल की नुकसानी का अनुमान आया है. ग्राम पंचायतों में सर्वे सूची चस्पा करके आपत्तियां आमंत्रित करने की बात की गई है . मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ब हुतसारी जगहों में ब्यूरोक्रेट्स के अंदर वर संवेदनशीलता नहीं रही है जो राज्य सरकार की है. और उन्होने सारी फसलों का, विशेष कर दलहन और तिलहन की फसलों का सर्वेक्षण नहीं किया है. उदाहरण के लिए मेरा जिला भी है. इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि दलहन और तिलहन की फसलों का भी सर्वेक्षण किया जाना चाहिए. 48 लाख 12 हजार किसानों को 3 हजार करोड़ की राहत राशि देने का जो प्रावधान किया वह काबिले तारीफ है. 15 दिवस के अंदर किसानों के बैंक खातों में राशि जमा कर दी जाएगी. इस बात की सरकार की घोषणा अपने स्पष्ट चिन्तन को व्यक्त करती है. सस्ती बिजली प्राप्त हो इसके लिए 5500 करोड़ रूपये देने का जो प्रावधान किया गया है यह भी काबिले तारीफ है. फीडर सेपरेशन से बिजली की उपलब्धता बढ़ी है. सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 80 प्रतिशत यूरिया दिया जा रहा है. मनरेगा में 100 के स्थान पर 150 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान किया गया है. इससे भी मजदूरों को लाभ होगा.

अध्यक्षजी, सभी बीजों में उपलब्धता सुनिश्चित की गई है. उर्वरक का अग्रिम और पर्याप्त भण्डारण भी किया गया है जो इस सरकार की सफलता है. 2014 के फसल बीमा योजना पर 4.25 लाख किसानों को 515 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है. 2015 के बीमित किसानों की प्रक्रिया चल रही है. सोयाबीन, मूंग,उड़द की नुकसानी का 3 हजार करोड़ रुपये के बीमा भुगतान की तैयारी है. रबी में मौसम की प्रतिकूलता के कारण अऋणी किसानों को भी राष्ट्रीयकृत बीमा योजना में बीमित करने का प्रावधान किया गया है.

अध्यक्षजी, मैं विंध्य से आता हूं. विंध्य में इस समय अच्छे बड़े-बुजुर्गों के पास भी बैठा जाये तो उनका कहना है कि ऐसा काल उन्होंने कभी नहीं देखा. प्रकृति पूरी तरह प्रतिकूल है. इसके पहले हमारे साथ अनुकूलता थी. मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं कि धान की फसल के साथ

उड़द,मूंग,तिल्ली आदि का भी सर्वे कराकर सहायता का प्रावधान वहां हो इस बात का विशेष प्रावधान रखा जाये.

अध्यक्षजी, सर्वेक्षण दलों में संवेदनशीलता जरुरी है. विंध्य भू भाग में पठारी भूमि बहुत अधिक है. अधिक मेहनत में, कम उत्पादन उसकी विशेषता रही है. इसलिए और अधिक संवेदना और आपकी कृपा का विंध्य आकांक्षी है. विंध्य क्षेत्र के गरीब तबके के, विशेषतः अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग शासकीय भूमियों पर पुश्तैनी काश्त करते हैं और उसका राजस्व अभिलेख उनके नाम पर नहीं है, ऐसी स्थिति में उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि वह जमीन म.प्र.शासन के नाम पर दर्ज है, पर पुश्तैनी रुप से अनुसूचित जाति,जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग उनमें खेती करते हैं. मेरा आग्रह है कि उनके मामले में भी सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये.

अध्यक्षजी, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में विशेष कर विंध्य में बंटाई की खेती परम्परागत रुप से होती है. उसमें भूमिधर को तो मुआवजा मिल जाता है लेकिन बंटाई में जो खेतीहर है उसको मुआवजा नहीं मिल पाता. इस दिशा में भी व्यावहारिक कदम उठाने की जरुरत है.

अध्यक्षजी, राहत राशि का बंटवारा तो ठीक है लेकिन राहत कार्य खोलना आवश्यक है. एक निश्चित मापदंड बनाकर प्रत्येक गांव में राहत कार्य खोले जाये. उनके समुचित मेहतनताना का बंटवारा हो सके. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

अध्यक्षजी, पशुपालन की बात सभी ने की है. पशुपालन को बढ़ावा तो देना है. पर विशेषकर विंध्य में पशु चारे बड़ी समस्या है. पशुचारे की व्यवस्था भी इस विभिषिका से निपटने का एक आधार है.

अध्यक्षजी, विंध्य सूखी खेती का क्षेत्र रहा है. सूखी खेती को बढ़ावा देना भी इस सरकार के उद्देश्य में शामिल होना चाहिए और सूखी खेती को बढ़ावा देकर ही हम बहुत सारा काम कर सकते हैं जो गरीबों को मदद करने वाला होगा. आपने समय दिया. धन्यवाद.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्षजी, नवदुनिया अखबार में एक चित्र छपा है (अखबार में छपा फोटो दिखाते हुए) इसको देखने के बाद आपकी संवेदनाएं क्या कहती है वह आप सोच लें.

अध्यक्षजी, मैं कुछ मांगे रखना चाहता हूं. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी के अभाव में लोग जबरजस्त रुप से पलायन कर रहे हैं और कहीं भी रोजगार मूलक कार्य नहीं है. कृपया तुरंत कार्य प्रारंभ कराये जायें और नुकसान का सर्वे पूर्ण कराकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की राहत राशि स्वीकृत की जाये.

अध्यक्षजी, पेयजल की व्यवस्था हेतु विशेष पैकेज स्वीकृत कर, पेयजल योजनाएं स्वीकृत की जाये. प्रभावित किसानों को केसीसी के ऋण माफ किये जायें एवं बैंक द्वारा खाद-बीज देकर तत्काल उन्हें रबी फसल की बोनी करायी जाये. मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित कराना चाहूंगा कि प्रदेश की कई सहकारी बैंकों ने KCC (केसीसी) का ऋण तो वापस ले लिया लेकिन इस बार केसीसी का फायनेंस नहीं किया है. बैंक केसीसी पर ऋण नहीं दे रही है. आप अपनी घोषणाओं का पालन कैसे करायेंगे वह भी देख लें.

अध्यक्षजी, कृषकों की फसल बीमा राशि जो आपने 2012-13 के 12 हजार करोड रुपये के दावे प्रस्तुत किये थे उसमें से 515 करोड़ रुपये ही मिले हैं उनको तत्काल बंटवाया जाये. फसल बीमा की इकाई किसान के खेत को बनाया जाये. जिन किसानों ने अभी तक आत्महत्या की है, उनका कर्ज चुकाने और परिवार में बच्चों की पढ़ाई का दायित्व सरकार ले और यथासंभव हो तो इन सभी परिवारों का एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ करे.

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ आपने जो आरबीसी में संशोधन किये हैं. उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं. आप बोलेंगे भी. आपने बढ़ाया भी है. प्राकृतिक आपदा में व्यक्तियों के मरने पर आपने राशि डेढ़ लाख रुपये से चार लाख रुपये की है उसके लिए धन्यवाद लेकिन किसान इसमें कैसे जुड़ेगे? जैसा रामेश्वर शर्मा जी कह रहे थे. आप कह रहे थे. एक माह का वेतन दे दो. मैं चार जगह गया हूं. दो जगह नकद 5-5 हजार रुपये किसानों को देकर आया हूं और आप सभी किसानों को, जिन्होंने आत्महत्या की है, हार्ट अटैक से मरे हैं, उनको प्राकृतिक आपदा में जोड़कर 4 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्रीजी करेंगे तो हमारा पूरा कांग्रेस दल मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि किसानों के हित में एक माह का वेतन देने के लिए पूर्णतः तैयार है लेकिन जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको आप प्राकृतिक आपदा में जोड़कर कवर करें.

श्री विश्वास सारंग—इसमें भी कंडीशन...? आप राहत में भी शर्त लगा रहे हैं..

(व्यवधान)

श्री रामनिवास रावत – माननीय अध्यक्ष महोदय एक लाइन और रह गई है कि बिजली के बिल भी एक वर्ष के कृषि पंपों के माफ किये जायें और आत्महत्या करने वाले किसानों को 5 – 5 लाख रूपये की सहायता दी जाय और जहां पर भी खाद बीज मुहैया कराया जाता है वहां पर रबी की फसल की बोनी की व्यवस्था कराई जाय और श्योपुर में नहरें पूरी बंद हैं सिंचाई बंद है अधिकारी कहते हैं कि सरसों नहीं होती है, श्योपुर के विधायक जी से भी पूछ लें इस तरह से विधायक निरंकुश हो गये हैं. बिना सूखा के सूखा पड़ गया है इनको भी तत्काल नहरें खुलवाने के आदेश दिये जायें. माननीय अध्यक्ष महोदय आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद्. कहना तो बहुत कुछ चाहता था, अध्यक्ष महोदय किसानों की बात हो रही है यहां पर रोना आ रहा है आज पूरे प्रदेश की और विधान सभा की स्थिति को देखकर कि किस तरह से भाजपा इस संवैधानिक व्यवस्था संवैधानिक सदन विधान सभा का राजनीतिक प्लेट फार्म के रूप में उपयोग कर रही है मैं इसकी घोर निंदा करता हूं...(व्यवधान)..

श्री रामेश्वर शर्मा – आपने 5 हजार रूपये दिये हैं तो सदन को न बतायें.

श्री मुकेश नायक (पवई) – माननीय अध्यक्ष महोदय जैसे ही मेरा नंबर बोलने के लिए आया है(XXX) . उन्हें पता था कि अब उन्हें.

श्री विश्वास सारंग – आध्यक्ष महोदय यह बहुत ही आपत्तिजनक है.

अध्यक्ष महोदय – यह (XXX) शब्द कार्यवाही से निकाल दें...(व्यवधान)..

श्री मुकेश नायक – अरे गुप्ता जी आप बैठ जायें. आप बैठो, बैठो..(श्री उमाशंकर गुप्ता जी के लगातार बोलते रहने पर)

श्री उमाशंकर गुप्ता – अरे हम क्यों बैठें..(व्यवधान)..

श्री मुकेश नायक – इसलिए कि नियम के विरूद्ध खड़े हैं आप. बैठिये जब चाहे(XXX) बोलने लगते हैं...(व्यवधान). आपका विभाग तो संभाला नहीं जा रहा है यहां पर व्यवधान पैदा कर रहेहैं..

अध्यक्ष महोदय – यह (XXX) शब्द विलोपित करें...(व्यवधान)..

श्री मुकेश नायक – यह क्या तरीका है अध्यक्ष महोदय, बोलने का एक नियम होता है, एक प्रक्रिया होती है एक मर्यादा होती है बोलने की(श्री उमाशंकर गुप्ता जी बिना माइक के लगातार बोलते रहे..व्यवधान...) जब चाहे खड़े होकर बोलने लगे,..(व्यवधान).. यह क्या तरीका है अध्यक्ष महोदय हम मुख्यमंत्री जी का भाषण नहीं होने देंगे अगर इस तरह से व्यवधान किया तो.. ध्यान रखिये. और यह गुप्ता जी की जिम्मेदारी होगी. ..(व्यवधान)..(XXX)

अध्यक्ष महोदय -- यह कार्यवाही में से निकाल दें...(व्यवधान)..कृपया नायक जी आप बैठ जायें. सभी लोग बैठ जायें...(व्यवधान)..

श्री मुकेश नायक – अध्यक्ष महोदय यह क्या तरीका है.(नाराज होकर जोर से बोलते हुए)..(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय – माननीय मुकेश नायक जी पूर्व मे उच्च शिक्षा मंत्री थे वह शायद भूल गये कि वहसदन में बैठे हैं, बाहर नहीं, इसलिए ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि शालीन भाषा में अपनी बात रखें...(व्यवधान)..

श्री मुकेश नायक – गुप्ता जी आपके बारे में जल्दी बात चीत करूंगा चिंता नहीं करना, जनता के बीच में भी और इस सदन में भी. (XXX) यह विधान सभा में बैठे हैं...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – नायक जी आप इस तरह से बोलेंगे तो बात नहीं बनेगी.

श्री मुकेश नायक -- अगर यह बोलेंगे.. आप इनको बैठा लिये..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – यह आप क्या कर रहे हैं..(व्यवधान).. नहीं तो आप इस तरह से बात करेंगे क्या..(व्यवधान).. यह निकाल दीजिये कार्यवाही से जो इन्होंने कहाहै....(व्यवधान)..(अनेक माननीय सदस्य आपस में जोर जोर से बिना माइक के बोलते रहे).

श्री मुकेश नायक – अध्यक्ष महोदय यह देखिये यह क्या हो रहा है.

अध्यक्ष महोदय – नहीं, पर क्या आप इस तरह की भाषा के लिए सपोर्ट करते हैं .(श्री राम निवास रावत जी के कुछ कहने पर).. आप लोगों ने यह क्या कर दिया है आप तो कम से कम समझाइये आप मुख्य सचेतक हैं. यहां पर भाषाएं तो अच्छी रखें...(व्यवधान)..

श्री मुकेश नायक –यह व्यवधान क्यों पैदा करते हैं.

अध्यक्ष महोदय – वह आपसे सीनियर हैं आप बोल नहीं पायेंगे उनसे.

श्री मुकेश नायक – इतनी गंभीर चर्चा हो रही है. अगर मैंने कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन से उठकर चले गये तो मैंने क्या गलत बात बोल दी है...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – अगर आप ऐसा बोलते तो कोई एतरारज नहीं होता.

श्री मुकेश नायक –(XXX)...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – यह निकाल दीजिये...(व्यवधान) आप बैठ जायें. आज भोजनावकाश नहीं होगा, अनुपूरक पर चर्चा जारी रहेगी । मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है । डॉक्टर साहब...

श्री गौरीशंकर शेजवार-- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने चेतावनी दी है कि सदन में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिये, आपने स्वयं ने चेतावनी दी है कि शालीन भाषा का उपयोग होना चाहिये । मुकेश नायक जी को इस पर खेद व्यक्त करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय-- मुझे विश्वास है कि वह ठीक से बात करेंगे अब । (व्यवधान) चलिये, आप 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे, अब ज्यादा समय नहीं है ।

श्री मुकेश नायक-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है प्रदेश की जनता के सामने कि 70 के दशक के बाद मध्यप्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा सूखा है और इस कठिन दौर में हमें इस बात पर विचार करना होगा कि सहकारी बैंक, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल और किसानों से जुड़े हुये जो सरकारी महकमे हैं उनमें किस तरह की उदारता और सहिष्णुता की इस संकट के समय में आवश्यकता है । 3 साल हो गये मध्यप्रदेश में, बुंदेलखंड जैसे अंचलों में 3 साल से फसलें नहीं आई हैं । सहकारी बैंक के लोग कर्ज वसूलने के लिये खड़े हुये हैं । बिजली विभाग के लोग मोटर साइकिल उठाकर ले जाते हैं, टेलीविजन उठाकर ले जाते हैं, पंखे उठाकर ले जाते हैं, साइकिल उठाकर ले जाते हैं, इस पर प्रतिबंध होना चाहिये, इस पर बहुत सरकार को सहिष्णुता की आवश्यकता है ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री जी से यह उम्मीद करता हूं कि जब वह विधानसभा में अपना उत्तर दें तब इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें कि माननीय प्रधानमंत्री जी और केन्द्र सरकार से जब मिलने गये थे, माननीय वित्तमंत्री जी का बयान भी अखबारों में आया था वह भी मिलने गये थे, तो कितनी राहत राशि के पेकेज की केन्द्र सरकार से उन्होंने मांग की और उसके उत्तर में केन्द्र शासन ने कितनी धनराशि उनको उपलब्ध कराई । मुझे जानकारी मिली है माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी सदन में बैठे हैं कि 3500 करोड़ रूपये के कर्ज की अनुमति केन्द्र सरकार से राज्य सरकार ने मांगी थी और 9 अक्टूबर को केन्द्र सरकार ने 3500 करोड़ रूपये की अनुमति राज्य सरकार को प्रदान कर दी थी । मैं जानना चाहता हूं कि अगर समय पर यह धनराशि आहरित कर ली जाती और किसानों को बांट दी जाती तो हो सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में जो किसानों ने आत्महत्या की है उन्हें कुछ राहत उपलब्ध हो सकती थी । एक तरफ सूखे की मार है, हितग्राही मूलक योजनायें मध्यप्रदेश में ठप्प पड़ी हुई हैं, आपनी विकलांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना । हम दौरे पर जाते हैं सौ-सौ, दो-दो सौ बुजुर्ग

महिलायें और पुरूष हमारे सामने आते हैं दरख्वास्त लेकर कि हमें पेंशन नहीं मिल रही, 8 महीने हो गये, इस तरह से आप सरकार चलाओगे। यह आपकी उदारता, सहिष्णुता है सरकार चलाने की।

माननीय मुख्यमंत्री जी इसीलिये मैंने कहा आप सदन छोड़कर चले गये क्योंकि मैं बहुत आपसे पूछना चाहता था। एक बात और बतायें आप म0प्र0 की विधानसभा को हम सब लोग जानना चाहते हैं, हमारा अधिकार है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब कितनी धनराशि, आप केटेगरीकली वर्षवार बतायें कि कितनी धनराशि म0प्र0 शासन को उपलब्ध कराई गई और माननीय मोदीजी जब प्रधानमंत्री हैं तब कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई। अब मुख्यमंत्री जी अनशन पर नहीं बैठते, अध्यक्ष महोदय, अब धरने पर नहीं बैठते। (XXX)

अध्यक्ष महोदय-- यह कार्यवाही से निकाल दें। आप कृपया समाप्त करें अब, आप समाप्त करें कृपया।

श्री मुकेश नायक-- मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, मुझे 5 मिनट और बोलना है।

अध्यक्ष महोदय –कृपया आप समाप्त करें. बजाए सूखे के आप राजनैतिक भाषण दे रहे हैं. कृपया एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करें. कुछ सुझाव हों तो दे दें.

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं. यह अव्यवस्था, अराजकता और वित्तीय कुप्रबंध के मूर्तमंत्र हो गये हैं. नरोत्तम मिश्रा जी जो अभी कह रहे थे कि कांग्रेस के विधायक मध्यप्रदेश में दौरे पर नहीं जाते हम लोग दौरे पर जाते हैं लेकिन आपकी तरह वसूली करने नहीं जाते, समझ गये न. आप हर महीने दौरे पर जाते हैं, वसूली करने, रेवेन्यू टेक्स लेने.

अध्यक्ष महोदय—यह उचित नहीं है. कार्यवाही से निकाला जाता है.

श्री मुकेश नायक – अध्यक्ष महोदय, यह कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक दौरे पर नहीं जाते हैं .

अध्यक्ष महोदय—आपको कुछ बोलना नहीं है. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया....

श्री मुकेश नायक—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी हम सरकार के खिलाफ तीखी बातें करते हैं, जब भी सरकार को हम जगाने का प्रयत्न करते हैं , जब भी हम जनहित की बात करते हैं आप कहते हैं बैठ जाओ, इस कारण हम बैठ रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—यह कोई जनहित की बात नहीं है. धन्यवाद आपको बैठने के लिये.

श्री यशपालसिंह सिसोदिया(मंदसौर) – माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय की गंभीरता है सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है. इस इच्छाशक्ति में दृढ़ संकल्प है. माननीय अध्यक्ष महोदय, संचित निधि में से प्रस्तावित अनुपूरक बजट के लिये आठ हजार चार सौ सात करोड़, चौबीस लाख, इक्यासी हजार आठ सौ चालीस रूपये की राशि की मांग की गई है साथ में ही पूरे प्रदेश में सूखे को लेकर के जो भयावह स्थिति निर्मित हुई है उसको लेकर के भी चर्चा हो रही है. मैं इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सूखे को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला बयान , वह बयान जिसमें उन्होंने किसानों को ढांढस बंधाने का काम किया आत्म विश्वास देने का काम किया है . बयान था "फसल हारी है – जिंदगी नहीं हारी" और मैं किसानों को जिंदगी नहीं हारने दूंगा चाहे विकास का पहिया एक साल के लिये थम जायेगा लेकिन अधिकतम बजट की राशि किसानों के लिये सूखा राहत के अंतर्गत प्रदत्त की जायेगी. यह मुख्यमंत्री जी की इच्छाशक्ति है. पूर्व कृषि मंत्री कांग्रेस पक्ष की ओर से जिन्होंने इस विषय की शुरूवात की. बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, लोक सभा के भी सदस्य रह चुके हैं. जल्दी जाना था प्रदर्शन को लेकर के कांग्रेस की ताकत और शक्ति बताने के लिये वे उठकर के यहां से चले गये. अखबार की कतरनों के माध्यम से जो नेता बयानबाजी करता है या अखबार के सहारे जो आंकड़ो को प्रस्तुत करता है, मैं समझता हूं कि वह अपने आपको भी धोखा दे रहा है, क्योंकि कभी कभी अखबार वालों को खंडन भी करना पड़ सकता है उन समाचारों का, वे अपनी बात को कहकर के चले गये.

श्री कमलेश्वर पटेल – ऐसा कहकर के तो आप अखबार-मीडिया के साथियों पर आरोप लगा रहे हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—अध्यक्ष महोदय, पिछली विधानसभा में तीन दिवसीय विशेष सत्र प्रदेश के विकास के रोडमेप को लेकर के आहूत किया गया था. मैं भी उस सत्र में सदस्य के रूप में शामिल था तीन दिवसीय उस विशेष सत्र में प्रतिपक्ष ने सत्र का बहिष्कार किया था. शेडो कैबिनेट का एक नया शब्द उन दिनों मैंने सुना था उसको देखा कि प्रतिपक्ष सदन से उठकर के जायेगा और अपने अलग से तय एक शेडो मंत्रि मंडल की बात करेगा और आने वाले सत्र में अलग अलग विभाग के मंत्री बन गये, कपोल कल्पित. और आकर के उन्होंने क्या किया, क्या खोया क्या पाया यह तो वही जाने उनका दल जाने. मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं. मेरे क्षेत्र में इसबगोल की फसल बड़ी मात्रा में होती है . पिछले दो वर्ष पहले भी अचानक आई बारिश के कारण से इसबगोल जैसी फसल को आरबीसी की धारा 6(4) के अंतर्गत सम्मलित करते हुये 25,000 रूपये प्रति हेक्टेयर किसानों को मुआवजा देने की बात कही गई है, और अगले वर्ष फिर जब किसानों को नुकसान हुआ तो उस राशि को बढ़ाकर के 26,000 रूपये प्रति हेक्टेयर के मान से उसकी पूर्ति की गई. शायद यह भी इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि एक विषय पर लगातार 5-6-7 घंटे की चर्चा की अनुमति आपने प्रदान की है. 164 अधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा करना शायद मुझे लगता है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इतने बड़े व्यापक पैमाने पर 164 अधिकारियों से चर्चा नहीं की होगी, मंत्रियों को जिले में प्रभावित क्षेत्र में भेजना और अलग से अधिकारियों को भेजकर के इस बात की टोह लेना इस बात की जानकारी लेना कि किसान क्या कह रहा है, किसान का दर्द क्या है. लगातार 3 दिवस तक चलने विशेष चर्चा में मुख्यमंत्री जी ने एक एक बातों को जिस प्रकार से अधिकारियों के बीच में शेयर किया , इतना ही नहीं अधिकारियों के साथ में बैठकर के एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, उस कार्यशाला में निकलकर के यह आया कि किसान क्या चाहता है, किसान को किस किस प्रकार की आने वाले वर्षों में भी किस प्रकार की सुविधा दी जा सकती है उसके बारे में चर्चा की. किस प्रकार की सुविधा दी जा सकती है, उसके बारे में चर्चा की गई है. मैं मालवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं. हम इस बात को सुनते थे,

चावला जी, राजेन्द्र पाण्डेय जी, ओमप्रकाश सखलेचा जी, दिलीप सिंह जी बैठे हैं, चन्दर सिंह सिसोदिया जी बैठे हैं. हमारे इधर फसल मेंजब फल नहीं लगता था, शब्द हमारे मालवा में होता था कि फसल बेंडा गई है. हमने पहली बार सुना कि अफलन हो गया है. मतलब पौधा तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन उसके ऊपर एक भी फली नहीं आई है. इस अफलन को भी जोड़ते हुए मुख्यमंत्री जी ने इस बार नहीं, पहले से ही तय कर दिया था कि अफलन की फसल पर भी किसानों को मुआवजा दिया जायेगा, उसमें शामिल किया जायेगा. जिन दो माह के संशोधित नियम की बात की जा रही है, अनेक सदस्यों ने कहा कि हमको यह आदेश प्राप्त नहीं हुआ. हिन्दुस्तान में नहीं एशिया में सबसे ज्यादा यदि कहीं कूप खनन होता है, कहीं कुए खोदे जाते हैं, तो मंदसौर और नीचम जिले में खोदे जाते हैं. मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं. वह आदेश मैंने पढ़ा है. माननीय चतुर्वेदी जी ने एक आदेश जारी करके मुख्यमंत्री जी के निर्देशों को और यह बात आज नहीं पैदा हुई. जब मुख्यमंत्री जी ने 12 तारीख को वीडियो कांफ्रेंसिंग ली थी, चौधरी चन्द्रभान सिंह जी ने छिंदवाड़ा में बैठ करके मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिये सुझाव दिया था और मैंने 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि चौधरी चन्द्रभान सिंह जी ने जो सुझाव दिया, मेरे क्षेत्र में मंदसौर, नीमच जिले में बहुत कुए हैं, वहां

1.11 बजे {सभापति महोदया (श्रीमती अर्चना चिटनिस) पीठासीन हुई.}

चार महीने का नीचे पानी ही नहीं है, चार महीने का कनेक्शन देने का क्या फायदा.

किसान को दो महीने का अतिरिक्त पैसा लगेगा. मुख्यमंत्री जी की संवेदना है, उसी समय वीडियो कांफ्रेंसिंग में उस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया और 4 दिन बाद ही वह आदेश जारी हुआ और मुझे बताते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि वह आदेश एक्जीक्यूट हो गया है. 50 प्रतिशत की जो नियामक आयोग की शर्त है कि डीपी, ट्रांसफार्मर खराब होने पर 50 फीसदी कम से कम राशि जमा होगी, तभी जाकर के उसको बदला जायेगा. मुख्यमंत्री जी ने सूखे के समय में न केवल जो सूखाग्रस्त तहसील है, पूरे मध्यप्रदेश में 10 प्रतिशत की राशि करके किसानों को बड़ी राहत दी. सभापति महोदया, सूखे के लिये मुख्यमंत्री जी अतिसंवेदनशीलता बरतते हुए, कल कांग्रेस के एक पूर्व सासंद, वरिष्ठ नेता का एक वक्तव्य मैंने टीवी में देखा. उन्होंने कहा कि साहूकारिता शुरु होना चाहिये और उसको लेकर मैं एक यात्रा निकालूंगा. अभी रावत जी यहां पर कह रहे थे कि साहूकारिता से प्रदेश के किसान पीड़ित हैं. मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को दोहराया भी है कि सहकारिता का ऋण तो ऋण अगर कोई साहूकार भी इस समय में किसी किसान से जबरदस्ती पैसे वसूल करने की बात करेगा, हम उसको भी ठीक करेंगे, उसके ऊपर भी कानूनन कार्यवाही करेंगे. एक तरफ कांग्रेस के एक नेता बयान देते हैं कि सहकारिता प्रारंभ होना चाहिये, जिस चीज को मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के हाथों से निकाल करके एक न्याय दिया. जीरो प्रतिशत की ओर अग्रसर करने का काम किया और कल मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की बैठक में इस बात की चिंता की है कि पूरे मध्यप्रदेश के किसानों को क्यों नहीं सहकारिता के क्षेत्र से जोड़ करके उनको जो कमर्शियल बैंक हैं, जो व्यावसायिक बैंक हैं, उनसे निकालते हुए सहकारिता के क्षेत्र

में जीरो प्रतिशत का लाभ दिया जाय. ऐसे केम्प आयोजित किये जायें और उसमें उनको जोड़ा जाय. नये नवाचार हुए हैं. स्वाइल हैल्थ कार्ड को लेकर के मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित थे. मध्यप्रदेश में 23000 पंचायतें हैं, मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में फूड प्रोसेसिंग को लेकर के एक अलग से यूनिट हो और उसमें युवा उद्यमी जुड़ें. यह संकल्प अभी जो सूखा पड़ा है, इस सूखे को लेकर के कार्य योजना में शामिल किया गया है. विभिन्न विभागों का जो बजट पारित किया गया था, हमने, सबने मिलकर के उसमें अभी वर्तमान में किस प्रकार से कटौती करके किसानों की भरपाई की जाय, किसानों को राहत दी जाय, यह संकल्प भी मुख्यमंत्री जी ने इसमें जोड़ा है. सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक निर्णय और करने की इस परिचर्चा में ठानी है. मंडियों में फल और फूल की सब्जियां, फल फूल बिके और वहां पर आढ़त से किसान मुक्त हो. यही सरकार है, जिसने कांग्रेस के जमाने में 10-12 प्रतिशत से अधिक आढ़त काटी जाती थी, आढ़त प्रथा से आज मध्यप्रदेश में किसानों को मुक्ति मिली है. जिस क्षेत्र का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, डोडा चूरा अफीम का एक बाय प्रोडक्ट है. कांग्रेस के जमाने में 300 रुपये क्विंटल डोडा चूरा बिकता था. आज 10 हजार में कम से कम सौ रुपये का समर्थन मूल्य मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तय किया है. इस सूखे के समय में एक और संवेदनशीलता का परिचय माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि उन प्रभावित किसानों के घरों में बटिया का विवाह है, उसको भी व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में जोड़कर के कोई आवश्यक नहीं है उसको एक समारोह के रूप में आयोजन करके उस बिटिया को सरकार की ओर से राहत दी जाए, यह तय कर दिया गया है. मैं कांग्रेस के मेरे मित्रों से कहना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस के दल में कहां कमियां और कहां पर खामियां हैं, वह यह अध्ययन कर लें. माननीय मानवेन्द्र जी इधर पधार गये, माननीय संजय पाठक जी इधर आ गये, माननीय नारायण त्रिपाठी जी ने कांग्रेस छोड़ दी, आज आप मंथन करें कि कांग्रेस की दुर्गति क्यों हो रही है, सिर्फ इस कारण से हो रही है कि सदन में चिल्लाना व्यर्थ का, मीडिया में जाकर के बयान देना यह बात जनता मध्यप्रदेश की पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी हुई है. बहुत बहुत धन्यवाद.

श्रीमती उषा चौधरी (सतना)—माननीय सभापति महोदय, सतना जिले को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है, लेकिन सतना जिले में आज तक कहीं पर भी पटवारी, तथा तहसीलदारों के द्वारा सर्वे का कार्य नहीं किया गया है. कलेक्टर केवल मीटिंग पर मीटिंग लेते हैं उसमें फटकार के निर्देश पर निर्देश देते हैं, जो कि मीडिया में भी आता है, लेकिन कहीं पर भी किसानों के खेतों में सर्वे नहीं हुआ है तथा उनको आज तक एक रूपये का भी मुआवजां नहीं मिला है. पिछले औलावृष्टि में जिन किसानों का नुकसान हुआ था उसका भी मुआवजा किसानों को नहीं मिला है. सरकार खूब कहती है मीडिया में आता है घोषणाएं ही घोषणाएं होती हैं, लेकिन धरातल पर किसानों के लिये वास्तव में चिन्ता करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है और न ही किसानों को आज तक मुआवजा मिला है, जबकि सतना जिले को सूखाग्रस्त जिला घोषित किया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसानों की बिजली आपूर्ति के कारण बताकर किसानों को पानी नहीं दे पा रहे हैं. आप कृषि की बात को तो छोड़ दीजिये यहां तक वहां पर पेयजल की समस्या भी

है, वहां पर छः छः महीनों से ट्रांसफार्मर जले हुए हैं किसान बिजली का बिल भर चुका है, लेकिन वह ट्रांसफार्मर जल गया फिर भी छः महीने के बाद किसानों को बिजली का बिल दिया जा रहा है, यह किसानों के ऊपर दोहरी मार है, जो कि किसान झेल रहा है. किसानों की खेती की समस्या है बिजली एवं पानी के कारण और पेयजल की समस्या यहां तक कि अगर 200 गांवों की एक दलित बस्ती है, वहां पर एक हैंडपम्प है, हमारी कार्य-योजना में सरकार तथा अधिकारीगण कहते हैं कि अगर 200 लोगों की दलित बस्ती है उसमें एक हैंडपम्प है उसमें दूसरा हैंडपम्प नहीं लगाया जाएगा वह कहते हैं कि यह कार्य-योजना में नहीं है. मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि कार्य योजना आखिर बनाएगा कौन ? तथा इस कार्य-योजना का चलाएगा कौन ? पानी की समस्या है, वर्षा के अभाव के कारण जलस्तर घटा है लोग मजदूरी करने के लिये जाते हैं उनका 8 तथा 10 बजे का समय होता है, लेकिन एक हैंडपम्प में के कारण उन लोगों को लाईन लगाना पड़ता है. पानी की समस्या के कारण छोटी-छोटी बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं वह सिर पर डिब्बा और कसैड़ी को रखकर एक-एक अथवा दो-दो किलोमीटर पानी के लिये जाती हैं. मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि सतना जिले को सूखाग्रस्त जिले की घोषणा तो की गई है, लेकिन वहां पर जो जलस्तर नीचे चला गया है उस जलस्तर को सुधारने के लिये यहां तक कि हम लोग विधायक निधि से तालाब की खुदाईकरण के लिये पैसा देते हैं उसमें कलेक्टर एवं सीईओ के यहां पर घूसखोरी के चलते उन पैसा का आहरण नहीं कर पाते हैं और उक्त पैसा लेप्स हो जाता है. चित्रकूट विधान सभा क्षेत्र में एक तालाब की गहरीकरण के लिये विधायक निधि से पैसा दिया गया, लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया जिसके कारण तालाब के गहरीकरण का कार्य रूक गया है. मेरा सुझाव है कि सतना जिले का पूरी तरह से ध्यान रखा जाये. मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी लिखकर के दिया था कि सतना जिले में जिन क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर 45 हैंडपम्पों के लिये और जो पी.एच.ई विभाग में 20 हैंडपम्प विधायक के अनुमोदन के माध्यम से होते हैं एक ब्लाक में होते हैं वहां पर एक भी हैंडपम्प नहीं खुदे हैं इसलिये किसानों के साथ-साथ मैं चाहूंगी कि क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था के लिये भी छोटे-छोटे डेम बनवाएं जाएं और हैंडपम्पों को खुदवाकर मजदूरों किसानों और दलितों के बीच में पानी की व्यवस्था की जाये ताकि जो पीने के पानी की व्यवस्था है उनको मुहैया हो सके. एक निवेदन और करना चाहती हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई है मनरेगा को स्वरोजगार योजना के तहत मजदूरों के लिये मनरेगा में न तो कोई काम चल रहा है और ना ही रोजगार गारंटी योजना चल रही है और यहां तक साल भर पहले जिन मजदूरों ने काम किया उनको मजदूरी आज तक नहीं मिली है. इस परिस्थिति में सूखे की मार हम कैसे झेल पाएंगे. कैसे किसान की हम सुरक्षा कर पाएंगे. माननीय सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगी कि सतना जिले को केवल सूखा घोषित करने से ही नहीं कलेक्टर को निर्देश दें कि सतना जिले में धरातल में काम करके पानी की व्यवस्था की जाये और पानी कैसे समाज के लोगों तक पहुंच सके. इसकी व्यवस्था की जाये. हैंडपंपों की व्यवस्था की जाये. कार्य योजना में उन कामों को शामिल किया जाये. इसी बात को कहते हुए और जो राशन की दुकानों में अनाज मिलेगा तो उनकी मदद होगी. आपने समय दिया धन्यवाद.

डॉ.गोविन्द सिंह(लहार) – माननीय सभापति महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों की समस्या और उनके दुखों को देखते हुए यह सत्र बुलाया है इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं. लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा परंपरा रही है कि कई मदों में बजट अधिक खर्च हो जाता है और उसको जब आगामी सत्र आता है तो अतिरिक्त बजट के द्वारा उसकी स्वीकृति मिल जाती है. इस सत्र की कोई जरूरत नहीं थी और मध्यप्रदेश में करीब साढ़े पांच लाख अधिकारी,कर्मचारी हैं उसमें से 30 परसेंट पद खाली हैं उससे अधिक ही हैं. प्रतिवर्ष 30 हजार करोड़ रुपये एक वर्ष में कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर खर्च होता है. 30 परसेंट पद खाली है तो उसके हिसाब से 9 हजार करोड़ रुपये आपके पास बचता है वह जाता कहां है उस पैसे से भी आप इसकी पूर्ति कर सकते थे. कृषि थ्रेशर और कृषि पंपों के लिये आपने विद्युत के बिल माफ करने के लिये बजट में प्रावधान किया है इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं क हना चाहता हूं आपने अभी एक आदेश निकाला कि 10 परसेंट किसान अगर ट्रांसफार्मर का देगा तो उसको आप ट्रांसफार्मर रखवा देंगे परन्तु स्थिति इससे अलग है इसमें कठिनाईयां हैं. व्यवहारिक रूप से यह उचित नहीं है. एक ट्रासंफार्मर पर 5 किसान पंप लिये हुए हैं. 2 किसानों का ट्यूबनेल फेल हो गया. पानी नहीं बचा. एक किसान छोड़कर चला गया और एक किसान बचा और उस किसान पर 50 हजार रुपये का 10 परसेंट जमा करना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में वह 10 हजार रुपये लायेगा कहां से. आप मुफ्त में सूखे के लिये नि:शुल्क दे रहे हैं तो यह जो 10 परसेंट का नियम है उसको भी हटायें. इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप किसानों को राहत देना चाहते हैं तो आप डीजल पर केवल कृषि के लिये वेट कम कर सकते हैं. इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कम से कम आज आप बिजली के लिये मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की थी कि हम किसानों को जेल नहीं जाने देंगे लेकिन कोई किसान चोरी से चलाता है तो धारा 138 में कार्यवाही करें परन्तु विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत् अनेक गांव ऐसे हैं एक गुरुथर गांव हमारे क्षेत्र में ऐसा है जहां बिजली के खम्भे,तार आंधी में टूट गये थे. वहां न खम्बे लगे हैं न तार हैं न ट्रांसफार्मर है लेकिन वहां 28 किसानों पर 70-80 हजार रुपये की वसूली निकाल ली. हमने निवेदन किया जब तक जांच होती उन पर न्यायालय में प्रकरण दर्ज हो गया और न्यायालय में आपके विभाग के तमाम वकीलों को नियुक्त कर दिया वकीलों की वकालत तो चलती नहीं है उनको 15 परसेंट कमीशन मिलता है तो उन किसानों पर मुकदमे दायर कर दिये गये. हमने न्यायालय के लोगों से राय ली कानूनी प्रावधान नहीं है 135 की धारा में गिरफ्तारी वारंट का प्रावधान है जमानत का प्रावधान नहीं है और दशहरे के दिन 4 किसान जेल में चले गये. छुट्टी थी 4 दिन की. लहार में कोई मजिस्ट्रेट तो गोहद न्यायालय पहुंचे और गोहद से उन्होंने वारंट बना दिया और उनको 4 दिन लहार जेल में रहना पड़ा. इस प्रकार अकेले 4 डिवीजन है भिण्ड विद्युत मण्डल में उन 4 डिवीजनों में से अकेले लहार में 680 किसानों की गिरफ्तारी हुई है यह आप अपने विभाग से जानकारी मंगा लें.

आपको जानकारी मिल जायेगी. मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी विद्युत कंपनी के द्वारा एक आदेश गया है कि किसान जो परमानेंट कनेक्शन ले रहे हैं चार महीने के पैसे उन्होंने कनेक्शन के जमा कर दिये लेकिन उनको कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि दो महीने के आप टेम्प्रेरी कनेक्शन के आप पैसे जमा करो तब आपको परमानेंट कनेक्शन देंगे. आपने किसानों को स्वयं के खर्चे पर कनेक्शन लगाने का प्रावधान किया है तो कई लोग कनेक्शन लगा रहे हैं।लेकिन दो महीने अतिरिक्त पैसे दो यह गलत है। यह आपका आदेश है, संभागीय अभियन्ता से भी बात हुई है, लेकिन वह कुछ कहने को तैयार नहीं है. उनको कहना है कि हमारे पास आदेश हैं. आप इसको भी देखें. मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि जैसे लगातार विपत्ती आ रही है, जैसे कहीं ओला,पाला,कहीं सूखे की विपत्ती आती है तो हमेशा यह परम्परा रही हैं की हम अकेले चलेंगे विपक्ष को सम्मान नहीं देंगे। लेकिन आप विपक्ष को भी साथ में लेकर चलेंगे और चर्चा करें तो रास्ते निकलते हैं। मेरे क्षेत्र के बगल में चार किलोमीटर दूर जालौन जिला है जो उत्तरप्रदेश में आता है। वहां पर आपने तहसील घोषित कर दी है। जालौन जिले में कई गांव ऐसे हैं जो जालौन जिले में होकर जाना पड़ता है। वहां पर आपने देखा नहीं जिस किसान पर 1 हैक्टेयर से अधिक जमीन थी वहां पर प्रत्येक किसान को 18 हजार रूपये जो 1 हैक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया है, जिनके पास 1 हैक्टेयर से कम जमीन है उसको 9 हजार रूपये दियेहैं। कई ऐसे लोग हैं जो जो हमारे क्षेत्र लहार में रहते हैं. आसपास के कई कस्बों में किसान हैं उनकों वहां से निकाल कर निर्देशित किया कि उनको चेक द्वारा जहां पर रहते हैं वहां पर दें। यह परम्परा है, आपकी नौकरशाही निरंकुश हो गयी है, आप जो आदेश देते हैं, वहां तक पहुंचते नहीं है। अगर पहुंचते हैं तो उसका पालन नहीं होता है। इसके कई उदाहरण है किसानों को अपमानित करना , गालियां देना और बेइज्जीत करना। वहां के अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है आप ट्रांसफार्मर पर भी किसानों को 10 प्रतिशत की छूट दें जब तक सूखे की मार चल रही है। उत्तरप्रदेश की तरह हर गांव के लिये किसानों के जो खाते हैं जिससे भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। क्योंकि आपके पास राजस्व अमला नहींहै।हमारे क्षेत्र में तीन तहसीलों में दो वर्ष से एक एक तहसीलदार है, एक एक पटवारी के पास पांच पांच छःछः हलके हैं, यह व्यवस्था हैजब तक आप राजस्व अमला नहीं बढ़ायेंगे तब तक आप ठीक से सर्वे नही कर पायेंगे. यही कारण है कि भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें आपके पास आती हैं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपको जो सुझाव दिये हैं उसको आप ठीक करें। क्योंकि इस समय सरकार की हालत ठीक नहीं हैं . आपने 12 वर्ष के कार्यकाल में 1 लाख 61 हजार का कर्जा आपने लाद दिया है। इसके बाद भी आप राहत देना चाहते हैं। लेकिन केन्द्र सरकार की कई योजना ऐसी हैं जिनसे आपको इस वर्ष 15 हजार करोड़ रूपये अनुदान में कटौती हुई हैं। जिसके कारण तमाम आर्थिक संकट आ रहा है। जब यूपीके की सरकार थी तो आप धरना प्रदर्शन करते थे . आप चलिये हम भी आप के साथ केन्द्र सरकार के पास चलते हैं हम प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कि आपदा है, संकट है इसमें आप सहयोग करें। मैं

आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जो शार्टटर्म लोन है उसमें नोडयूस की परम्परा कर दी है अब हर बैंक से जाकर किसानों को नोडयूस कराना पड़ता है। बैंकों ने अपनी फीस फिक्स कर दी है, कहीं सौ रूपये कहीं पचास रूपये है और बिजली विभाग का भी नौ डयूज चालू कर दिया है। किसानों को जो आप राहत देना चाहते हैं वह किसानों को नहीं मिल पायेगी। हमने जो सुझाव दिये हैं उसकोआप गंभीरता से लें। तभी आप जो किसानों को राहत देना चाहते हैं वह मिल पायेगी। इस सूखे की विपदा से किसानों को तभी राहत मिल पायेगी। आपने बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद। किसानों को जो राहत आप देना चाहते हैं वह मिल नहीं पायेगी हमने जो सुझाव दिये हैं हमें उम्मीद है आप उन पर गंभीरता से विचार करते हुए कुछ मानेंगे ताकि किसानों के लिये आपकी जो मंशा है जो इच्छा है उस हिसाब से आप उनको राहत दे पायेंगे और उनको सही तरीके से राहत मिल पायेगी इस आपदा के समय में सूखे के समय में किसानों का कल्याण होगा. सभापति महोदया, आपने बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद.

स्वल्पाहार की घोषणा

सभापति महोदय—माननीय सदस्यों के लिये स्वल्पाहार की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करने का कष्ट करें.

श्री विश्वास सारंग (नरेला)—माननीय सभापति महोदया, मैं वित्त मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं. माननीय सभापति महोदय पूर्व के वक्ताओं ने भी आज के इस विशेष सत्र को अविस्मरणीय और ऐतिहासिक बताया और मैं भी इस बात से सहमति व्यक्त करता हूँ क्योंकि माननीय मुख्यमंत्रीजी ने विगत दिनों जो किसानों पर आपदा आई और उसमें जो संवेदनशीलता दिखाई जो कदम उठाये उसी कड़ी में एक और आगे कदम था कि पूरे मध्यप्रदेश के किसानों को मुआवजा देने के लिये अनुपूरक मांगों में परिवर्तन करते हुए ज्यादा से ज्यादा मुआवजा किसानों को मिल सके इसके लिये विशेष सत्र आहूत किया गया. रामनिवास भाइसाहब अभी यहां पर बोल रहे थे कि उनको रोना आ गया नरोत्तम जी ने भी एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि यदि विपक्ष के सदस्यों को इतना ज्यादा किसानों के साथ दुख और दर्द था तो वे प्रदेश में कहां पर घूमे कहां पर दौरा किया. नरोत्तम भैया किसी ने कहा है कि –

कौम के गम में डिनर खाते थे हुक्काम के साथ,
रंज लीडर को बहुत था मगर आराम के साथ.

श्री मुकेश नायक—आपने नरोत्तम जी के बारे में बहुत अच्छा बोला. (हंसी)

श्री विश्वास सारंग—मुकेश भाइसाहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें यहां पर कहीं वे किसान से पायजामे तक पहुंच गये मैं उस विषय में ज्यादा नहीं पडूंगा.

श्री रामनिवास रावत—आपने क्या कभी तेंदूपत्ता तोड़ने में पसीना बहाया है?

श्री विश्वास सारंग—पिछली बार मुकेश भाई ने बोला था कि तुम्हें किसानों से क्या लेना देना विगत दिनों जब मुंबई की...

श्री मुकेश नायक—मैंने यह पूछा था कि आलू जमीन के अन्दर फलता है या ऊपर. (हंसी)

श्री विश्वास सारंग—माननीय सभापति जी विगत दिनों मुंबई की डांस बार खुलने के बारे में...

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—माननीय सभापति महोदय, यह ऐसी बातें तो कहा जाता (XXX)

सभापति महोदया—मैं समझती हूँ कि सभी माननीय सदस्य अपनी विषयवस्तु किसानों तक सीमित रखें सूखे तक सीमित रखें.

श्री रामनिवास रावत—सभापति महोदय, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में की गई टिप्पणी विलोपित होना चाहिये.

सभापति महोदया—नरोत्तम मिश्रा जी ने जो कहा है वह विलोपित कर दें.

श्री विश्वास सारंग—रामनिवास जी विगत दिनों जब मुंबई के बार के बारे में बात हुई थी तो आपने उसका समर्थन क्यों किया था क्या आप जाते हो वहां पर.

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रुप से माननीय मुख्यमंत्रीजी ने सरकार ने एक बहुत साहसिक कदम उठाया है और विगत 10-12 वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है किसानों के हित में और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिये सरकार ने यथायोग्य कदम उठाये हैं. अभी यशपाल सिंह सिसोदियाजी ने कहा कि पिछली विधान सभा में माननीय मुख्यमंत्रीजी ने स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाने के लिये तीन दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया था और उसमें खेती किस ढंग से मध्यप्रदेश में फायदे का सौदा बन सके इस पर विचार विमर्श हुआ और जो भी बातें आईं उसको पूरी तरह से मध्यप्रदेश में लागू किया गया उसी का परिणाम निकला शून्य प्रतिशत पर ऋण दिया गया जिससे किसानों के बहुत लाभ मिला. आपने भी अपने वक्तव्य में कहा था कि इस देश के इतिहास में शायद पहली बार सिंचाई का रकबा इतना बड़ा होने का रिकार्ड मध्यप्रदेश में कायम हुआ है. मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूँ आजादी के बाद और जब तक हमारी सरकार नहीं बनी थी केवल साढ़े सात हेक्टयर और जब से हमारी सरकार बनी है तब से 36 लाख हेक्टयर.

श्री कमलेश्वर पटेल—माननीय राजस्व मंत्रीजी को तो पता नहीं है कि सिंचाई का रकबा कितना बढ़ा है.

श्री विश्वास सारंग-- माननीय सभापति महोदया, सिंचाई के मामले में जो रिकार्ड कायम हुआ उसी का परिणाम निकला. मुकेश भाई बोल रहे थे कि यू पी ए की सरकार में हमें क्या मिला, अभी हमें क्या मिला है, माननीय मुकेश भाई, यू पी ए की सरकार में भी हमें कृषि कर्मण अवार्ड मिला और इस सरकार में भी हमें कृषि कर्मण अवार्ड मिला, यह मिला है हमें. (मेजों की थपथपाहट) क्योंकि हमने काम किया. हमने इस बात को स्थापित किया कि एक किसान के घर में पैदा हुआ यदि मुख्यमंत्री बनता है तो वह किसान के दर्द को समझता है और उसी का परिणाम है कि लगातार मध्यप्रदेश में नवाचार हो रहा है, कृषि के मामले में, कृषि केबिनेट के माध्यम से किसानों के हित के लिए विचार-विमर्श हो रहा है. मैं, कृषि के क्षेत्र में जो कृषि विकास की जो वृद्धि दर है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार उसमें वृद्धि हुई है. 2011-12 में उन्नीस प्रतिशत, आठ पाँच प्रतिशत की वृद्धि हुई. 2012-13 में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई

और 2013-14 में लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि मध्यप्रदेश में कृषि की हुई है. यदि हम पूरे देश के राष्ट्रीय फसल का जो उत्पादन का औसत है उसमें भी मध्यप्रदेश ने लगातार आगे बढ़ने का काम किया है. जैसा मैंने पूर्व में कहा कि केवल कृषि के बारे में जो रुटिन है, उसी पर हमने काम नहीं किया है, यदि कहीं विपत्ति आई है, यदि कहीं प्राकृतिक आपदा आई है, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ किसानों के साथ खड़ी रही है. अभी मुकेश भाई और रामनिवास जी बोल रहे थे कि पहले जो ओला और अतिवृष्टि हुई है, उसमें कुछ हुआ नहीं, मैं उनको बताना चाहता हूँ 2012-13 में रबी में लगभग 4 हजार गाँवों में ओला पाला से नुकसान हुआ, खरीफ की फसल बारिश से प्रभावित हुई और उसमें लगभग 15 सौ करोड़ रुपये किसानों को दिया गया और बीमा की राशि लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये किसानों की दी गई. इसी तरह 2013-14 में रबी की जो फसल है उसमें 25 हजार गाँवों में लगभग 445 करोड़ रुपये की बीमे की राशि किसानों को दी गई. यह इतिहास है मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ. किसी एक वर्ष में पीड़ित किसानों को मुआवजा देने का मध्यप्रदेश ने इतिहास रचा है. पिछले साल लगभग 12 हजार 345 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में बँटे. अलग अलग विभागों का है. राजस्व विभाग में प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर मुआवजा राशि लगभग 47 लाख किसानों को 3048 करोड़ रुपये, मुकेश भाई, वितरित की गई, केवल राजस्व विभाग में, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा धान, मक्का, गेहूँ आदि पर बोनस के रूप में 12 लाख किसानों को लगभग....

श्री मुकेश नायक-- सभापति महोदया, 150 रुपये क्विंटल बोनस कम कर दिया है. माननीय मुख्यमंत्री जी बताएँगे यदि मैं असत्य कथन कर रहा हूँ तो.

सभापति महोदया-- विश्वास जी को अपनी बात कर लेने दें. पहले आपको बोलने का समय मिला था. विश्वास जी, आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें.

श्री विश्वास सांरग-- माननीय सभापति जी, उससे आधा ही समय मिल जाए, जितना गोविन्द सिंह जी को मिला.

सभापति महोदया-- दो मिनट में कर लें.

श्री विश्वास सारंग-- सभापति महोदया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा धान, मक्का, गेहूँ आदि पर बोनस के रूप में 12 लाख किसानों को लगभग 1300 करोड़ रुपये पिछले साल वितरित किए गए. इसी तरह किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत दावों के भुगतान के लिए 17 लाख किसानों को लगभग 2500 करोड़ रुपये वितरित किए गए. किसान कल्याण विभाग द्वारा हितग्राही मूलक योजना अंतर्गत लगभग 1 लाख किसानों को 237 करोड़ रुपया अनुदान दिया गया. ऊर्जा विभाग द्वारा 37 हजार किसानों को लगभग 4667 रुपये प्रदान किए गए. यह मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें हर महीने लगभग 2600 रुपये हर किसान को सब्सीडी के रूप में बिजली के दिए जा रहे हैं. देश में और कोई राज्य नहीं है. इसी तरह सहकारिता विभाग द्वारा लगभग 31 हजार किसानों को 560 करोड़ रुपये प्रदान किए गए. अभी बात हो रही थी, इस सरकार ने कुछ नहीं किया, हमने बहुत किया. मैं बताना चाहता हूँ काँग्रेस के मित्रों को आर बी सी के बस दो आँकड़े बताना चाहता हूँ. हमारे समय आर बी सी में जो परिवर्तन हुआ और काँग्रेस के समय क्या मिलता था. यदि दो हैक्टेयर की असिंचित भूमि पर नुकसान होता था तो जब काँग्रेस की सरकार थी, 1992 में तो केवल 500 रुपये प्रति हैक्टेयर मिलता था. हमने हर साल में उसमें बढ़ोत्तरी की. 2006 में हमने 2000 रुपये किए, 2010 में 3000 किए. वर्ष 2006 में 2 हजार रुपये किया ,2010 में 3 हजार किया और 2013 में हमने लगभग 5 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा निर्धारित किया. कांग्रेस के समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं था पर हमने उसको बढ़ाकर लगभग 9 हजार रुपये मुआवजा देने की आरबीसी में व्यवस्था की है . माननीय सभापति महोदया, मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बार भी जब सूखा पड़ा तो पूरी संवेदनशीलता के साथ सूखे में किसानों के साथ रहकर उनके दुख में दुख बांटने की बात की है और उसी के अंतर्गत लगभग 3 हजार करोड़ रुपये मुआवजा देने की बात हुई ,3 हजार करोड़ रुपये उनको बीमा योजना के अंतर्गत देने की बात हुई और इस पूरे मामले में जो लोन इस साल नहीं लिया जाएगा और उसका जो 1 हजार करोड़ रुपये का सहकारी बैंकों पर भार पड़ेगा वह भी सरकार देगी इस प्रकार लगभग 7 से 8 हजार करोड़ रुपये सरकार इस वर्ष किसानों को देगी मैं निश्चित रूप से बहुत बधाई देना चाहता हूं.

सभापति महोदया, मैं इस बात के लिए भी मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने केवल फौरी तौर पर रिलीफ देने की बात नहीं की है पर आगे जाकर किसान की खेती फायदे का सौदा हो उसका

भी संकल्प लिया है और उसी के तहत आल्टरनेट खेती के मामले में चाहे वह दूध का मामला हो, चाहे पशुपालन का मामला हो ,चाहे हार्टीकल्चर का मामला हो, पोली हाउस , ग्रीनहाउस बनाने की बात हो उसमें भी किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहायता देने की बात हुई. बिजली उपलब्धता ज्यादा हो सके इसलिए औऱ ज्यादा कदम उठाने की बात की. जो ट्रांसफार्मर जल गये हैं वह पहले 50 परसेंट राशि जमा होने के बाद बदले जाते थे अब उसकी राशि घटाकर 10 प्रतिशत कर दी है . लब्बोलुआब यह है कि भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह किसानों के साथ हैं और मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य होता है कि अभी लगभग आधा दर्जन कांग्रेस के विधायकों ने वक्तव्य दिया पर एक भी विधायक ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वह अनुपूरक मांगों का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं. एक दर्जन ने यहाँ पर बात कर दी, बहुत वरिष्ठ हैं, मैं पूछना चाहता हूं वह अनुपूरक मांगें जो किसानों के हित के लिए सरकार मांग रही है, उस पर आप खड़े होकर यह बताइए कि उन अनुपूरक मांगों का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं. यह सदन में जरूर कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने के मौका दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद.

सभापति महोदया-- मैं सदन से यह आग्रह करना चाहती हूं कि सभी माननीय सदस्य पुनरावृत्ति न करें और अपनी विषयवस्तु किसानों औऱ सूखे पर केंद्रित रखें.

श्री बाला बच्चन(राजपुर)-- माननीय सभापति महोदया, मैं सदन में इस वर्ष की द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांगों पर जो चर्चा चल रही है उसमें हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ हूं. जो पूरे प्रदेश में खेती किसानी पर संकट आया है.

श्री विश्वास सारंग--- आप इसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं यह जरूर उल्लेखित करिये.

श्री बाला बच्चन--- जब आप प्रभावित किसानों के ऊपर पूरा पूरा आप खर्च करोगे, तो हमारा समर्थन रहेगा. आप सूखे पर खर्च करने की बात को पहले स्वीकार करें ,सूखे पर चर्चा करायें तो हमारा समर्थन रहेगा अगर नहीं करोगे तो हमारा विरोध रहेगा.

सभापति महोदया--- आप सदस्य से मुखातिब होकर बात न करें आप अपनी बात पूरी करें.

श्री बाला बच्चन—माननीय सभापति महोदया, हम खेती किसानी से प्रभावित किसानों और खेती पर चर्चा कर रहे हैं . मैं सबसे पहले आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि ओला गिरे तो किसान का सिर फूटे, सूखा पड़े तो किसान अपना सिर कूटे, अतिवर्षा हो तो किसान कीचड़ में फंसे, अति सर्दी हो तो किसान ठिठुककर मरे. और मैं समझता हूं कि यह जो लाइनें मैंने अभी रखी हैं, इससे हमारे प्रदेश के किसान जुड़े हुए हैं और सरकार को जितनी किसानों की केयर करना चाहिए वह सरकार नहीं कर पा रही है. एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्रीजी झोला फैलाए विदेश में घूम रहे हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया खाली झोला लेकर प्रदेश में घूम रहे हैं .

सभापति महोदया--- आप अपने विषय पर बात करें.

श्री बाला बच्चन—सभापति महोदया, मध्यप्रदेश का जो सूखा प्रभावित क्षेत्र या जिले हैं वहाँ तो किसान आत्महत्यातें कर ही रहे हैं लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने हमारे जिलों को सूखा घोषित नहीं किया है . जिसमें बड़वानी भी है, खरगौन भी है पर वहां पर भी किसान आत्म हत्याएँ कर रहे हैं. अभी 31 अक्टूबर को भीमसिंह पिता डोंगरसिंह ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या की है और मैं समझता हूँ कि मीडिया ने उसको पूरे प्रदेश और देश में हाइलाइट किया है तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किसान आत्महत्याओं से बचे और यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इसके पूर्व के वर्षों में जो अतिवृष्टि,ओलावृष्टि, अधिक बारिश से जो किसानों का नुकसान हुआ है, केन्द्र सरकार से मुआवजा मिलने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने किसानों को मुआवजा नहीं बांट था.मैं वह आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ,यह एनसीआरबी(नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो) के आंकड़े हैं कि 2014 में पूरे देश में 5630 किसानों ने आत्महत्याएँ की थीं उसमें से 138 किसान मध्यप्रदेश के भी हैं. उसके अलावा अभी वर्ष 2015 में अप्रेल से अक्टूबर तक 2230 किसानों ने आत्महत्याएँ की हैं और उसमें से सैकड़ों किसान मध्यप्रदेश के भी हैं. तो ऐसी नौबत क्यों बनी है और इसको सरकार किस तरह से रोके, इसकी योजना किसानों के लिए सरकार को बनाना चाहिए तो तो मैं समझता हूँ कि यह जो चर्चा यहां पर हो रही है वह चर्चा सार्थक होगी. मैं आपकी जानकारी मैं लाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पैकेज अभी वर्ष 2014 में केन्द्र सरकार से मांगा था 5723 करोड़ रुपये, मैं इस सदन के सदस्य के नाते जानना चाहता हूँ कि उससे संबंधित कितनी राशि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को दी और वह राशि क्या किसानों में बंटी और अगर राशि नहीं मिली तो केन्द्र सरकार से क्यों नहीं मिली और अगर राशि नहीं मिली है तो राज्य सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किया है. माननीय वित्त मंत्री जी, पहले तो आप और आपके मुख्यमंत्री जी और समूचा मंत्रिमण्डल और आपके सभी विधायकगण और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण केन्द्र सरकार के खिलाफ जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो आप धरने पर बैठते थे, प्रदर्शन

करते थे, कभी मुख्यमंत्री जी साइकिल से विधानसभा आते थे लेकिन अब यह सब क्यों नहीं कर रहे हैं.अब किसानों को राहत मिले इससे संबंधित आप क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने यह बात शुरुआत में बोली है कि देश के प्रधानमंत्री जी झोला फैलाये विदेशों में घूम रहे हैं, वहां राशि दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी तो खाली झोला लेकर घूम रहे हैं. प्रदेश में तो कुछ मिल नहीं रहा है. यह बड़ा चिन्तनीय विषय है,आपको देखना पड़ेगा,आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, किसानों को राहत राशि देना पड़ेगी. नहीं तो मरने वालों की संख्या और बढ़ती जाएगी. एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही गांवों में खेती प्रभावित जो हुई है उनका सर्वे नहीं होता है. बिना पैसे के खाद नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं मिलता, खेतों का सर्वे नहीं होता है और सर्वे अगर हो जाता है तो बिना राशि दिये,किसान जब तक कर्मचारियों अधिकारियों को राशि नहीं देते हैं तब तक उनको मुआवजा राशि नहीं मिलती है.आपको विचार करना पड़ेगा. मैं केवल सूखा प्रभावित इलाकों में ही नहीं, बाकी हमारे जिलों में भी बहुत सारे किसान परेशान हो

रहे हैं और तो और फसलों का जो उत्पादन होता है, मार्केट में उनका जो मूल्य मिलना चाहिए, कपास आज किस भाव पर है, सोयाबीन का भाव क्या हो गया है, गेहूं और मक्का पर जो बोनस मिलता था, वह बोनस आपकी केन्द्र सरकार ने बंद कर दिया है. आपको विचार करना पड़ेगा, यह अनुदान मांग और इनसे संबंधित बजट तब दिया जाए, तब मैं समझता हूँ कि किसानों पर यह खर्च हो तो यह चर्चा भी सार्थक होगी.आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्री सुन्दरलाल तिवारी(गुढ़)—माननीय सभापति जी, मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं हैं. मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता था और सत्तापक्ष के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि धैर्य से सुनें,हम उनकी प्रशंसा भी करेंगे,जहां सत्य है लेकिन आज यह विषय गंभीर है. करोड़ों किसान मध्यप्रदेश के पीड़ा से भरे हुए हैं. मन दुःखी है और उनके सामने एक चिन्ता है कि वे और उनका परिवार भविष्य में किस तरह अपना जीवनयापन कर पायेगा. दोनों पक्ष से सत्ता पक्ष से विपक्ष से यह आवाज उठ रही है कि हम किसानों का हित चाहते हैं लेकिन कुछ सवाल खड़े हैं. मेरा यह कहना है कि सरकार ने जो वर्तमान में अनुमान लगाया है वह अनुमान है 13846 करोड़ की क्रॉप का नुकसान है पूरे मध्यप्रदेश में , ऐसे आंकड़े हैं. तो जहां लगभग 14 हजार करोड़ रुपये की फसल नुकसानी पूरे राज्य में है तो 14 हजार करोड़ रुपये की जब हम भरपाई करेंगे तब जाकर सामान्य स्थिति राज्य के अंदर आएगी. हमारे वित्त मंत्री महोदय भी यहां बैठे हुए हैं. यह सरकार के आंकड़े हैं और सरकार 3 हजार करोड़ रुपये राहत राशि के रूप में राज्य के किसानों को देना चाहती है तो सवाल यह है कि यह जो शेष 10 हजार करोड़ रुपये का भार किसके ऊपर जा रहा है यह चिंतनीय विषय है. यह भार कौन उठाए, किसके कंधों पर यह 10 हजार करोड़ का भार यह सरकार छोड़ रही है. क्या मध्यप्रदेश के ये किसान 10 हजार करोड़ का भार सहने लायक हैं, अगर सरकार नहीं उठा पा रही है. सरकार अच्छे से राहत देने को तैयार नहीं है, कानून में मुआवजे की बात करके, आरबीसी की बात करके और सहायता करने की बात कर रही है. मैं वित्त मंत्री जी आपसे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यह जानना चाहूंगा कि ये 10 हजार करोड़ रुपये का भार प्रदेश के अंदर कौन सहे और किनके कंधों पर यह डाला जा रहा है. दूसरी बात मैडम मुझे यह कहना है कि बार-बार यह सवाल उठता है कि किसान ने आत्महत्या की है. उधर से भी यह सवाल उठता है जो सत्ता पक्ष में रहता है वह कह देता है नहीं किसान या तो पागल था या पारिवारिक परेशानियों की वजह से मर गया या अन्य कारण हम ढूंढते हैं. सरकार बचना चाहती है और विपक्ष आरोप लगाता है. असाधारण स्थिति जब राज्य में रहेगी, किसी परिवार में रहेगी तो स्वाभाविक है कि वह परिवार पीड़ा से ग्रसित होगा और जब पीड़ा से ग्रसित होगा तो आत्महत्या भी कर

सकता है, जब कर्ज से दबा है तो हार्ट-अटैक भी उसको हो सकता है और अगर जीवन जीने के उसके पास कोई संसाधन भविष्य में नहीं हैं वह केवल कृषि पर आधारित है तो लड़की की शादी भी है अन्य चिंताएं उसको सताएंगी, उससे उसे हार्ट-अटैक भी हो सकता है और जो कमजोर दिल के लोग होंगे वे आत्महत्या भी कर सकते हैं. लेकिन जो यह मजाक राज्य के अंदर आज किसानों का उड़ाया जा रहा है जो मृत हो गए फांसी लगा ली या हार्ट-फेल हो गया या अन्य किसी कारण से मर गए और हम कहते हैं कि वे फसल नुकसानी से उसकी मृत्यु हुई है या आत्महत्या उसने की है और सत्ता पक्ष कहता है कि एक आदमी नहीं मरा तो आखिर हमें कोई न कोई मैकेनिज्म, कोई न कोई एक तरीका ढूंढना पड़ेगा. अगर एक्सीडेंट से कोई मरता है तो एफआईआर होती है, धारा 304 ए में मामला कायम होता है और स्पष्ट हो जाता है कि एक्सीडेंट से मृत्यु हुई. यहां होमीसाइडल सुसाइडल मृत्यु हुई है यह विवाद नहीं है, विवाद है कारण का, तो राज्य सरकार से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि वह मैकेनिज्म, वह तरीका बताए जो व्यवस्था इन्होंने बना रखी हो जिससे ये पूरे दावे के साथ बता सकते हैं कि इस किसान ने आत्महत्या इस कारण से की है तो ऐसी विपत्ति के समय मेरा माननीय सभापति महोदया के माध्यम से सरकार से यह मांग है कि आज हम लोग इस पर निर्णय लें, यह सदन निर्णय ले कि मजाक के बजाय अगर किसान कोई मरता है(XXX). हमारे जिले में भी अभी तीन किसानों की मृत्यु हुई है और वहां सांसद सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उन्होंने कह दिया वह पागल था इसलिए मर गया. हम कह रहे हैं कि फसल नुकसानी की वजह से उसकी मृत्यु हुई क्योंकि पीड़ा को वह सह नहीं पाया तो पूरे राज्य में कोई ऐसा कानून बनाया जाए, चाहे कमीशन बनाया जाए, कोई तरीका बनाया जाए जिससे भविष्य में इस बात की जांच हो सके कि इस किसान की मृत्यु इस कारण से हुई है. तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि नाम एक और मुख्यमंत्री दो. माननीय शिवराज सिंह जी यहां नहीं बैठे हैं वे कौन से शिवराज सिंह जी थे जिन्होंने यह घोषणा की थी कि 15 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर किसानों को दिया जाएगा. मेरा यह कहना है कि वो कौनसे शिवराज सिंह जी थे , जब माननीय डॉ. मनमोहन सिंहजी देश के प्रधान मंत्री थे तब किसानों के हित में अनशन पर बैठे थे वो कौन से शिवराज सिंह थे. जब केन्द्र सरकार ने यह कहा था कि हम पूरा का पूरा पैसा देंगे ,लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी गए और अनशन पर बैठ गए, और बोले कि हम केन्द्र सरकार के विरोध में अनशन पर बैठे हैं. आज अभी तक किसी अखबार में ,रेडियो में,टी.वी. में यह खबर नहीं आयी कि केन्द्र सरकार ने एक पैसा भी दिया है. और मेरा यह कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अनशन पर नहीं बैठे. उस समय जब वे अनशन पर बैठे थे तब उनकी राजनीतिक दृष्टि थी. क्योंकि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए वो बैठे थे और आज उनकी सरकार है ,हम भी उनके साथ अनशन पर बैठने के लिए तैयार हैं. ये बतायें कि केन्द्र सरकार ने एक भी पैसा दिया है कि नहीं दिया है और अगर नहीं दिया है तो अनशन पर बैठने में देरी क्यों हो रही है और उसके पीछे उनकी छिपी राजनीति क्या है. चौथी बात हमारी यह है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें किसानों की पीड़ा है. सही है, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं ,सदन के नेता हैं. जब आप बात कहेंगे तो अखबारों में बड़ी बड़ी आएँगी. लेकिन उस पीड़ा

को भी ध्यान में रखें. अभी रीवा जिले में हम लोगों ने राहत के प्रश्न को लेकर जिले में बीस हजार किसानों ने आन्दोलन किया और ज्ञापन के माध्यम से राहत की मांग की. मध्यप्रदेश के अंदर हर जिले में,कस्बों में ,तहसीलों में वो किसान आन्दोलन कर रहे हैं. उनके हृदय में क्या पीड़ा नहीं है. केवल मुख्यमंत्री जी अपनी पीड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी पीड़ा बलाये ताक रख रहे हैं. हमारा यह कहना है कि हम लोगों ने भी अपने जिले से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भिजवाया है. वह ज्ञापन कहां है. उस पर क्या कदम उठाया गया. अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आर बी सी की बात करते हैं. कृषि मंत्री जी सदन में बैठे हैं. आर बी सी को देख लें. 15 दिवस के अंदर राहत राशि पहुंचानी चाहिए. आज तक कहीं भी एक रूपया भी नहीं गया है और कृषि मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो गत वर्ष की मुआवजे की राशि है वह 80 प्रतिशत किसानों को नहीं बटी है. यह सरकार की विश्वसनीयता है. अगर सरकार किसानों के साथ खड़ी है तो गत वर्ष की जो मुआवजे की किसानों की राशि नहीं बटी है उसको पहले बाटें और फिर इस वर्ष की जो राशि है उस मुआवजे की राशि को दिया जाय. मेरा कहना है कि तत्कालीन राहत की बात जो कही जा रही है ,मेरा कहना है कि अगर किसान को तत्काल राहत नहीं दी जाती ,बिजली के बिल माफ नहीं किये जाते,उनके कर्ज माफ नहीं किये जाते हैं ,उनको बीमा की राशि उपलब्ध नहीं करायी जाती तो ये कौनसी राहत है. ये तो हमारा कानूनी अधिकार है जो आर बी सी में लिखा है. आर बी सी में उल्लेख है. प्रशंसा की बात कहना चाहता हूं कि हमने पिछली बार जब किसानों पर चर्चा थी तो हमने मुख्यमंत्री जी से इसी सदन में यह मांग की थी कि जो किसान इनकम टैक्स दे रहे हैं उनको मुआवजे की राशि नहीं दी जानी चाहिए. मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि यह बात उचित है. इस पर विचार करेंगे और इस तरह उन्होने उन आयकर दाताओं को मुआवजे की राशि के वितरण से बाहर कर दिया.

श्री गोविंद सिंह पटेल(गाडरवारा)—सभापति महोदया, मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों में सूखा है. मध्यप्रदेश की सरकार ने इसकी चिंता करते हुए मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने त्वरित कार्रवाई करने के लिए पहले अधिकारियों को भेजा फिर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभारी मंत्रियों को भेजा. मुख्यमंत्री स्वयं गये. आज किसानों के विषय पर और सूखे पर चर्चा और उनको मदद देने के लिए बजट व्यवस्था के लिए आज विशेष सत्र बुलाया है. मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि किसानों के संकट की घड़ी में आपने किसानों की चिन्ता की.,

अध्यक्षजी, सूखा पहले भी पड़ा है और आज भी पड़ा है. हमारे मित्र जो कह रहे हैं, उनके जमाने में भी सूखा पड़ता था लेकिन किसानों को इन पर विश्वास नहीं था क्योंकि कुछ देते-लेते नहीं थे.

सभापति महोदया—आप अपने क्षेत्र पर आईये. अपने क्षेत्र के बारे में सुझाव दीजिए. समय कम है.

श्री गोविंद सिंह पटेल—आज किसानों का मध्यप्रदेश की सरकार पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री पर विश्वास है. पिछले समय ओला-पाला पड़ा या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आयी है तो प्रदेश की सरकार ने आगे बढ़कर मदद की है. पिछले वर्ष ओला गिरा था. मुख्यमंत्रीजी ने हर जिले का दौरा किया और जहां जो नुकसान हुआ, उस हिसाब से भरपाई की. हमारे अकेले नरसिंहपुर जिले में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी. ऐसी व्यवस्था प्रदेश सरकार करती रही है. आज म.प्र.की सरकार पर विश्वास है, उसके मुखिया पर विश्वास है. इसको हमारे मित्र भी मानते हैं. पहले धरना आंदोलन इसलिए करते हैं कि शिवराज जी तो करने ही वाले हैं, इसका श्रेय हमें मिल जाये. इसलिए हमारे मित्र भी आंदोलन-धरना करते हैं कि सरकार तो करने ही वाली है और सरकार तो हमेशा करती भी रही है.

सभापति महोदया, ट्रांसफार्मर बदलने पर जो 50 प्रतिशत लगता था उसको 10 प्रतिशत कर दिया. किसान को राहत मिल गयी है. ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं. चार महीने का जो टीसी कनेक्शन था उसको एक महीने का कर दिया. अब जो अस्थायी कनेक्शन है जिससे भी किसानों को परेशानी होती है. अभी प्रदेश में 9 लाख अस्थायी कनेक्शन है. सरकार ने विचार किया है कि उन 9 लाख अस्थायी कनेक्शनों को एक दो साल में स्थायी कर देंगे. सब किसानों के खेतों में ट्रांसफार्मर लग जायेंगे. सरकार दीर्घकालीन योजना पर विचार कर रही है.

सभापति महोदया, सूखा पड़ने पर किसान को पर्याप्त मुआवजा मिल जाये. पहले 1500 रु. प्रति हेक्टर मुआवजा था अब सरकार ने 11 हजार रुपये प्रति हेक्टर मुआवजा की व्यवस्था की है. आज किसान की स्थिति पहले जैसी नहीं रही है. प्रदेश की सरकार ने इन 10 वर्षो में किसानों के हित में बहुत से ऐसे कदम उठाये हैं जो कि किसानों के लिए लाभदायक हैं. आज सूखे की स्थिति है और कम वर्षा कई जगह हुई है लेकिन सिंचाई की क्षमता में जो वृद्धि हुई है उसके कारण कई जगह किसानों की फसलें पैदा हो गई है.

सभापति महोदया, वर्ष 2003 में 7 लाख हेक्टर में सिंचाई होती थी आज 87 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है. यदि सिंचाई क्षमता में इतनी वृद्धि नहीं होती तो आज सूखे की और भय़ावह स्थिति होती.

सभापति महोदया—कोई पर्टिकुलर सुझाव देना हो तो दीजिए.

श्री गोविंद सिंह पटेल—सभापति महोदया, मेरे कुछ सुझाव हैं. कृषि विभाग में कुछ सुधार की आवश्यकता है. दलहन की परेशानी आ रही है. दालों के रेट बढ़ रहे हैं. दलहनी फसलों के प्रोत्साहन के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए. दलहनी फसलों में खासकर जैसा हमारा जिला दाल उत्पादक जिला है. जिसमें तुअर,चना और मसूर की फसल होती है. किसानों का दाल की तरफ रुझान इसलिए कम हुआ कि चना 2-3 साल दो-ढ़ाई हजार रुपया बिका. तुअर तीन हजार रुपया बिकी. इसलिए किसानों ने उन फसलों को बोना कम कर दिया. इसलिए रेट की सुनिश्चतता जरुरी है. यदि दाल का उत्पादन बढ़ाना है तो दलहन फसलों के रेट थोड़े स्थिर रखे जायें. फसल का उचित रेट मिले तो दलहन की फसल की तरफ किसान का रुझान बढ़ेगा. दलहन और तिलहन फसलों की आज देश और प्रदेश में आवश्यकता है. सरकार को उसके प्रोत्साहन के प्रयास करने चाहिए.

सभापति महोदया, बिजली के क्षेत्र में सरकार बहुत कुछ प्रयास कर रही है. अनुदान देकर ट्रांसफार्मर लगा रही है. फीडर सेपरेशन काम हुआ है. एसबीडीएस का काम हुआ है. कुछ दिक्कतें हैं उसके लिए मंत्रीजी ने घोषणा भी की है. धन्यवाद.

जितू पटवारी (राऊ) – आदरणीय सभापति महोदय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं हैं सम्मानीत सदस्यगण जो यहां पर उपस्थित हैं सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के , मैं आपके माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूं बहुत कम समय में अपनी बात को रखूंगा. जिस तरीके से आज किसानों के सूखे पर चर्चा चालू हुई, जिस तरीके से आज सदन में चर्चा हो रही है. मैं समझता हूं कि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं लेकिन हर सदस्य के मन में चिंता है कि किसानों का भला कैसे हो.

मेरी विधान सभा में भी जब एक किसान ने अपने जीवन को त्याग दिया तो मैं वहां पर गया मैंने देखा कि उसके घर में दीवार टूट गई है वह 35 बीघा का किसान था दीवार उसकी टूटी तो एक टाट आता है खाद का उस टाट से उसने अपनी दीवार को बांध रखा है और वह ठीक ठाक कच्चा मकान था. उ सके पिताजी की उम्र 70 साल थी जब मैं उनके पास में बैठा और बात की तो वे रोने लगे दो बच्चे थे एक बेटी थी उसकी वह शादी करने लायक थी एक बुजुर्ग मां भी थी. जब हम लोग विश्राम घाट पहुंचे तो वहां पर बात करने में उस 6- और 70 साल के बुजुर्ग ने कहा कि पटवारी जी अगले जन्म में मैं मुझे भिखारी के घर में जन्म मिल जाय लेकिन किसान के घर में जन्म न मिले. यह उसके भाव थे. मैं भी चूंकि किसान हूं मैं भी उस मर्म को समझता हूं. मेरे पिताजी भी खेती करते थे और हमारा पूरा घर परिवार उस पर ही चलता है. आप सब भी उ समें से लगभग लोग किसान ही होंगे. लेकिन मुझे दुख हुआ कि जब अग्रवाल जी बार बार उठ रहे थे आप कितने बड़े किसान हैं मुझे नहीं पता. लेकिन यह जरूर मैं समझता हूं कि किसान के दर्द को जो समझता है वह इन बातों पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगायेगा जब इस सदन का एक सम्मानित सदस्य

बात करता है. यह अलग बात है कि जब सत्तापक्ष के लोग खड़े होते हैं तो यह मुख्यमंत्री जी बैठे रहते हैं मंत्रिमण्डल की विस्तार की बात होती है अपनी अपनी बातें और मलाईदार बातें उनको कहते हैं.

मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ भी इस विषय पर करना चाहता हूं कि जब जब भी ऐसा अवसर आता है जब भी पीड़ा होती है जब किसान तकलीफ में आता है किसान को आवश्यकता होती है और सरकार के मरने से पहले एक बार जब किसान आत्महत्या करता है तब मरता है और जब उस समय सरकार उसे खड़े होकर मदद नहीं कर पाती है या नहीं करती है तब वह फिर से मरता है उसका परिवार मरता है. मुख्यमंत्री जी सबसे पहले जाते हैं 15 – 20 जिलों का हेलीकाप्टर से दौरा करते हैं किसी को गले लगाते हैं, और अपनी अच्छी बातें जो कि अखबारों में छपें और आम जनता में एक छवि सहिष्णु और अच्छे नेता की बनी रहे उसका पूरा प्रयास होता है और उसका मीडिया मैनेजमेंट भी होता है.

मैं आपके माध्यम से इस बात का भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जब यहां पर किसान सूखे में आत्महत्या कर रहा था तो मुख्यमंत्री जी बाहर विदेश में थे और उसके बाद में जब वहां से आये तो बिहार चुनाव में चले गये और बिहार चुनाव का एक वक्तव्य आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है. उन्होंने वहां पर कहा कि मध्यप्रदेश का किसान खुशहाल है, उन्होंने कहा कि हमने किसानों की खुशहाली के लिए कभी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है, सदन के सारे सदस्य इस बात को कहते हैं कि किसान का 18 प्रतिशत ब्जाय था जो कि धीरे धीरे 15, 13, 9, 3 प्रतिशत हुआ और फिर जीरो प्रतिशत हो गया है फिर अंत में मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य था कि अब हमने एक योजना अगले साल से बनायी है कि एक लाख ले जाओ और 90 हजार दे जाओ. मैं यहां पर आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि....(व्यवधान)..(श्री शंकरलाल तिवारी माननीय सदस्य के कुछ कहने पर) आपकी सीट पर आप बैठकर मुझे रोकेंगे तो आप मेरे पिता तुल्य हैं अच्छा नहीं लगेगा बीच में बच्चे जैसे उचक रहे हैं. मेरा यहां पर सम्मानित सदस्यों से सभापति महोदय के माध्यम से अनुरोध है कि जो किसान होगा...(व्यवधान..श्री के के श्रीवास्तव सदस्य के कुछ बोलने पर) आप भी बैठ जायें भइया अभी जेल से आये हैं.

सभापति महोदया – आप अपनी बात को पूरा करें.

श्री जितू पटवारी – मेरा अनुरोध यह है कि अगर व्यवधान नहीं होगा तो मैं अपनी बात अच्छे से रख सकूंगा.

सभापति महदोया – आप लोग व्यवधान न करें...(व्यवधान..)(श्री के के श्रीवास्तव माननीय सदस्य बिना माइक के जोर जोर से बोलते रहे) आप अपनी बात को जारी रखें.

श्री जितू पटवारी – सभापति महोदया क्या यह सदन की मर्यादा है.

सभापति महदोया – नहीं यह सदन की मर्यादा नहीं है..आप विषय वस्तु पर बात करें और अपनी बात तत्काल समाप्त करें. सम्माननीय सदस्य से निवेदन है कि वह बैठ जायें यह तरीका उचित नहीं है(श्री के के श्रीवास्तव जी के लगातार जोर जोर से बिना माइक के बोलते रहने पर) यह बिल्कुल अनुचित तरीका है बात करने का. आप अपनी बात पूरी करें....(व्यवधान)...

मैंने यह कहा कि मैं आपके बेटे की उम्र का हूं, मैंने यह नहीं कहा कि मेरे बेटे आपकी उम्र के हैं ।

सभापति महोदया-- आप किसान और सूखे पर बात करें ।

श्री जितू पटवारी-- मैं अनुरोध करता हूं सभापति महोदय, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीरो प्रतिशत ब्याज के बाद हम 1 लाख लेंगे और 90 हजार भरना पडेंगे यह व्यवस्था हमने अगले साल से की है । मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं और मेरा सौभाग्य भी है, मैं भाग्यशाली भी हूं कि वह सदन में आये और मुझे अवसर मिला इस बात का कि मुझे बोलने का मौका दिया । अगर मध्यप्रदेश इतना ही खुशहाल है मुख्यमंत्री जी तो शिक्षाकर्मी जिन्होंने सबसे ज्यादा मदद करके आपकी सरकार बनाई थी वह दुखी क्यों हैं ।

सभापति महोदया-- जीतू जिराती जी मैं आपसे आग्रह करूंगी कि हम किसान पर और सूखे के विषय से बाहर बात नहीं करेंगे ।

श्री जितू पटवारी—सभापति महोदय, मैं किसान के अलावा कहीं नहीं जाउंगा । अगर इस मध्यप्रदेश में इतनी खुशहाली है तो मुझे मुख्यमंत्री जी अपने इसमें बताने की कोशिश करें अपने भाषण में और हम तनमयता से सुनेंगे की इस मध्यप्रदेश में एक करोड़ लोग बेरोजगार क्यों है, युवा साथी । आप यह भी बतायें और वह किसान ही हैं अर्द्ध बेरोजगारी और बेरोजगारी, किसानों से जुड़ी हुई बेरोजगारी है । इसलिये इस बात का बार-बार निवेदन करता हूं । मैं अनुरोध करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि अपने वक्तव्य मैं वह यह भी बताने की कोशिश करें कि वह जनप्रतिनिधि कांग्रेस के नहीं भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, पंचायत से चुने हुये लोग, वह परेशान क्यों हैं आपके राज में, आपके खिलाफ, आपके लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं । मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी आप यह बताने की कोशिश करें कि वह किसान, जब आप इतनी अच्छी योजनायें चला रहे हैं सभापति महोदय तो रोज किसान आत्महत्यायें क्यों कर रहा है, क्या कारण है इसका कि रोज किसान मरता है और आदरणीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा था कि कितने लोग गये उन किसानों के घर जिन्होंने आत्महत्यायें कीं । मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी कि वो कितने उन किसानों के घर पर गये इस वर्ष जो सूखे के कारण जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, वह बताने की कोशिश करें । सभापति महोदय मेरा अनुरोध यह है कि जो एक प्रशंसनीय कार्य मुख्यमंत्री जी ने किया पर थोड़ा लेट किया । उन्होंने अधिकारियों को किसानों के बीच भेजना चालू किया और उन्होंने यह भी बताया कि वह बिहार के दौरे पर रहे, वह विदेश के दौरे पर रहे । दो महीने बाद जब फसल का सब समाप्त हो गया था सोयाबीन का उसके बाद उनकी नींद उड़ी और उन्होंने सब अधिकारियों को भेजा । मैं किसी और से यह अनुरोध नहीं करना चाहता, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक आइना बताना चाहता हूं कि मुख्य सचिव एंटोनी डिसा.... (सत्तापक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने पर)

सभापति महोदय, यह क्या है यह तरीका तो ठीक नहीं है ।

सभापति महोदया-- आप अपनी बात समाप्त करें । सदस्य सदन का सहयोग करें और आप अपनी बात आधे मिनट में समाप्त करें ।

श्री जितू पटवारी-- मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा भी अच्छी नहीं लगती इन लोगों को तो मैं क्या करूं ।

सभापति महोदया-- आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री जितू पटवारी-- मैं मुख्यमंत्री जी से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जो आपके अधिकारी क्षेत्र में गये थे, कोई ने सफारी की सबारी की, कोई बाट्सएप खेल रहा था, यह अखबारों की कटिंग है ।

सभापति महोदया-- कोई सुझाव हो तो आप बोल कर बात समाप्त करें ।

श्री जितू पटवारी-- यह सूखे से जुड़ी हुई बात है, अगर यह बताना गुनाह है तो मैं नहीं समझता हूं कि ठीक बात है । सभापति महोदय मुझे दो मिनट और देना पड़ेंगे ।

सभापति महोदया-- आशीष शर्मा जी आप अपनी बात शुरू करें ।

श्री आशीष गोविंद शर्मा (खातेगांव)-- इस बार म0प्र0 के बहुत बड़े क्षेत्र में सूखा पड़ा है, इसलिये किसान परेशान है, लेकिन भला हो म0प्र0 की सरकार का कि लगातार पिछले 10-12 वर्षों में जो किसानों को केन्द्रित करके सरकार ने जो नीतियां बनाईं, उन नीतियों का प्रभाव है कि आज म0प्र0 में किसान की स्थिति सुधरी है । आज म0प्र0 का किसान आत्मनिर्भर बना है और आज म0प्र0 के किसान को इस बात का संतोष है कि कैसी भी संकट की घड़ी आ जाये म0प्र0 की सरकार हमारे साथ खड़ी है । सभापति महोदय, इसलिये मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर भी किसान बड़ी संख्या में है. वहां खेती मुख्य व्यापार है .इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज का दिन मध्यप्रदेश के किसानों के हित में एक स्वर्णिम दिन के रूप में याद रखा जायेगा. मैं विपक्ष के सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी हिम्मत और बहुत बड़ा साहस माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है विकास की जो बहुत बड़ी धनराशि जो मध्यप्रदेश के विकास में खर्च होनी थी वो किसान के हितों को सर्वोपरि रखते हुये मध्यप्रदेश की सरकार किसानों को राहत के रूप में प्रदान कर रही है. इसलिये मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं . हमारे क्षेत्र में भी सोयाबीन बहुत प्रचुर मात्रा में उत्पादित होता है लेकिन लगातार पिछले दो वर्षों से तीन वर्षों से सोयाबीन की फसल खराब हो रही है इस बार भी पहले एक माह तक पानी नहीं गिरा, इस कारण किसानों ने मंहगी दवाईयां और रसायन खरीदकर फसलों से इल्ली के बचाव में छिड़काव किया .लगातार तीखी धूप निकली जिसके कारण वो पौधे मुरझा गये फिर अचानक जो पानी गिरना शुरू हुआ तो एक माह तक लगातार बारिश होते रही, पौधे अच्छे बढ़ भी गये उसमें फलियां भी आ गई लेकिन जब फसल पकने पर आई और किसान उसको खेत से निकालने के लिये गये तब उनका उत्पादन जितना उन्होंने लगाया था उससे आधा से भी कम हुआ. किसी ने 1 क्विंटल सोयाबीन का बीज बोया था तो उसके यहां 50 किलो सोयाबीन निकला और वह बीज भी इतनी खराब मात्रा में था कि न तो उसको किसी प्रकार से बेचा जा सकता है और न ही अगली फसल के लिये उसको उपयोग में लिया जा सकता है. इसलिये किसान को पिछले 20-25 वर्षों में सबसे बड़ी तबाही इस बार देखने को मिली. हम किसानों के खेतों तक गये और किसान को धीरज देने का काम किया कि आप चिंता मत करो, संकट की इस घड़ी में सरकार आपके साथ में है. माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कदम यह उठाया कि सभी वरिष्ठ अधिकारियों को गांव का दौरा करने के लिये भेजा. हम भी कई जगह उन अधिकारियों से गाव में मिले और अधिकारियों ने बहुत संतोषजनक ढंग से किसानों को समझाने का काम

किया फौरी तौर पर जो सरकार ने राहत दी थी वह राहत भी उन तक पहुंचाई. आज सरकार ने बिजली के ट्रांसफारमर बदलने के लिये जो 10 प्रतिशत की राशि देकर के ट्रांसफारमर बदले जाने की व्यवस्था की है वह बहुत सराहनीय है. अब किसान की अगली फसल जो रवि की है वह ठीक तरह से आ जाये इसके लिये हम लोगों को ठीक तरह से प्रयास करना चाहिये. सरकार की भी मदद उसमें मिलनी चाहिये. किसानों को खाद बीज की भी पर्याप्त उपलब्धता सोसायटी के माध्यम से हो रही है इसलिये मैं आज के इस सत्र के लिये पुन: माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं. सभापति महोदय आपने मुझे बोलने के लिये अवसर प्रदान किया इसके लिये आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद.

सभपाति महोदय—जीतू पटवारी जी आप 1 मिनिट में अपनी बात को पूरा करें.

श्री जीतू पटवारी – माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद जो आपने समय दिया. मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी की यह तारीफ करना चाह रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने थोडे विलंब से ही सही परंतु अच्छा कदम उठाया कि अधिकारियों को वस्तु स्थिति जानने के लिये भेजा . पर एक बात मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आपके मंत्रि मंडल के सदस्य बेलगाम हो गये हैं, इस बात को हम सबको समझना पडेगा. सदन में मंत्री जो वक्तव्य देते हैं वह मुख्यमंत्री से जुड़े हुये होते हैं . एक संसदीय परंपरा का पालन मंत्रियों को करना चाहिये. एक मंत्री ने यह कहा कि अपना बाप मर जाये तो भी कोई आत्महत्या नहीं करता तो फसल के खराब होने पर क्या आत्महत्या करेगा. अब उस फसल के खराब होने की पीड़ा और बाप के मरने की पीड़ा को जब मंत्री समझता ही नहीं तो वह आम जनता के साथ में कैसे न्याय कर सकता है,आम किसान के साथ में न्याय कैसे कर सकता है. अभी एक मंत्री महोदय ने 15 लाख में से 1 लाख रूपये मांगने वाले को एक लात दी. क्या यह मंत्रियों का संस्कारिक या संसदीय व्यवहार है . मुख्यमंत्री जी मौन रहे तो यह सवाल उठता है. मेरा अनुरोध है मुख्यमंत्री जी कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर जिस तरीके से किसानों को ऐसी स्थिति जैसी मध्यप्रदेश में हुई तो 12 हजार रूपये प्रति एकड़ मुआवजा बिना सोचे समझे एक जैसा वहां की सरकार के द्वारा दिया गया. मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है, हम सब आपके साथ हैं जैसा आप कहेंगे आपके नेतृत्व में हम करने को तैयार हैं , किसान के हित में आप निर्णय लें चाहे विकास का पहिया रूके तो रूके इस आपको स्लोगन में हम भी आपके साथ हैं पर आप वस्तुस्थिति में जमीन में इस बात को आपको उतारना पड़ेगा . एक और अनुरोध है कि पंजाब में और हरियाणा में कोई बिल किसानों को नहीं लगता है . किसी भी प्रकार का बिल नहीं लगता है. तो ऐसी स्थिति में जब किसान प्रदेश में आत्म हत्या कर रहा है तब एक साल के क्या हम किसानों के बिल माफ नहीं कर सकते हैं ? रामेश्वर शर्मा जी वेतन की बात कर रहे थे , आप एक महीने की बात करते हो हम पांच महीने का वेतन किसानों के पक्ष में देना चाहते हैं आप एक साल का बिजली का बिल किसानों का माफ करो, कर्ज समाप्त करो. तब जाकर के उनकी आत्महत्यायें रूकेंगी. हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी आपका साथ देना चाहती है पर अनुरोध इसमें एक और है मुख्यमंत्री जी कि जिस तरीके से आपने अभी मुआवजे की प्लानिंग की है यह ऊंठ

के मुंह में जीरे के समान है. अभी मुआवजे की प्लानिंग की है. यह ऊंट के मुंह में जीरा है. आप अगर 2-3 हजार रुपया बीघा देना चाहते हैं, तो इससे किसानों का खेत साफ नहीं होता है. ट्रेक्टर एक बार में चलता है, उतना मुआवजा देना चाहते हैं. ट्रेक्टर से खेत की सफाई हो जाय, इतना तो करो. जितने से खेत की सफाई नहीं हो सकती, उतना मुआवजा देने की बात करते हैं. मुख्यमंत्री जी, आप मुआवजा दो तो 15 हजार प्रति एकड़ दो, नहीं तो किसानों को समझाने की जरुरत नहीं है. किसान आपको समझ चुके हैं. जिसके लिये यह सत्र बुलाया गया है, किसानों के हित में जो बजट पास होना है, उसका कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है और मैं भी समर्थन करता हूं, पर यह राहत राशि बढ़ाई जाय. धन्यवाद.

श्री बाला बच्चन – सरकार कितनी संवेदनशील है, उपाध्यक्ष महोदय सदन में बैठे हैं और आसंदी पर सभापति महोदया हैं. इससे पार्शलिटी दिखती है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- आपको भी सोचना चाहिये कि कौन सी बात कहां बोलना चाहिये.

श्री बाला बच्चन -- विपक्ष को सरकार कितना साथ लेकर के चल रही है, इससे इस बात का पता चलता है.

2.21 बजे {अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

श्री दुर्गालाल विजय (श्योपुर) – अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का किसान बहुत जटिल और कठिन परिस्थिति के अन्दर है और इस जटिल और कठिन परिस्थिति में लगातार ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और सूखे के कारण से आई प्राकृतिक आपदा से परेशान किसान को समुचित राहत देने की दृष्टि से प्रदेश की सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने जो प्रबंध किये हैं, वास्तव में वह प्रशंसनीय और सरहानीय कदम हैं. प्राकृतिक आपदा ने किसान को परेशान तो किया, लेकिन यह किसान के लिये संयोग है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, किसान के बेटे और किसान के प्रति संवेदनशीलता रखने वाले, अतिसंवेदनशीलता रखने वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसके कारण से पिछले 2-3 वर्षों से लगातार जिस प्रकार की आपत्ति, विपत्ति किसान के ऊपर आई, उस आपत्ति, विपत्ति में किसान के साथ खड़े होकर तमाम सारी परिस्थितियों में किसान को अनुकूलता में लाने के लिये मध्यप्रदेश की सरकार और मुख्यमत्री जी ने बहुत अच्छे प्रबंध किये हैं. मैं उनकी पुनरावृत्ति तो नहीं करना चाहता, जो मेरे पूर्व साथियों ने बातें रखी हैं. लेकिन यह बात कहने में कोई संकोच और अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रदेश के किसानों के लिये जितना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है, यह बात केवल मैं नहीं कहता, पूरे प्रदेश के किसान जिनको मुख्यमंत्री जी के ऊपर भरोसा और विश्वास है. हमारे कई विपक्ष के साथियों ने भी उनके द्वारा किसानों के हक में लिये गये फैसलों की प्रशंसा की है. पिछले समय में जो ओलावृष्टि हुई थी, हमारे श्योपुर जिले के अन्दर और विशेष करके श्योपुर विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी जब श्योपुर में पधारे थे, उस समय किसानों की पीड़ा को देखने के लिये, उनका दुख-दर्द बांटने के लिये और उन्होंने जिस प्रकार का एलान किया था, केवल श्योपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 24 करोड़ रुपये की राशि धनिया की फसल नष्ट होने के कारण से वहां प्रदान की गई और अन्य सुविधायें भी दी गईं. कन्याओं के विवाह करने का

कार्यककिया गया. बिजली के बिलों में सुविधा देने का काम किया गया, एक रुपये किलो अनाज देने का काम किया गया, जिनके यहां ओलावृष्टि हुई थी, बहुत सारे फैसले किसान के हक में लिये. जिसके कारण किसान अपने आपको बैलेंस कर सका. मैं मुख्यमंत्री जी और सरकार से विनम्रतापूर्वक 2-3 बातों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं. अभी हमारे जिले के अन्दर विशेषकर श्योपुर विधान सभा क्षेत्र में विशेषकर श्योपुर विधान सभा क्षेत्र में सोयाबीन की फसल बहुत अच्छी फसल थी और लगता था कि यह आयेगी तो हमारे ओलावृष्टि से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हो जाएगी. धान की फसल भी बहुत अच्छी थी और लोग जो ओले की मार से पीड़ित हुए थे उस कठिनाई को दूर करने का मौका आया, लेकिन अच्छी फसल होते हुए पूरी फसल नष्ट हो गई. धान की फसल जो कि बहुत अच्छी थी, वह ओलावृष्टि के कारण ऐसा दुर्भाग्य रहा है कि अक्टूबर माह में कभी भी ओलावृष्टि नहीं होती है, लेकिन जो धान की फसल जो कि कटने वाली थी, वह भी नष्ट हो गई. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां से जो चंबल नहर निकली है उसका पानी श्योपुर के लोगों को अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि यह जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगा तो श्योपुर के किसानों को ठीक तरह से लाभ हो जाएगा. हमारे जिले में जलस्तर बहुत ही नीचे चला गया है जलस्तर नीचे चले जाने से ज्यादा दिक्कत आ रही है इसके कारण हमारी आपसे प्रार्थना है कि श्योपुर जिले को पेयजल अभावग्रस्त जिला घोषित करके किसानों की समस्या को दूर करेंगे.बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री शैलेन्द्र पटेल—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सब लोग किसानों की परेशानी दूर करने के लिये क्या कदम उठा सकते हैं, उसकी चर्चा करने के लिये यहां पर बैठे हैं. उम्मीद है कि हम अन्नदाता किसान के आंसू पोंछने में कामयाब होंगे. लोकतंत्र के इस मंदिर में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि संकट की घड़ी में हम किसानों के साथ में खड़े हों उनसे लोक-लुभावने वायदे न कर मदद का दिखावा न हो तथा उसमें आश्वासन की राजनीति बंद हो. पिछले तीन सालों से लगातार कभी ओला, कभी अतिवृष्टि तो कभी सूखे के मौसम के कारण किसानों की फसलें लगातार खराब होती जा रही हैं जिसके कारण किसान परेशान हैं, वह कर्ज की खेती कर मौत की फसल उगा रहा है. किसानों के ऊपर बैंकों, सहकारी समितियों और साहूकारों का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है. प्रदेश सरकार लगातार खेती को लाभ का धन्धा बनाने का ढिंढोरा पीटती रही है, लेकिन इस दिशा में सरकार ने जो कदम उठाये हैं, वह नाकाफी हैं अब वक्त आ गया है कि किसानों के हित में कागजी कार्यवाही के बजाय कोई ठोस कदम उठाये जाएं पिछले छः महीने के दौरान प्रदेश भर में हजारों किसानों ने आत्म-हत्याएं की हैं. पिछले साल की तुलना में किसानों की आत्म-हत्याओं का आंकड़ा दुगना हो गया है.

अध्यक्ष महोदय—कृपा करके पढ़कर के न बोलें.

श्री शैलेन्द्र पटेल—समय कम है इसलिये बोल रहे हैं आप समय दे दीजिये तो बगैर पढ़े बोल देंगे.

अध्यक्ष महोदय—समय कम है आप तो पढ़ दीजिये.

श्री शैलेन्द्र पटेल—पाईंट छूट जाएंगे अध्यक्ष जी.

श्री गोपाल भार्गव—आप पटल पर रख दें.

श्री शैलेन्द्र पटेल—आप भार्गव जी समय दिलवा दीजिये मैं दो घंटे लगातार बोलूंगा. इसमें भी आपको मजाक सूझ रहा है, कृपया आप गंभीर हो जाएं.

अध्यक्ष महोदय—परम्परा नहीं है पढ़कर बोलने के लिये इसलिये कहा और कोई बात नहीं है.

श्री शैलेन्द्र पटेल—माननीय अध्यक्ष महोदय मैं मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से आता हूं जिसमें मेरा विधान सभा क्षेत्र भी आता है इस जिले में पिछले महीने में चार किसानों ने आत्म-हत्याएं की हैं और 8 किसानों की मृत्यु सदमें के कारण हुई है और यही हाल पूरे प्रदेश के हैं. मुझे कुछ पंक्तियां एक कवि की याद आ रही हैं उन्हें धन गुरूओं ने बताया था प्रवचनों में कि आत्म-हत्याएं करने वाले सीधे जाते हैं नर्क में हैं, तब भी उन्होंने आत्म-हत्याएं कीं, क्या नर्क से भी बदतर हो गई थी उनकी खेती, यह सवाल आज सबके ऊपर रहता है. खेती के हालात किस तरह से प्रदेश में बिगड़ते हैं मैं उन किसानों का नाम नहीं लेना चाहता हूं. मैं किसान हूं तथा मेरे मन में पीड़ा है और मेरे कुछ चुभते हुए सवाल हैं जिनका मैं सिलसिलेवार जिक्र करना चाहता हूं आईये महसूस करिये जिन्दगी की किताब को मैं किसानों की गली में लेकर के चलता हूं आपको. सोयाबीन की लागत साल-दर-साल बढ़ती चली जा रही है और आज प्रति एकड़ की लागत 9 से 10 हजार रूपये हो गई है. सोयाबीन की लागत साल दर साल बढ़ती जा रही है. 9 से 10 हजार क्विंटल प्रति एकड़ की लागत आ रही है.

अध्यक्ष महोदय – आप तो अपनी बात सीधे-सीधे रख दीजिये.

श्री शैलेन्द्र पटेल - लागत बढ़ रही है यही तो सबसे बड़ी समस्या है. आप बात ही नहीं करने देंगे तो किसलिये सत्र बुलाया है.

अध्यक्ष महोदय - समय नहीं है. 30 नाम हैं. पूरा नाम आपही को दे देंगे.

श्री शैलेन्द्र पटेल - जब किसानों के लिये सत्र बुलाया है. हम रात भर बात करेंगे.

अध्यक्ष महोदय - बोलिये ना आप.

श्री शैलेन्द्र पटेल - आप ही तो रोक रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय - आप भाव पर भाषण दे रहे हैं कि पहले यह था अब यह है. आप सीधे-सीधे विषय़ बताईये.

श्री शैलेन्द्र पटेल - क्या बोलने पर लगाम लगेगी. क्या किसानों की बात नहीं रखी जाये.

अध्यक्ष महोदय - बोलिये अच्छा बोलिये.

श्री शैलेन्द्र पटेल - कविता नहीं कर रहा हूं. आपके यहां 3 किसानों ने आत्महत्या की है आदरणीय गुणवान जी आष्टा के अंदर. सोयाबीन की लागत साल दर साल बढ़ती जा रही है. 9 से 10 हजार रुपये क्विंटल प्रति एकड़ की लागत आ रही है. जो मुआवजा राशि दी जाती है वह भी अपनी जगह मेग्जिमम दी जायेगी तो आरबीसी एक्ट के अंतर्गत तीन हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगी. जब मुआवजा राशि आयेगी तब उसके बारे में बात करेंगे. मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जहां लागत बढ़ रही है वहां गेहूं का

बोनस भी कम कर दिया गया है. पिछले वर्ष जब धान की वैकल्पिक खेती के बारे में बताया गया था बहुत से किसानों ने धान की खेती की और जो धार चार हजार रुपये क्विटंल में बिकता था वह तेरह सौ रुपये क्विंवटल में आज बिक रहा है. किसानों की दलहन की फसल जब वह बेचता है तो 40 से 50 रुपये किलो के हिसाब से बेची जाती है वही दाल जब बाजार में आती है तो 200 रुपये किलो से बिकती है यह बीच का अंतर कहां जा रहा है उसके ऊपर विचार करने का आज समय आ गया है.किसानों के खेत में जब आलू प्याज टमाटर लगता है जब वह बेचता है तो 4 से 5 रुपये प्रति किलो में बिकता है और मंडियों में 40 से 50 रुपये प्रति किलो में बिकता है उस अंतर को पाटने की आज सबसे ज्यादा जरूरत है बाजार में हर उत्पादन की कीमत उसका उत्पादक तय करता है लेकिन किसानों को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने उत्पादन की खुद कीमत कर सकें. इस ओर सोचने की बात है. किसानों को राहत देने के नाम पर सरकार ने पिछले वर्ष सहकारिता के माध्यम से ठगा है.टाईम्स आफ इंडिया में कल ही छपा था कि किस तरीके से सुपर फास्फेट की बोरी पर 40 रुपये प्रति बैग के हिसाब से पूरे प्रदेश में ज्यादा वसूला गया था और लगभग 60 करोड़ रुपये किसानों की जेब से चोरी कर लिया गया था और यह पैसा क्या यह सरकार वापस दिलाएगी.ताकि उन किसानों को राहत मिल सके.

अध्यक्ष महोदय – कृपया समाप्त करें.

श्री शैलेन्द्र पटेल – अध्यक्ष जी, बात शुरू की है. किसानों की बात कर रहा हूं. विषय से बाहर एक भी बात नहीं जा रही है. मैं समाप्त करता हूं. मेरे कुछ सुझाव हैं. पिछले साल रबी व खरीफ फसल के नुकसान के कारण सहकारी बैंक और अन्य बैंकों का कर्ज किसान नहीं चुका पाया था और जब वह कर्ज नहीं चुका पाया था तो वह ओवर ड्यू हो गया था और ओवर ड्यू होने के कारण उसकी बीमे की प्रीमियम राशि जमा नहीं हो पाई थी. आज की स्थिति में उन किसानों को बीमे का लाभ नहीं मिलेगा. उन किसानों के बारे में सोचने की जरूरत है कि उनको बीमे का कैसे लाभ मिल पाएगा. उसे सिर्फ मुआवजे का लाभ मिल पाएगा. सरकार को योजना बनानी चाहिये कि पिछले साल जो किसान ओवरड्यू हो गये थे उनके लिये क्या कर रहे हैं. मेरा एक सुझाव और है कि जिस तरह आज वक्त आ गया है कि कर्मचारियों के समान कृषि उत्पाद मूल्य आयोग बनाया जाये जो कृषि उत्पाद की लागत का आकलन करे. बाजार की चीजों के भाव के अनुपात से किसानों की पैदावार का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करें. खेती की लागत प्रति एकड़ निकाली जाये जिसमें खाद,बीज,कीटनाशक,ट्रेक्टर,डीजल,सिंचाई,बिजली और मजदूरी जोड़कर किसानों के खेत की प्रति एकड़ लागत निकाली जाये और किसानों की पैदावार की कीमत कम से कम लागत की डेढ़ गुना तय की जाये. जब मुआवजा या राहत राशि की बात हो उसकी लागत का ध्यान रखा जाये. विपदा की इस घड़ी में कांग्रेस किसानों के साथ है. हमारी कुछ मांगे हैं. किसानों के बिजली के बिल तुरंत माफ किये जायें.

अध्यक्ष महोदय – आपकी बात हो गई आप बैठ जायें.

डॉ.मोहन यादव(उज्जैन) - अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी माननीय जयंत मलैया द्वारा रखे प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा. उल्लेखनीय है कि 141 तहसीलों को जो

सूखाग्रस्त घोषित करने का मुख्यमंत्री जी ने अद्वितीय निर्णय लिया है और संसदीय इतिहास में पहली बार विशेष सत्र बुलाकर इतना बड़ी कदम उठाते हुए इतना बड़ा पेकेज देने के लिये जन अनुमति और संसदीय व्यवस्था से चलते हुए जो निर्णय किया मैं उसकी प्रशंसा करता हूं. मुख्यमंत्री जी का आभार मानता हूं. हम सब अत्यंत आनंदित हैं हम तो यद्यपि इस सदन के पहली बार के विधायक हैं इसलिये एक नयी परंपरा में सहभागी हुए हैं वह अत्यंत हर्ष की बात है. यद्यपि यह बात जरूर है कि किसानों के मुद्दे पर भी विपक्ष के द्वारा जिस तरह से टीका टिप्पणी और हल्कापन लिया गया मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है मैं उल्लेख नहीं करना चाहता लेकिन मुकेश नायक जी ने जिस ढंग से अमर्यादित व्यवहार किया है. जितू पटवारी जी ने अपनी बात कही कि मैं प्रशंसा कर रहा हूं लेकिन कष्ट बताने के बजाय कीचड़ उछालने का जो प्रयास किया है वह सर्वथा निंदनीय है. मैं बताना चाहूंगा बेहतर होता जितू जिराती जी इस तरफ ध्यान आकर्षित करते कि मात्र सूखे के बजाय हमारे यहां अतिवृष्टि भी हुई है वहां इंदौर आपका जिला भी है जहां जरूरत से ज्यादा पानी गिरा है उसके कारण अफलन की स्थिति है और फसल का नुकसान हुआ है. बेहतर होता कि इस दिशा में उज्जैन को और बाकी जिलों को भी जोड़ते. मैं अध्यक्ष जी इस दिशा की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि जहां फसल पर पानी का अभाव हुआ है उसके उल्टे कुछ जिलों में ज्यादा पानी गिरा. अकेले उज्जैन में एक जिले में 18 इंच पानी गिरा इसके कारण जो तकलीफ हुई है इस दिशा में भी हमें विचार करने की आवश्यक्ता है कि हम अपने किसानों को उन जिलों में कैसे राहत दिला पाएं क्योंकि यह सूखे-सूखे की बा हुई है ज्यादा पानी गिर गया उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है.मैं एक दूसरे विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे द्वारा जो राहत की राशि दी जा रही है उस संबंध में मैं एक निवेदन कहना चाहूंगा कि उज्जैन विधान सभा क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर सिंहस्थ के कारण पिछले एक साल से उनकी फसल न होने के कारण रोका है. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस राहत राशि के अलावा चारे और भूसे का प्रबंधन भी हम करें, चूंकि पिछले एक साल से उनके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है, जिससे वह चारा और भूसा ले पायें। अगर पशुओं के लिये उनकी व्यवस्था करवा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा क्योंकि मैं विषय को दोहराना नहीं चाहूंगा . काफी विषय बिन्दूं आ चूंके हैं, लेकिन फिर भी काफी बड़ा निर्णय हुआ है. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मलैया जी का सबका आभार मानता हूं। जिन्होंने एक विशेष कदम उठाते हुए किसानों के इस दर्द में हाथ बढ़ाये, उनके इस कष्ट की घड़ी में उनके साथ खड़े हुए। भगवान न करे की ऐसा मौका आये, लेकिन हमने जैसा कहा कि कृषि के अलावा और ऐसे कौन कौन से तरीकें हैं जिन तरीकों के आधार पर उनको राहत दी जाये, आपने मनरेगा का भी सौ के अलावा एक सौ पचास दिनों का काम बढ़ाया है. इसी प्रकार से और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और कौन कौन सी योजना हो सकती है खासकर के पशुपालन के क्षेत्र में और बाकी योजनाओं के बारे में ध्यान दिलवायेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं धन्यवाद्।

श्री मनोज कुमार अग्रवाल :- मैं एक ऐसे विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगी हुई है। मेरी विधान सभा में एक तहसील में कोतमा अनुपपूर का भाग आता है। विडम्बना यह है कि कौतमा विधान सभा क्षेत्र पूरी तरह से असिंचित है और करेला और निमचढ़ा कैसे की वहां कोयला खदानें हैं जिसके कारण वहां का जल स्तर जो है वह न के बराबर है। कुंए और तालाब में किसी में भी पानी नहीं रहता है। जैसे कि एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हा-हाकार की स्थिति हो जाती यदि सिंचित नहीं होता. मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र पूरी तरह है असिंचित है और वहां पर हा-हाकार की स्थिति है. कोयला खदान वहां पर इस तरह से फैली हुई है , इतना ज्यादा खनन होता है कि वहां पर किसी तरह का जलस्तर नहीं है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिये स्पेशल पैकेज देना चाहिये । मैं मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह और करना चाहूंगा कि अनुपपूर विधानसभा क्षेत्र को उपेक्षित समझता हूं। वह इसलिये कि अनुपपूर जिले के दो विधान सभा क्षेत्र से दो विधायक कांग्रेस के हैं।इसलिये मुझे ऐसा लगता है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र पूरी तरह से उपेक्षित है। वहां पर 8 नायबतलसीलदार के पद स्वीकृत हैं, लेकिन एक नायब तहसीलदार है, वहां पर डिप्टी कलेक्टर नहीं हैं, एसडीएम पार्ट टाईम बैठते हैं जब की कौतमा एक संवेदनशील तहसील है। हम इस सूखे की स्थिति में किसानों की क्या मदद कर पायेंगे। जब वहां पर तहसीलदार नहीं रहेंगे, एसडीएम नहीं रहेंगे , कलेक्टर के पास जाओ तो कहते हैं कि मेरे पास कोई आदमी नहीं हैं। वहां पर तो ऐसी स्थिति हो गयी कि पुराने मध्यप्रदेश में जैसी बस्तर की स्थिति होती थी कि वहां पर कोई जाना नहीं चाहता था। मुख्यमंत्री जी इसके लिये आपको कड़ाईसे पालन करना पड़ेगा।वहां पर किसानों को मुआवजा किस प्रकार से बटवायेंगे। उनको आकलन कौन करेगा। हमारे पास अमला नहीं है, पटवारी नहीं हैं, हमारे पास नायब तहसीलदार नहीं हैं,सूखे की स्थिति में जहां हा हाकार मचा हुआ है, ऐसे हम किसानों को जब सूखे की स्थिति बनी है उनको कुछ दे ही नहीं पायेंगे। क्योंकि मैं जाकर उनको मुआवजा नहीं बांट सकता, सूखे का आकलन नहीं कर सकता, आकलन तो पटवारी ही करेगा। कलेक्टर साहब देंगे. मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि उस जिले को इतना उपेक्षित न रखें। यह मैं अपनी व्यथा बता रहा हूं।इतना उपेक्षित है कि योजना का अधिकारी चला जाता है तो वहां से छ:छ: महीने कोई नहीं आता है। जब भोपाल में प्रभारी अधिकारी से बात करतेहैं तो वह सीधे बोलने हैं कि अनुपपूर कोई जाना ही नहीं चाहता है। मेरा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर अधिकारी नहीं रहेगा तो हम किसानों को क्या देंगे। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद् .

श्री कमलेश्वर पटेल (सिंहावल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा और संक्षेप में बात करूंगा. मेरा विधान सभा क्षेत्र दो जिलों में लगता है उसमें सिंगरौली जिले के देवसर तहसील अंतर्गत ढोंगा पंचायत के जो बैगा जाति के लोग हैं उन्होंने गरीबी के कारण कंदमूल खाये जिसके कारण तीन दिन पहले तीन लोगों की मृत्यु हुई जो निंदनीय है और आज भी छह लोग देवसर चिकित्सालय में भर्ती हैं और एक महिला की मृत्यु जिला चिकित्सालय सिंगरौली हुई है जो डाक्टरों की देखरेख की कमजोरी की वजह से हुई है देवसर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र था वहां से रेफर करने बाद यहां पर उसकी ठीक से देखरेख नहीं हुई जिसकी वजह से उस महिला की मृत्यु हो गई. एक तरफ सरकार बैगा जाति के लोगों को उत्साहित करने के लिये बहुत सारी योजनायें चलाये हुए है दूसरी तरफ बैगा जाति के लोग जो मेरे क्षेत्र की ढोंगा पंचायत में हैं वहां बोदरहिया टोला है जहां बैगा जाति के लोग निवास करते हैं कल मैं वहां गया था उनसे मिलकर आया हूँ उनकी व्यवस्था करके आया हूँ. मेरे जाने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने कलेक्टर साहब से चर्चा की जबकि पेपर में यह सारी बातें आ गईं थीं परन्तु जिस तत्परता से ध्यान देना चाहिये था मेरे जाने के बाद अधिकारी पहुंचे जबकि उसके पहले भी अधिकारी जा सकते थे. जंगली कंदमूल खाने की वजह से यह घटना घटी है जिनकी मृत्यु हुई है उनका उल्लेख में आपके सामने करना चाहूंगा. मुख्यमंत्री महोदय और पूरी सरकार बैठी हुई है अधिकारी दीर्घा में भी सारे अधिकारी बैठे हैं. एक दिवंगत आत्मा शिवकुमार आत्मज रामकिशन बैगा इनकी मृत्यु हुई 31.10.15 को हुई गुलाब कली पत्नी श्री धनीराम बैगा इनकी मृत्यु 2.11.15 को जिला चिकित्सालय बैढ़न मुख्यालय में हुई. एक छह साल के बच्चे की कंदमूल खाने से मृत्यु हुई उसका नाम धनपति बैगा आत्मज बोरा बैगा, गुलाब कली और यह दोनों एक ही परिवार के थे. छह लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था वे अपने घर आ गये थे यदि कल हम समय पर नहीं पहुंचते और उनको दोबारा अस्पताल नहीं भेजते तो फिर कोई अप्रिय घटना हो जाती हमने दोबारा डाक्टरों को बुलाकर उन्हें भर्ती कराया. आज सूखे के संकट से किसान परेशान है, गरीब परेशान है तत्परता से सरकार को ध्यान देना चाहिये था सरकार को तीन महीने पहले वैज्ञानिकों द्वारा यह जानकारी मिल गई थी कि अवर्षा की स्थिति रहेगी फिर इतनी लेट लतीफी क्यों हुई क्यों अभी तक सर्वे नहीं हो पाया है. मनोज अग्रवाल जी अभी बता रहे थे कि सरकारी अमले का अभाव है मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी पटवारियों का अभाव है अमले के अभाव में सर्वे नहीं होगा और आप समय-सीमा तय कर देंगे कि इतने दिन के अन्दर रिपोर्ट चाहिये इससे कई किसान छूट जायेंगे जैसा कि पहले भी हो चुका है मेरा आपके माध्यम से विशेष निवेदन है कि सर्वे कराने के लिये अमले को बढ़ाया जाये इस तरह से कंदमूल खाने से गरीबों की मृत्यु न हो इस तरह की व्यवस्था की जाये. एक तरफ माननीय मुख्यमंत्रीजी बोल रहे थे कि कांग्रेस पक्ष के साथी वे सूखे के प्रति संवेदनहीनता दिखा रहे हैं अब हम संवेदनशीलता वाली बात कर रहे हैं इस तरह की घटना नहीं घटे इसके मेरा एक निवेदन है आपका संरक्षण चाहता हूँ.

श्री कमलेश्वर पटेल-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सरकारी खाते में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग बसे हुए हैं, जो पट्टाधारी नहीं हैं, उनको भी राहत राशि देनी चाहिए क्योंकि उनकी सारी फसलें चौपट हो गई हैं.

अध्यक्ष महोदय-- ठीक है. श्री सौरभ सिंह बोलें.

श्री कमलेश्वर पटेल-- अध्यक्ष महोदय, जो सर्वे करने के लिए...

अध्यक्ष महोदय-- नहीं, अब बैठ जाएँ. बिल्कुल नहीं.

श्री कमलेश्वर पटेल-- वे विशेष फसलों का ही सर्वे कर रहे हैं. सारी फसलों का सर्वे करें और नुकसानी मिलना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय-- अब हो गई बात.

श्री कमलेश्वर पटेल—दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा...

अध्यक्ष महोदय-- पहले करना चाहिए. श्री सौरभ सिंह अपनी बात रखें. अब बात हो गई. आप कृपया बैठ जाइये, बड़ी मुश्किल से बैठते हैं. अब कुछ नहीं लिखा जाएगा. आपका रिकार्ड में नहीं आएगा. श्री सौरभ सिंह बोलिए.

श्री कमलेश्वर पटेल-- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- यह कोई बात नहीं है.

श्री कमलेश्वर पटेल-- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- सबकी सुन रहे हैं. आप भी समय की सीमा में मर्यादा रखिए. आप बैठ जाइये. श्री सौरभ सिंह बोलें. दूसरे लोगों का भी समय है. कोई आपका ही समय नहीं है. श्री सौरभ सिंह जी बोलिए.

बहिर्गमन.

आसंदी द्वारा बात न सुने जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन.

श्री कमलेश्वर पटेल-- हमारी बात नहीं सुनी जा रही है इसलिए मैं सदन से बहिर्गमन करता हूँ.

(श्री कमलेश्वर पटेल द्वारा उनकी बात न सुने जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

कुँवर सौरभ सिंह(बहोरीबंद)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो विशेष सत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद. उन्होंने किसानों की स्थिति देखते हुए सहयोग किया और यह सत्र बुलाया. अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा में और जिले में, पूरे प्रदेश में किसानों के लिए एक योजना चलती है , रबी फसल के लिए, अन्नपूर्णा योजना, सूरज धारा योजना, एक, एन एस एस एम योजना, आर के वाय और आइसोपाम, ये पाँच योजनाएँ चलती हैं. प्रथम दो योजनाओं को सिर्फ आदिवासी और हरिजनों के लिए रखा गया है. मेरा कहना है कि पहले इसमें 75 परसेंट का अनुदान मिलता था. अर्थात् कृषक 25 परसेंट पैसा देकर के अपना बीज ले सकता था. अभी एक नया व्ही सी से यह फरमान जारी हो गया है. जिसके तहत सौ परसेंट पैसा आदिवासी, हरिजन से पहले लिया जाएगा. **(बैठे बैठे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा आदिवासी, हरिजन शब्द पर आपत्ति लेने पर)** मैं क्षमा चाहूँगा. अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा मेरी बात से अगर किसी को ठेस पहुँची हो. एस सी और एस टी वर्ग के लिए 75 परसेंट का अनुदान था. अब सरकार ने एक नया व्ही सी से एक फरमान जारी कर दिया है जिसके तहत पहले सौ परसेंट पैसा जमा होगा और 75 परसेंट पैसा सब्सीडी के रूप में उसके खाते में जाएगा. अकाल की स्थिति में एस सी और एस टी वर्ग का व्यक्ति कहाँ से सौ परसेंट देगा. यही अन्य तीन योजनाओं में सामान्य वर्ग के लिए भी है. मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इसको शिथिल किया जाए. जिस तरह पहले 75 परसेंट अनुदान मिलता था, 25 परसेंट देने के बाद बीज मिलता था. वैसे ही इस रबी के लिए योजना चालू की जाए. दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हमारे कटनी जिले में औसत वर्षा 1160 मिलीमीटर होती है. जो इस वक्त मात्र 521 मिलीमीटर हुई है और जब पहले हमने अपने शासकीय अधिकारियों से कृषि विभाग से पूछा था कि कितना नुकसान हुआ है तो उनका आकलन था लगभग 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और बाद में सर्वे करके यह बताया जा रहा है कि नुकसान कम हो रहा है. मेरा आप से निवेदन है पानी कम गिरने से 1160 मिलीमीटर से 521 मिलीमीटर होने से स्टेटिक्स की तरह खेती नहीं बढ़ जाएगी कि इतना सर्वे

बढ़ जाएगा. जब 100 करोड़ रुपये का नुकसान है तो 100 करोड़ रुपये का दिखाने की आवश्यकता है. अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पर एक रीठी जनपद में एक किसान फागुराम पिता रामलाल पटेल ने आत्महत्या कर ली है. यह उसके कागज हैं मात्र 35 हजार रुपये का उसके ऊपर कर्जा था, मात्र प्वाईंट पिचहत्तर हैक्टेयर का किसान था. पिछले वर्ष उसकी बेटी की शादी हुई थी. मेरा आप से निवेदन है कि इन आत्महत्याओं को को इस दृष्टि से न देखें कि हम राजनीति कर रहे हैं. मेरा आप से सुझाव सिर्फ यह है कि जो पड़त का सर्वे हो रहा है, जब पटवारी साहब मौके पर जाते हैं तो पटवारी साहब यह देखते हैं कि वहाँ पर धान खतम हो चुकी है....

अध्यक्ष महोदय-- कृपया समाप्त करें.

कुँवर सौरभ सिंह—माननीय, इस तरफ आप जल्दी बोल देते हैं उस तरफ थोड़ी देर से बोलते हैं.

अध्यक्ष महोदय-- अब आप ही बचे हैं इधर.

कुँवर सौरभ सिंह-- मेरा निवेदन है पड़त का सर्वे हो रहा है तीन तरह का नुकसान हुआ है. पहला, जिन्होंने बोया और नहीं हो पाया, दूसरा, जिन्होंने बोया बिना वर्षा के कारण खतम हो गया और चारा पैदा हो गया. तीसरा नुकसान उनका हुआ है, हमारा धान का क्षेत्र है, जिन्होंने धान बोई है और धान कम हुई है, धान में बदरा निकल आया. मतलब दाना नहीं पड़ पाया, हम लोग बदरा कहते हैं, तो पहले दो तरह के जो नुकसान हुए हैं वे आपके सर्वे में पड़त की श्रेणी में आ रहे हैं. मतलब लगभग हमारे यहाँ का 60 प्रतिशत किसान सर्वे में आ ही नहीं रहा है. मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर एक बार पुनः विचार करें . दूसरा एक आदेश के तहत बोरिंग पर बैन लग गया है जब स्टेटा कम हो गया है ,पानी का लेवल गिर गया है और यदि बोरिंग पर बैन लगा देंगे तो पीने के पानी की समस्या उत्पन्न होगी. आपके अधिकारी आपसे कह रहे हैं कि गांव में हैंडपंप चल रहे हैं लेकिन किसी गांव में 10 हैंडपंप हैं तो उसमें से 2 ही चल रहे हैं ,पानी का लेवल कम हो गया है ऐसे में बोरिंग पर बैन लगा देंगे तो पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी. एक निवेदन और है कि पहले परिवार में जो जमीन बंटती थी, परिवार का जो बंटवारा हुआ करता था वह निशुल्क हुआ करता था अब आपने उस पर ढाई परसेंट स्टेम्प ड्यूटी लगा दी है. मेरा निवेदन है कि इस अकाल के समय इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए क्योंकि जो नुकसान किसान को हुआ है, अन्नदाता को हुआ है, वह अकल्पनीय है. हम लोग अपने शब्दों से राजनीति नहीं कर रहे हैं मेरा तो इतना ही कहना है कि कोई भी पक्ष हो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो हम आपके साथ खड़े हैं ,पर सिर्फ किसान के लिए खड़े हैं.

डॉ.रामकिशोर दोगने(हरदा)--- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद. यह सत्र जो बुलाया गया है उसके लिए सरकार एवं आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप किसानों के लिए संवेदनशील हैं,उनके हित के लिए काम करना चाहते हैं ,किसानों के हित में सूखे पर बात तो हो रही है जैसा कि अभी मोहन यादव जी ने अभी बताया कि गीले पर भी बात होनी चाहिए, अतिवर्षा पर भी बात होनी चाहिए . मेरे जिले हरदा में अतिवर्षा हुई और उससे काफी नुकसान हुआ है और उसी के कारण अभी जैसा मुख्यमंत्रीजी ने उल्लेख किया, रेल दुर्घटना हुई है लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बात नहीं की जा रही है.मुख्यमंत्री जी तो संवेदनशील हैं पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधिकारी वर्ग गलत जानकारी देकर आप लोगों को गुमराह करते हैं अभी जो मुख्यमंत्री जी ने बताया कि रेल दुर्घटना माचक नदी के ऊपर हुई , जबकि माचक नदी पर कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, माचक नदी का कोई पुल नहीं टूटा, माचक नदी से पहले एक नाले के पुल टूटने से वह घटना हुई थी और आज पूरे भारत में यही जानकारी जा रही है कि माचक नदी का पुल टूट गया और मुख्यमंत्री जी ने भी यही बताया. इसी तरह से हमारी कृषि के सर्वे की रिपोर्ट अधिकारी वर्ग दे रहे हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बार बार कलेक्टर और अधिकारी से बोल रहे हैं कि आप पंचायत में सर्वे की रिपोर्ट लगाइए , जिला लेवल पर उसको लगाइए, सर्वे की रिपोर्ट दीजिये, सर्वे की रिपोर्ट देंगे तो किसान को पता लगेगा कि कितना नुकसान हुआ ,क्या हुआ और क्या मिलनेवाला है. पर वह कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है. वह बताना बहुत

अनिवार्य है. मेरा निवेदन है कि सर्वे की रिपोर्ट को स्पष्ट करें कि क्या नुकसान हुआ है उसको क्या मुआवजा मिल सकता है और मेरा निवेदन है कि मुआवजा भी अच्छा मिलना चाहिए क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है. हमारे यहाँ माचक नदी के आजू-बाजू जो बाढ़ आई थी उससे पूरे खेत बह गये पर कोई सर्वे नहीं किया गया , कोई जानकारी नहीं दी गई न ही मुआवजा के लिए सिफारिश की गई है. वहाँ कम से कम 21 गांव डूबे थे उन सबको पांच पांच हजार रुपये देकर आश्वस्त कर दिया गया , वह किसान हैं, उनका अनाज भी बह गया, बोनी का सामान बह गया, घर भी बह गया और पांच पांच हजार रुपये देकर उनको संतुष्ट कर दिया गया इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसका भी सर्वे होना चाहिए. अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं होशंगाबाद जिले में तालकेसरी गांव में बाबई तहसील में सोयाबीन बोया गया था पर पटवारी ने धान की रिपोर्ट दी उसके कारण वह गांव मुआवजे से वंचित रह गया. तो यह जांच कौन करेगा. यह गलत रिपोर्ट क्यों दी जा रही है.

श्री विजयपाल सिंह--- रिपोर्ट में धान नहीं सोयाबीन लिखा है.

अध्यक्ष महोदय--- विजयपाल जी उस क्षेत्र के विधायक हैं उनको पता है.

डॉ.रामकिशोर दोगने--- जो बाहर होशंगाबाद के लोग खड़े हैं उन्हीं ने मुझे यह जानकारी दी है . मैं उदाहरण दे रहा हूं कि इस तरह की घटना हो रही हैं. कई जगह इस तरह की गलत जानकारियाँ देकर मुआवजा से वंचित किया जा रहा है . मेरे दो तीन प्वाइंट है कि सर्वे रिपोर्ट पंचायत एवं जिला स्तर पर लगाई जाए जिससे किसानों को पता लगे . मुआवजा राशि का हिसाब बताया जाये कि वह किस हिसाब से दी जाएगी और मेरी मांग है कि कम से कम 10 हजार रुपये एकड़ मुआवजा राशि दी जाना चाहिए. कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा जो गलत रिपोर्ट दी गई है उसको सुधारा जाए किसानों को शासकीय योजना के अंतर्गत तो जल कर देना पड़ता है.पर हमारे यहां शासकीय योजना के बजाय नदी से या कुएँ से पानी ले रहा है उसको भी जल कर देना पड़ रहा है,यह गलत है, जल कर नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि कुएँ से या नदीं से जो पानी ले जाता है तो लम्बी दूरी से पानी ले जाने में ज्यादा खर्चा होता है और दूसरी बात मंत्री और अधिकारीगण जो सर्वे के लिए गये थे वह स्थिति अगर हम देखें जब एक महीने के बाद फसल कट गयी है तो कैसे सर्वे करने गये थे तो यह चीजें हैं.

अध्यक्ष महोदय—आप समाप्त करें.आपकी सारी बातें आ गयीं.श्रीमती पारुल साहू.

श्रीमती पारुल साहू(सुरखी)—माननीय अध्यक्ष महोदय और इस सदन के सभी माननीय सदस्यगण,आज हकीकत बात है कि मध्यप्रदेश में एक बड़ा संकट आया है.इस संकट की घड़ी में जब सभी लोगों को एक होकर के किसानों के हित में बात करनी चाहिए. उस वक्त भी मैं यह देख रही हूँ कि विपक्ष लगातार किसानों के लिए सुझाव न दे के केवल आरोप लगाने का काम कर रहा है.आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि मध्यप्रदेश में किसान हमारी रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं. जब हमारे किसान भाइयों पर आपदा आयी है.इस मुसीबत की स्थिति में मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराजसिंह चौहान जी ने हमारी सरकार ने लगातार किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी है और जहां तक मेरा विचार

है और जो मैंने देखा है कि आज यहां हमारे विपक्ष मे उपस्थित जितू पटवारी जी ने एक बात कही कि प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराजसिंह चौहान जी लगातार एक दिन में चार-चार, पांच-पांच जिलों का दौरा कर रहे हैं. इसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहूंगी कि यह एक किसान के बेटे होने की एक सही पहचान है कि उनको दर्द है कि आज हमारा किसान परेशान है, ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जा के हर खेत में, हर किसान से मिलने का काम कर रहे हैं.आप उस दिन को देखें या बात पुरानी देखें, काफी लोग उपस्थित हैं, जब 90-92 में सूखा पड़ा था तब आपकी सरकार ने किसान भाइयों के लिए क्या किया था, तब एक माहौल था. बात आज व्यक्तिगत नहीं हो रही है, आज मध्यप्रदेश की बात हो रही है, उस समय जो प्रदेश के मुखिया थे वे राजा बन के और जनता हमारी किसान.आज भी उस स्थिति को देखें तो 10 वर्ष पूर्व जो स्थिति खराब की गयी थी, मध्यप्रदेश पूरा अन्धेरे में डूबा था उसको उबारने का अगर काम किया है तो आज भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने यह काम किया है न कि कांग्रेस सरकार ने किया है और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि बहुत आसान है बैठकर आरोप लगाना, बड़ा मुश्किल है जमीन पर उतर के काम करना और काम करवाना. साथ ही साथ इस बात को कहते हुए मुझे खुशी हो रही है,हमारे बाकी सदस्यों ने इस बात को रखा है कि हमारा मध्यप्रदेश में इरीगेशन एरिया जो है लगातार हर साल बढ़ा है और अगर आज इस तरह की परिस्थिति सूखे की अगर मध्यप्रदेश में आयी है तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे किसान भाइयों को मिला है कि सूखे से लड़ने की क्षमता उनको मिली है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव भी मैं देना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना बनायी है कि एक रुपये किलो गेहूं और राशन हमारे गरीब भाइयों को दिया जाता है हर महीने, इस बात पर मैं एक बात कहूंगी कि जब परिस्थिति कठिन है, सूखे की परिस्थिति है उस वक्त समय पर राशन हर महीने की 15 तारीख को 100 परसेंट राशन वितरण हेतु हर जिले के कलेक्टर चीफ सेक्रेट्री आफ स्टेट को एक अण्डर टेकिंग दे दे तो इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि हर महीने समय पर राशन जो अभी नीडी हैं वह हमारे किसान भाइयों को मिलेगा. धन्यवाद.

श्री नीलेश अवस्थी (पाटन) – माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आज का सदन बुलाया गया है यह मात्र किसानों को राहत देने के लिए है, मैं इसमें भाषण नहीं दूंगा. सदन में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से सिर्फ मैं यह बोलना चाह रहा हूँ कि आज का अन्नदाता सब आप पर नजर रखा हुआ है. जैसे कि जब सैलेरी बढ़ाने की बात आती है तो पूरे लोग एकमत होकर सैलेरी बढ़ाने का प्रस्ताव रखते हैं. आज हमारा अन्नदाता रो रहा है और मेरा सबसे निवेदन है कि दोनों हाथ खोलकर सरकार के खजाने से उस अन्नदाता को राहत दी जाए. आने वाले समय में किसानों को अगर हम मजबूत नहीं कर पाए तो हा-हा कार मचेगा और प्रदेश की वास्तविक स्थिति खराब होगी क्योंकि मेरा जिला एवं मेरी पाटन विधान सभा सूखाग्रस्त घोषित हुई है और जो राहत किसानों को मिलनी चाहिए, अगर फील्ड में जाकर देखा जाए तो उनको बिल्कुल नहीं मिल रही है. 6-6 महीने से ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं, नहरों की स्थिति खराब है, बिजली के बिलों की स्थिति

खराब है, अगर 5 एचपी की मोटर है तो उनको 10 एचपी का बिल मिल रहा है ऐसी स्थिति फील्ड में है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि किसानों का मामला है, किसान प्रधान देश है, प्रदेश है, दोनों हाथों से किसानों को 15 हजार प्रति हेक्टेयर कम से कम राशि दी जाए. बिजली के बिल उनके माफ किए जाएं और चूँकि हमारा 80 प्रतिशत किसान नेशनलाइज्ड बैंकों से लोन लेता है उन बैंकों को भी यह आदेश जारी किया जाए कि तीन साल उनसे वसूली न की जाए और उनका इंटरेस्ट माफ किया जाए. मैं चाहता हूँ कि किसानों की मदद दोनों हाथों से करनी चाहिए. धन्यवाद.

श्री पन्नालाल शाक्य (गुना) – सम्माननीय अध्यक्ष महोदय और इस सदन में उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्यगण, सबको मेरा प्रणाम. मैं पहली बार बोल रहा हूँ सबसे अपेक्षा करूंगा कि मेरी पूरी बात हो जाए. कम से कम समय में अपनी बात पूरी कर दूंगा. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कितने समय बोलूँ.

अध्यक्ष महोदय – दो मिनट.

श्री पन्नालाल शाक्य – बिल्कुल दो मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र से चुनकर आता हूँ जहां सूर्यनारायण देव और चंद्रनारायण देव का प्रभाव है. इसके कारण यहां तक आने में बहुत लंबा समय लग गया. आज का जो विशेष सदन बुलाया गया है उसके लिए मैं सदन के मुखिया और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. सारे आंकड़े हमने सुन लिए हैं किसानों के हित में, सभी प्रकार की राहत भी सुन ली है किसानों के हित में, पर मेरा एक प्रश्न है कि यहां जो अपने आपको किसान बताते हैं उनमें से कौन ट्रैक्टर चलाता है और कौन हल-बक्खर पकड़ता है. जो किसान के मरने की बात कर रहे हैं, वहां वह किसान नहीं मर रहा है वहां मजदूर मर रहा है, किसान तो यहां बैठे हैं. उसको राहत राशि नहीं मिलती, जबकि राहत राशि उसको मिलनी चाहिए. हम तो ट्रैक्टर में बैठते हैं और सोफों में बैठकर राहत राशि हड़प लेते हैं. माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे इस तरफ ध्यान देंगे, यह बहुत संवेदन बिंदु है, इस प्रदेश को तीन बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ, चौथी बार भी मिलता पर हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है. यह भारत भूमि मध्यप्रदेश मालवा शस्य श्यामला भूमि है, एक दाने का हजार दाने देती है, सिंचाई की सुविधा सब है, मुआवजा भी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सब मिल रहा है, पर मैं आप सबका ध्यान बड़ी गौर से आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो जमीन हमको हजारों दाने दे रही है उस पर वह कीटनाशक कहां से आ रहा है. कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जहरीला कीटनाशक षडयंत्रपूर्वक अपने प्रदेश में फैलाया गया हो और माननीय मुख्यमंत्री जी को चौथी बार कृषि कर्मण पुरस्कार न मिले .इसकी जांच की जाय,जांच की जाय और जो जांच में फसे उसको हत्या के मामले में दण्डित करना चाहिए. मैं मेरी बात यहीं समाप्त करके सारे सदन को धन्यवाद देता हूं और हाथ जोड़ता हूं.

श्री सुन्दरलाल तिवारी- अध्यक्ष महोदय, कहीं इस षडयंत्र में कैलाश विजयवर्गीय जी तो नहीं..

श्री सोहनलाल वाल्मीक(परासिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यहां विशेष सत्र बुलाया गया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और सरकार के द्वारा जिस तरीके से व्यक्त किया गया कि संवेदनशील मामला है. सूखे के संबंध में, किसानों के हितों के संबंध में हम सब लोगों को चर्चा करना है. हम लोगों ने लगातार कई सदस्यों ने अपनी बात रखी है,कुछ दलगत तरीके से रखी जा रही है,कुछ राजनीतिक तरीके से रखी जा रही है. मगर सच्चाई यह है ,हम अपनी आत्मा पर हाथ रख कर ध्यान दें ,उससे पूछें तो आज पूरे प्रदेश के अन्दर किसानों की स्थिति गंभीर होती चली गयी है, उनकी हालत खराब होती गयी है. लगातार तीन फसलें खराब हुई हैं जिससे किसानों पर आर्थिक संकट बहुत बुरी तरह से गहराया हुआ है. मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं ,समय का सदुपयोग करते हुए कहना चाहता हूं , अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र परासिया में सोयाबीन और मक्के की फसलें बाई गई थीं. और जिस तरह से मक्के के फसल की आवक लगभग काफी हद तक ठीक है, मगर सोयाबीन की लगभग 90 प्रतिशत फसलें खराब हो चुकी हैं. परन्तु जिस तरीके से आकलन किया गया और मेरे छिन्दवाड़ा में जिस तरीके से कलेक्टर महोदय ने सूची जारी की उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र में (0-0)जीरो जीरो कर दिया जिसके कारण किसी भी किसान को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. मैं सदन के माध्यम से आपको यह अवगत कराना चाहता हूं और मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो 0-0 का आकलन किया गया है उसे पुनः जांच करके सर्वे करके सभी किसानों को राहत देने का कष्ट करें. साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हाल ही में पिछली रबी की फसलों का जो आकलन आया है, जो बीमा राशि आयी है ,सामाचार पत्र दैनिक भास्कर में जो उल्लेख किया गया है, कि किसी को 16 रूपये की राशि है,किसी को 68 रूपये की राशि है. क्या किसानों के बीमा की राशि का इस तरह से आकलन होना चाहिए. क्या यह किसानों के साथ अन्याय नहीं है? यह इस तरीके का जो बीमे का आकलन किया जा रहा है यह किसानों के हितों पर आघात हो रहा है. उनके हक का हनन किया जा रहा है. माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से सोयाबीन की जो फसले निरन्तर खराब होती चली गयी हैं और पिछले पांच सालों का अगर आप आकलन करेंगे तो पायेंगे कि यह केवल किसानों का नुकसान नहीं हुआ है, इस प्रदेश के उद्योगों का भी नुकसान हुआ है. अधिकतर सोयाबीन प्लान्ट धीरे धीरे बन्द होते चले जा रहे हैं. यह कहीं न कहीं हम सब के लिए और प्रदेश के लिए एक चिन्ता का विषय है. इसके कारण धीरे धीरे रोजगार के अवसर भी समाप्त होते जा रहे हैं. साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं यह भा ध्यान मुख्यमंत्री जी को दिलाना चाहूंगा कि जो आनावारी का आकलन होता है उस तरीके से अंग्रेजों के जमाने से आकलन होता चला आ रहा है. हम लोगों को इस आकलन के तरीके को बदलना चाहिए. वर्तमान में जो आने-पैसे में इसका आकलन होता है वह प्रतिशत के आधार पर किया जाय ताकी सही आकलन होकर किसानों को उसका लाभ मिल सके. मेरा सुझाव है और विश्वास है कि इसमें आप निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन करेंगे. साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे छन्दवाड़ा जिले के अंदर 35 हैक्टेयर भूमि सिंचित है. वहां पर बहुत सारे जलाशय जो स्वीकृत होने हैं वे नहीं हो पा रहे हैं. ज्यादा से ज्यादा जलाशय बनने से किसानो को लभ मिलता है, मेरे परासिया विधान सभा क्षेत्र के अंदर में

मात्र 900 हैक्टेयर भूमि सिंचित है ,तीन जलाशय हैं, मैने माननीय वित्त मंत्री जी को 5 जलाशयों का प्रस्ताव भेजा है, परन्तु उसमें हमेशा इस बात को बोला जाता है कि पैसे के कारण जलाशय नहीं बन पा रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, अगर हम लोग जलाशय नहीं बढ़ायेंगे तो किसानों को लाभ नहीं मिल पायेगा.यदि हम लोग जलाशयों को नहीं बढ़ायेंगे तो किसानों को लाभ नहीं मिल पायेगा. जलाशयों के हिसाब से यह अतिरिक्त व्यवस्था करना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय—कृपया एक मिनट में समाप्त करें.

श्री सोहनलाल वाल्मिक—मेरा सुझाव है. मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं. बहुत सारी बातें हो चुकी हैं. जलाशय बनने का जो आकलन करते हैं वह जलाशय नहर के साथ 3.50 लाख रुपये प्रति हेक्टर करते हैं. और बिना नहर का जलाशय 3.00 लाख रुपये प्रति हेक्टर करते हैं. स्टाप डेम बेरक 1.75 लाख रुपये प्रति हेक्टर का आकलन करके स्वीकृति प्रदान करते हैं. मेरा वित्तमंत्रीजी से निवेदन है कि इसका आकलन बढ़ना चाहिए, इसमें राशि बढ़ना चाहिए. राशि बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा भूमि सिंचित हो सकेगी.

अध्यक्षजी, मैं किसानों के संबंध में यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में, जैसा हम लोग कहते हैं किसानों को अतिरिक्त लाभ कैसे मिलेगा. उनके रोजगार की व्यवस्था कैसे बनेगी तो जो किसान भाई दूध का व्यापार करते हैं. पिछले 3 वर्ष के पहले 5 रुपये 80 पैसे प्रति फेट मिलता था आज हमारे जबलपुर दुग्ध संघ में 4 रुपये 60 कर दिया गया. सीधे-सीधे किसानों को जो 29 रुपये प्रति लीटर की राशि मिलना चाहिए वह आज मात्र 22 रुपये मिल रही है. यह एक बड़ा नुकसान है. इस पर सरकार को सोचना और समझना चाहिए. इसी का आकलन करें तो भोपाल दुग्ध संघ को 40 पैसे ज्यादा राशि मिलती है तो म.प्र. में एक संघ को अलग राशि और दूसरे संघ को अलग राशि मिलेगी ! इसका आकलन कहीं न कहीं गलत हो रहा है. कोई भी नीति या पॉलिसी बनती तो एक जैसी राशि मिलना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय—कृपया समाप्त करें.

श्री सोहनलाल वाल्मिक—अध्यक्षजी, एक और बात कहना चाहूंगा. जिस तरह चर्चा हो रही है. मुख्यमंत्रीजी ने प्रारंभ में जिस तरीके से बात कही कि (XXX) राजनीति कर रहे हैं तो यह (XXX) राजनीति करने का समय नही है.

अध्यक्ष महोदय—इस शब्द को विलोपित कर दीजिए.

श्री सोहनलाल वाल्मिक—जो विपक्ष होता है वह अपनी बात रखता है. यदि संवेदनशील मुख्यमंत्रीजी इस तरह की बात करेंगे....

श्रीमती शीला त्यागी—अध्यक्ष महोदय,

श्री सोहनलाल वाल्मिक—अध्यक्ष महोदय, माईक बंद कर देते हैं.

अध्यक्ष महोदय—माईक वहीं से अपने आप बंद हो जाता है. कोई बंद नहीं करता है.

श्री सोहनलाल वाल्मिक—हम लोगों का अपमान करते हैं.

अध्यक्ष महोदय—नहीं, नहीं कोई अपमान नहीं करता. आप बटन दबाईये. आपका माईक चालू है.

श्री सोहनलाल वाल्मिक—कृपा करके अपमानित न करें.

अध्यक्ष महोदय—देखो, माईक चालू है या नहीं.

श्री सोहनलाल वाल्मिक—यह चालू हो जाना अलग बात है. हम अपमानित महसूस कर रहे हैं कि हम अपनी बात रख रहे हैं और माईक बंद कर दिया जा रहा है.

अध्यक्ष महोदय—बैठिये आप. माईक बहुत सेंसेटिव होते हैं. अपने आप बंद हो जाता है.

श्री सोहनलाल वाल्मिक—आने वाले समय में इस व्यवस्था को खत्म करना चाहिए.

श्रीमती शीला त्यागी—अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के किसानों की दयनीय एवं चिन्तनीय स्थिति से निपटने के लिए आपके द्वारा एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं.

अध्यक्षजी, जिस प्रकार पूरे देश और प्रदेश में सूखे की वजह से किसानों की कमर टूट गई उसी तरह हमारे रीवा जिले में भी किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. खासकर हमारे मनगवां विधानसभा की जो स्थिति है जो रीवा की सर्वे रिपोर्ट है, उसमें सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र नईगढ़ी, गंगेऊ,मनगवां और सिरमौर हैं.

अध्यक्षजी, असिंचित फसलों का नष्ट होना तो स्वाभाविक ही था लेकिन जो सिंचित फसलें थीं वह बिजली की कमी और जले हुए ट्रांसफार्मर्स की वजह से नष्ट हो गई है. जैसा की पूरे सदन को विदित है, पूरे प्रदेश की जनता को मालूम है कि 70 के दशक के बाद आज तक का सबसे बड़ा सूखा इस साल पड़ा है. जो अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई थी, उससे हमारे किसान पूरी तरह से बरबाद हो गये थे और रही-सही कसर इस बार के सूखे ने पूरी कर दी.

अध्यक्षजी, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं. हम सभी जानते हैं कि कोई व्यक्ति जब बहुत ज्यादा हताश-निराश हो जाता है अतिवाद का शिकार हो जाता है तब वह आत्महत्या कर लेता है.

अध्यक्षजी, हमारी सरकार का और हमारा इस सदन के माध्यम से यही उद्देश्य है कि हमारे देश का पेट भरने वाला जो हमारा अन्नदाता है वह आखिर आत्महत्या क्यों कर रहा है. 1962 के बाद से अभी तक का जो आंकड़ा आया है. अभी तक 1.30 लाख किसानों ने आत्महत्या की. अगर प्रतिदिन का आंकड़ा निकाला जाये तो पूरे देश में 35 से अधिक किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं.

अध्यक्षजी, मैं आप सब से यही गुजारिश करती हूं और यह मेरा सुझाव है कि आपकी सरकार प्रदेश में भी है और केन्द्र में भी है. आपको विशेष पैकेज लेने में कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए. आपको कोई विशेष पैकेज लेने में कोई कमी नहीं होना चाहिए खासकर मध्यप्रदेश के लिए तो विशेष पैकेज मिल ही सकता है. मैं यहां पर यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे रीवा जिले में अधूरी पड़ी नहरें है उनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उनको व्यवस्थित किया जाय, साथ ही साथ सहकारी समितियों को निर्देशित किया जाय कि वह जो बीज और खाद बांट रहे हैं वह नकली न बांटें और सही सही दें, आपने सहकारी

समितियों को जो प्रमाण पत्र दे रखा है और जो कंपनियां बीज बनाती हैं उसमें नकली बीज बनाने वाली कंपनियों को बंद करें, साथ ही साथ आने वाले समय में जो जल संकट है उससे निपटने केलिए रीवा जिले में जो नलजल योजनाएं अधूरी पड़ी हैं उनको भी चालू किया जाय, हैण्ड पंप सुधारे जायें... अध्यक्ष महोदय आप देखें आपके कहते ही हमारा माइका बंद कर दिया गया है.

एक माननीय सदस्य – अध्यक्ष महोदय यह तो हमारे अधिकारों का हनन है कि हमारे माइक ही बंद कर दिये जाते हैं.

अध्यक्ष महोदय – नहीं यह हमारी तरफ से नहीं है यह तो अपने आप ही बंद हो जाते हैं.

श्रीमती शीला त्यागी – क्या सरकार जिस प्रकार से आईएएस आईपीएस अधिकारियों के माध्यम से सर्वे कराये हैं उन्हीं के माध्यम से क्या सही मुआवजे का वितरण किया जायेगा. मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आप सही मुआवजा राशि का वितरण करायें जिससे हमारे किसान आत्महत्या न करें और आने वाली खरीफ की फसल है उसको वह लोग सही तरीके से कर सकें.

श्री निशंक कुमार जैन (बासौदा) – माननीय अध्यक्ष महोदय आज तो आपने यहां परएक नया सिस्टम चालू कर दिया है आप वहां पर इशारा करते हैं उधर से माइक बंद हो जाता है.

अध्यक्ष महोदय – आप तो अपने काम की बात करें.

श्री निशंक कुमार जैन – जब माइक ही चालू नहीं होगा तो काम की बात कैसे करेंगे. पूरे मध्यप्रदेश के साथ साथ चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं हैं और हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी भी सदन में नहीं हैं. मुख्यमंत्री जी आप हमारे 4 बार सांसद थे और प्रभारी मंत्री जी भी हमारे सांसद थे. हमारे विदिशा जिले में भी सूखा पड़ा है. हमारे कुरवाई विदिशा और शमशाबाद के विधायक जी भी यहां पर मौजूद हैं. हमारे यहां पर सिंरोंज में बारिश हुई है लेकिन एक साथ बारिश होने की वजह से उसके बाद की जो भयावह स्थिति बनी है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. मेरी विधान सभा क्षेत्र के एक गांव में 15 अक्टूबर को एक किसान हरप्रसाद कुशवाह ने आत्महत्या की 16 अक्टूबर को सुषमा जी का दौरा था यह बात मैंने उनके संज्ञान में लायी. मैं 15 अक्टूबर की रात को उस किसान के घर गया और जो मुझसे बन सका वह राहत मैंने उसको प्रदान की, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ईमलानी में एक किसान ने आत्महत्या की हम और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी भी वहां पर गये. अभी संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे थे वह भी सदन में नहीं हैं, कि क्या कांग्रेस के विधायकों ने खुद के क्षेत्र के अलावा कहीं और दौरा किया है. हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि कांग्रेस के विधायकों ने तो दौरा किया लेकिन जिन किसानों ने आत्महत्या की उनके यहां पर सरकार का कौन कौन सा मंत्री गया और उन किसानों को क्या मुआवजा दिया गया. हमने कलेक्टर से कहा कि इनको कुछ राहत राशि दिला दी जाय. उन्होंने कहा कि हमारे पास में कोई अधिकार नहीं हैं स्वेच्छानुदान के लिए प्रस्ताव भेजा है कब मंजूर होगा पता नहीं है

हमारे यहां पर कलेक्टर ने सर्वे बहुत ईमानदारी से किया है इस बात के लिए हम उनका धन्यवाद भी देना चाहेंगे और उनको बधाई भी देना चाहेंगे.

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि गंजबासौदा, ग्यारसपुर और त्योंदा तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया जाय क्योंकि वह विदिशा विधान सभा का भी पार्ट है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी विधान सभा होती थी. अध्यक्ष महोदय मैं सरकार से मांग करता हूं कि 15000 और 20000 हजार प्रति एकड़ के मान से मुआवजा दिलाया जाय.अभी चार दिन पहले की बात है हो सकता है कि सदन मेरी बात से सहमत न हो, मैंने 4 दिन पहले रात में डिप्टी डायरेक्टर को फोन किया कि फलां व्यापारी के गोदाम में खाद की बोरी बदली जा रही है नकली खाद को असली खाद की बोरी में डाला जा रहा है. हमें कहीं न कहीं एक प्रयास करना चाहिए कि सरकार खेती का न्यूनतम लागत मूल्य तय करे. सरकार खेती का न्यूनतम लागत मूल्य तय करे और न्यूनतम लागत मूल्य को खाद बीज और डीजल की महंगाई से जोड़ दिया जाये और जब भी यदि कोई मुआवजे की बात आती है सरकार उस तरफ मुआवजा दे सके । माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा एक सुझाव है कि हर गांव में छोटे-छोटे स्टॉप डेम बनाये जायें और जो विधायक निधि की राशि अभी मात्र 70 लाख रूपये है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 330 गांव हैं, हमारी राशि मात्र 70 लाख रूपये है उसको बढ़ाकर कम से कम 2 करोड़ रूपये की जाये । माननीय अध्यक्ष महोदय अभी हम सूखे पर चर्चा कर रहे हैं कल के दिन हम पीने के पानी के लिये संघर्ष करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय-- श्री बहादुर सिंह चौहान अपनी बात कहें कृपया ।

श्री बहादुर सिंह चौहान (महिदपुर)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कृषि को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा सदस्यों द्वारा की जा रही है । माननीय अध्यक्ष जी समय का अभाव है इसलिये संक्षिप्त में मैं सदन में अपने सुझाव देना चाहूंगा । जो म0प्र0 का सर्वे आया है लगभग 33 हजार गांवों में सूखा का आकलन किया गया है जिसमें 44 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सूखा पड़ा है उसको लेकर यह विशेष सत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा यह बुलया गया किसानों के हित में । माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि 2003 में पहली बार इस सदन के अंदर विधायक बनकर मैं आया था, उस समय म0प्र0 के अंदर सिर्फ 3 हजार मेगावाट बिजली थी, आज म0प्र0 के अंदर 14 हजार मेगावाट बिजली है । जब 2003 में पहली बार विधायक बनकर आया था मैं उस समय सिंचाई का रकवा म0प्र0 में साढ़े सात लाख हेक्टेयर था आज माननीय अध्यक्ष जी म0प्र0 का सिंचाई का रकवा 31 लाख हेक्टेयर से भी अधिक है । बिजली के कारण और सिंचाई के कारण एक बार नहीं दो बार नहीं भारत सरकार ने इस म0प्र0 को 3-3 बार कृषि अवार्ड दिया है माननीय अध्यक्ष जी । माननीय अध्यक्ष जी सोयाबीन एक ऐसी फसल है कि केस क्राप्ट है । हम किसान को सलाह देते हैं कि यार सोयाबीन का रकवा कम करो, लेकिन किसान हमारी बात को नहीं मानेगा, चूंकि सीधा-सीधा सोयाबीन की फसल बेचने से उसका लाभ होता है । 35 वर्षों से लगातार-लगातार मालवांचल में 95 प्रतिशत किसान सोयाबीन की फसल बो रहा है और उसमें कोई संशय नहीं है कि उनकी माली हालत बहुत अच्छी हुई 35 वर्षों में परंतु,

धीर-धीरे, धीर-धीरे इस सोयाबीन की फसल में चाहे वह 335 हो या 9560 हो उसके अंदर वायरल आ गया है और एक फसल बोने से जो पैदावर पर हेक्टेयर आना चाहिये वह आधी हो गई है जिससे लागत मूल्य बढ़ गया है और जो पैदावार होना चाहिये वह कम हो गया है । मेरा आग्रह है कि हम एक ऐसी नीति बनायें, चूंकि मानसून कोई सरकारों के हाथों में नहीं होता है, हमारे हाथ में नहीं होता है । जब रवी फसल बोते हैं तो कही पर अतिवृष्टि होती है, कहीं पर अल्पवर्षा होती है, जहां अल्प वर्षा होती है वहां पर सूखा पड़ गया, जहां अतिवृष्टि होती है वहां पर सोयाबीन की फसल खराब हो गई । अब रवी की फसल आ रही है, कहीं शीतलहर से फसल खराब हो जायेगी, कहीं ओलावृष्टि से फसल खराब हो जायेगी । मेरा कहने का तात्पर्य है कि मौसम विभाग के अनुसार हमें म0प्र0 के किसानों को ऐसा बनाना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय-- कृपया समाप्त करें अब ।

श्री बहादुर सिंह चौहान-- माननीय अध्यक्ष जी मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं यह बात यह है कि सोयाबीन की फसल लगातार-लगातार बोने से जो लाभ हो रहा था वह लाभ अब नहीं हो रहा है, मैं मुख्यमंत्री को इसलिये धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि जो बिजली को लेकर चार महीने के जो कनेक्शन थे वह दो महीने के कनेक्शन कर दिये । मैं बिजली में एक महत्वपूर्ण सुझाव देकर मेरी बात को समाप्त करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय । चूंकि बिजली के कारण ही किसानों का आने वाला समय सही हो पायेगा इसलिये मैं बिजली के बारे में ऊर्जा मंत्री जी को बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूंगा कि एक ट्रांसफारमर के ऊपर 25 उपभोक्ता हैं जिसमें से 15 लोग रेग्यूलर बिल भरकर अपनी बिजली लेते हैं लेकिन 10 बिजली के कनेक्शन अतिरिक्त होने के कारण वो ट्रांसफारमर जल जाता है और जलने वाले ट्रांसफारमरों की संख्या लगातार प्रदेश में बढ़ती जा रही है तो मेरा सुझाव है कि अभी जो अस्थाई रूप से किराये का ट्रांसफारमर दिया जाता है उसको अविलंब लागू किया जाये और आने वाले समय में जो अस्थाई कनेक्शन देकर बिजली दी जाती है इसको स्थाई कनेक्शन में कनवर्ड करके कनेक्शन दिया जायेगा तो निश्चित रूप से ऊर्जा विभाग और तरक्की करेगा और अंत में कहना चाहता हूं कि महाकाल की नगरी उज्जैन में आज तक अधिक वर्षा होने से कभी भी उनके गर्भगृह में पानी नहीं आया था लेकिन इतनी वर्षा उज्जैन में हुई है कि महाकाल के गर्भ गृह तक पानी पहुंच गया. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत धन्यवाद.

श्रीमती झूमा सोलंकी(भीकमगांव)- माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष सत्र के लिये बहुत बहुत आभारी हूं किंतु बड़े दुख के साथ मैं कह रही हूं कि मेरा विधानसभा भीकनगांव झिरिन्या जहां पिछले 3 वर्षों से लगातार ओलावृष्टि, अल्प वर्षा और इस वर्ष भारी सूखे के कारण से पहाड़ी अंचल और समतली क्षेत्र की फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, बड़े दुख के साथ मैं यह भी कह रही हूं कि इतनी बर्बादी के बाद भी हमारे क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र शासन के द्वारा घोषित नहीं किया गया है. वर्तमान में भीषण प्राकृतिक आपदा के पश्चात मेरे क्षेत्र में 4 किसानों ने आत्महत्यायें की हैं, और सभी की आयु 30-35-40 वर्ष के बीच की हैं . मैं उनके बीच में स्वयं गई हूं किंतु आज तक वहां पर न तो कोई मंत्री, न कोई प्रशासन का व्यक्ति उन पीडित

किसानों की हालत जानने के लिये उनके बीच नहीं पहुंचा है और ना ही पीडित किसानों को सरकार की तरफ से कोई राहत प्रदान की गई है. मैं सरकार से अपेक्षा करती हूं कि जिन्होंने भयंकर सूखे के कारण आत्महत्यायें की हैं ऐसे परिवार को ऐसे दुख के समय में कम से कम 1 लाख रूपये की सहायता मिले साथ में उनके ऊपर जितना कर्जा हो उसको माफ किया जाये. हमारा क्षेत्र महाराष्ट्र से लगा हुआ है और महाराष्ट्र के लिये काम धंधे के समय हमारे क्षेत्र के लोगों का पलायन इतना होता है कि आज यदि किसी गांव में जायें तो वहां पर कोई व्यक्ति नहीं मिलता . हजारों की तादात में पहले तो मजदूर ही जाया करते थे किंतु आज स्थिति यह है कि मजदूरों के साथ साथ किसानी करने वाला किसान मजदूरी करने के लिये वहां से पलायन करके गुजरात और महाराष्ट्र में चला गया है. सरकार के लिये यह बेहद जरूरी है कि किसी भी योजना के तहत रोजगार के कार्य वहां पर तत्काल प्रारंभ किये जाने चाहिये. तालाब बनाये, सड़क बनाये, या अन्य योजनायें जिससे उनको राहत मिल सके और उनकी दिनचर्या अच्छे से निकल सके ऐसे प्रयास सरकार को करना चाहिये.

अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में भी बिजली की बहुत ज्यादा समस्या है . किसानों को बिजली देने के लिये सरकार के द्वारा प्रचारित किया जाता है कि सरकार 24 घंटे उनको बिजली दी जा रही है लेकिन वास्तविकता कुछ और है. धरातल पर जाकर के देखा जाये तो किसानों को 4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है. मेरी सरकार से मांग है कि किसानों को कम से कम 18 घंटे बिजली प्रदाय की जानी चाहिये जिससे कि आने वाले समय में जिस किसान के पास में जो साधन है जैसे कुंआ है या तालाब है या नालों से नदी से वह किसान पानी ले जाकर के खरीफ की फसल की बुवाई कर सके तो उससे उनको फायदा होगा. अध्यक्ष महोदय बिजली का ट्रांसफारमर जलता है , सरकार के नियम के अनुसार उसको 72 घंटे के अंदर ठीक होना चाहिये किंतु 2-3 माह का समय उन ट्रांसफारमरों के ठीक होने में लगता है. अधिकारियों का ध्यान इस और बिल्कुल नहीं है. किसान पीडित है वह अपनी बात अधिकारियों के सामने रखने जाता है तो उस किसान को भगा दिया जाता है , उसका अपमान किया जा रहा है. इंदिरा सागर हमारे क्षेत्र से लगा है, वहां से नहरें निकलते हुये बड़वानी जिले तक गई हैं. क्षिप्रा में भी पहाड़ के ऊपर से पानी को चढ़ाकर के नर्मदा का पानी ले जाया जा रहा है किन्तु इतने पास होने के बाद भी हमारे यहां के किसानों को पानी की सुविधा नहीं है और नर्मदा जी तो दूसरी आयेंगी नहीं . यदि सरकार चाहे तो हमारे विधानसभा के शोषित पीडित किसानों की मदद के लिये उद्वहन सिंचाई योजनाओं के माध्यम से पानी दिया जा सकता है.

अध्यक्ष महोदय, हमारा निमाड़ क्षेत्र मिर्ची के लिये बहुत प्रसिद्ध है और निमाड़ की मिर्ची से ही पहचान है. हमारे जिले में ही मिर्ची मंडी है, पूरे प्रदेश में एकमात्र मिर्ची की मंडी हमारे यहां पर ही है . इस साल मिर्ची की उपज नगण्य है. हमारे किसानों ने बहुत अधिक संख्या में मिर्ची लगाई थी किंतु उनकी मिर्ची में वायरस आने से पिछले वर्ष भी कोई मुआवजा सरकार की तरफ से उनको नहीं मिला और इस वर्ष भी उनकी पूरी मिर्ची की फसल बर्बाद हो गई है . मिर्ची की मुआवजा दिया जाये यह हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है. हमारे जिले के विधायक भी यहां पर बैठे हैं मैं चाहती हूं कि उनका समर्थन इस बात के

लिये हो. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दो बातें और हैं आप सुन लीजिये क्योंकि महिलायें व्यवधान डालती नहीं है. मैं चाहती हूं कि पहली बार बोल रही हूं तो मुझे बोलने दिया जाये और आपका पूरा संरक्षण मुझे प्राप्त हो. अध्यक्ष महोदय, अपर वेदा डेम जो हमारे क्षेत्र में एकमात्र भरा हुआ है और वह भी एक ही दिन की वर्षा से भर गया. उसकी दाईं और नहर यदि निकाल दी जाय, जल्दी से जल्दी उसको पूरा करके उससे किसानों को पानी दिया जाय, तो निश्चित तौर से 10 से 20 गांव लाभान्वित होंगे और इन्दिरा सागर का पानी हमारे क्षेत्र के लिये, मुख्यमंत्री जी से विशेष निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के लिये इतना जरुर करें. ताकि ऐसे 60 बड़े बड़े गांव है, जिनमें बड़े बड़े किसान हैं, अच्छी खेती करते हैं और पानी के अभाव में कृषि को लाभ का धंधा बनाने का जो सपना आप दिखाते हैं, वह कभी पूरा नहीं होने वाला है. अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद.

सुश्री हिना कावरे (लांजी) -- अध्यक्ष महोदय, मैं बालाघाट जिले की बात करना चाहूंगी. बालाघाट जिले में खरीफ में मुख्य रुप से धान की फसल होती है. मेरे विधान सभा क्षेत्र लांजी में भी धान की बहुत अच्छी फसल थी. वर्षा कम हुई, किन्तु जब जब धान को पानी की जरुरत पड़ी, बारिश हुई. जब हम खेत की तरफ देखते थे, तो ऐसा लगता था कि फसल बहुत शानदार है और निश्चित रुप से इसमें कोई दो मत नहीं था कि फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन माऊ कीट के प्रकोप से चारों तरफ खड़ी फसल पूरी खराब हो गई. आज माऊ कीट का प्रकोप इतना भयानक है कि छोटे से छोटा किसान जिसने 15 से 20 हजार रुपये दवाई के प्रयोग में पूरा खत्म कर दिया और आज जो उसकी खेत में फसल है, उसको यदि वह घर लेकर आता है, तो फसल को खेत से घर लेकर आने में जितना खर्चा उसको लगेगा, वह खर्चा भी उस पूरी फसल से वह नहीं निकाल सकता. आज बालाघाट जिले में केवल लांजी ही नहीं लांजी के अलावा हमारे यहां कटंगी, तिरोड़ी, लामता ये ऐसी हमारी तहसीलें हैं, जहां पर सूखे का प्रकोप है. मैं यहां सरकार से यह मांग करना चाहती हूं कि लांजी तहसील को कीटग्रस्त घोषित कर दिया जाय. उसके साथ साथ जो तहसीलें सूखाग्रस्त हैं कटंगी, तिरोड़ी, इनको सूखाग्रस्त घोषित किया जाय. मैं एक बात जरुर कहना चाहती हूं कि हमारे यहां, जो हमारे साथी विधायकों ने भी बात कही कि नुकसान का सर्वे कैसा होगा. यह हम सबके लिये चिंता का सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि पूरे प्रदेश में बालाघाट सहित पूरे प्रदेश में बालाघाट जिला एक मात्र सबसे नक्सल प्रभावित जिला है और जहां तहसीलदार, नायब तहसीलदार,आरआई, पटवारी इनकी भारी कमी है. मेरी जानकारी के अनुसार हमारे जिले में 11 तहसीलदार के पद हैं, जिसमें से केवल 5 तहसीलदार कार्यरत् हैं. ऐसी ही स्थिति नायब तहसीलदार, आरआई और पटवारियों की है. ऐसी स्थिति में हमारे यहां पटवारी आज धरने पर बैठे हुए हैं. मैं एक बात कहना चाहती हूं कि इस देश में किसानों की माली हालत का अंदाजा केवल इस बात से हम लगा सकते हैं कि देश की जीडीपी, सकल घरेलू आय में कृषि क्षेत्र की भागीदारी केवल 17 प्रतिशत है और इस 17 प्रतिशत आय पर इस देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या जीवन यापन करती है. मैं यह कहना चाहती हूं कि राजनैतिक हलकों में यह आम चर्चा है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो प्राकृतिक

आपदा के समय मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार के सामने धरना, प्रदर्शन एवं आंदोलन यह सब करते थे. लेकिन आज वे ऐसा नहीं कर रहे हैं. मैं सरकार के बारे में यह बात कहना चाहती हूं कि केंद्र सरकार पूरा व्यापारिक दृष्टिकोण से काम कर रही है . चूंकि जीडीपी में कृषि का योगदान, हिस्सेदारी कम है. इसलिये किसी भी कीमत पर केंद्र सरकार किसानों को राहत के नाम पर मध्यप्रदेश को पैसा नहीं देगी. फसल बीमा का लाभ किसानों को बिलकुल नहीं मिल रहा है. पहले फसल बीमा की इकाई तहसील हुआ करती थी. अब इस इकाई को हटवारी हलका बना दिया गया है, किन्तु जब तक किसान को इकाई नहीं बनाया जाएगा तब तक किसानों को उसका लाभ नहीं मिलेगा. मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदाएं तहसील अथवा पटवारी हल्का देखकर के नहीं आतीं हैं. आपने समय दिया धन्यवाद.

श्री हेमन्त खंडेलवाल (मुलताई)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज किसान मौसम की मार से परेशान हैं, वह मुसीबत में है. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी संवेदनशीलता के कारण पिछले तीन वर्ष से किसान को राहत मिल रही है. पिछले वर्ष भी उनको 2 हजार करोड़ रूपये का मुआवजा किसानों के लिये रखा. मेरे अपने जिले में 37 करोड़ रूपये मुआवजे के रूप में बांटे गये. इस साल मेरे अपने जिले में बैतूल जिले में 2 लाख 29 हजार हैक्टेयर फसलें बर्बाद होने का आकलन किया गया है और लगभग 110 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है. ऐसा नहीं है कि फसलें पहली बार बर्बाद हुई हैं, फसलें लगातार तीन साल से बर्बाद नहीं हो रही हैं 15-20 साल से बर्बाद हो रही है, लेकिन जब प्रदेश का मुखिया संवेदनशील नहीं था और इसलिये बैतूल के मुलताई में जब किसान मुआवजे की मांग कर रहे थे तो उन पर गोलियां चला दी गईं और इसलिये मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मौसम पर किसी का बस नहीं चलता, लेकिन उनकी संवेदनशीलता के कारण लगातार किसानों को मदद मिल रही है. मैं आपके माध्यम से अपने दूसरे विषय को रखना चाहूंगा कि हम हमेशा मुआवजे की मांग करते हैं उसके लिये सत्र बुलाते हैं, लेकिन अब समय आ गया कि हमारे देश एवं प्रदेश में अमेरिका, यूरोप और जापान की तरह मौसम बिगड़ता जा रहा है इसलिये एक सत्र इस बात के लिये बुलाएं कि जिसमें हमारी जो कृषि नीति है उसमें बदलाव की चर्चा करें उसमें हम इस बात की चर्चा करें कि हम उसमें ऐसी कौन सी फसलें लगवाएं जिससे हमारे किसान को राहत हो सके. जैसे हम डेयरी को आगे बढ़ाते हैं आदिवासी क्षेत्रों में बकरी पालन, मछली पालन, गन्ना, धान, मक्का, पाली हाऊस या ग्रीन हाऊस से सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो किसानों को कम नुकसान होगा. हम इस बात की चिन्ता करें कि हर क्षेत्र में, हर जिले में दो या तीन फसलें चिन्हित करें उन फसलों का चयन वहां के कृषि वैज्ञानिक, वहां के जनप्रतिनिधि तथा वहां के अधिकारी बैठकर के करें. मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह जो चिन्हित फसलें हैं उन पर जो उद्योग लगे, उन जिलों में सिर्फ उन्हीं फसलों को आगे बढ़ाएं और उनको चिन्हित करें उनको सरकार सहायता दें. उन जिलों में वेयर हाऊस और कोल्ड स्टोरेज भी उनके लिये बनायें और जैसे गन्ना ढोने के लिये ट्रांसपोर्ट लगता है उसको भी टेक्स की छूट दें, साथ ही साथ उन जिलों में कृषि पॉलिटेक्निक खोलकर उन्हीं चिन्हित फसलों को पढ़ायें तथा उन पर रिसर्च करवाएं ताकि किसान उस जिले का और उन फसलों को लगाने में आत्म-निर्भर हो सकें.

मैं अपनी बात बैतूल जिले के उदाहरण के साथ समाप्त करना चाहूंगा जो बात मैं कह रहा हूं अगर बैतूल जिले में गन्ने, डेयरी और सब्जी के उत्पादन को आगे बढ़ाया जाए तो बैतूल जिला मध्यप्रदेश में दूध के उत्पादन, सब्जी में अग्रणी हो सकता है, गन्ने में किसान आत्म-निर्भर हो सकता है. अंत में इस बात का अनुरोध करते हुए कि अगली बार जब हम बैठेंगे तो नयी नीति, नयी योजना की बात करेंगे ताकि किसान समान से जी सके, आत्म-निर्भर हो सके धन्यवाद.

श्रीमती सरस्वती सिंह(चितरंगी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंगरौली जिले की चितंरगी विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं जहां पर सबसे ज्यादा सूखा पड़ा है और हमारे जो भाजपा के विधायकगण बैठे हैं उनसे भी आप पूछ लीजिये. सबसे ज्यादा हमारी चितरंगी विधान सभा में एस.सी., एस.टी. के लोग रहते हैं जो कि बहुत ही गरीब हैं वहां के क्षेत्र में धान के सर्वे करने के लिये अनुमति दी गई है हमारे यहां पर ज्यादातर मक्का, उड़दा जो कि धान की बुवाई नहीं होती है मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि तहसीलदार जी को निर्देशित किया जाए कि वहां पर सभी फसलों का सर्वे किया जाए. मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में जो पांच पांच महीने से ट्रांसफार्मर जले हुए हैं.फिर भी किसानों के पास बिजली का बिल पहुंचाया जाता है अगर वे बिजली का बिल जमा नहीं करते हैं तो उनको नोटिस दिया जाता है. बार-बार उनको धमकी दी जाती है कि आप बिजली का बिल जमा नहीं करेंगे तो आपको जेल में भेज दिया जायेगा. इस तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय जी उनको धमकी दी जाती है और मैं कहना चाहती हूं साथ में बैठे हुए हमारे शासन प्रशासन से कि जो किसान कर्ज लिये हैं बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं उनके बिल तत्काल माफ किये जायें और उनके कर्ज माफ किये जायें तो जो किसान खून के आंसू रो रहे हैं आत्महत्या कर रहे हैं यह शायद रुक जायेगा. जैसा अभी हमारी दीदी बोल रही थीं कि 1 रुपये किलो गेहूं, 1 रुपये किलो चावल दिया जा रहा है. हर व्यक्ति को 5 किलो बढ़ाकर कम से कम 15 किलो हर व्यक्ति को दिया जाये. यह मेरी सदन में अपेक्षा है. धन्यवाद.

<u>श्री फुन्देलाल सिंह मार्को(पुष्पराजगढ़)</u> – माननीय अध्यक्ष महोदयत आज वास्तव में पूरे मध्यप्रदेश में और जहां सूखे की स्थिति निर्मित हुई है. किसान परेशान है और वह चिंतित है अपने परिवार की परवरिश के लिये बेटियों की शादी के लिये बिजली के बिल पटाने के लिये और साहूकारों के कर्ज पटाने जैसी समस्या उत्पन्न हुई है. आज पूरे प्रदेश में खासकर अपने अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र से संबंधित बात कहना चाहूंगा. पुष्पराजगढ़ मां नर्मदा के उद्गम क्षेत्र अमककंटक के साथ ही जंगल पहाड़ों में निवास कर रहे अनुसूचित जाति,जनजाति के लोग वहां जीवन यापन कर रहे हैं और वहां एक मात्र साधन खेती है और वर्तमान में सूखे की स्थिति निर्मित होने के कारण कृषक मजदूरी के लिये भटक रहे हैं. लगभग पुष्पराजगढ़ विधान सभा की तहसील अनूपपुर में 60 हजार कृषक खातेधारी हैं और हमारे वर्तमान में जो धान,उड़द,सोयाबीन,मक्का,कोदू,कुटकी का जो बोहनी किया गया वह लगभग धान का 33782 हेक्टेयर है,उड़द का 8880 हेक्टेयर में और मक्का 8100 हेक्टेयर में और कोदू 7100 हेक्टेयर में और कुटकी 3265 हेक्टेयर में बोहनी की गई. जो 65 हजार कृषक खातेदार हैं. उनके खेतों में सर्वे करना है और हमारे अनूपपुर

तहसील में जो पदस्थापना की स्थिति इस प्रकार है कि वहां पुष्पराजगढ़ में एक तहसीलदार का पद वर्तमान में रिक्त है. 4 नायब तहसीलदार के पद हैं उनमें से 1 भरा है और बाकी रिक्त हैं. वहां 119 ग्राम पंचायतों के 120 पटवारी हल्के में मात्र 60 पटवारी कार्यरत् हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, जी, जिस तरह से वहां के गरीब अनुसूचित जाति,जनजाति के लोग वहां खेती कर रहे हैं और तत्काल वहां जो सर्वे किया जाना है और शासकीय अमला न होने के कारण सभी खेतों में सर्वे नहीं हो पा रहा है. पटवारी सही समय पर अपने प्रकरण तैयार नहीं कर पा रहे हैं और तहसीलदार और नायब तहसीलदार न होने के कारण मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समय पर भुगतान होना संभव नहीं हैं. मेरे पुष्पराजगढ़ विधान सभा में ऐसे कृषक हैं जिनके पास कृषि भूमि नहीं है. 8772 ऐसे किसान हैं जिनके पास कृषि भूमि नहीं है. मैं ऐसा मानता हूं कि प्रदेश के कोने-कोने में ऐसे किसान होंगे जो दूसरे की भूमि पर अध्या खेती करके जीवन यापन करते हैं. जो आज हम मुआवजा भुगतान करेंगे वह कृषि भूमि धारक को करेंगे लेकिन जो वास्तव में अध्या खेती करके जीवन यापन कर रहा है उनको हम मुआवजा भुगतान नहीं कर रहे हैं. अत: आपसे निवेदन है कि उनका भी सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति राशि से लाभ दिलाया जाये. मैं दो बिन्दु और बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से यदि आप अनुमति दें तो.......

अध्यक्ष महोदय – जल्दी से बोल लीजिये.

..........माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि जल स्तर बहुत कम हो गया है। मेरे क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में 80;90 गांव ऐसे हैं जो विकराल एक पेयजल के संकट से आने वाले समय में झूचले वाले हैं। मेरा निवेदन है कि कम से कम 100 हैंडपंप वहां पर स्वीकृत किये जायें, ताकि वहां पर किसानों को शुद्ध पानी पीने का मिल सके। दूसरी बात यह है कि बिजली की जो समस्या है इससे पहले भी मैंने यहां पर रखा है। पुष्पाजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वनांनचल होने के कारण वहां पर बहुत सारे ट्रांसफार्मर वहां पर जल गये हैं, सालोंसाल से उसका परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जले हुए ट्रांसफार्मर हैं उनको तत्काल बदला जाये। अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रति एकड़ 15 हजार रूपये एवं चालीस हजार रूपये का भुगतान किया जाये। आपने बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद्।

श्री ओंकार सिंह मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं क्षेत्र से निकला तो किसानों ने कहा कि आप हमारे सुख दुख की बात वहां जाकर बतायें। जब हम आगे बढ़े तो हमारे घर में हमने जो गैया और बझड़े रखे हैं वह भी चिल्लाने लगे और मैं लोटा और गैया और बझड़े के बीच में गया तो उनके भी आंख में आंसू दिखाई दिये और में उनको पारले जी बिस्कुट खिलाकर मैंने कहा कि प्रदेश के मुखिया के पास मैं जा रहा हूं . यह जो आपने 11 विभागों में 84 अरब, 7 करोड़, 65 लाख, 4 हजार 840 रूपये जो आपने दिये हैं. मुझे उन मुक जो हमारे मित्र की तरह हैं, जो हमारे घर में रहते हैं,हमारे मवेशी उस विषय में हमारे मुख्यमंत्री जी हम और आप कहीं न कहीं समझे उसके लिये एक रूपये का प्रावधान इसमें नहीं है। उसमें मैं

माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पशु विभाग की तरफ से कितनी मात्रा में चारा उनको आवश्यकता पड़ती है, कितने लाख पशु हैं अगर उनकी व्यवस्था आप करेंगे तो आपको उनका भी आर्शीवाद मिलेगा कि आपने पूण्य का काम किया है। मैंने देखा जब हम आ रहे थे तो हमें हैंडपम्प भी दिखाई दिया पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने एक रूपये भी इसके लिये नहीं रखा है। मैं समझता हूं कि सरकार भी अपने नियम कानून प्रक्रिया के अंदर है किन्तु इसका प्रबंधन करने के लिये भी बड़ी दिक्कत होगी और वर्तमान समय में भी जो कृषक हैं, उसके लिये भी बताना चाहूंगा कि मैं रौपा भी लगाता हूं, चना भी बोया है थोड़ा सा भाजी खाने के लिये भी आवश्यक हैं। मैं पड़वा नागर भी जोतता हूं. वह भी हम बता दें,बत्तर की नागर भी जोड़ते हैं वह भी बता दें, चार बजे उठकर गढ़ाई करते हैं यह भी हम आपको बताते हैं परन्तु कृषकों का वास्तविक दर्द समझने की आवश्यकता है। मैं यह बताना चाहता हूं उद्योग की बात जो आप करते हैं उसमें गरीब आदमी का दूर दूर तक जुगाड़ ही बन पाता है। जो बड़े बड़े लोग जो कृषि में बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करते हैं। वह व्यवसाय को आगे ले जाते हैं। उसमें गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। मेरा यह निवेदन है और मैं एक बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं एक मां के दो बेटे हुए बड़े बेटे ने बहुत मेहनत करी एक पौधा लगाया, छोटा बेचा खेलता रहा। बड़े बेटे ने बहुत मेहनत करके उसको फलने लायक बनाया इत्तेफाक से वह छोटे बेटे के हिस्से में चला गया और जब पेड़ सूखने लगा तो बड़े भाई को दर्द हुआ और उसने कहा कि आप पेड़ को थोड़ा पानी दो तो छोटे भाई के परिवार वाले बोले कि यह आपका नहीं है,आप गलत बोल रहे हो,ऐसा कहने लगे। वैसे ही आज भाजपा के लोग हमको कह लोगों को कह रहे हैं जिस लोकतंत्र को कांग्रेस के लोगों ने दिया जिसकी व्यवस्था कांग्रेस ने लाया उसकी सूखने की स्थिति आ रही है, इसलिये सभी लोगों को परिवार की तरह इस लोकतंत्र को बेहतर बनाने में हमको और आपको मेहनत करना पड़ेगी । मैं यह निवेदन करूंगा कि सबकी गरिमा के अनुरूप यहां पर राहत वितरण में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हो, अन्यथा ब्योरेकेसी के लोग इतना भी सम्मान नहीं करेंगे। आपने बोलनेका समय दिया उसके लिये धन्यवाद् ।आपको और हमको सहयोग करना चाहिये आप और हम के विषय में जनता देख रही है. हमारे जितने सदस्य हैं सभी की गरिमा के अनुरुप राहत वितरण में माननीय मुख्यमंत्रीजी के निर्देश हों अन्यथा ब्यूरोक्रेसी के लोग विधायकों का कहीं पर भी सम्मान नहीं करते हैं सत्तापक्ष के लोग सरकार के कारण बोल नहीं पा रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—अब आप बैठ जायें. श्री सखलेचा जी अपनी बात कहें.

श्री ओमकार सिंह मरकाम—अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो..

अध्यक्ष महोदय—अब श्री ओमकार सिंह मरकाम जो कहेंगे वह नहीं लिखा जायेगा.

श्री ओमकार सिंह मरकाम—(XXX)

अध्यक्ष महोदय—कृपया आप बैठ जाये. यह कुछ नहीं लिखा जायेगा.

श्री ओमप्रकाश सकलेचा (जावद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के प्रति अतिसंवेदनशील माननीय मुख्यमंत्रीजी को मैं इस विशेष सत्र के लिये बहुत धन्यवाद देता हूँ वास्तव में इस सत्र की बहुत जरुरत थी क्योंकि जब तक अनुपूरक बजट का समय आता तब तक किसानों के लिये काफी देर हो जाती किसानों को राहत की तुरंत जरुरत थी अगला सत्र दिसंबर में आता तब तक एक डेढ़ महीना लग जाता इस बीच किसान की दीवाली और अन्य त्यौहार बर्बाद हो जाते इसलिये मैं इन सब की चिन्ता करते हुए इस विशेष सत्र के लिये धन्यवाद देता हूँ.

मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा प्रदेश में कुछ क्षेत्र में सूखा है वहीं नीमच, मंदसौर मालवा में अतिवर्षा हुई और वर्षा शुरु में हो गई उसके कारण अफलन काफी हो गया उसके नुकसान के मुआवजे के लिये माननीय मुख्यमंत्रीजी सहमति दी और उसके लिये जो प्रावधान किया उसके लिये मैं विशेष रुप से धन्यवाद देना चाहता हूँ. साथ ही मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ कि किसानों के लिये लांग टर्म और शार्ट टर्म दो तरह की योजनायें बनानी पड़ेंगी क्योंकि हम पिछले पांच-सात सालों से देख रहे हैं हर साल कुछ न कुछ हर क्षेत्र में समस्या आ रही है. मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी की उस सोच के लिये बधाई और धन्यवाद दूंगा. पंचायत स्तर पर जो फूड प्रोसेसिंग के बारे में माननीय मुख्यमंत्रीजी ने सोचा है वह काफी अच्छी सोच है कि पंचायत स्तर पर आना चाहिये लेकिन पंचायत स्तर पर जैसे ही आप फूड प्रोसेसिंग की सोचेंगे तो उसके साथ ही उसका मूवमेंट आफ मटेरियल्स, हर जगह टेकनालॉजी कैसे पहुंचेगी क्या होगा उसकी पूरी प्रोसेसिंग के बारे में दो दिन का एक अलग से सत्र बुलाकर केवल उसी विषय पर चर्चा करना चाहिये. मध्यप्रदेश में हर क्षेत्र में अलग-अलग रुचि है अलग-अलग आईटम हैं अलग-अलग उसकी प्रोसेसिंग होगी और उन सब को कैसे करेंगे. जहां तक सवाल है हार्टिकल्चर की बात करें खेती में आज की तारीख में सबसे ज्यादा फायदे का सौदा हार्टिकल्चर है यदि हम देश का पूरा आकलन देखें तो हार्टिकल्चर का एक्सपोर्ट पिछले दस वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा है और उस बढ़े हुए एक्सपोर्ट में मध्यप्रदेश का क्या योगदान है उसके लिये आप क्या-क्या योजनायें बना रहे हैं कितन कोल्ड स्टोरेज के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि शार्ट टर्म तो हम सभी डिसकस कर लेते हैं लांग टर्म भी हमको सोचना चाहिये हमें कितने ग्रीन हाउस कितने पॉली हाउस लगेंगे. एक और विषय है..

अध्यक्ष महोदय—बस अब आप समाप्त करें.

श्री ओमप्रकाश सकलेचा—मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा.

अध्यक्ष महोदय—दो मिनट नहीं एक मिनट में प्लीस, एक वाक्य कहकर समाप्त कर दीजिये, सबसे अधिक टाइम..

श्री ओमप्रकाश सकलेचा—आप कहें तो मैं बैठ जाता हूँ, आप नाम न लिखा करें, धन्यवाद मैं ज्यादा और क्या बोलूं. ट्यूबवेल खनन के मामले में कहना चाहता हूँ कि अगर पानी नहीं होगा और किसान ट्यूबवेल खोदेगा मवेशियों को पानी कैसे पिलायेगा इधर हम पशुधन बढ़ाने की बात कर रहे हैं अधिकारी

कर्मचारी उसकी आड़ में गरीबों का शोषण करते हैं ट्यूबवेल खनन वाले दोगुना रेट लेते हैं कृपया उसके बारे में भी गंभीरता से चर्चा करें कहीं न कहीं कुछ हमें हायड्रोपोनिक्स...

अध्यक्ष महोदय-- अब कृपया समाप्त कर दें.

श्री ओमप्रकाश सखलेचा-- हायड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स कि जहाँ हम जरूरत से ज्यादा मिट्टी के ऊपर आधारित खेती की बात कर रहे हैं. आप मिट्टी से हट कर भी खेती की बात कर सकते हैं. जिस खेती में न मिट्टी की जरूरत हो, सीधा हायड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स के बारे में भी हमें कुछ योजना बनाना चाहिए और उससे कैसे आगे...

अध्यक्ष महोदय-- श्री गोवर्धन उपाध्याय बोलें.

श्री ओमप्रकाश सखलेचा-- क्योंकि मिट्टी का परीक्षण...

अध्यक्ष महोदय-- अब आप से अनुरोध है कि आप कृपया समाप्त करें.

श्री ओमप्रकाश सखलेचा-- चलो ठीक है, धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय-- श्री गोवर्धन उपाध्याय, कृपया दो मिनट में अपनी बात कहें. इससे अधिक अब समय नहीं है.

श्री गोवर्धन उपाध्याय-- मैं तो डेढ़ मिनट में ही निपटा दूँगा. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विशेष सत्र बुलाया, काँग्रेस के कहने पर, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ. आज प्रदेश के अन्दर किसान दुखी और परेशान है. किसान की आज सोयाबीन की फसल नष्ट हो चुकी है. पिछले साल भी किसान की सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई थी और उसकी बीमा राशि इस साल मिली है, विदिशा जिले में जो बीमा राशि मिली है, कई जगह तो ठीकठाक है लेकिन कई जगह 15 रुपये, 20 रुपये, मैं नहीं समझ पा रहा कि यह किस ढंग से यह 15 और 20 रुपये बीमा राशि में आए हैं, थोड़ा इस पर विचार करने का कष्ट करें. दूसरा, मेरा आप से एक निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की टीम जिले लेवल पर भेजी, गाँव गाँव में गई, मैं उनको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूँगा कि जिला विदिशा का सर्वे अगर लगभग मध्यप्रदेश में कोई सर्वे हुआ होगा, उसमें जिला विदिशा नंबर वन पर रहा होगा. मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज किसान की सोयाबीन में इतनी बुरी हालत हुई जब हम गाँव गाँव में गए अधिकारियों के साथ तो किसान रो रहे थे. मेरे विधान सभा क्षेत्र सिरोंज में लगभग 4 किसानों ने आत्महत्याएँ कीं. इसकी रिपोर्ट प्रशासन को भी दी है. जिन गाँवों के नाम हैं अनूपपुर, ओखली खेड़ा और आपका अलीगंज आदि गाँवों में फाँसी लगाकर किसान लोग मर गए हैं.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया अब समाप्त करें.

श्री गोवर्धन उपाध्याय-- दूसरी बात यह है कि बिजली का बड़ा गहरा संकट है.

अध्यक्ष महोदय—सारी बातें रिपीट हो रही हैं.

श्री गोवर्धन उपाध्याय-- अगर बिजली नहीं होगी तो किसान फिर से दुखी होगा.

अध्यक्ष महोदय-- श्री लाखन सिंह यादव...

श्री गोवर्धन उपाध्याय-- अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ. मेरे सिर्फ 4-5 सुझाव हैं.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया एक एक लाइन में दे दीजिए.

श्री गोवर्धन उपाध्याय-- किसानों की उड़द और सोयाबीन की फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका तत्काल उचित मुआवजा समय सीमा में दिलाया जाए. जिससे लोग जो दिवाली आ रही है....

अध्यक्ष महोदय-- ठीक है, आगे बढ़िए.

श्री गोवर्धन उपाध्याय-- बैंक का ऋण और बिजली का बिल माफ किए जाएँ और फसल बीमा की राशि प्रभावित किसानों को तुरन्त दी जाए. किसानों के पिछले कृषि ऋण ए सी सी की जो वसूली न करने की आगामी फसल खाद बीज वितरण की तत्काल व्यवस्था की जाए.

अध्यक्ष महोदय-- श्री लाखन सिंह यादव...

श्री गोवर्धन उपाध्याय-- बढ़ती हुई महँगाई पर अंकुश लगाया जाए. आज जो गरीब की थाली थी जिसमें दाल आती थी आज उसका दो सौ रुपये भाव हो गया. प्याज बहुत महँगा हो गया.

अध्यक्ष महोदय-- ठीक है. श्री लाखन सिंह यादव, कृपया दो मिनट. उपाध्याय जी, कृपया बैठ जाइये.

श्री गोवर्धन उपाध्याय-- आप सुन ही नहीं रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय-- आपने डेढ़ मिनट का बोला था ज्यादा समय हो गया.

श्री गोवर्धन उपाध्याय-- डेढ़ मिनट कोई बोला जाता है क्या?

अध्यक्ष महोदय-- बैठ जाइये रिपिटिशन हो रहा है. वही बातें कर रहे हैं. जो आप कह रहे हैं यह बात पूरी सदन के रिकार्ड पर आ चुकी है. आपने दूसरों का भाषण सुना नहीं.

श्री लाखन सिंह यादव-- माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री मुकेश नायक-- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक बहुत असहज और अपमानित महसूस कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं, रिपीटिशन हो रहा है. माननीय, आप वरिष्ठ सदस्य हैं. विषय पूरा आ गया है.

श्री मुकेश नायक-- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में विधायक क्या बोलेगा.

अध्यक्ष महोदय-- सारे विषय आ चुके हैं, वही वही बात आ रही है.

श्री मुकेश नायक-- विधान सभा के अन्दर एक मिनट का भाषण !

अध्यक्ष महोदय-- ऐसा ही होता है, 2-2 मिनट 3-3 मिनट में ही बोलते हैं. हम लोगों ने भी बोला है.

श्री मुकेश नायक-- मैं भी इतने बार सदस्य रहा हूँ ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- श्री लाखन सिंह यादव बोलें...(व्यवधान)..

श्री कमलेश्वर पटेल-- जब मौका ही नहीं देना था तो क्यों बुलाया आपने हम लोगों को...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- तो इतनी देर से चर्चा किस पर हो रही है...(व्यवधान)..श्री लाखन सिंह यादव बोलें...(व्यवधान)..

श्री लाखन सिंह यादव-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माइक का रिमोट आपके पास है क्या? जिसको चाहो उसको दबा दो वहाँ से कृपा करके मुझे थोड़ा समय दें...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- नहीं है भाई आप बैठ जाइये.

श्री रामनिवास रावत-- आप निर्देश देकर रोक सकते हैं इस तरह से माइक बंद कराना....

अध्यक्ष महोदय--- अरे, माइक नहीं बंद करा रहे हैं, पहले भी होते थे, आप नये विधायक नहीं हैं , आप कई बार चुनकर आए हैं, क्या ऐसा पहले नहीं होता था**?**

श्री रामनिवास रावत--- नहीं होता था. कभी नहीं होता था.

अध्यक्ष महोदय--- पहले भी होता था. आप लोग बैठ जाइए, लाखन सिंह यादव जी बोलिये.

श्री सुंदरलाल तिवारी--- **(XXX)**.

श्री लाखन सिंह यादव(भितरवार)---माननीय अध्यक्ष महोदय, समूचे प्रदेश का किसान सूखा, ओला,अतिवृष्टि, पाला ,डेंगू, स्वाइन फ्लू की वजह से संकट की घड़ी में है और ऐसी संकट की घड़ी में आपने, आपके दल ने, सदन के नेता ने लीडर ऑफ अपोजीशन के अनुरोध पर जो सत्र बुलाया इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपको और पूरे सदन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय आज के दिन समूचे प्रदेश का किसान सुबह 10.30 बजे से टकटकी लगाए देख रहा है कि आज हाउस में हमारे हित में क्या-क्या निर्णय होने वाले हैं. इस समय मुझसे पूर्व वक्ताओं ने यहाँ अपने अपने क्षेत्र के बारे में किसानों की समस्याओं के बारे में बात रखी और सबका मत एक ही है कि उनके क्षेत्र का जो किसान है उसको ऐसे संकट की घड़ी में सरकार की तरफ से ठीकठाक राहत मिले . उसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय हमारे प्रदेश के किसान पर दो तरह की मार है एक तो प्राकृतिक

मार जो न आपके बस में है न हमारे बस में है ,ईश्वरीय मार है तो उसको हम और आप कोई नहीं रोक सकते हैं. लेकिन जो धरातलीय मार है, जो जमीनी मार है उस मार को तो हम और आप रोक सकते हैं . वह जमीनी मार यह है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में दुबा गांव है वहाँ पर एक बच्चूसिंह परिहार जब अपने खेत पर गया तो उसकी सात बीघा धान की फसल जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पकी हुई खड़ी हुई थी, किन्तु ट्रांसफार्मर फुंकने की वजह से वह फसल को पानी नहीं दे पाया जिसकी वजह से उसकी सात बीघा जमीन में बोई धान की पकी हुई फसल खत्म हो गई . जब उसने खेत पर जाकर देखा और लौटकर आया तो गांव तक नहीं पहुंच पाया और घर पहुंचने के पहले ही उसकी ह्रदयाघात से उसकी मौत हो गई.

अध्यक्ष महोदय—कृपया समाप्त करें.

श्री लाखनसिंह यादव--- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैं शुरु कर रहा हूं मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय--- आप विषय पर आए और सुझाव दें.

श्री लाखनसिंह यादव--- मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा की कि समूचे प्रदेश में 10 परसेंट बिजली का बिल जमा करें तो आपका ट्रांसफार्मर बदल दिया जाएगा. मैं मानता हूं कि आपकी सोच अच्छी है, आप किसानों के हितैषी हैं, आप अपने आपको किसान पुत्र कहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री जी , मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जिन जिन घोषणाओं को करते हैं,पलटकर देखना चाहिए कि वह धरातल में अमल में हैं या नहीं. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 9 साल पहले आपने मेरे क्षेत्र में घोषणाएं की थीं, यह माननीय नरोत्तम मिश्रा जी बैठें हैं, यह भी मेरे क्षेत्र से पहले विधायक रहे हैं.मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिला रहा हूं चूंकि वह प्रदेश में बहुत सारी जगह जाते हैं, आपको याद नहीं रहता. आपने भितरवार को बाईपास की बात की थी.

अध्यक्ष महोदय--- आप विषय पर बोले.

श्री लाखनसिंह यादव-- यह उससे ही लगा हुआ विषय है. आपने मोहना को नगर पंचायत बनाने की बात की, आपने करैया हास्पिटल को उन्नयन की बात की आज तक तीनों घोषणाएं शून्य के संदर्भ में हैं. एक मंत्री जी अभी कह रहे थे कि यह पैसा और बजट इसलिए यहाँ आज पारित करना चाहते हैं कि उन्न किसानों को पैसा बांटेंगे. मुख्यमंत्री जी आप मेरे क्षेत्र में पचौरा गांव में गये थे, वहाँ पर ओलावृष्टि की वजह से गेहूं खत्म हो गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस खेत में उतरे उनका, हेलिकॉप्टर जहाँ उतरा , जहाँ मंच बना.

अध्यक्ष महोदय--- अब समाप्त कर दें. अब हो गया.

श्री लाखनसिंह यादव— जिस किसान के खेत में हेलीकाप्टर को उतारा उसी किसान को आज तक मुआवजा नहीं मिला और मुख्यमंत्री जी आप उस गांव में यह घोषणा करके आये थे कि यह समूचा गांव 100 प्रतिशत ओलावृष्टि से प्रभावित है. मैं जानता हूँ आपकी मंशा अच्छी है, आप किसान हितेषी हैं लेकिन यह भी देखना चाहिए कि हमारे पीछे, हमारी घोषणा के बाद उस पर अमल हो रहा है या नहीं. या तो मैं इसको यूं मानूं कि आपकी मंशा ठीक है और अमल में नहीं आता तो फिर मैं यूं मानूं कि आपके ब्यूरोक्रेट्स आपके हाथ में नहीं हैं और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप इस पर गौर करें.माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध यह है कि ग्वालियर जिले का भितरवार विधानसभा क्षेत्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें अनुसूचित जनजाति के 90 प्रतिशत लोग निवास करते हैं और मेरा अत्तुरोध है कि वह पूरा का पूरा ड्राइ एरिया है, मैं चाहता हूँ कि भितरवार की जो दो तहसीले हैं, भितरवार और गाटीगांव और समूचे जिले को सूखा घोषित करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ और आने वाले समय में वहां चूंकि पानी की विकराल समस्या है. मैं चाहता हूँ कि पीएचई विभाग को निर्देशित करें कि जो ड्राई एरिया हैं वहां हैण्डपम्प खनन कराने की अनुमति प्रदान करें. आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्री जयवर्द्धन सिंह(राघौगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ. इस समय जो पूरे प्रदेश में किसान परेशान हैं उसके मुख्य रुप से दो बिन्दु हैं जिसके कारण आज किसान परेशान ही नहीं त्रस्त है, गुस्से में है. पहला बिन्दु यह है और जिसमें शायद न तो प्रशासन की या कोई भी विधायक या सांसद का उसमें कोई नियंत्रण नहीं है और जो सूखा पड़ा है अनेक जिलों में, कहीं कहीं अतिवृष्टि भी हुई है और उसके कारण जो सोयाबीन की फसल कुछ साल पहले प्रति बीघा 3 या 4 क्विंटल उत्पादन होता था इस बार राघौगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसानों की स्थिति यह है कि एक बीघा पर मुश्किल से 20-30 किलो का उत्पादन हुआ है और इसके कारण जो लागत थी जो किसान ने प्रति बीघा लगायी थी वही वह वसूल नहीं कर पाया है , बहुत घाटे में भी है और इंग्लिस टर्मोनाजी में हम उसको पॉवर्टी ट्रेप के नाम से कहलाते हैं जहां किसान की बचत नहीं हो पाती है और बचत न होने के कारण वह और कर्जे में डूब जाता है, ब्याज और अधिक दर पर उसको सहन करना पड़ता है इसके कारण वह परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता है और आने वाली फसल के लिए भी वह तैयार नहीं हो पाता है. इसके कारण कुछ दिन पहले राजगढ़ जिले में ब्यावरा तहसील के गंगाहोनी गांव है वहां पर लोढ़ा समाज के किसान ने आत्महत्या की थी और उसके बाद जब उसके बच्चों ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया था तो पुलिस ने मृतक के बच्चों पर भी मुकदमा दर्ज किया है. मैं मानता हूँ कि यह बहुत ही एक गंभीर मामला है इस पर जरुर कार्यवाही होना चाहिए. माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरा दूसरा बिन्दु था जिसके कारण किसान परेशान है वह जो मुद्दे हैं वह पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में हैं वह यह बिन्दु हैं जिनके बारे में मुख्यमंत्री जी पहले भी घोषणा कर चुके हैं, जब बजट पेश हुआ था उसके बाद सदन में हम सब को बताया गया था कि पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिलेगी, सिंचाई के लिए पर्याप्त 12 घंटे 3 फेज में बिजली

मिलेगी मगर जो वास्तविक स्थिति है कि एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर 24 घंटे बिजली मिल रही हो, हर गांव में अधिक से अधिक 4 या 6 घंटे बिजली मिल रही है और उसके साथ साथ एक और बिन्दु है और वह सोसाइटीज का है. माननीय अध्यक्ष महोदय, हर किसान ओवरड्यू है जो उसने सोसाइटी से पैसा लिया था वह वापस नहीं दे पा रहा है. इसके कारण खाद की मांग उसके सामने आ रही है उसको खाद नहीं मिल पा रही है इसलिए उसका जो भी ड्यू है वह स्थगित होना चाहिए और इसके साथ ही साथ अभी जो सर्वे होना है जिसके द्वारा मुआवजा मिलेगा, स्थिति ऐसी है कि एक-एक पटवारी के पास 6-6 हल्के हैं और जैसे शिक्षकों ने, सरपंचों ने और जिला पंचायत के अध्यक्षों ने धरना किया था वैसे ही पटवारी भी धरना कर रहे हैं.

श्री हरदीप सिंह डंग (सुवासरा) – माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद, बोलने का मौका दिया. मेरा सीधा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो सूखाग्रस्त तहसीलें घोषित की गई हैं उसका आधार क्या था. क्या सूखाग्रस्त घोषित करने का आधार उत्पादन था या बारिश थी. हमारे मंदसौर जिले में चार विधान सभा क्षेत्र हैं और नीमच जिले में तीन विधान सभाएं हैं मेरा मानना है कि ये सातों विधान सभा क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित होने चाहिए. आपने मल्हारगढ़ विधान सभा को सूखाग्रस्त घोषित किया है उसके लिए धन्यवाद. परंतु मेरा मानना है कि अगर उत्पादन के मान से सूखाग्रस्त घोषित किया गया है तो सुवासरा विधान सभा में सीतामऊ तहसील जहां प्रति हेक्टेयर 4 क्विंटल 8 किलोग्राम सोयाबीन उत्पादित हुई तो उसको आपने सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया और मल्हारगढ़ में जहां 5 क्विंटल 40 किलोग्राम सोयाबीन का उत्पादन हुआ है तो इसको सूखाग्रस्त घोषित किया है. मल्हारगढ़ को सूखाग्रस्त घोषित किया है उसका स्वागत है वे भी हमारे किसान हैं उनको फायदा मिले लेकिन जहां प्रति हेक्टेयर 4 क्विंटल 8 किलोग्राम सोयाबीन उत्पादित हुई है, यह कलेक्टर के यहां का रिकार्ड है, तो आप उसको सूखाग्रस्त घोषित नहीं कर रहे हैं. मेरा मानना है कि जो प्रदेश में सूखाग्रस्त तहसीलें घोषित हुई हैं तो ये सर्वे के हिसाब से हुई हैं या रिकमंड के हिसाब से हुई हैं, इसको थोड़ा क्लियर करें. मेरा मानना है कि सुवासरा विधान सभा में चारों तहसीलें सुवासरा, श्यामगढ़, गरोठ और क्यामपुर सूखाग्रस्त घोषित होना चाहिए. इसके अलावा अगर सूखाग्रस्त घोषित करने का आधार वर्षा है तो जो एक दिन में बारिश देखी जाती है दिन और रात करके और उसे आप मीटर से नापते हैं तो वर्षा ज्यादा होती है और चार महीने तक अगर एक बूंद भी पानी नहीं गिरता है तो वह बारिश हम नापते हैं जब दो दिन बारिश हुई थी, मेरा मानना है कि दो दिन की बारिश को न देखते हुए चार महीने तक एक बूंद पानी न गिरा हो, उसको पैमाना बनाया जाए. दूसरी बात यह है कि आपने 4 महीने के जो बिल स्थाई कनेक्शन के लिए हैं जिसके दो महीने में अगर पानी खत्म हो जाता है उसको दो महीने की राशि वापिस की जाए और जो ट्रांसफार्मर किसानों के जल जाते हैं वे खुद ट्रांसफार्मर को गाड़ी से लाते हैं. चांपाखेड़ी में एक किसान 8 बार अपनी गाड़ी से ट्रांसफार्मर लाया और ले गया जबकि वह एमपीइबी का काम था किंतु खुद किसान एक हजार रुपये एक बार के देता है और बार-बार

ट्रांसफार्मर ले जाता है. शायद हो सकता है कि एमपीइबी वाले अपने खाते में भी डाल देते हैं और रुपये किसान के लगते हैं इसमें भी सुधार किया जाना चाहिए. अभी कहा कि 10 प्रतिशत लाइट का बिल कर दिया गया है उसके पहले अगर किसी का 25 हजार रुपये का बिल बाकी होता था, अगर उसमें 10 उपभोक्ता हैं और किसी एक का अगर बिल बाकी रह गया तो 25 हजार पूरे जमा करोगे तो ही आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा तो भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नियम बनाया जाए कि जिन 9 उपभोक्ताओं के बिल जमा हैं तो उन्हें लाइट दी जाए और उन्हें एक उपभोक्ता के पीछे नहीं रोकना चाहिए. भगौर में एक बड़ी नदी चंबल नदी निकलती है उसकी पाल टूटी, वह पानी से पूरा डूब चुका था वहां पर 223 परिवारों को नुकसान हुआ और मात्र 9 लाख रुपये मुआवजा दिया गया है जबकि मेरा मानना है कि वहां पर 90 लाख भी अगर दिए जाएं तो कम है. हमारे सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में एक चंबल नदी निकलती है जो पूरे विधान सभा क्षेत्र को कवर करती है, हम वहां स्टाप डैम बना रहे हैं, वित्त मंत्री जी थोड़ा ध्यान देंगे, लाखों रुपयों के स्टाप डैम बना रहे हैं और हमारे पास पानी है वहां पर चंबल नदी का, केवल वहां पर अगर लाइन बिछा दें तो आपके करोड़ों रुपये बच जाएंगे और किसानों को पानी मिल जाएगा. मेरा निवेदन है कि इसे आप गंभीरता से लें. धन्यवाद.

श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना)(मऊगंज)—अध्यक्ष महोदय, आज सूखे पर चर्चा के लिए सदन बुलाया गया है , सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा लगातार चर्चा हो रही है. लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सत्तापक्ष द्वारा मुख्यमंत्री को सिर्फ संवेदनशील घोषित करने के लिए यह सत्र बुलाया गया है. अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटासा उदाहरण देना चाहता हूं. रीवा जिले में भी सूखा पड़ा है. मैं समझता हूं कि पूरी तरह से जितना रीवा जिले में सूखा पड़ा है उतना कहीं नहीं पड़ा है. पूरे प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं. उसी तरह नईगढ़ी में एक किसान की आत्महत्या हुई . माननीय मुख्यमत्री जी बैठे हुए हैं और उनके सांसद वहां पर जाते हैं और आकर के आनन फानन में पत्रकार वार्ता करते हैं और ये बोलते हैं कि यह जो किसान की आत्महत्या हुई है वह विक्षिप्त था. तो मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र था. अगर प्रमाण पत्र था तो कोई बात नहीं. अगर प्रमाण पत्र नहीं था तो उन सांसद के ऊपर अपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए. अगर इस बात पर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर अपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए. अगर इतनी संवेदनशीलता है , आज भी बिजली में अवैध बिल भेजे जा रहे हैं और किसानों को नोटिस भेजे जा रहे हैं . अगर आपमें संवेदनशीलता है तो कम से कम इस समय बिजली के बिल न भेजे जायें और जो एक बत्ती कनेक्शन किसानों को दिया जा रहा था ,कम से कम उसमें किसानों को जेल न भेजा जाय. इसलिए कि कुंवर अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री थे ,उन्होंने एक बत्ती कनेक्शन दिया था. अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो थोड़ा बहुत मुआवजा जाने वाला है या किसानों के हित में जायेगा, तो बहुत सारे पट्टेदार ऐसे हैं, जिनके पट्टे नहीं है ,मुस्तरका में हैं किसान . तो उनको मुआवजा नहीं मिल पायेगा. तो उनके लिए भी एक ठोस कदम होना चाहिए. दूसरी बात, इसी तरह फसल बीमा की चर्चा

होनी चाहिए. लेकिन आपकी सरकार,आपके नेता,आपके अधिकारी सिर्फ जन धन बीमा योजना की चर्चा कर रहे हैं जबकि इस समय जनधन योजना रोक कर के फसल बीमा योजना पर चर्चा करना चाहिए. आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री यादवेन्द्र सिंह (नागौद)—अध्यक्ष महोदय, आपने सत्र बुलाया उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन मुझे या मेरे यहां के किसानों को माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास नहीं है क्योंकि पिछले मार्च में मेरे यहां जाटकी गांव में ओला पड़ा था. उसके लिए 8 लाख रूपये की सहायता स्वीकृत हुई. मेरे पास तहसीलदार का प्रमाण है. मगर आज तक उन किसानों को पैसा नहीं मिला और दूसरा सूखा पड़ गया. आपने यह सत्र बुलाया है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि किसानों को इससे कोई राहत मिलेगी , किसान को विश्वास नहीं है. पिछली बार जब अतिवृष्टि हुई ,तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसानों चिन्ता न करो आपका गेहूं खलिहान में जम गया है, नुकसान हुआ है ,मैं आपको राहत दूंगा लेकिन किसान अभी भी उसका इन्तजार कर रहे हैं कि कब उनके खाते में राहत की राशि आएगी. ये हाल हैं आपकी सरकार के . जब आपकी बिजली, आपकी एक साल से पेंशन ,आपके खलिहानों में आग लगी,मकानों में आग लगी. आज दो साल से इन लोगों को पैसा नहीं पहुंचा. परिवार सहायता तक का नहीं गया जो बी.पी.एल.कार्ड धारी को मिलता है. तो मैं कैसे मान लूं कि आपकी सरकार किसानों और गरीबों को मुआवजा देगी. मेरे पास सब चीजों का प्रमाण है , जब पिछले साल के 8 लाख मुख्यमंत्री जी ने दिये, तब मैने प्रमुख सचिव जी को पत्र दिया,कलेक्टर को दो बार दिया ,जब आपके पास ,शासन के पास पैसा नहीं है तो कैसे हो सकता है.,क्यों स्वीकृत हुआ. पिछले साल की मार्च की बात कर रहा हूं. जनसंपर्क का पैसा मिलना था लेकिन 31 तारीख को आपका सर्वर ही खराब हो गया. हमने 5 लाख लोक निर्माण विभाग को दिये ,आज तक पैसा नहीं गया. मुख्यमंत्री जी जो विधायक निधि आप 60-70 लाख क्या दे रहे हैं उसको बन्द कर दें. मुख्यमंत्रीजी विधायक निधि 60-70 लाख रुपये दे रहे हैं. आप उसको बंद कर दें.(XXX) . सरपंच चढ़ रहे हैं. कहां से काम होगा.

अध्यक्ष महोदय—इस शब्द को विलोपित करें. कृपया बैठ जाईये.

श्री यादवेन्द्र सिंह—2 मिनट का टाईम दीजिए. सुनेंगे नहीं ? मैं यह निवेदन कर रहा था कि सतना जिला पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पानी की समस्या है. पानी की व्यवस्था तुरंत करायी जाये. टेंकर भेजें पानी की व्यवस्था करें. किसानों को मुआवजा दें. पहले 1978-80 तक किसानों को तकाबी दी गई. आप तकाबी की व्यवस्था करें ताकि किसान आगे अपनी फसल बो सकें. आपने सदन का सत्र बुलाया है. सरकार का पैसा खर्च हुआ है वह अलग बात है.

अध्यक्ष महोदय—कृपया बैठ जाईये.

श्री यादवेन्द्र सिंह—हम लोग तो घर मैं बैठे थे आप बुला लिये तो आ गये. ना बुलाते तो काहे को आते बैठे ही तो थे वहां. क्षेत्र में घूम रहे थे, दुर्दशा देख रहे थे. धन्यवाद.

श्री प्रताप सिंह (जबेरा)—अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में 3 साल से सूखा,ओला पड़ा है. मेरे दमोह जिले की चारों तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित हुई है इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं. लेकिन जो किसान 4 HP का टीपी कनेक्शन ले रहे थे उसको मुख्यमंत्रीजी ने,सरकार ने 2 HP का किया लेकिन वह आदेश अभी तक पहुंचे नहीं हैं.

अध्यक्षजी, इसी प्रकार ट्रांसफार्मर में यदि 10 प्रतिशत राशि जमा होती है तो ट्रांसफार्मर रख जायेंगे लेकिन उसके भी आदेश कल तक पहुंचे नहीं है. मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि इस सूखे की स्थिति में जो आपने घोषणा की है, उस पर तत्काल अमल हो, ऐसा मेरा अनुरोध है.

अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में जब उप चुनाव हुआ था. आदरणीय मुख्यमंत्रीजी जबेरा गये थे और वहां पर पालना जलाशय के बारे में घोषणा की थी कि वहां निर्माण किया जायेगा लेकिन आज तक पालना जलाशय प्रक्रिया में नहीं है. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यदि उस क्षेत्र में वह जलाशय हो जायेगा तो सूखे की जब जब स्थिति आती है तो वहां के हजारों किसानों का आप भला करेंगे और वहां की जमीन सिंचित हो जायेगी.

अध्यक्षजी, जो ट्रांसफार्मर हैं वह फेल निकल रहे हैं. मिशन वाला ट्रांसफार्मर वहां पहुंचता है और दूसरे दिन लगाते हैं तो पता चलता है कि वह जला हुआ है. मैं चाहूंगा कि ट्रांसफार्मर की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाये जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहां पर रोजगार के अवसर भी दिलाये जाये. मनरेगा के तहत मजदूरी भी तत्काल दी जाये.धन्यवाद.

श्री मधु भगत(परसवाडा)—अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद.

अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्रीजी से कुछ सवाल भी करना चाह रहा था लेकिन समय नहीं है. मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं. मैं बालाघाट के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आता हूं. हमारा जो बेल्ट है वह 80 प्रतिशत

आदिवासी और नक्सलाईट वाला है. उसमें 28 पंचायतों में 70 से 80 गांव हैं. उन 80 गांवों की बालाघाट की जो दूरी है वह 50 किलोमीटर है. वहां ऊंचा एरिया होने से पानी का पूरी तरह से संग्रहण नहीं हो पाता लेकिन वह ही 80 गांव जिले की प्यास बुझाता है. वहां धोटी बांध है जो बालाघाट जिले को सिंचित करता है लेकिन उन 80 गांव में पानी नहीं पहुंचता. वहां तालाब में पानी नहीं रुकता. मुख्यमंत्रीजी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता. मंत्रीजी और जनप्रतिनिधि वहां पर बार बार जाते हैं और कहते हैं कि हम बहुत अच्छी सरकार देंगे, हम बहुत अच्छी विकास की योजनाएं देंगे लेकिन कोई उस बांध की बात नहीं करता. इस बांध का काम लगभग 80 प्रतिशत पिछले 10-15 सालों से हो चुका है. हमने पिछले 2 सालों में जो प्रयास किया उसमें हमारे सामने जो दिक्कत आयी है वह वन विभाग की है कि उन्होंने सवा छः करोड़ रुपये की रिकवरी इरीगेशन डिपार्टमेंट पर निकाली है. सरकार आपकी है, विभाग आपके हैं. पद आपके हैं. सातनारी बांध आप वहां पर किसी भी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी बनवा दें तो 80 गांव के लोग जो अपने धान के लिए पानी की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे. मैं एक दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि वहां पर

अभी रेल्वे का ट्रेक बंद होने वाला है. बालाघाट से लेकर नैनपुर तक के 9 स्टेशन मेरे यहां के आते हैं. वहां पर स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है. आज की स्थिति में जो ट्रेन का भाड़ा है और जो बस का भाड़ा है उसमें 80 प्रतिशत का अंतर है लेकिन हमने आंदोलन किया तो कलेक्टर साहब जी ने वहां पर 50 प्रतिशत पर स्टूडेंट पास की बात कर दी. हम चाहते हैं कि वहां पर रेल्वे का जो टिकिट होता है उ स टिकिट पर हमारे किसानों को जाने के लिए और हमारे बच्चों को पास मिले जिसमें सुविधा पूरी मिले . मैं यहां परकिसानों के सूखे के विषय पर ही बोल रहा हूं मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर एक तहसीलदार हैं उस तहसीलदार के चलते हमारी पूरी स्थिति चरमरा गई है. पटवारी आरआई कहां हैं किस दिशा में काम कर रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आता है, वहां पर जाकर देखें तो किसान कतार लगाकर बैठे रहते हैं. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि एक हमारी उप तहसील हैं लांगटा की उसको अगर आप तहसील घोषित कर देते हैं क्योंकि वह मापदण्ड भी पूरे करती है. यदि उसको तहसील बनाते हैं तो वहां पर व्यवस्था पूरी तरह से बन सकेगी.

श्री अजय सिंह (चुरहट) – माननीय अध्यक्ष महोदय मैं काफी देर से सुन रहा था कि आप काफी विधायकों को मिनट के अंदर ही समाप्त करने की बात कर रहे थे आखिरी दोविधायकों को आपने कहा कि आप विषय के बाहर बोल रहे हैं. मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि विधान सभा सचिवालय से हम लोगों को जो पत्र मिला है वह किस विषय के लिए मिला है. मात्र एक विषय था सूखे पर चर्चा तो यह पतली गली से अनुपूरक बजट कहां से आ गया. यदि सरकार सही में संवेदनशील होती मुख्यमंत्री जी , सही रूप से सूखे पर चर्चा करना चाहिए थी यह विनियोग और अनुपूरक बीच में कहां से आ गया है.

श्री कैलाश विजयवर्गीय – अध्यक्ष महोदय इस पर आपके निर्देश भी हो गये हैं सुबह व्यवस्था का प्रश्न उठा था. उसके बाद में इस विषय को उठाना मैं समझता हूं कि उचित नहीं हैं.

श्री रामनिवास रावत – निर्देश हो जाने से बात समाप्त नहीं हो जाती है.

श्री अजय सिंह – निर्देश होने से बात समाप्त नहीं होती है क्या सरकार गंभीर है.

श्री विश्वास सारंग – यह चर्चा शुरू होने के 4 घंटे के बाद में आये हैं यह इतने संवेदनशील हैं.

डॉ नरोत्तम मिश्र – सुबह से सभी लोग सूखेक पर ही बोल रहे हैं विनियोग विधेयक पर तो एक भी नहीं बोला है.

श्री मुकेश नायक – अध्यक्ष महोदय आपने एक दिन का सत्र बुलाया है इसको 2 या 3 दिन का नहीं बुला सकते थे. एक तो एक दिन का सत्र बुलाया है उसमें केवल 3 घंटे की चर्चा है. एक साल में 3 घंटे की चर्चा विधान सभा में, आप अगर इतना संवेदनशील हैं उदार हैं सहिष्णु हैं जनोनमुखी हैं तो कृपया करके आपको समय का ठीक से वितरण करना था. पक्ष और विपक्ष को समय का आवंटन ठीक तरह से करना था और सदन अगर एक दिन के लिए और बुला लेते तो क्या लोकतंत्र की हत्या हो जाती.

श्री कैलाश विजयवर्गीय—अगली बार से आप रायबहादुर से राय लेकर सदन चलाने की बात करना.

अध्यक्ष महोदय – समय का आवंटन आप देख लेना कि किस दल को कितना समय दिया गया है और किस दल ने कितना समय लिया है.

श्री मुकेश नायक – 10.30 बजे विधान सभा शुरू होती है आप 9.45 पर कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाते हैं, समय आवंटन के लिए कभी ऐसा मध्यप्रदेश की विधान सभा में पहले नहीं होता था.

अध्यक्ष महोदय – आप यह परंपराएं मत बताइये. हम लोग भी इस विधान सभा के सदस्य वर्षों रहे हैं माननीय नायक जी.

श्री मुकेश नायक – जब सभी सदस्य चिंतित हैं तो ज्यादा समय दे देते तो यह कौन सा नियम के विरूद्ध होता कौन सा परंपरा के विरूद्ध है कौन सा लोकतंत्र के विरूद्ध है....(व्यवधान).. यह ही तो हमें दुख हो रहा है, आप इतने सम्मानित सदस्य रहे हैं, नियम और प्रक्रिया को समझते हैं सर्वोच्च सत्ता पर विराजमान हैं. हम सब लोगों के संरक्षक हैं उसके बाद में इ स तरह से हो रहा है विधान सभा में.

श्री कैलाश विजयवर्गीय-- अध्यक्ष महोदय, आपने कार्यमंत्रणा समिति में दो घंटे का समय निर्धारित किया था, यह आपकी उदारता है, मेरा ख्याल है 5 घंटे हो गये, इसके लिये सदन को धन्यवाद देना चाहिये आपको अध्यक्ष महोदय कि दो घंटे के 7 घंटे हो गये अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी उदारता क्या हो सकती है ।

श्री मुकेश नायक-- आगे से आप लोग इतना तकलीफ क्यों उठाते हैं, हम लोग घर से भाषण लिखकर भिजवा दिया करेंगे, छपवा दिया करो किताब में, हम इससे सहमत हैं ।

अध्यक्ष महोदय—आप बैठ जायें मुकेश नायक जी ।

श्री अजय सिंह (चुरहट)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, कैलाश भाई ने उदारता की बात कही ।

अध्यक्ष महोदय-- यहां कोई इस पर डिवेट नहीं हो रही है उन्होंने विषय इसलिये लिया कि आपने जो चर्चा की वह सुबह हो चुकी थी, आप नहीं थे उस समय ।

श्री अजय सिंह-- हम लोगों को पत्र मिला विधानसभा में उपस्थित होने का, उसमें सिर्फ सूखे पर चर्चा होना थी, आपने कहा उदारता की, पूरे दिन दो घंटे की जगह पूरे दिन हो गई, बहुत-बहुत धन्यवाद । लेकिन अध्यक्ष महोदय में आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इसी छोटे से बिंदू में यह पूरे सरकार की सोच छिपी हुई है । माननीय महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, जब ओला पड़ता है तो मुख्यमंत्री के छाती में पीढ़ा होती है, जब अतिवृष्टि होती है तो भी मुख्यमंत्री दुखी होते हैं, किसान के बेटे हैं और सही में उनको दुख होता है, लेकिन उस किसान के पास पहुंच क्या रहा है, इस पर थोड़ा चिंतन करिये । 2011 में बहुत सारी आत्महत्यायें हुई थीं, आपको याद होगा आपने एक मानव अधिकार आयोग की एक कमेटी बनी थी, 2011 की रिपोर्ट आज तक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है । आत्महत्या के उपर, किसानों की आत्महत्या के उपर वह रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मानव अधिकार को सौंपा था, आप ही के सदस्य लोग थे । दिक्कत यह है कि मुख्यमंत्री चाहते जरूर सब ठीक होना चाहिये, लेकिन नीचे के बात दूसरी जा रही है ।

श्री रामनिवास रावत-- सोचते हैं ठीक होना चाहिये, चाहते कुछ नहीं है ।

श्री अजय सिंह-- मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, चार दिन पहले मैं अपनी विधानसभा के आखिरी गांव में बैठकर आ रहा था, गमी के समय किसी के घर गया था, वह भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, कोआपरेटिव सोसायटी के अध्यक्ष हैं, उनके बड़े भाई का देहांत हो गया था, कह रहे थे भइया अपना कही थें कि सरकार सूखे पर चर्चा होवे वाली है, लेकिन कलेक्टर हमें डंडा डाले है कि 10 लाख रूपये जमा करो, माननीय अध्यक्ष महोदय यह है अंतर । आप कहते हैं कि बिजली का बिल नहीं लिया जायेगा, लेकिन जिस तरह से वसूली हो रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सोचना पड़ेगा । सोसायटी, बिजली आज हा हाकार मचा हुआ है, प्राकृतिक आपदा जो आई है वह किसी पार्टी को देखकर नहीं आई है । मैं बड़े दुख के साथ यह कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग आपस में यह बातें कर रहे थे कि वह भाजपा के है वह कांग्रेस के हैं, यह बात नहीं होना चाहिये । किसी के खेत में हुआ वह कौन सी पार्टी का है उससे क्या लेना-देना । लेकिन उस दुख के समय उसको कुछ राहत मिल जाये यह हमारी चिंता होनी चाहिये, जनप्रतिनिधि के नाते । इस तरह से नहीं होना चाहिये कि जिस तरह से मुआवजा पिछली दफा मिला । मैं अपने जिले का एक उदाहरण देता हूं मेरे खेत में एक एकड़ तो क्या एक डेसीमिल फसल नहीं थी, मेरे यहां यूकेलिप्टस के पेड़ लगे थे, लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष था तो एसडीएम साहब 24 हजार रूपये का चेक देने आये आपदा के लिये । मैंने कहां मेरे पूरे खेत में जाकर देख लो, मेरे, मेरे भाई के, मेरी मां के किसी खेत में दलहन लगी हो उसकी आपदा दे रहे हो आप । इस तरह से न हो माननीय मुख्यमंत्री जी । यह मुआवजा जो दिया जाये जितनी भी राशि तय हो वह उचित उस किसान को मिले जिसके घर पर आज खाने को नहीं है, मौत का मातम है । आपने मुझे टोका नहीं इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं. नहीं तो अभी तक मैं सोच रहा था कि 2 मिनिट हो गये ?

अध्यक्ष महोदय—आप कितना समय लेंगे ?

श्री अजय सिंह – अध्यक्ष महोदय बस दो मिनिट. माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत ही संवेदनशील हैं लेकिन निचले स्तर पर मामला थोड़ा संवेदनहीन है आप उसमें थोड़ा अंकुश लगायें. पटवारी सर्वे करने कहीं नहीं जा रहा है, वैसे भी सर्वे का समय तो अब निकल चुका है खेत में कुछ बचा नहीं है तो सर्वे कैसे होगा किस चीज का होगा, अब कौन सी आपदा वह पटवारी तय करेगा. लेकिन जो भी हो पटवारी वहां पर जाये तो, लेकिन उसके बारे में कहीं कोई बात चीत नहीं है. आप चाहे मंथन करा लें,चाहे कुछ करा लें, अधिकारियों को आपने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भेजा तो कोई अधिकारी मढई जा रहा है कोई कहीं जाये इस तरह से यदि अधिकारी जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को उस पर विचार करना चाहिये. आज की चर्चा का बिंदू यही है. माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रैल 2008, फरवरी, 2010 और 6 मार्च 2014 में केन्द्र सरकार से ज्यादा राशि मिले इसलिये हड़ताल में बैठे थे . मैं आप उनसे पूछना चाहता हूं कि आज हम तैयार है पूरी कांग्रेस तैयार है, सब विधायक तैयार हैं आप बैठिये हड़ताल में, आमरण अनशन करें केन्द्र सरकार पैसा दे

20 हजार करोड़ 30 हजार करोड़ जो आपको चाहिये आप बैठिये हम आपके साथ में बैठने को तैयार हैं. आप लगाईये तो तंबू हम तैयार हैं.

श्री कैलाश विजयवर्गीय –मुख्यमंत्री जी इनके चक्कर में नहीं आना यह फुर्सत में हैं. (हंसी)

श्री अजय सिंह --माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी तरह की दिक्कत मुख्यमंत्री जी को नहीं होनी चाहिये क्योंकि संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं.(XXX).

श्री मुकेश नायक – अरे माननीय मुख्यमंत्री जी आप अनशन पर बैठिये तो मोदी जी इंतजार कर रहे हैं, आप हड़ताल पर बैठिये तो.

अध्यक्ष महोदय—कृपया समाप्त करें. नायक जी बैठ जायें.

श्री अजय सिंह – अध्यक्ष महोदय, यदि सही में गंभीरता से बात करें तो..

श्री शंकर लाल तिवारी—मालूम है आप कितने गंभीर हैं.

श्री अजय सिंह – तिवारी जी कृपया बैठिये . जितना गंभीर आप हैं हम आपको बाद में बता देंगे. अध्यक्ष महोदय, यह हंसी मजाक की बात नहीं है. यह प्रदेश के किसानों की दु:ख और पीड़ा की बात है यदि मुख्यमंत्री जी उस समय बैठे थे तो आज भी बैठने को तैयार होना चाहिये और हम लोग उनके साथ में बैठेंगे. आप हम लोगों को दिल्ली ले चलिये हम लोग दिल्ली चलने के लिये तैयार हैं. जंतर मंतर में बैठना हो तो वहां बैठने को हम तैयार हैं. लेकिन यदि सरकार की वित्तीय हालत नहीं है और केन्द्र सरकार से ही आपदा राशि मिलनी है तो उसके लिये हम आपके लिये किसानों के हित के लिये हर समय तैयार हैं. लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब आपदा होती है तो राज्य सरकारें उसके ऊपर डोजियर निकालती हैं , लेकिन पिछले पांच साल से वह डोजियर नहीं निकला है, और बिना डोजियर के केन्द्र सरकार सुनती भी नहीं है इसलिये आप थोड़ा उसका भी दिखवा लीजिये कि क्या हालत है.

अध्यक्ष महोदय—कृपया समाप्त करें.

श्री अजय सिंह – अध्यक्ष महोदय, फिर से आपने टोक दिया. अध्यक्ष महोदय आप इस सत्र में कोई निर्णायक रूप ले यह हमारी सबकी मंशा है चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, चाहे वह कांग्रेस का हो चाहे अन्य किसी पार्टी का हो, 10-15 विधायकों को छोड़कर के सभी ग्रामीण अंचल से चुनकर के आते हैं . अपनी अपनी पीड़ा वह जानते हैं कि क्षेत्र में किसानों की क्या स्थिति है. लेकिन जिसने आत्महत्या की उसके परिवार वाले के पास हम लोग सिर्फ दो मिनिट जाकर के आंसू पोंछ कर आ जायें उससे काम चलने वाला नहीं है, उसके लिये सरकार को कुछ देना पडेगा जिससे उसको राहत मिल सके . ऐसा न हो कि कोई सांसद चला जाये जैसा सुखेन्द्र सिंह बन्ना ने कहा कि सांसद महोदय ने कहा कि शिव विक्षिप्त था, कोई कह दे कि प्यार संबंध था इसलिये उसने आत्म हत्या की. अध्यक्ष महोदय, इसको भी गंभीरता से लें कि जो आत्महत्या किसान ने की है उसके बारे में हमारे हिन्दु शास्त्रों में लिखा है कि मरने के बाद में टिप्पणी नहीं करना चाहिये, कृपा करके इस बात का ध्यान रखें. माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जो सत्र बुलाया

इसकी सार्थकता सही तभी निकलेगी जब वह किसान , और अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकार की तरफ से राहत राशि मिलेगी. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया धन्यवाद.

श्री कमलेश्वर पटेल – अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है.

अध्यक्ष महोदय – अब कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं. प्रतिपक्ष के नेता जी बोलें. इसमें क्या पाइंट ऑफ आर्डर है.

श्री कमलेश्वर पटेल – अध्यक्ष महोदय, मोदी जी मध्यप्रदेश सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, उनकी मुख्यमंत्री जी से नाराजगी हो सकती है, प्रधानमंत्री जी की मध्यप्रदेश के किसानों से तो नाराजगी नहीं हो सकती. कम से कम मध्यप्रदेश के ऐसे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे निवेदन करें कि वे मोदी जी से बात करें, तो हो सकता है कि मदद मिल जाय.

श्री दिनेश राय (सिवनी) -- अध्यक्ष महोदय, आज मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई एवं धन्यवाद दूंगा कि एक दिवसीय विशेष सत्र आपने आमंत्रित किया है, जिससे हमारे किसानों की विशेष समस्या है, आज मुआवजा राशि हर हालत में निवेदन करता हूं कि दीपावली के पूर्व अगर उनको भुगतान हो जाय, जिससे उन्हें आने वाली फसल और बड़े त्यौहार जो हमारे होली, दीपावली, रक्षा बंधन , ईद चार त्यौहार ऐसे हैं, जिनमें हर व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है, ऐसा आपसे निवेदन है. मैं पुनः मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि जो हमारे यहां माछागोरा बांध और पेंच की जो नहर आ रही है, जो 10 हजार हेक्टेयर को सिंचित करने के लिये अभी जो आपने स्वीकृति प्रदान की है, उसके लिये मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं. यहां पर बहुत बातें आ चुकी हैं. मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में सिंचाई के लिये कोई भी बड़ा तालाब नहीं है और न कोई हमारे क्षेत्र में नहर है. हमारे यहां कुआं और नल से ही खेतों में सिंचाई होती है और उसी से ही पेयजल की व्यवस्था होती है. हमारे यहां अतिवृष्टि, ओलावृष्टि पूर्व में हुई रबी की फसल में, इस खरीफ की फसल में हमारे यहां बारिश न होने की वजह से वर्तमान में एक भी तालाब पूरा भरा हुआ नहीं है. कुओं में भी पानी नहीं है. वर्तमान में यह स्थिति है कि हमारे 90 प्रतिशत हैंडपम्प सूख चुके हैं. कुआं भी सूख चुके हैं. कैसे हम यह गर्मी का मौसम निकाल पायेंगे. मैं चाहता हूं कि सूखे के साथ साथ, किसानों के साथ साथ आपसे निवेदन है कि हमारे यहां पेयजल की व्यवस्था जरुर करायें. हमारे यहां कहीं न कहीं से पानी का परिवहन करना पड़ेगा और परिहन मोल या किराये से न कराते हुए टेंकर की विशेष रुप से व्यवस्था करवा दें, पूरी पंचायती स्तर पर, जिससे इस पानी की समस्या से हम निपट सकते हैं. जैसा कि अभी कहा जा रहा था कि बिजली का बिल, बैंकों की वसूली और क्षेत्र में सिंचाई में जो भी वसूली की जा रही है, वह वास्तव में पूर्णतः बंद नहीं हुई है. अभी भी किसानों से, जो अनपढ़ किसान हैं, उनसे वसूला जा रहा है. अभी हमारे क्षेत्र में एक साहूकारी पद्धति, विशेषकर सिवनी प्रॉपर शहर में एक इतना जमकर झगड़ हुआ है. अभी एक क्रेशर संचालक भी है और किसान भी है. यह नहीं कह सकते कि उसने कृषि की वजह से आत्महत्या की है, फांसी लगाई है. उसको साहूकारों के चार नाम आये हुए हैं, जो प्रायवेट साहूकार हैं. उन्होंने उससे पिछली 28 तारीख को, कल

उसकी तेरहवीं है. 28 तारीख को पांच एकड़ की रजिस्ट्री की लिखा पढ़ी करवा ली थी, उसने 24 तारीख को फांसी लगा ली. मेरा निवेदन है कि बैंकों में, बिजली में, इसके अलावा भी साहूकारों के ऊपर भी आप सरकार की तरफ से डंडा पटकवाइये , तब जाकर मैं समझूंगा कि किसानों के हित में काम हो रहा है. सरकार से मेरा निवेदन है कि सभी प्रकार की जो ब्याज की दरें लगाई गई हैं, वह पूर्णतः इस वर्ष माफ कर दी जायें. मेरा एक निवेदन और है. मेरे क्षेत्र में एक सामूहिक पेयजल व्यवस्था हमारे यहां होने जा रही थी करीब 300 गांव के लिये, जब हमारे यहां कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर भीमगढ़ डेम से आना है, तो आज इस सूखे को देखते हुए उसका कार्य पूर्ण करा दिया जाय, तो ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या खतम हो जायेगी, धन्यवाद.

श्रीमती ममता मीना (चाचौड़ा) – अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के द्वारा बार-बार हमारे मुख्यमंत्री जी को कहा जाता है कि ये अतिसंवेदनशील सिद्ध होने के लिये यह बार-बार विधायकों से कहलवाया जाता है, जबकि किसी भी क्षेत्र के किसान से जाकर पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी बहुत अतिसंवेदनशील हैं, किसानों के हित में बात करते हैं, किसानों के लिये हमेशा वे चिंता करते हैं. किसानों के लिये हमेशा चिन्ता करते हैं, किसानों के हित में नीति बनाते हैं. खेती को लाभ का धन्धा कैसे बनाया जाये उसके लिये दिन-रात बैठकर के चिन्ता करते हैं. आपने देखा होगा पिछले महीने अक्टूबर माह में सभी हमारे आई.ए.एस., आई.पी.एस. लोगों को तीन दिन में पूरे क्षेत्र का दौरा करवाया इसके लिये हमारे अधिकारियों तथा विपक्ष के सदस्यों से भी निवेदन है कि उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिये हमारे अधिकारियों ने 25,26,27 तीन दिन में पूरे प्रदेश का खाका लेकर वन-टू-वन चर्चा करके पूरे प्रदेश की स्थिति को बताया उनको धन्यवाद देना चाहिये. जहां तक बात करें तुलनात्मक कांग्रेस के जमाने में आपने देखा होगा कि यह जो पुराने सदस्यगण हैं पिछले वर्षों में सोयाबीन की फसल का बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन किसानों को किसी को 300 रूपये, किसी को 800 रूपये, तथा किसी को 900 रूपये उस समय सरकार एक हजार रूपये का आंकड़ा पार नहीं कर पायी थी कांग्रेस की सरकार ऐसा मुआवजा दिया था ऊंट के मुंह में जीरे के समान आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, किसान के बेटे हैं इसलिये उनके द्वारा किसानों के हित में यह विशेष सत्र बुलाया गया है और इस विशेष सत्र के माध्यम से हमारे किसानों के लिये बजट पास करके हमारे किसानों के लिये राहत राशि का प्रावधान रखा गया है. आप बिजली की बात करते हैं मेरे क्षेत्र में पर्याप्त बिजली मिल रही है. माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसी दिन से 10 प्रतिशत पैसे देकर के ट्रांसफार्मर बदले भी जा रहे हैं और किसानों को बिजली भी दी जा रही है और उनको पर्याप्त बिजली दी जा रही है, उनको 24 घंटे बिजली, जो फीडर सप्रेशन का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है जिसके कारण गांव-गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है. हमारे कांग्रेस के मित्रों के यहां से बात आ रही है कि किसान आत्म-हत्याएं कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है, किसान आत्म-हत्याएं इस वजह से नहीं कर रहे हैं, आत्म-हत्या के कई कारण हैं आप खुद का कार्यकाल उठाकर के क्यों नहीं देख रहे हैं आप लोगों ने किसान को आत्म-हत्या करने के लिये मजबूर किया था आपने 18 प्रतिशत का ब्याज जैसे किसान कर्ज लेता

था उसका बेटा कर्ज में डूब जाता था, उसके बाद बेटा कर्ज को चुकाता था. बड़े बड़े साहूकारों की लिस्ट टांग दी जाती थी पंचायत भवनों तथा स्कूलों में, उस समय की बात अलग थी आज प्रदेश विकसित राज्य के रूप में खड़ा है, वह बात अलग थी, आज बात अलग है. आपने समय दिया आपका धन्यवाद.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बैठे बैठे बोलने की मुझे इजाजत है. मुझे लंबा भाषण नहीं देना है, हमारे दल के सभी लोगों ने बोला है, बहुत सी बातें रिपीड होती हैं. मैं तो एक बात को कहना चाहता हूं उसके दो हिस्से हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने इसके लिये सरकार से भी निवेदन किया था आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, विधान सभा से भी निवेदन किया कि किसान पीड़ित हैं, परेशान हैं उसको सभी जान रहे हैं. हमने यह मांग की है कि जो किसान पीड़ित हैं उसमें मृतक किसान को पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाये. जो ऐसे एरिया हैं जहां पर सूखा पड़ गया हैं, कहीं अतिवृष्टि हो गई है, कहीं ओलावृष्टि हुई है जिसके कारण किसान कई तरह से पीड़ित हुआ है जो किसान पीड़ित एरिया में हैं उन किसानों को 5 हजार रूपये प्रतिमाह अगस्त 2015 से अगस्त 2016 तक सरकार की ओर प्रत्येक पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी जाए दूसरी हमारी मांग यह है कि इन दोनों को हमने दिया था, आपसे भी कहा था इस बात को अशासकीय संकल्प के रूप में भी दिया हुआ है आपके रिकार्ड में.

श्री सत्यदेव कटारे - आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो अध्यक्ष महोदय, फिर ऐसे ही रह जाता है जब आप ध्यान नहीं देंगे मुख्यमंत्री जी काहे को ध्यान देंगे. वैसे मुख्यमंत्री जी को हमने कार्य मंत्रणा समिति में भी धन्यवाद दिया था आपने ध्यान नहीं दिया. मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल सेशन बुलाया इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं. खुले दिल से पूछो कि हमने 9 सितम्बर को पत्र लिखा था आपको कि नहीं. आपके पास जाता है आप देखते हो कि नीचे ही लौट जाता है. ऐसा भी कहते हैं आपके बारे में कोई पत्र गौर साहब ने देख लिया नहीं तो नरोत्तम पीछे बैठे हैं फिर अधिकारी तो इस काम के लिये बैठे ही हैं. अच्छा नरोत्तम आप नहीं देखते कोई बात नहीं. खैर,सवाल वह नहीं है. सवाल यह है कि आपकी भी इच्छा है किसान की मदद करने की. मेरी भी इच्छा है किसान को मदद करने की फर्क सिर्फ इतना पड़ रहा है मदद हो किस ग्रांट में तो मिलकर बैठकर एक ग्रांट बना दिया करो स्पीकर ग्रांट. कोई अकाउंट खोल दो स्पीकर ग्रांट से हेल्प होगी हम और आप दोनों बैठेंगे और किसी की जरूरत हो बैठा लो तो मदद कर दिया करें और हंसी मजाक जैसी चीजें ऐसे विषय पर ऐसे सत्र के दौरान कभी नहीं उठानी चाहिये. मैं लोगों से कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है. सीखते हैं कभी गल्ती भी होती है. यह पहला सेशन है इस विधान सभा का और यह तब हो रहा है जब तीन साल संकट में किसान रहा है. बहुत बुरी तरह से वह परेशान रहा है. रोता है झेलता है मर जाता है. जिसको हमने देखा हुआ हो मरते हुए. कलेक्टर रिपोर्ट दे रहे हैं कि उसने तो अपनी बीबी से झगड़े की वजह से आत्महत्या कर ली. और भी चीजें हैं. आपने क्या देखा. आप ने अधिकारियों की ड्युटी लगाई. तीन दिन गांव में रहेंगे गांव में जायेंगे. आपने देखा कि आपके नीचे से ही निकला एक अधिकारी फाईव स्टार का खाना गांव में खा रहा है. एक अधिकारी फाईव स्टार में ही रुक रहा है और रिपोर्ट दे रहा है गांव में. आपने

इस पर कुछ किया नहीं परिणाम इसका क्या होगा. अध्यक्ष महोदय, एक बात तो मुझे यह कहनी थी बिजली की समस्या पर. हमारा मोबाईल हमारे कमरे में रह गया है उस पर फिगर्स आ गये हैं. आज की डेट में कौन सा संयंत्र कितना बिजली का उत्पादन कर रही है. आपको मालुम है. आपकी उत्पादन क्षमता 4320 मेगावाट है आज की तारीख में और आप बता रहे थे 10 हजार या 14 हजार. जी न्यूज के प्रोग्राम में. हम और आप यहीं बैठे हैं पूरा सदन यहीं बैठा है आप अभी प्लांट से जानकारी लेकर सदन को दे दें. हम टेली कर देते हैं. आज की तारीख में 12 बजे से 4 बजे तक किस प्लांट ने कितना उत्पादन किया. यह जानकारी मेरे पास आ गई है 2 बजे तक की.(जानकारी दिखाते हुए) अध्यक्ष महोदय, आप कहो तो मैं पटल पर रख दूं.

अध्यक्ष महोदय – नहीं.

श्री सत्यदेव कटारे – अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या दिक्कत है. इससे किसी का क्या नुकसान है.

अध्यक्ष महोदय – किसी का नुकसान नहीं है. आप पढ़ दीजिये.

श्री सत्यदेव कटारे – प्रमोशन उनको दो जो अच्छा काम करें और अगर इस विभाग ने अच्छा काम किया है तो इसके एम.डी. को और प्रमोशन दो. यह सब फिगर्स हैं. अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इसे पटल पर रख रहा हूं. यह आज के फिगर हैं.

श्री रामनिवास रावत – शासकीय दस्तावेज है.

अध्यक्ष महोदय – अनुमति नहीं है.

श्री सत्यदेव कटारे – अध्यक्ष महोदय, शासकीय दस्तावेज है. कहीं-कहीं तो मान लिया करें. आप बड़े अच्छे आदमी सुने थे भले आदमी सुने थे कि किसी को रोकते नहीं हैं और हम देख रहे हैं तब से खराब-खराब देख रहे हैं. खैर, यह बात हमें कहनी थी. आपने पावर प्लांट बंद करके रखे. पावर प्लांट खण्डवा में क्या लिखा था लो डिमांड इन सिस्टम. कम्प्यूटर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहे. लो डिमांड इन सिस्टम. मतलब आपको बिजली एक हजार मेगावाट भी नहीं चाहिये. आज आपकी केपेसिटी कितनी है दस हजार मेगावाट है. है तो सदन में खड़े हो जाओ(मुख्यमंत्री जी से)

मुख्यमंत्री(श्री शिवराजसिंह चौहान) – मैं उत्तर दूंगा.

श्री सत्यदेव कटारे – हम तो बैठे हैं सुनेंगे पूरे दिन. अध्यक्ष महोदय, जब आप सिस्टम में डिमांड नहीं है तो प्लांट बंद क्यों हैं और बंद हैं तो फिर आप बिजली बेच क्यों रहे हो. दो चीज हमने आपके ही राज्य में देखी हैं,बिजली उत्पादन हो रही है क्योंकि उसकी जरूरत है। बिजली बेच रहे हैं क्योंकि सरप्लस है. बिजली चला नहीं रहे हैं क्योंकि सिस्टम में जरूरत ही नहीं है और यह रिकार्ड में है इसको डिनाई मत कर लेना, कोई आपको करवाए तो क्योंकि आप बड़े सीधे आदमी हो, मान जाते हो. अध्यक्ष महोदय, आसपास ऐसे चंगु-मंगु लग गए, ये रिक्त पदों का है. आपके यहां खाली पद किसके कितने पड़े हैं ये पढूंगा तो इसमें दो पेज हैं. इसको भी पटल पर रख रहा हूँ यदि आप कहें तो मैं जिम्मेदारी से हस्ताक्षर करके रख दूँ कल विथड्रा नहीं होऊंगा. अध्यक्ष महोदय, बस इतनी सी हम बात कह रहे थे, आपने इस सत्र में बुलाया इसके लिए हम

आपको धन्यवाद देते हैं लेकिन इन्होंने आपकी नहीं चलने दी, नहीं तो आप सत्र में आराम से सबको बुलाते. हमें यह बताएं कि किसी को चर्चा में ले लें उससे क्या नुकसान है. राजस्व पुस्तक परिपत्र आपके पास रखा है इसमें जो संशोधन आपने किए हैं या मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने किए हैं उन्हीं संशोधनों को लागू नहीं किया है आप उन्हीं पर नहीं मान रहे हैं, उन्हीं पर आपकी सरकार काम नहीं कर रही है. अब इसे देखेगा कौन. क्या हम देखेंगे, हम तो आपको याद कराएंगे कि आप देखो. क्या मैं परिपत्र दूँ आप देख लेना. पटवारी के 16622, तहसीलदार के 517, 1336 पटवारी हल्कों पर पटवारी हैं ही नहीं. 2167 आरआई, 390 आरआई के पद खाली पड़े हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो मूल डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट के लिए जड़ का काम करता है. वहां से सर्वे हम करवाते हैं कि मास्टर कितने हैं क्या हो रहा है तो सर्वे करने वाला डिपार्टमेंट ही आधा है. मैं चाहूंगा कि यदि आप रेवेन्यू की पूर्ति और खाली पदों की जानकारी दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी. ये सब आपके प्रोडक्शन का है एमपीईबी का, अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ इतना ही कहना था. मैंने कोई ऐसा शब्द बोल दिया हो जो बिलो द बेल्ट हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे.

अध्यक्ष महोदय - आज की कार्यसूची में उल्लेखित विनियोग विधेयक पारित होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए, मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है.

श्री शिवराज सिंह चौहान (मुख्यमंत्री) - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है, आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ. इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर न केवल उन्होंने चर्चा में भाग लिया है बल्कि कई मित्रों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी मुझे दिए हैं. यह बात सच है कि सूखे का संकट बड़ा है और केवल बड़ा ही नहीं, गहरा भी है. पर ये पहला साल नहीं है इसके पहले भी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, पिछले साल भी थीं उसके पहले वाले साल भी थीं लेकिन इस साल की स्थितियां पिछले सालों के मुकाबले कुछ अलग तरह की हैं. अभी हमारे विधायक साथीगण कह रहे थे कि कुछ जगह बारिश हुई तो इतनी बारिश हुई कि अतिवृष्टि का खतरा पैदा हो गया विशेषकर भोपाल, इंदौर,उज्जैन संभागों में भयानक बाढ़ें आयीं, अतिवृष्टि के कारण फसलों का नुकसान हुआ.अतिवृष्टि भी अनावृष्टि भी उसके साथ साथ कई जगह एक साथ वर्षा हो गई और बरसात का गैप भी हुआ. अब कई मित्रों ने कहा पहले आकलन नहीं कराया इस साल सच में विचित्र-सी स्थिति थी जहां सूखे का संकट था वहां कोई दिक्कत नहीं थी पता था पहले से अंदाज लगाया जा सकता था जहां कीट का प्रकोप हुआ वहां भी अंदाज लग गया कि कीट के प्रकोप के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं लेकिन सोयाबीन जहां हुआ था अधिकांश क्षेत्र ऐसा था जहां ऐसा लग रहा था कि फसल बहुत अच्छी आ रही है. हरी भरी फसल खड़ी थी, फल्लियां भी लगी थीं, किसान को भी अहसास नहीं था लेकिन जब फसल कटी और थ्रेसिंग हुई तो पता चला जितना बोया था उतना काटने की स्थिति नहीं है. यह मैं जो कह रहा हूँ उससे आप लोग सहमत होंगे,

पहले से आभास नहीं था, पहले से जानकारी नहीं थी और इसलिये यह बात सच है कि इतनी भयंकरता का आभास न होने के कारण, फसलों की क्षति का आकलन बहुत पहले नहीं किया जा सकता था लेकिन जब संकट की गंभीरता का आभास हुआ. यह भी कई मित्रों ने कहा कि अब क्या करोगे अब तो फसल ही कट गई लेकिन इसके बाद भी प्रयास किया कि क्षति का आकलन करें. यदि फसल के आधार पर खेत के आधार पर न हो उत्पादन के आधार पर करें. यह हिन्दुस्तान में पहली बार हुआ मैंने कहा कि अगर खेत में फसल नहीं है तो उत्पादकता के आधार पर भी आकलन करेंगे. किसान तकलीफ में है, किसान संकट में है, किसान परेशान है और सचमुच में जब उसकी फसल सूखती है तो केवल फसल नहीं सूखती है उसकी जिंदगी सूखती है, उसके सपने सूखते हैं, उसके बच्चों का भविष्य सूखता है. अभी बात संवेदनशीलता की हो रही थी. अगर संवेदनशीलता न होती तो यह सत्र भी न होता. मन में दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है आपके भी है हमारे भी है.

श्री रामनिवास रावत—आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आप कोई अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहे हैं किसान संकट में है आपको संवेदनशील होना चाहिये संवेदनशील हैं तो कोई अहसान नहीं कर रहे हैं अगर आपने सत्र बुलाया है तो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पत्र भी लिखा है आपके बुलाने से पहले पत्र लिखा है.

अध्यक्ष महोदय—आप कृपया बैठ जायें.

श्री शिवराज सिंह चौहान—अब मुझे बोल लेने दिया जाये मैंने आप सबको बड़े ध्यान से सुना है बहुत दिनों के बाद सदन में चर्चा.....

श्री रामनिवास रावत—आपने उत्पादकता के आकलन की बात कही है किसान की उत्पादकता का आकलन किस तरह से करेंगे यह भी सदन को बता दें तो हमें भी समझ में आये और हम भी जब क्षेत्र में जायें तो किसानों की उत्पादकता के आकलन के बारे में बात करें.

श्री शिवराज सिंह चौहान—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि इस सदन में केवल बहस के लिये बहस न हो केवल तर्क और कुतर्क न हो हम पूरी गंभीरता के साथ इस समस्या पर विचार करें विचार करके समाधान निकालने की कोशिश करें. महेन्द्र सिंह जी सदन में नहीं हैं. वे कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले वक्ता थे. उन्होंने बात आत्महत्याओं से प्रारंभ की थी. अनेकों माननीय सदस्यों ने आत्महत्याओं का जिक्र किया है, मृत्यु कोई भी हो, आत्महत्या कोई भी करे, वह तकलीफदेह है, दुखद है, आज तक हमने कोशिश यह नहीं की कि कारण क्या है. देख लीजिए मेरे पूरे स्टेटमेंट. अगर आत्महत्या करते हैं तो इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता, इससे पीड़ादायक कुछ हो नहीं सकता. किसान करे, गैर किसान करे, आखिर मानवीय जीवन महत्वपूर्ण है, उसकी अपनी गरिमा है. अगर उसको कोई समाप्त करता है तो यह अत्यंत दुखद है. लेकिन बात की जा रही थी, अनेकों तरह की चर्चाएँ यहाँ हो रही थीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि दुखद है, बहुत दुखद है. लेकिन यह आत्महत्याओं का दौर केवल आज प्रारंभ नहीं हुआ. मैंने कहा उस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है. एक भी आत्महत्या दुखद है. अभी आत्महत्याएँ किसान भी करते हैं, गैर किसान भी करते हैं. केवल मध्यप्रदेश में ही नहीं करते, दूसरे प्रदेशों में भी करते हैं.

लेकिन अगर उसको हम केवल राजनीति से जोड़ें, कि केवल आप हैं इसलिए आप आत्महत्या हो गई, तो यह समस्या के साथ न्याय नहीं होगा. अध्यक्ष महोदय, यह आँकड़े कह रहे हैं, एन सी आर बी के, जिसका जिक्र उन्होंने किया था. 1997 में 2390 किसानों ने आत्महत्या की थी. 1998 में 2278 किसानों ने आत्महत्या की थी. 1999 में 2654 किसानों ने आत्महत्या की थी. 2000 में 2607 किसानों ने आत्महत्या की थी. पहले 5 साल जो थे 1997 से लेकर 2003 तक के उस दौरान जब 6 साल काँग्रेस की सरकार थी, तब 17187 किसानों ने आत्महत्या की थी, यह एन सी आर बी के आँकड़े कहते हैं. लेकिन मैं यह राजनीति करने के लिए नहीं कह रहा हूँ. तब भी दुखद थी, अब भी दुखद है. अगर ऐसी परिस्थितियाँ आए कि जिसके कारण लोगों को अपने जीवन की लीला समाप्त करनी पड़ती है, वह दुखद है, उनको बदलने की गंभीर कोशिश होना चाहिए. तब भी ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है और आत्महत्याओं के कई कारण होते हैं. यह बात सच है कि किसान स्ट्रेस में आता है. अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि खेती फायदे का ऐसा धंधा नहीं है कि जिसमें किसान को इतनी आमदनी हो जाए कि उसके कारण एक बार, दो बार, अगर उसकी फसलें तबाह....(श्री सुन्दरलाल जी तिवारी के अपने स्थान पर खड़े होने पर) माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं बोलने की इजाजत नहीं देता...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- नहीं, नहीं, बिल्कुल एलाउ नहीं करेंगे. तिवारी जी आप बैठ जाइये. सदन के नेता बोलते हैं तो इंट्रप्ट नहीं करते. प्लीज, आप समझदार सदस्य हैं आप बैठ जाएँ....(व्यवधान)..यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है. कृपया बैठ जाइये. बिल्कुल नहीं.

श्री शिवराज सिंह चौहान-- अध्यक्ष महोदय, मैंने यही निवेदन किया कि तब भी ठीक नहीं थी, अब भी ठीक नहीं है...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आप कृपया बैठ जाएँ. तिवारी जी, यह कोई प्रश्नकाल नहीं है. अब बात पूरी हो गई. कोई एलाउ नहीं. यह नहीं लिखा जाएगा...(व्यवधान)..

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- (xxx)..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- तिवारी जी, बैठ जाइये. आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- (xxx)

श्री शिवराज सिंह चौहान-- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय मीडिया का फोकस और ध्यान इतना नहीं जाता था इसलिए वह वैसा विषय नहीं बनती थी, प्रकाश में नहीं आती थी. लेकिन यह आँकड़े भी तथ्यात्मक हैं, प्रामाणिक हैं, जो मैंने रखे हैं. आज एक भी आत्महत्या होती है तो वह मीडिया के माध्यम से चर्चा का विषय बनती है, नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए...(व्यवधान)..

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- यह कोई प्रश्नकाल है क्या...(व्यवधान)..

श्री शिवराज सिंह चौहान-- नहीं, मैं बिल्कुल यह नहीं कह रहा. मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि एक भी छोटी सी चीज होती तो वह प्रकाश में आती है. पहले प्रकाश में आती ही नहीं थी, पता ही नहीं चलता था. लेकिन मैं यह कहता हूँ कि आत्महत्याओं पर राजनीति कृपा करके न करें. तब भी गलत थी, अब भी गलत है, यह नहीं होना चाहिए और मिल कर कोशिश यह होना चाहिए कि इन परिस्थितियों को कैसे सुधारा जाए और मैं आप से यह कहता हूँ कि हमने गंभीर प्रयास किए हैं.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे)-- मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अच्छा बोल रहे हैं अभी उन्होंने हमारी पार्टी को ब्लेम नहीं किया, लेकिन अभी पार्टी को ब्लेम किया, यह न करें तो ज्यादा अच्छा होगा. हम गूंगे नहीं बैठे हैं.

श्री सुंदरलाल तिवारी-- कितने किसान मरे, मुख्यमंत्री जी यह तो बता दें .

अध्यक्ष महोदय--- तिवारी जी, बैठ जाइए कृपया.

श्री जितू पटवारी-- क्या यह अन्याय नहीं होगा कि पहले के 10 साल के आंकड़े हैं तो 12 साल के आंकड़े भी मुख्यमंत्री बतायें....(व्यवधान)....जो भी करें, मौत पर राजनीति नहीं होना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय-- यह कोई प्रश्नकाल नहीं है. तिवारी जी बैठ जाइए, आपके पास में कुछ नहीं है. आप बैठ जाइए, आप बैठ रहे हैं कि नहीं..आपकी बात आ गई है यहाँ पर. आप बार बार वही बात कहते हैं. तिवारी जी आप बैठिये .

श्री सुंदरलाल तिवारी--- हम किसान कितने मरे , वह जानकारी चाहते हैं.

श्री रामेश्वर शर्मा--- मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे यह आप तय करेंगे,क्या कमाल की बात है यार.

श्री शिवराज सिंह चौहान--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी आंकड़े बताये हैं, अब इस साल की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं लेकिन पिछले साल अलग अलग कारणों से, मैं कारणों पर नहीं जा रहा हूं कि कौनसा फसल के कारण कौनसा फसल के कारण नहीं. लेकिन पहले हर साल 2000 से ज्यादा मृत्यु होती थी ,पिछले साल 1108 मृत्यु हुई हैं, मैं मध्यप्रदेश की बात कर रहा हूं तिवारी जी और यह कहते हुए कर रहा हूं. ..(व्यवधान).. हर बात पर टोकेंगे तो फिर....

श्री सुंदर लाल तिवारी--- मैं तो मध्यप्रदेश में कितनी हुई हैं उसकी जानकारी चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय--- तिवारी जी बैठें.

श्री रामेश्वर शर्मा--- हमने सभी सदस्यों को सुना है जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं, आप तय करेंगे हर चीज को ...(व्यवधान)...

श्री सुंदरलाल तिवारी---- हम मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं, प्रदेश में कितने किसान मरे हैं , उसकी जानकारी दे दें. सदन अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता है, जानकारी चाहता है.

अध्यक्ष महोदय--- कृपया सभी सदस्य बैठ जाएं. (श्री रामनिवास रावत जी से) आप उनको समझाइए , वह कितनी बार उठ रहे हैं. डॉ. दोगने जी आप बैठ जाइए. आप तिवारी जी की बात पर ज्यादा उत्तेजित मत हुआ करिये(XXX) . बैठिये आप.

श्री रामनिवास रावत--- (XXX) यह तो कम से कम निकाल दीजिये.वह वकील हैं.

अध्यक्ष महोदय—इसको निकाल दें.

श्री कैलाश विजयवर्गीय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं. यह सदन परंपरा और नियम से चलता है हमेशा जब भी सदन के नेता खड़े होते हैं साधारणतया परंपरा रही है कि कोई भी सदस्य खड़ा नहीं होता है यदि उसको कुछ बोलना होता है तो वह हाथ खड़ा करता है नेताजी बैठते हैं, तब वह बोलता है. अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि इस सदन की परंपरा,इस सदन की जो प्रतिष्ठा है वह प्रतिदिन खराब हो रही है इस पर आप निर्देशित करिये और प्रताड़ित करिये . इतनी गंभीर चर्चा हो रही है सदन के अंदर.

श्री सुंदरलाल तिवारी-- आपने भी इजाजत नहीं ली है बोलने की.

अध्यक्ष महोदय-- आप दोनों बैठ जाइए, तिवारी जी आप बैठ जाइए.

श्री कैलाश विजयवर्गीय--- इतनी गंभीर चर्चा हो रही है सदन में उस सदन की चर्चा को अगंभीर बनाने का काम यहाँ पर हो रहा है.

अध्यक्ष महोदय-- सभी बैठ जाएं. कैलाश जी आप भी बैठ जाइए.

श्री कैलाश विजयवर्गीय--- अध्यक्ष महोदय, इस पर आप व्यवस्था दीजिये और प्रताड़ित करिये यह परंपरा बिल्कुल ठीक नहीं है. सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा खराब हो रही है.मेरा इसमें प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है.

श्री रामनिवास रावत--- सत्ता पक्ष के सदस्य इसका कितना पालन करते हैं...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय--- अब सुन लें कृपया. इस बात से सभी सहमत हैं मैं भी सहमत हूं कि सदन में जब प्रतिपक्ष के नेता और सदन के नेता बोलते हैं तब सामान्यतः कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाता है . श्री सुंदरलाल तिवारी जी तो सदन के नेता ही नहीं, वह तो अध्यक्ष के बीच में बोलते हैं .मेरा सुंदरलाल तिवारी जी से अनुरोध है कि वह कृपा करके मर्यादाओं का पालन करें . पहले तिवारी जी, आप बैठ जाइए और कृपा करके बिल्कुल नहीं बोले और उनके दल के माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है, विशेष कर मुख्य सचेतक जी से कि वह बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, किन्तु आप उनको थोड़ा सा समझाएं. माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपना भाषण जारी रखें.

श्री शिवराजसिंह चौहान—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता के साथ यह निवेदन कर रहा था कि आत्महत्याएँ राजनीति का विषय नहीं बनायी जानी चाहिएं. तब भी आत्महत्याएँ होती थीं, मैं इतना जरुर कह सकता हूँ कि तब से अब कम आत्महत्याएँ हो रही हैं लेकिन एक भी अगर होती है तो वह दु:खद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है उस पर हम राजनीति न करें, नहीं तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें कि आपके समय इतनी होती थी,हमारे समय उतनी होती थीं. किसान को इससे क्या मिलेगा? जहां तक संवेदनशीलता का सवाल है , मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, तथ्यों के साथ कहना चाहता हूँ कि यह सरकार आने के बाद हमने कई गुना ज्यादा राहत की राशि बढ़ाने का काम किया है. अगर आप आंकड़े देखना चाहते हैं, संवेदनशीलता की बात हो रही थी, सदन के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय अजयसिंह जी जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, आदर करता हूँ, वह संवेदनशील होने की बात कर रहे थे , हां हूँ मैं संवेदनशील, अगर मैंने यह कहा था कि ओले पड़ते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी छाती पर पड़ते हैं. कोई लोग इसको व्यंग्य में ले सकते हैं, अलग ढंग से ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप लेने के लिए, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में उस समय भी अकाल पड़े थे, उस समय भी प्राकृतिक आपदाएँ आती थीं, उस समय भी किसान दिक्कत में आता था तब यह कह दिया जाता था कि नुकसान का आकलन कम से कम हो, ज्यादा न लिखे, ज्यादा बांटना पड़ेगा. कांग्रेस के 10 सालों में केवल 670 करोड़ रुपये की राशि किसानों को बांटी गयी थी आपदा राहत की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 सालों में 7600 करोड़ रुपये की राशि किसानों को वितरित करने का काम किया है,यह तथ्य है(मेजों की थपथपाहट)

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- उस समय सोना क्या भाव था और आज सोने का क्या भाव है. इसकी तुलना करिये.

अध्यक्ष महोदय—तिवारी जी आप बैठ जाएं.

श्री शिवराजसिंह चौहान—माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सोने चांदी के भाव की बात हो रही है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ...संवेदनशीलता की बात हो रही है, आप लोगों ने बात उठाई, आप लोगों ने संवेदनशीलता की बात उठाई.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- सोने की वेल्यू से मनी की वेल्यू निकाली जाएगी.

अध्यक्ष महोदय—तिवारी जी, आप सुनेंगे कि बोलेंगे ही बोलेंगे. आप बैठ तो जाओ.

श्री शिवराजसिंह चौहान-- अब आप सुनेंगे नहीं अपनी बात कर के, यह कोई बात होती है क्या? अध्यक्ष महोदय, अब मुझे पता है कि मेरी बातें ढंग से तो सुनेंगे नहीं, बीच में टोका-टोकी, रोका-रोकी क्योंकि सच कड़वा होता है. हम जब चाहें कुछ भी आरोप लगा लें और उत्तर देने खड़े हों तो कदम कदम पर टोकें, यह कौन सी शालीनता है.

श्री रामनिवास रावत—पूरी गंभीरता से सुन रहे हैं और गंभीरता से सुनने के लिए बैठे हैं. आपने ही कहा है कि किसी भी तरह के भाषण में राजनीति नहीं होनी चाहिए. आप राजनैतिक भाषा का प्रयोग करते हुए अपने आपको स्वंय सिद्ध करना चाहते हो, आप प्रदेश के बड़े हितैषी हो और अगर तिवारी जी कहते हैं, आप स्वयं ही तिवारी जी को उत्तेजित कर रहे हो. आप सीधे सीधे बोलिये किसानों को बचाना कैसे है.

श्री शिवराजसिंह चौहान-- वह भी मैं आपको बताऊंगा(व्यवधान)

श्री केदारनाथ शुक्ला—आपने जो आरोप लगाये हैं,उनका जवाब देना तो जरुरी है.

श्री शिवराजसिंह चौहान—माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर संवेदनशीलता की बात आती है तो जब उधर की सरकार थी तब जीरो से लेकर दो हेक्टेयर तक असिंचित फसल में केवल एक हजार रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाती थी. अध्यक्ष महोदय, सिंचित में प्रावधान ही नहीं था, फूटी कौड़ी नहीं देते थे. आप फूटीकौड़ी नहीं देते थे, हम प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं. जीरो से दो हेक्टेयर तक के किसानों को असिंचित में ये एक हजार रुपये देते थे, हम 8 हजार देते हैं. सिंचित में प्रावधान नहीं था, हम 15 हजार देते हैं और बारहमासी में हम 18 हजार देते हैं.

श्री बाला बच्चन (राजपुर) – मध्यप्रदेश को यूपीए सरकार ने कितनी मदद की और वर्तमान सरकार ने कितनी मदद की. (व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय – बाला बच्चन जी कृपया बैठ जाएं.

श्री शिवराज सिंह चौहान – मैं इस पर भी आऊंगा. (व्यवधान..)

श्री रामनिवास रावत – आप आरबीसी निकलवा के देख लें. आप कह रहे हैं कि सिंचित का उस समय प्रावधान ही नहीं था. मैं कह रहा हूँ कि उस समय सिंचित का भी प्रावधान था और असिंचित का भी प्रावधान था, प्रावधान कम था यह बात सही है लेकिन वह उस समय की मूल्य वृद्धि के हिसाब था, आज कितनी मूल्य वृद्धि हो गई. आपने बढ़ाया है आपको संवेदनशील मानते हैं इसमें किसी को कहां आपत्ति है लेकिन आप विपक्ष को असंवेदनशील कहें और स्वयं संवेदनशील बनना चाहें यह गलत तरीका है. (व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय – रावत जी, आपकी बात रिकार्ड में आ गई है, आप कृपया बैठ जाएं.

श्री शिवराज सिंह चौहान – मैं आपको असंवेदनशील नहीं कह रहा हूँ मैं केवल यह बता रहा हूँ कि जब आप थे तब ऊँट के मुँह में जीरे जैसी राशि मिला करती थी और जब हम आए तो हमने कई गुना ज्यादा बढ़ाई है. (व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय – तिवारी जी कुछ भी बोलेंगे नहीं लिखा जाएगा.

(व्यवधान..)

श्री रामनिवास रावत – उस समय 14 हजार रुपये का कितना क्विंटल गेहूँ आता था और आज 14 हजार रु. में कितना क्विंटल गेहूँ आता है यह भी हिसाब लगा लें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी -- XXX

अध्यक्ष महोदय – तिवारी जी आप बैठ जाइये, सारा जिम्मा आपने नहीं लिया है.

(XXX) - आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया.

श्री शिवराज सिंह चौहान – माननीय अध्यक्ष महोदय, पान बरेजे के ये 2 हजार देते थे हम 20 हजार देते हैं. (व्यवधान..) माननीय अध्यक्ष महोदय, हर बात में टोका टाकी ऐसे में कैसे बोलेंगे. (व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय –आपके अधिकतम सदस्य बोले, सबको मौका दिया. आपसे अनुरोध है कि यदि आप सचमुच किसानों की बात सुनना चाहते हैं. आपने भी जो बात बोली यहां से कोई बहुत विरोध नहीं हुआ, आपने भी आरोप लगाए, सबने आरोप सुने. तिवारी जी आप जरा बैठ जाएं. कृपा करके यदि आप सचमुच किसानों के लिए चिंतित हैं जो कि आपने अभी तक की है. सारे सदन ने चिंता की और इसलिए सारे सदन के अधिकांश सदस्य बोलना चाहते हैं किंतु अब जब वह फाइनलाइज हो रहा है तो आपको उसे धीरे से

सुनना चाहिए. मेरा अनुरोध है और सदन की परंपरा भी है कि जब सदन के नेता बोलते हों तो हमें सुनना चाहिए जब तक कि वे खुद न बैठ जाएं. श्री यादवेन्द्र सिंह जी आप बैठ जाइए, आपका नाम नहीं था फिर भी आपको एलाऊ किया. आप कृपा करें बैठ जाइए. आपने जब बोला तब तो किसी ने नहीं टोका. कृपया सभी लोग बैठ जाएं. (व्यवधान..)

श्री यादवेन्द्र सिंह – सूखे पर चर्चा हो रही है तो सूखे पर बोलें, आंकड़ों की बात हो रही है तुलना हो रही है. (व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय – आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे. आप किसी को निर्देशित नहीं कर सकते कि कैसा बोलना है. आप कृपया बैठ जाएं. (व्यवधान..)

श्री शिवराज सिंह चौहान – तुलनात्मक बात क्यों नहीं की जाएगी.

श्री कैलाश विजयवर्गीय – अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है. मुझे एक मिनट या आधे मिनट का समय दीजिए. जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया है कि सदन के नेता या नेता प्रतिपक्ष जब भी बोलते हैं तब जो सदस्य बोलना चाहें हाथ उठाए, सदन के नेता या प्रतिपक्ष के नेता जब बैठ जाएं उसके बाद वे बोल सकते हैं. लगातार सदन की मर्यादा भंग हो रही है. अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक स्थाई आदेश आप जारी करें कि जब तक सदन के नेता या नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे और बैठेंगे नहीं, कोई भी बोलेगा रिकार्ड में नहीं आएगा तो यह सदन नियंत्रित हो सकता है नहीं तो इस सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा दोनों खराब हो रही है. इसके बारे में निवेदन है कि आप स्थाई आदेश जारी करें. (व्यवधान..) अध्यक्ष महोदय, मैं दु:खी इसलिए हूँ कि मैं 1990 से आपके साथ सदस्य था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि नेता खड़े हों और इतने सीनियर सदस्य आकर सदन की मर्यादा तोड़ें, यह बहुत शर्म की बात है.

अध्यक्ष महोदय – आपकी बात आ गई. पहले भी आपसे सहमति जताई थी कि वे ठीक नहीं कर रहे हैं.

श्री शिवराज सिंह चौहान (मुख्यमंत्री)—अध्यक्ष महोदय, बात चूंकि संवेदनशीलता की आई थी और इसलिए मैने यह बात कही , आप संतरे जैसी फसल के लिए भी साढ़े सात हजार प्रति हैक्टेयर देते थे और हम 500 रूपये प्रति पेड़ देते हैं. हम संवेदनशील ज्यादा हैं. इसमें क्या दिक्कत है. अध्यक्ष महोदय, सब्जी, मसाले, इसबगोल,ये कुछ देते ही नहीं थे. हम 18000 प्रति हैक्टेयर देते हैं 3 प्रतिशत नुकसान पर 26 हजार प्रति हैक्टेयर देते हैं. अध्यक्ष महोदय, सेरीकल्चर जैसी फसलों में आप कुछ देते ही नहीं थे हम 6000 रूपये हैक्टेयर देते हैं. आप गाय के लिये 2100 रूपये देते थे और हम प्राकृतिक आपदा में अगर गाय मर जाये तो 30 हजार रूपया देते हैं. भैंस, बैल,घोड़ा के लिए आप 4125 देते थे हम 25 हजार देते हैं. बछड़ा बछड़ी के लिए आप 300 रूपये देते थे हम दस हजार देते हैं. बकरी के लिए आप 700 देते थे हम 3 हजार रूपया देते हैं. अध्यक्ष महोदय, मैं एक एक आंकड़े आपको पढ़ कर बता सकता हूं. पक्का मकान पूरी तरह से नष्ट होता था आप 10 हजार देते थे हम 95100 देते हैं. कच्चे मकान के लिए आप 6 हजार देते थे हम

95100 देते हैं. झुग्गी झोपड़ी के लिए हम 6 हजार रूपये देते हैं , एक एक आंकड़े मैं बता सकता हूं. मैने यह बात केवल इसलिए कही ,मैं इस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा. लेकिन मैने यह बात इसलिए कही कि इस सरकार में संवेदनशीलता है. लोगों की तकलीफ से हम द्रवित होते हैं. मन में तकलीफ होती है. किसान अगर पीड़ा में होता है तो हमारे मन में भी दर्द होता है और उसी संवेदना के साथ हम काम करते हैं और आज मैं आपके माध्यम से इस सदन को और पूरे प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि साल खराब हुआ है ,साल हारे हैं लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जिन्दगी नहीं हारने देंगे, हर संभव कोशिश करेंगे किसान को राहत देने के लिए. और इसलिए अध्यक्ष महोदय ,मैं निवेदन करना चाहता हूं पिछले दिनों में भी जो काम हुए हैं, खेती की भलाई के लिए, विकास के लिए भी कम काम नहीं हुए. यह मध्यप्रदेश है जहां सिंचाई की क्षमता केवल साढ़े सात लाख हैक्टेयर थी. हमें इस बात का गर्व है कि हमने उस सिंचाई की क्षमता को बढ़ा कर 36 लाख हैक्टेयर करने का चमत्कार किया है. यह मध्यप्रदेश की धरती पर हुआ है,. अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा. लेकिन मालवा में पानी जमीन के नीचे चला गया. कई माननीय सदस्य चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों. सबने चिन्ता प्रगट की, ट्यूबवेल खनन की बात हुई. लेकिऩ अध्यक्ष महोदय, उसी मालवा में नर्मदा जी का पानी जाये, नर्मदाजी को क्षिप्रा में मिलाया और अब नर्मदाजी के पानी को गंभीर में ले जाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है, फिर कालीसिंध में ले जायेंगे,फिर पार्वती में ले जायेंगे. ये सरकार है जिसने बुन्देलखंड में जनता को पानी पहुंचाने के लिए केन और बेतवा को जोड़ने का अभियान प्रारंभ किया है. यह वह सरकार है जिसने गांधीसागर के पानी को मन्दसौर और नीमच जिले लाने का ले जाने का फैसला किया है. यह वह सरकार है कि बाणसागर के माध्यम से पूरी विन्ध्य की धरा को हमने सिंचित करने का प्रयास किया है. और माननीय अजय सिंह जी यहां बैठे हैं. हमारे स्वर्गीय नेता अर्जुन सिंह जी ,मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं.उन्होने गुलाब सागर योजना प्रारंभ की थी उसको पूरा करने का काम भी किया तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है. हमने सिंचाई के रकबे को बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास किये हैं. और जहां नहरों से पानी नहीं जा सकता वहां दूरगामी परिणामों की दृष्टि से हम कोशिश कर रहे हैं नर्मदाजी के पानी को पाईप लाईनों के जरिये पहुंचायेंगे. अभी अलिराजपुर जिले में, झाबुआ जिले में, क्योंकि वहां केनाल इरीगेशन नहीं हो सकता ,ऊंची नीची ,उबड़ खाबड़ जमीन है, और कोई बड़ा बांध बनने की वहां गुंजाईश नहीं थी तो हमने नर्मदाजी के पानी को लिफ्ट करके पहले बड़ी पाईप लाईन से,फिर ग्रेविटी से लाकर और फिर पाईप लाईनों से जोड़ कर किसान के खेत तक पानी पहुंचा कर वहां से ड्रिप और स्प्रिंकलर के जरिये किसानों के खेतों में पहुंचाने की कोशिश की है. पेंच जैसी परियोजना अगर छिन्दवाड़ा और सिवनी जिले में आ रही है तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इच्छा शक्ति का परिणाम है. हमने परिदृष्य को बदलने की कोशिश की है. आप खेती को फायदे के धन्धे की बात करते हैं तो पहली चीज चाहिए सिंचाई. और मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारे प्रयास जारी रहेंगे. अभी तो हमने 36 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की क्षमता विकसित की है , 2018 तक हम बढ़ा कर हम 50 लाख हैक्टेयर तक ले जायेंगे.पानी होगा तो सिंचाई की

कल्पना की जा सकती है. माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे. उनको और उनके सहयोगियों को एक साथ आंकड़े दे देना चाहिए. वे एक साथ आंकडे नहीं देते. अभी वह कह रहे थे कि बिजली कितनी पैदा हुई. आज कितनी पैदा हुई. अध्यक्ष महोदय, एक जमाना था जब बिजली का उत्पादन प्रदेश में 2900 मेगावॉट होता था. उस समय हमारे मित्रों की सरकार थी. आज मध्यप्रदेश में बिजली की उपलब्धता 15 हजार मेगावॉट है.

अध्यक्ष महोदय, अभी भी हम 10-10 हजार मेगावॉट बिजली की सप्लाय करते हैं. आज की स्थिति पूछ रहे थे कि आज कितनी बिजली सप्लाय कर रहे हैं. आज 8500 मेगावॉट यानि 19 लाख यूनिट बिजली की सप्लाय हो रही है. मैं बिजली के बारे में इतना जरुर कहना चाहूंगा कि कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं. मैं ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हूं. अगर कोई कमी हो तो मैं उसको छुपाने का प्रयत्न करुं. मैंने फील्ड में जो अफसर भेजे थे. विधायक साथियों से जो चर्चा की थी. उस चर्चा में कई तरह के तथ्य सामने आये थे. इंदौर एयर पोर्ट पर मुझे कांग्रेस के कुछ मित्र मिले थे. मैं जल्दी जल्दी मिला था लेकिन उनका ज्ञापन भी लिया था. हमारे सारे विधायक मित्रों का उस समय कहना था कि अस्थायी कनेक्शन 4 महीने का नहीं, घटाकर 2 महीने का कीजिए. हमारे मित्रों ने कहा था 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दें और सब जले हुए ट्रांसफार्मर बदल दो. अध्यक्ष महोदय, मुझे भी लगा कि यह न्याय नहीं है. हमने तत्काल फैसला किया और यह तय कर दिया कि 50 से घटाकर 25 नहीं करेंगे केवल 10 प्रतिशत पैसा भी अगर जमा करेंगे तो जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जायेंगे.

अध्यक्ष महोदय, शायद 7 हजार के आसपास ट्रांसफार्मर जले हैं. उनको बदलने में थोड़ा सा समय लग सकता है. लेकिन हम तेजी से उनको बदलने का काम करेंगे ताकि किसान के खेतों में पानी पहुंच सके. अध्यक्ष महोदय, 10 प्रतिशत राशि बहुत कम होती है. लेकिन मैं यह जरुर कहना चाहता हूं कि बिजली पूरे प्रदेश में देने में जो जमीनी हकीकत है उसमें कई कठिनाईयां विधायक साथियों ने बतायी. मैंने जिन अफसरों को भेजा तो उन्होंने भी बतायी है. हम कल बैठे थे. बिजली विभाग के पूरे अधिकारियों को मैं साथ लेकर बैठा था. यह मध्यप्रदेश है जहां हमने फैसला किया और मुझे उस फैसले से गर्व है कि हम गांवों में, घर में 24 घंटे बिजली देंगे और खेती की बिजली 8 घंटे देंगे.

अध्यक्ष महोदय, जिन राज्यों में यह प्रयोग हुए हैं कि सिंचाई के लिए बिजली कितने घंटे चाहिए. मैं मानता हूं कि 24 घंटे नहीं चाहिए. क्योंकि सूखे के समय तो ट्यूबवेल में भी उतना पानी नहीं होता. कुए में उतना पानी नहीं होता कि आप 12-15 घंटे लगातार बिजली चलाते रहो. हमारे मालवा के कई मित्रों ने बताया कि लगातार 10 घंटे भी मोटर चलने की कई जगह स्थिति नहीं है. जब यह बात आयी कि एक साथ बिजली दें तो कई किसानों ने कहा कि एक साथ बिजली देने की जरुरत नहीं है क्योंकि 5-6 घंटे में पूरा पानी खत्म हो जाता है इसलिए अगर 2 चरणों में देंगे तो ज्यादा लाभ होगा. मैं, आपको और सब मित्रों को आश्वस्त करता हूं कि बिजली के क्षेत्र में जो कठिनाईयां बतायी गई है. बिल की समस्या या दूसरे प्रकार की समस्या हैं मैं उनको, बिजली मंत्री भी यहां पर बैठे हैं, पूरी तरह से समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोडेंगे.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्षजी, मैं चाहूंगा कि जो 10 प्रतिशत का आदेश निकाला है वह पहुंच गया होगा, अभी तक तो नहीं पहुंचा था. मैं जानना चाहूंगा कि गांव की बिजली भी जिससे गांव की सप्लाय, उसे भी 10 प्रतिशत में बदलने के आदेश इसमें सम्मिलित हैं क्या?

श्री शिवराज सिंह चौहान—अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी पक्ष के लोग हों, हमारा एक काम यह है कि व्यवस्थाएं भी सुचारु रुप से चलती रहें. एक कड़वी सचाई यह भी है कि वसूलियों का जहां तक सवाल है वह बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं. अब आपको लगातार बिजली चलाना है तो कोयला भी आपको खरीदना है. कर्मचारियों की तनख्वाह भी आपको देना है. अगर हम वास्तविकता पर, यथार्थ पर बात करें. अगर वह सिस्टम पूरा बैठ गया तो जो व्यवस्था चल रही है वह व्यवस्था भी पूरी तरह से बैठ जायेगी,प्रभावित होगी. इसलिए हमको दोनों काम करने होंगे. एक, जो पीड़ित किसान है उनको राहत देना पड़ेगी. उनको राहत देने के लिए हम किसी भी सीमा तक आगे जायेंगे. लेकिन गांवों में या शहरों में जो लोग बिजली के बिल भर सकते हैं, उनको बिजली के बिल भरना चाहिए नहीं तो पूरी व्यवस्था हम लंबे समय तक नहीं चला सकते. इसलिए आप सरकार में हों या हम सरकार में हों, हमको लंबे समय की योजना भी बनानी पड़ेगी जिससे एक सिस्टम को हम सदा एक गति में चलाने में सक्षम सिद्ध हो पायें इसलिए जो सक्षम लोग हैं, जो बिजली के बिल के पैसे दे सकते हैं उनको बिजली के बिल के पैसे देना चाहिए यह मेरा निवेदन है. जो परेशान है जो नहीं दे सकते, जिनकी फसलें खराब हुई है, हमने यहां तक फैसला किया है कि उनसे, जिनकी 50 प्रतिशत से ज्यादा फसलें खराब हैं, बिजली के बिलों की वसूली स्थगित कर दी जायेगी. उन किसानों से बिजली के बिलों की वसूली हम लोग नहीं करेंगे. जब उनकी फसल आ जायेगी तब उनसे ये जो डेफर्ड बिल है, उनके वसूली की बात होगी. क्योंकि आज वे संकट में है, परेशान हैं. वह कहां से देगा. (कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने का अनुरोध करने पर) अब हरेक बात पर नहीं.....आपने (श्री रावत) हाथ उठाया मैं बैठ गया. अगर चर्चा का यह भाव रहेगा तो मैं भी अपनी बात कह पाऊंगा. किसानों तक भी अपनी बात पहुंचेगी. देखिये आपने हाथ उठाया था तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ बैठ गया था. यह अगर भाव रहेगा चर्चा का तो मैं भी अपनी बात कह पाऊंगा, किसानों तक भी अपनी बात पहुंचेगी, आपकी बातों के उत्तर भी आयेंगे. आपकी चिंताओं का भी समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा.

श्री मधु भगत – बिजली की बात कर रहे हैं तो अगर पानी तो होगा लेकिन बिजली नहीं होगी तो पानी का उपयोग कैसे होगा. आजादी के बाद में और आजादी के पहले तो आज वहां पर कैसे सिंचाई हो.

श्री शिवराज सिंह चौहान – जहां पर बिजली नहीं है वहां पर बिजली पहुंचाने का प्रयास करेंगे.

श्री मधु भगत – आप बिजली पहुंचाने का प्रयास करें मैं अपने गांवों के नाम माननीय बिजली मंत्री जी को दे दूंगा.

श्री शिवराज सिंह चौहान -- अध्यक्ष महोदय प्रश्नोत्तर काल तो है नहीं लेकिन जहां पर बिजली नहीं है वहां पर बिजली पहुंचाने का प्रयास किया जायेगा. लेकिन एक चिंता से मैं सहमत हूं मुझे कल अपने

विधायक मित्रों ने भी बताया और मैं भी मानता हूं कि टेम्परेरी कनेक्शन को परमानेंट कनेक्शन करें और परमानेंट कनेक्शन के तो हमने 6000 रूपये प्रति वर्ष कर दिये हैं, 1200 रूपये प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष के हिसाब से साल भर के 6000 रूपये होते हैं लेकिन वास्तव में लागत कितनी है, आज मैं यहां पर सदन को इससे भी अवगत कराना चाहता हूं. जो विद्युत नियामक आयोग ने रेट तय किये हैं 31000 रूपये प्रतिवर्ष के 5 हार्स पावर की मोटर के तय किये हैं. 25 हजार रूपये हम 5 हार्स पावर की मोटर पर सब्सिडी दे रहे हैं यह भारी सब्सिडी हम यह किसान को बिजली पहुंचाने के लिए दे रहे हैं.

माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे मेरे विधायक मित्रों ने और अधिकारियों को भी हमने भेजा था यह आलोचना भी हुई कि कौन कहां पर रूक गया, लेकिन मैं विनम्रता के साथ में कहना चाहता हूं कि हर अधिकारी गावों में गया. मैंने 164 अधिकारियों से वन टू वन बात की है वह क्या देखकर आये हैं इसकी मैंने पूछताछ की है. लेकिन विधायक मित्रों से जो चर्चा हुई किसानों से जो चर्चा हुई है और उस चर्चा के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमको यह टेम्परेरी कनेक्शन की व्यवस्था समाप्त करना चाहिए धीरे धीरे परमानेंट कनेक्कशन सभी किसानों को दे देना चाहिए. इसलिए हमने कल ही बैठ कर एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है जिसमें हमने तय किया है कि 2017-18 तक जिन 6 लाख किसानों के पास में टेम्परेरी कनेक्शन हैं उनको परमानेंट कनेक्शन देने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि टेम्परेरी कनेक्शन से वह मुक्ति पा सकें. टेम्परेरी कनेक्शन में एक दिक्कत आती है किसानों को कि वह मांगते हैं तो दे देते हैं सीमा से ज्यादा होते हैं तो ट्रांसफार्मर ओवर लोड हो जाता है, ओवरलोड होता है तो वह बार बार जलता है, बार बार जलता है तो सिंचाई प्रभावित होती है किसानों का नुकसान होता है और विद्युत विभाग का भी नुकसान होता है.

मैं मानता हूं अध्यक्ष महोदय कि इसमें लगभग 5000 करोड़ रूपये लगेंगे , भारी धन राशि लगेगी हम लोग उस धनराशि को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे. लेकिन धीरे धीरे हम टेम्परेरी की व्यवस्था से परमानेंट की व्यवस्था में जायेंगे. तब तक जो आज आपने बिजली की समस्याएं बतायी हैं कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाते हैं अगर ज्यादा अस्थायी कनेक्शन दे दिये गये तो वहां पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये जाना चाहिए उसके लिए निर्देश हम देंगे, बिजली मंत्री हमारे यहां पर बैठे हैं वह इस समस्या पर ध्यान देंगे और तत्काल अगर बिजली की कुछ समस्याएं हैं तो हम उनका समाधान करेंगे, लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि बिजली की व्यवस्था को हमने पहले से कई गुना बेहतर करने का प्रयास किया है और किसी किसान की फसल हमने न तो सूखने दी है और न ही सूखने देंगे.

श्री रामनिवास रावत – माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि जबरदस्ती किसानों से 60 हजार रूपये लिये जा रहे हैं और मैं दूर नहीं हूं श्योपुर के विधायक पास में बैठे हैं उनसे पूछ लें किस तरह से किसानों को लूटा जा रहा है.

श्री शिवराज सिंह चौहान – मैंने आपका पूरा सम्मान किया जब आपने हाथ उठाया था तो मैं बैठ गया था अब हर बात में टोका टोकी न करें.

डॉ गोविन्द सिंह – माननीय मुख्यमंत्री जी अभी मैंने अपने भाषण में जिक्र किया है कि परमानेंट कनेक्शन के पैसे जमा हैं, लेकिन टेम्परेरी कनेक्शन के पैसे जमा किये बिना परमानेंट कनेक्शन नहीं दे रहे हैं यह इस तरह का आदेश आपके अधिकारी बता रहे हैं कि गया है.

श्री शिवराज सिंह चौहान -- मैं जरूर इसको दिखवाऊंगा अगर ऐसी गलती होगी तो सुधार कर लेंगे, अगर जरूरी होगा तो आपसे अलग से चर्चा भी कर लेंगे. ऐसा नहीं है कि हम सदन में आमने सामने ही चर्चा करें मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से इस सदन के अलावा भी, कोई भी विधायक चाहे वह सत्तापक्ष का हो या विपक्ष का हो कोई समस्या अगर बतायेंगे तो हम ध्यान से सुनेंगे और उसके समाधान का ईमानदार प्रयास करेंगे, क्योंकि यह हमारी ड्यूटी है यह हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि कोई समस्या कहीं से भी आये, मैं यह नहीं कहता कि हमारा पूरा सिस्टम पूरी तरह से परफेक्ट है, कमियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं. क्योंकि मैं यह नहीं कहता कि पूरा सिस्टम हंडरेड परसेंट परफेक्ट है, कमियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं और अच्छी सरकार वह है कि अगर कोई कमी है तो उस कमी को दूर करने का गंभीरता पूर्वक प्रयास करे । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने पिछले दिनों जो प्रयास किये उन प्रयासों का परिणाम था, जो सच है कि कृषि विकास दर म0प्र0 की लगातार 4 साल से 20 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है, 20 प्रतिशत के उपर या 18.91 प्रतिशत, यह जब यूपीए की सरकार थी तब भी यूपीए की सरकार ने कृषि कर्मण अवार्ड म0प्र0 को दिया था, एनडीए की सरकार ने भी कृषि कर्मण अवार्ड म0प्र0 को दिया है । पिछले दिनों हम लोगों ने जो प्रयास किये, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जीरो प्रतिशत ब्याज पर हमने कर्जा दिया । सीड रिपलेसमेंट की दर हमने बदली, 30 प्रतिशत तक हमने पहुंचाई, अलग-अलग हमने हार्टीकल्चर पर एवं दूसरी चीजों पर जो सब्सिडी दी उसके बहुत विस्तार में मैं नहीं जाउंगा, गिनाउंगा तो बहुत देर लगेगी, लेकिन उसी का परिणाम है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जहां 2004 और 2005 में 1 करोड़ 33 लाख 44 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था, 2014-15 में यह बढ़कर 4 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन हुआ जो अपने आप में हिंदुस्तान में रिकार्ड है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मध्यप्रदेश के किसान है जो पंजाब को गेंहूं के उत्पादन में टक्कर दे रहे हैं । अगर आप मध्यप्रदेश को देखेंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, सोया, चना दाल, तिलहन, लहसुन में हम देश में नंबर एक हैं, गेंहूं, प्याज, संतरा, धनिया में देश में नंबर 2 हैं, टमाटर, खरबूज, गुलाब, सीताफल में देश में नंबर 3 हैं, हमने निश्चित तौर पर कृषि का उत्पादन बढ़ाने में अनेकों रिकार्ड बनाये हैं, मैं उसकी विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात भी सही है कि पिछले तीन-चार साल से लगातार हमारा किसान संकट में रहा है, परेशानी में रहा है और इस साल का जो संकट है मैंने बताया यह संकट अपने आप में अभूतपूर्व संकट है, क्योंकि ओले अगर गिरते हैं तो ओले एक इलाके में गिरते हैं, ओले जहां गिरते हैं वहां फसल का नुकसान होता है, पट्टी में गिरते चले जाते हैं और वहां जाकर सर्वे करना भी सरल होता है, लेकिन सोयाबीन की फसल का जहां तक सवाल है पूरे प्रदेश में सोयाबीन की फसल को व्यापक नुकसान पहुंचा है, एलोमोजिक के कारण पहुंचा, अतिवृष्टि के कारण पहुंचा, कम वर्षा के कारण

पहुंचा और अभी तक हमें जो जानकारी है लगभग 33 हजार गांव में 44 लाख हेक्टेयर की फसल खराब हुई है, बरबाद हुई है । लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि सोयाबीन बिलकुल पैदा ही नहीं हुआ, अगर आप आंख उठाकर देखेंगे, मंडियों में जो आवक है सोयाबीन की उसको देखते हुये लगभग यह अंदाज है कि 37, 38 लाख मीट्रिक टन उत्पादन फिर भी मध्यप्रदेश में हुआ है । आज हम कहें कि मंडियों में पुराना रखा आ रहा है तो यह सच नहीं होगा । इस समय आप कहीं भी किसी भी मंडी में जाकर देख लीजिये सोयाबीन लगातार आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सोयाबीन की फसल को नुकसान नहीं हुआ, सोयाबीन की फसल को भी नुकसान हुआ है, उड़द की फसल को भी नुकसान हुआ है, मूंग की फसल को भी नुकसान हुआ है और हम पूरे अगर उधर शहडोल संभाग में देखें, विंध्य की धरा पर, महाकौशल के कई जिलों में जहां धान उत्पादित होती है, सूखे के कारण धान की फसलें तबाह और बरबाद हुई हैं, लेकिन इसमें भी एक तथ्य और है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां किसानों ने मिश्रित फसलें बोई हैं जहां एक फसल यदि खराब हुई है तो दूसरी फसल उनकी आ गई है वह उतने घाटे में नहीं रहे जितने एक फसल बोने वाले किसान रहे । हमको यह भी सोचना पड़ेगा कि आगे यह संकट न आ पाये, माननीय अध्यक्ष महोदय, पुराने जमाने में हम देखते थे, हमारे बुजुर्ग यह कहते थे कि भई खेत हैं तो चार खूंट पर अलग-अलग चीज बोना, एक मत बोना और यह इसलिये करते थे कि एक फसल अगर बिगड़ जाये तो दूसरी फसल आ जाये । दूसरी बिगड़ जाये तो तीसरी आ जाये । हमने सिंचाई का रकवा तो बढ़ाया लेकिन उसका एक नुकसान भी हमें समझ में आया है, पहले हम दलहन बहुत बोते थे, तुअर बोते थे, मटर बटरी बोते थे, तेबड़ा बोते थे, मसूर बोते थे, चना बोते थे, अब जहां जहां सिंचाई है माननीय अध्यक्ष महोदय, अपवाद छोड़कर या तो धान या गेंहूं और एक फसल सोयाबीन की, जहां तीन फसल आती है वहां मूंग की फसल भी लेते हैं । अब वैज्ञानिक अध्ययन यह बताता है कि अगर केवल सोयाबीन की फसल एक ही खेत में आप लगातार बोते चले जाओगे तो कीटव्याधी उसमें आयेगी, फसल खराब होगी, अगर जमीन की पोषक क्षमता को पूरी तरह से नष्ट नहीं होने देना है तो फसल बदल-बदल कर बोना चाहिये और इसलिये हमको यह प्रयास भी करने पड़ेंगे. अगर हर साल सोयाबीन बोया जायेगा तो खराब होने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ेगी, इसलिये किसान को एजूकेट भी करना पड़ेगा कि आधे में सोयाबीन इस साल बोया तो आधे में मत बोयें, दूसरी फसल बोयें । इस तरह के प्रयास भी माननीय अध्यक्ष महोदय हम लोगों को करने पड़ेंगे, लेकिन अभी जो संकट आया है उस संकट के बारे में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, हम लोगों ने यह फैसला किया है कि राहत की राशि किसान को मिले, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगें । वित्तमंत्री यहां बैठे हैं अभी विनियोग विधेयक पारित होना है, हमने बैठक बुलाई और बैठक बुलाने के बाद आकलन किया कि लगभग कितनी धनराशि खर्च होगी तो लगभग यह आया कि 3 हजार करोड़ से लेकर 3500 करोड़ के बीच राहत की राशि बांटनी पड़ेगी तो 3 हजार करोड़ से ज्यादा हमको राहत की राशि का प्रावधान करना था, लेकिन राहत की राशि नहीं. अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना की चर्चा आज मैं जरूर करना चाहूंगा .कई वर्षों से जो फसल बीमा योजनायें चल रही हैं ,कई कई वर्षों से चल रही हैं, यह फसल बीमा योजनायें किसान के

साथ धोखा है, यह किसान की फसल का बीमा नहीं है, यह किसान के बैंक के ऋण का बीमा होता है और इसलिये किसान हर साल ठगा जाता है , हर साल छला जाता है . मैंने फसल बीमा योजना का अध्ययन किया हमने अच्छी फसल बीमा योजना कैसे बन सकती है उसके लिये एक कार्यशाला का आयोजन किया था . इस फसल बीमा योजना में किसान का प्रीमियम तो कट जाता है लेकिन मापदंड जो बने हैं वह ऐसे बने हैं कि 3 साल का एवरेज निकालेंगे . अब हर साल अगर नुकसान होगा तो एवरेज फसल का कहां से अच्छा आयेगा . पिछले साल भी हो गया, इस साल भी हो गया, अब भी हो गया तो एवरेज अच्छा आयेगा नहीं और अच्छा एवरेज नहीं आयेगा तो एवरेज के आधार पर अगर फसल बीमा योजना की राशि दी जायेगी तो या तो मिलेगी नहीं या बहुत कम मिलेगी. इस बार हम लोगों ने पूरी कोशिश की. मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं माफ कीजियेगा डंडा चलाने जैसा काम किया है हमने और कहा कि एक एक किसान के प्रीमियम की राशि जमा करो फसल कटाई प्रयोग पूरे करो और ठीक क्लेम बनाओ,बीमा कंपनी से पैसा लेने के लिये. अब बीमा कंपनियों का भी यह जो खेल है इसको बदलना पड़ेगा. भारत सरकार इस पर बहुत गंभीरता के साथ में विचार कर रही है. हमारे देश के प्रधान मंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी गंभीरता से विचार कर रहे हैं कृषि मंत्री जी और वित्त मंत्री जी भारत सरकार के गंभीरता से विचार कर रहे हैं. उस बैठक में मैं भी सम्मलित हुआ था. जो नई फसल बीमा योजना बनाने के लिये बुलाई थी भारत सरकार ने. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फसल बीमा योजना छलावा है, इस बार हमने फसल कटाई प्रयोग ठीक किये हैं और उसके आधार पर जो हमने क्लेम किया है और उस क्लेम के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 3 हजार से लेकर के साढे तीन हजार करोड़ रूपया तक हम फसल बीमा योजना के भी किसानों के लिये ले लेंगे. यह गंभीर प्रयास हमने किये हैं लेकिन उसमे भी , वो रकम फसल बीमा करने वाली कंपनी नहीं देती, वो यह कहते हैं कि हम तो उतना ही देंगे जितनी प्रीमियम की राशि जमा होगी, और प्रीमियम की राशि से ज्यादा पैसा अगर फसल बीमा योजना का बनता है तो हम नहीं देंगे. वो केन्द्र सरकार आधा दे और आधा राज्य सरकार दे. आज जो प्रावधान हम लोग कर रहे हैं जिसके बारे में जिक्र वित्त मंत्री जी करेंगे हम 1500 करोड़ रूपये का प्रावधान इसलिये कर रहे हैं कि फसल बीमा योजना का मध्यप्रदेश के हिस्से का पैसा हम दे सकें. 1500 करोड़ हमारा, 1500 करोड़ केन्द्र सरकार का और बाकी साढ़े तीन सौ करोड़ के आसपास बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के रूप में जो पैसा इकट्ठा किया वह मिला कर लगभग साढे 3300 करोड़ रूपया की राशि बनेगी और मैं मानता हूं कि यह राशि किसान के खाते में पहुंचेगी. इसमें हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे. और एक हद तक किसान के नुकसान की भरपाई करने की स्थिति में हम पहुंच जायेंगे, लेकिन केवल इतना ही नहीं. किसान लगातार परेशान रहा है और इसलिये वह कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं है , कर्जा दोनों तरह का किसान पर है. एक तो कर्जा है उस पर जो खाद और बीज के लिये उसने लिया है, सहकारी बैंकों से और दूसरी व्यवस्थाओं से कर्जा लिया है और दूसरा कर्जा है प्रायवेट साहूकारों से जो कर्जा लिया है और इसलिये हम लोगों ने यह फैसला किया है कि किसान से कर्ज वसूली स्थगित करेंगे . हमने सहकारी बैंकों के अलावा जो कामर्शियल बैंक है उन बैंकों को भी यह लिखा है और आग्रह किया है कि उनकी कर्ज वसूली भी स्थगित

हो जाये, जो प्रभावित किसान है मैं उनकी बात कर रहा हूं. जो किसान पैसे दे सकता है जिसकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा उसको पैसा देना चाहिये. क्योंकि जैसी मैंने बिजली की बात कही है वैसे ही हमारे बैंकिंग सिस्टम को भी हमको बचाना पडेगा. ऐसे कुचक्र में हमारे सहकारी बैंक न पड़ जायें कि कल कर्जा देने की स्थिति में ही न रहें . तो हमको उससे भी सावधान रहना पडेगा लेकिन जो किसान जिनकी फसलें खराब हुई हैं प्रभावित हुई है उनसे कर्ज वसूली स्थगित कर दी गई है . माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल कर्ज वसूली स्थगित नहीं की है हमने, हमने यह फैसला भी किया है कि कर्ज के 1 साल का ब्याज भी किसान नहीं चुकायेगा प्रदेश की सरकार चुकाने का काम करेगी. और हमने यह केवल कहा नहीं है, इस बजट में हमने उसके लिये प्रावधान भी किया है क्योंकि हम जानते हैं कि पहले केवल अल्पकालीन ऋण अगर दीर्घकालीन ऋण में परिवर्तित कर दिये जाते थे, मध्यावधि में परिवर्तित कर दिये जाते थे , ब्याज का मीटर लगातार चालू रहता था और ब्याज के मीटर के लगातार चालू रहने के कारण किसान के ऊपर ब्याज, दंड ब्याज, और पता नहीं कौन सा ब्याज पर ब्याज इतनी बड़ी धनराशि हो जाती थी जिसको किसान चुकाने की स्थिति में नहीं रहता था . इसलिये यह फैसला किया है कि ऋण वसूली स्थगित और ऋण के एक साल का ब्याज सरकार चुकाने का काम करेगी और अगले साल के खाद बीज का कर्जा भी उसको ओवरड्यू होने के बाद भी मिल जाये इसका इंतजाम करने का फैसला प्रदेश की सरकार ने किया है. ताकि जो रवि की फसल बोनी है उसकी किसान की बोनी ठीक ढंग से हो जाये. लेकिन एक बात और भी हमने तय की है और जिसको सख्ती से हमको अमल करना पडेगा और वह सख्ती इसलिये कि प्रायवेट जो साहूकार है, प्रायवेट साहूकार से भी लोगों ने, किसानों ने पैसा लिया है. आज वह पैसा किसान चुकाने की स्थिति में नहीं है. ज्यादा दिक्कत इससे होती है कि किसी प्रायवेट साहूकार से पैसा ले लिया और वह डंडा लेकर पीछे पड़ गया कि मेरा पैसा वापस लौटाओ, तो हमने कलेक्टर्स को, एसपीज को यह निर्देश दिये हैं कि ऐसे साहूकार जिन्होंने किसान को कर्ज दिया है और किसान देने की स्थिति में नहीं है, वह कर्ज की वसूली नहीं करें. अगर करेंगे, तो उनको दंडित करने का काम किया जायेगा. इस समय जब किसान परेशानी में है और संकट में है, तब उनसे जबरदस्ती प्रायवेट कर्ज की भी वसूली न हो उस दिशा में हमने कहा है कि एसपीज और कलेक्टर्स इस मामले में ध्यान रखें. लेकिन एक बात और है यह राहत की राशि है, केवल किसानों के लिये है. हमने देखा कि कई किसान ऐसे हैं, जो खुद खेती नहीं करते हैं, खुद खेती के साथ साथ अनेकों काम धंधों में लगे रहते हैं. शासकीय सेवा में हैं. राजनीति में काम कर रहे हैं. व्यापारी हैं और कुछ कर रहे हैं. अब वह किसान जो इनकम टैक्स पे करते हैं, अब ऐसे उदाहरण आये, अब अजय सिंह जी के पास अगर चैक जाये, तो उस समय चेक की, मैंने केवल प्रसंगवश नाम लिया है, तो चेक की आवश्यकता नहीं है. कोई आईएएस, अईपीएस अफसर ले ले, तो हम में से सब तय करें कि हम कोई राहत की राशि नहीं लेंगे. जो इनकम टैक्स देता है, वह राहत की राशि पाने का पात्र नहीं होगा. यह फैसला भी हमने किया है, क्योंकि जिनके पास आदमनी के और जरिये हैं, जो अपनी खेती के अलावा भी अपने परिवार को चला सकते हैं दूसरे काम धंधों के माध्यम से, उनको राहत राशि की पात्रता नहीं रहेगी,

क्योंकि मैं मानता हूं कि वे अपने साल भर का, क्योंकि यह राहत इसलिये होती है कि मुसीबत, संकट में अगर किसान है, तो उसके काम आ जाये. इसलिये इस बार यह फैसला किया है. जहां तक सूखाग्रस्त तहसीलों की बात आई. इधर और उधर के मित्रों ने भी कहा. मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने इस बार यह फैसला किया है कि केवल तहसील नहीं, तहसील में वर्षा मापक यंत्र कितने हैं आपके पास. जिले में लगा हुआ है. कई तहसीलों में है, कई तहसीलों में है ही नहीं और जब पानी के आधार पर अभी सूखाग्रस्त कैसे होता है कि बारिश कितनी प्रतिशत कम हुई है. मुख्य आधार यही होता है और कई जगह बारिश का सही मापन भी कठिन है और मापन तो क्या है कि अगर जिला मुख्यालय पर पानी खूब गिर गया, तो पता चला कि तहसील में नहीं गिरा. तहसील मुख्यालय पर गिर गया, तो चार किलोमीटर बगल के गांव में पानी नहीं गिरा. हालत तो यह होती है कि टीटी नगर में पानी गिरता है और बैरागढ़ सूखा रह जाता है. एक ही शहर में दो तरह की बारिश का जो पैटर्न है, वह देखने में आता है. इसलिये हमने तय किया है कि अगर जरुरत पड़ी तो 5-5,10-10 गांव के क्लस्टर भी अगर सूखा प्रभावित हैं, तो उनको भी सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जायेगा. पूरी तहसील में अगर नहीं है तो जिन पेचेज में होगा, वहां सूखाग्रस्त घोषित कर देंगे. दूसरी चीज जो उपाय हमने किये हैं, जैसे हमने कहा कि फसल अगर खराब है, तो राहत के लिये सूखाग्रस्त घोषित करने की जरुरत ही नहीं है. अब कई जह तो उन्होंने कहा कि पानी खूब गिरा, एक साथ गिर गया और गिरकर बहकर निकल गया. उस आधार पर वह सूखाग्रस्त घोषित ही नहीं हो सकती.लेकिन अगर उस आधार पर भी किसान की फसल खराब हुई है, तो हम सारी सुविधायें, जो सूखाग्रस्त किसानों को दी जाती हैं, वह सारी की सारी सुविधायें हम वहां भी देंगे, ताकि पूरी तहसील अगर सूखी नहीं है, ज्यादा बरसात के कारण सूखाग्रस्त घोषित नहीं कर सकते, तो फसल जिन किसानों की प्रभावित है, उनको हम लाभ दे सकें. इसलिये हमने यह फैसला किया है. हम लोगों ने यह भी फैसला किया है, कई मित्रों ने कहा कि जो बंटाई पर दे दी, उनका क्या होगा. अधिया पर दे दी, तिया पर दे दी, यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो लेता है, वह जो मालिक होता है खेती का, उसको पैसा दे चुका होता है. अब जब राहत की राशि बांटने का सवाल आता है, तो जो मालिक है अधिकारिक रुप से, वैधानिक रुप से वही पात्र होता है. अब उसमें जो ईमानदार निकल जाये, वह तो कह देते हैं कि हमें नहीं इसको दे दो. लेकिन अगर वह ईमानदार न हो, तो लीगली हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम उसको दिला सकें.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, जो वाकेही परेशान हैं, गरीब हैं और जिन पर बैंक का लोन है, किसी का ऋण है. हम राहत राशि बैंकों के माध्यम से लगभग प्रदाय करते हैं. आपके ई पेमेंट सिस्टम के माध्यम से. तो कभी कभी बैंक वह राहत राशि को अपने कर्ज में जमा कर लेती हैं और वह राहत राशि किसान तक नहीं पहुंच पाती है. तो ऐसी स्थिति में आप ऐसी व्यवस्था बनायें कि वह राहत राशि किसान तक पहुंच जाये किसी भी तरह से.

श्री शिवराज सिंह चौहान – अध्यक्ष महोदय, हम पूरा प्रयास करेंगे, बैंकों से आग्रह करेंगे कि यह राहत की राशि है, इस राशि से वह कर्जा न काटे. लेकिन एक बात जो मैं अभी कह रहा था इसमें विधान सभा के अगले सत्र में मुझे लगता है कि हमको जो हमारी भू राजस्व संहिता है, उसमें संशोधन करना पड़ेगा और यह मैं इसलिये कह रहा हूं आज अगर कोई बटाई पर जमीन देता है पोलीय या लीज कोई कह ले अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम कहते हैं तो यह उनका वैधानिक अधिकार नहीं है, लिखा-पढ़ी केवल सूखी होती है, उस लिखा-पढ़ी पर बदल जाए, नहीं बदल जाए, यह विश्वास का सवाल होता है. अब मैं मानता हूं कि जोत के आकार भी कई बहुत छोटे हो गये हैं, कई छोटे किसान भी कोलीब या बटिया दे देते हैं. कई बड़े किसान ऐसे हैं उनसे छोटा किसान ले लेता है उसको हम अगर लीगल कर देंगे और उसका वैधानिक अधिकार जब हो जाएगा कि वह अगर बटिया पर या लीज पर देता है तो भी वह दे सकता है, लेकिन जमीन पर अधिकार उसी का रहेगा, भू-स्वामी वही रहेगा इस मामले में विचार करके मुझे लगता है कि अगर हम संशोधन लेकर के आयेंगे तो ऐसे किसानों को काफी फायदा होगा उस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन हमने यह प्रयास किया है कि अधिया-बटिया पर जिन्होंने जमीन दी है पैसा उनको ही मिल जाए, क्योंकि उन लोगों ने खाद-बीज डाल लिया, जमीन का पैसा उन्होंने दे दिया अगर उनको राहत की राशि भी न मिले या बीमा योजना का पैसा भी न मिले तो उनके साथ बड़ा अन्याय होगा. एक बात और मुझे इस संबंध में लगती है हमारे कुंवर सिंह टेकाम जैसे माननीय सदस्यों ने जो कि आदिवासी क्षेत्रों के विधायक हैं, उन लोगों ने कही है कि जिनको वनाधिकार के पट्टे मिल गये हैं, लेकिन वह वैधानिक अधिकारों और कई अधिकारों से वंचित है और इसलिये फैसला भी कर रहे हैं कि राहत की राशि सूखे से या कैसी भी फसलों का नुकसान हो उन किसानों को राहत की राशि प्रदान की जाएगी जिनको वनाधिकार कानून के अंतर्गत पट्टे देकर जमीन के मालिक बनाने का हमने काम किया है ताकि वह भी उससे वंचित न रह पाये. मिर्ची जैसे नुकसान की कई मित्रों ने चर्चा की है और भी फसलें जैसे उड़द की फसलों को कई जगह अलीराजपुर, टीकमगढ़ में नुकसान पहुंचा है, उनको भी सम्मिलित किया जाएगा, मूंग की फसल को हुए नुकसान को भी सम्मिलित किया जाएगा. मैं पूरी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सदन से यह कहना चाहता हूं की कोई भी प्रभावित व पीड़ित किसान वंचित न रहे उस बात का हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे. अब एक बात यह है कि फसलें तो खराब हो गईं, लेकिन एक बेटी की भी शादी की बात आयी थी, अभी संकट है इसलिये फैसला किया है कि इस संकट से निकालने का हर संभव सरकार प्रयास करेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं. एक फैसला और किया है कि अगर किसान की फसल ऐसी तबाह और बर्बाद हो गई हैं तो उनके यहां पर भोजन की भी दिक्कत आयेगी तो हम लोगों ने यह फैसला किया है कि एक रूपया किलो गेहूं, एक रूपये किलो चावल और एक रूपया किलो नमक अगली फसल तक किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि राहत की राशि से उसको भोजन के लिये खर्च न करने पड़े हम वह इंतजाम भी करेंगे. हमने यह भी फैसला किया है कि बिटिया की शादी है, फसल खराब हो गई है, कई जगहों पर ऐसी चीजें पढ़ने में आयी हैं उसके कारण से किसान हताश, निराश हो जाता है उसके कारण कई बार ऐसे कदम

उठाता है जो मानवीय गरिमा के अनुकूल नहीं है और इसलिये फैसला किया है कि अभी तक मुख्यमंत्री कन्यादान अथवा निकाह योजना में सामूहिक रूप से एक कार्यक्रम होता था तो राशि देते थे अब यह फैसला किया है कि बिटिया की अगर शादी है तो कोई किसान चिन्ता न करें, बिटिया की शादी के लिये किसानों को 25 हजार रूपये का चेक उस किसान के घर में भेजा जाएगा, उसको केवल आवेदन देने की आवश्यकता है कि मेरी बिटिया की शादी है, हम उसकी बिटिया की शादी में साथ देंगे. मैं वह हर संभव व्यवस्था करना चाहता हूं जिसके कारण इस संकट की घड़ी में किसान को निराश-हताश न होना पड़े इसलिये कर्ज वापसी से लेकर, फसल बीमा के पैसे से लेकर, राहत की राशि लेकर तथा बिजली के पैसे जमा करने को लेकर बिटिया की शादी तक हर संभव उपाय करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम बजट में और कटौती कर देंगे. नहीं बनाएंगे एक साल तक सड़कें-पुल-पुलियाएं और नहीं बनाएंगे एक साल तक बांध, लेकिन किसान को हताश नहीं होने देंगे. संकट की इस घड़ी में पूरी ताकत के साथ सरकार किसानों के साथ खड़ी है. मैं आप सबको भी आव्हान करना चाहता हूं कि पक्ष अथवा विपक्ष के जो भी माननीय सदस्य हों अगर बीच में आपको दिक्कत लगती है तो आप उसको अवगत कराईये, यह एक ऐसा समय है जिसमें हम सबको मिलकर के मुकाबला करने की जरूरत है. इस मामले में न हम राजनीति करें ना ही आप राजनीति करें, मिलकर के किसान की सेवा करके, यह साल कैसे बेहतर निकल जाए और अगली फसल कैसे ठीक आ जाए हम इसमें सब मिलकर के कोशिश करेंगे. मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार इसमें अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी. यह बात भी आवश्यक है कि व्यापक पैमाने पर राहत के काम चालू किये जाएं इसलिये एक फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, केन्द्र की सरकार ने किया वह फैसला यह किया कि जो साल में 100 दिन की मजदूरी देते थे साल भर में मनरेगा में उसको बढ़ाकर के 150 दिन कर दिया जाएगा. 150 दिन उसको कर दिया गया है.

श्री रामनिवास रावत—यह तो यूपीए की सरकार ने पहले ही कर दिया था.

श्री शिवराज सिंह चौहान—नहीं भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी किया है मान भी लो भाई. मनरेगा के अंतर्गत व्यापक पैमाने पर राहत के काम प्रारंभ किये जायेंगे और उसमें एक बात मेरे दिमाग में यह आई है उससे सारा सदन सहमत होगा. मुकेश जी कुछ कह रहे हैं शायद.

श्री मुकेश नायक – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो कृषि विभाग ने सहकारी बैंकों को जो मांग पत्र दिया है उसके अनुसार सहकारी बैंकों ने भंडारण नहीं किया और उसका परिणाम यह हो रहा है कि किसान जब बैंक और सोसायटी में जा रहे हैं तो खाद,बीज और पेस्टीसाइड उनको नहीं दिया जा रहा है इसमें विलंब हो रहा है. जैसे पन्ना जिले में भूमि विकास बैंक ने एंटीसिपेट कर लिया था कि अब किसान बोहनी नहीं करेगा इसीलिये अगर हम भंडारण कर लेंगे तो बैंक को क्षति पहुंचेगी तो उन्होंने कृषि विभाग ने जो मांग पत्र दिया था उसके अनुसार भंडारण नहीं किया है इसकी भी व्यवस्था आप कराने की कृपा करें.

श्री शिवराजसिंह चौहान - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि किसान को रबी की फसल के लिये खाद की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी. अगर किसी भी माननीय सदस्य को ऐसा लगता है कि दिक्कत है तो आप जरूर बताईये हम उस दिक्कत को दूर करेंगे. खाद भरपूर उपलब्ध है. अगर आपको लगता है तो उस दिक्कत को आपके साथ खड़े रहकर दूर करने का प्रयास करेंगे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं इस साल हमारे पास बड़े बांधों में पर्याप्त पानी है. एक तो हमें तात्कालिक राहत है दूसरी हमें यह कोशिश करनी है कि अगली रबी की फसल उसकी कैसे ठीक आये ताकि इस कुचक्र से उसको मुक्ति मिल पाये. 28 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई के लिये हमारे पास पानी मौजूद है. यथा संभव बड़े बांधों में पानी का भंडारण बहुत अच्छा है. अभी भिण्ड की बात सामने आई थी. श्योपुर की बात सामने आई थी. श्योपुर के विधायक कल मुझसे मिले थे. आज भी दूसरे विधायक जी ने अवगत कराया. हम राजस्थान के लगातार संपर्क में है. हमारी अधिकारियों की टीम राजस्थान में बैठी हुई है. गांधी सागर बांध से जो पानी आता है चूंकि राजस्थान से होकर वह पानी आता है तो उनकी अपनी समस्याएं हैं लेकिन हम लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि मध्यप्रदेश के हिस्से का पूरा पानी हमें मिल जाये. हम लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि वह पानी हमको मिले. थोड़ी देर हो सकती है. फसलों के चक्र के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा. हम किसानों से भी निवेदन करें कि जहां पानी कम है वहां हम ऐसी फसल बोयें जिसमें पानी कम लगता है. जहां पर्याप्त पानी है वहां गेहूं जैसी फसलें बोयें. हमने पूरी योजना बनाने की कोशिश की है. सिंचाई मंत्री जी हमारे वित्त मंत्री भी हैं. हमने हर संभव कोशिश यह की है कि जहां जितनी पानी की उपलब्धता है उसके आधार पर हम किसानों का जागृत कर सकें कि कौन सी फसल उनके यहां हो सकेगी. उसका प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं. मैं मनरेगा की योजना के बारे में बात कर रहा था.

श्री रामनिवास रावत – माननीय मुख्यमंत्री जी.. नकली खाद की बात है.

श्री शिवराजसिंह चौहान – माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं पूरा कर लूं इसके बाद उत्तर दूंगा.

अध्यक्ष महोदय - पूरा हो जाने दीजिये. बैठ जाईये.

श्री शिवराजसिंह चौहान – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मनरेगा की बात कर रहा था. मनरेगा के माध्यम से एक व्यापक अभियान हम जल संरचनाएं बनाने का करेंगे. चेक डेम,स्टाप डेम,बोरी बंधान,छोटे तालाब और जो पुराने तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार और हमारे वन मंत्री बैठे हैं जो फारेस्ट की जमीन है उस पर भी हम तालाब बनाएंगे ताकि वाटर रीचार्जिंग का काम हम पूरा कर सकें. तालाब से कुंओं में और ट्यूबवेल्स में भी पर्याप्त पानी आ सके उसका अभियान हम चलाने का काम करेंगे. लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजें और हैं जो युद्ध स्तर पर करने की आवश्यकता है. माननीय अध्यक्ष महोदय, शार्ट टर्म प्लानिंग के अलावा क्योंकि इस बार हम अच्छी फसल ले आएं इसका तो हम पूरा प्रयास करेंगे लेकिन कुछ दीर्घकालिक उपाय हमको करने पड़ेंगे इसलिए अध्यक्ष महोदय, एक बात मैंने कही थी कि स्थाई कनेक्शन देने का अभियान चलाया जायेगा. दूसरी चीज हम यह तय कर रहे हैं कि मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड, स्वाईल हेल्थ

कार्ड हम 2017 के अंत तक हर एक किसान को उपलब्ध करा देंगे. आज एक दिक्कत और है अध्यक्ष महोदय कि किसान को जब यह पता नहीं होता कि उसकी जमीन में कौन से पोषक तत्व हैं कौन से पोषक तत्व नहीं हैं तो कई बार जिस खाद की जरूरत नहीं होती वह डाल दिया जाता है. यूरिया की भरमार के कारण कई जगह फसलें भी खराब हो रही हैं और जमीन की उर्वरता भी व्यापक पैमाने पर प्रभावित हो रही है. अगर यह स्वाईल हेल्थ कार्ड हमने किसान को बनाकर दे दिये तो इसके बाद किसान को यह पता चल पायेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाला समय सौर ऊर्जा का समय है अभी हम जो बिजली पर सब्सिडी दे रहे हैं वह भारी सब्सिडी है बड़ी सब्सिडी है यदि हम सोलर पंप किसानों को उपलब्ध करा दें, मैंने जो प्रयोग हुए हैं उनको देखा है यदि पांच हार्स पॉवर की मोटर चलानी है तो हम अगर एक सोलर पंप ले लेते हैं तो उसके पांच हार्स पॉवर की मोटर बहुत अच्छे ढंग से दिन भर चल सकती है और आजकल धूप की जरुरत भी नहीं है अगर पर्याप्त रोशनी है तो ऐसी टेक्नॉलाजी आ गई है जिसके कारण सोलर मोटर चलाई जा सके इसलिये हम सोलर मोटर पर भी सब्सिडी देने का प्रावधान कर रहे हैं इससे हम खंभे और तार की झंझट से मुक्त हो जायेंगे, ट्रांसफार्मर जलना हमारा बच जायेगा और भविष्य की ऊर्जा तो सौर ऊर्जा है उस दिशा में हमको तेजी से आगे बढ़ना चाहिये इसलिये हम यह प्रयास करेंगे. अब हमको क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा. एक निवेदन मैंने माननीय सदस्यों के सामने किया था कि लगातार सोयाबीन बोने से भी नुकसान होता है मैं यह नहीं कहता हूँ कि सोयाबीन नहीं बोया जाना चाहिये लेकिन फसल परिवर्तित होती रहनी चाहिये इसलिये फसल चक्र को बदलने का भी एक अभियान चलायेंगे. दो तरह की चीजें हम कर रहे हैं एक तो एक ऐसे डिमास्ट्रेशन फार्म बना रहे हैं जिसमें अगर एक हेक्टयर जमीन है या पांच एकड़ जमीन है तो कौन-कौन सी फसल बोयें और कैसे बोयें जिससे किसान फायदा कमा सके और खेती को फायदे का धंधा बना सके क्योंकि यदि वह सिर्फ परम्परागत फसलें किसान बोता है तो उसमें उतना लाभ नहीं होता है वह हम बनाने का काम करेंगे लेकिन उसके साथ-साथ हम कृषि और उद्यानिकी को हम कैसे बढ़ावा दें कुछ किसान हार्टिकल्चर की बेहतर खेती कर रहे हैं नीमच, मंदसौर में अभी लहसुन की फसल हो रही है लहसुन बहुत अच्छा आया है मंडियों में लाइन लगी हुई है अगर इस तरह की मसालों की फसलें, फलों की फसलें, फूलों की फसलें, औषधीय खेती हम करने लगें तो उसमें किसान का जो लाभ होता है तो वह काफी ज्यादा होता है इसलिये उस दिशा में हमको किसान को बढ़ाना पड़ेगा इसलिये एक बात मेरे मन में आई है जैसे हम लोग मिल्क रुट बनाते हैं दुग्ध संघ होता है मिल्क रुट होते हैं उस मिल्क रुट पर संबंधित किसान दूध का उत्पादन करते हैं उनके दूध का कलेक्शन होता है उनको दूध का ठीक दाम मिल जाता है वैसे ही फलों का और सब्जियों का रुट एक फेडरेशन बनाकर हमको बनाना पड़ेगा ताकि फल और सब्जियां अगर किसान पैदा करें तो उनकी फल और सब्जियां ठीक दाम पर खरीदी जा सकें फेडरेशन वह काम करे और फेडरेशन फिर किसानों के ठीक दाम दे सके नहीं तो ऐसा होता है कि टमाटर पैदा कर लिये और टमाटर के दाम ही नहीं मिले, किसान कहां जायेगा. कई बार 50 पैसा किलो टमाटर बिक जाता है इसलिये यदि वह फलों और सब्जियों की वह खेती करे तो उसके ठीक दाम उसको मिल सकें यह प्रयास हमको करना पड़ेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने यह भी फैसला किया है कि सहकारिता आंदोलन से अभी सभी किसान नहीं जुड़े हैं जो जुड़े हैं वे तो उसका लाभ उठा लेते हैं जो अऋणी किसान हैं उनको उसका लाभ नहीं मिलता है साल भर अभियान चलाकर हम सभी किसानों को सोसायटियों से जोड़ने का काम करेंगे ताकि उन किसानों को भी जीरो परसेंट ब्याज पर जैसी जो योजनायें हैं उनका लाभ मिल सके. अनकों छोटी-छोटी अनुदान की योजनायें चल रही हैं. जैसे सब्जी के बीज का पैकेट, कहीं यह पैकेट कहीं वह पैकेट इनकी मॉनीटरिंग करना बहुत कठिन होता है इनमें गड़बड़-सड़बड़ भी हो जाया करती है इसलिये हमने यह फैसला किया है कि इस तरह छोटी-छोटी सब्सिडी देने की बहुत सी योजनायें हैं उन सब को समाप्त कर दिया जायेगा उनके स्थान पर चुनी हुई दो-तीन योजनाएं जिनका लाभ किसान को हो. केवल वे ही योजनायें चलायेंगे जिससे किसान को लाभ भी पहुंचा सकें और लाभ के साथ साथ उनकी खेती को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में हम लोग ठीक ढंग से कदम उठा सकें.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी विचार कर रहा हूँ अभी हमने जो कृषि मंथन किया था आप भी इससे सहतम होंगे कि खेती से जनसंख्या का बोझ हमको कम करना पड़ेगा खेती हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है इसमें कोई दो मत नहीं है और आने वाले वर्षों में भी भारत में या मध्यप्रदेश में ऐसी परिस्थिति नहीं आने वाली है कि जिसके कारण हम खेती से बड़ी संख्या में हम जनसंख्या का बोझ कम कर सकें लेकिन खेती के साथ-साथ आपने भी सुझाव दिया कि खेती के साथ-साथ पशुपालन की बात हुई, मछली पालन की बात हुई, शहद के उत्पादन की बात हुई, बांस के पेड़ लगाने की बात हुई यह सहायक उद्योग हमको खेती के साथ जोड़ना ही पड़ेंगे. अभी डेयरी की बात कोई कर रहे थे, दुग्ध उत्पादन की बात कर रहे थे. यदि दो भैंस, दो गाय दे दें तो क्या दूध के धंधे में लाभ हो पायेगा ? इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फैसला किया गया है कि कम से कम पांच भैंस की एक यूनिट हो या पांच गाय की एक यूनिट हो एक यूनिट पांच, दस की और फिर पच्चीस की इस मॉडल पर यदि हम डेयरी बनायेंगे तो तो किसान या गरीब डेयरी से कमा पायेगा नहीं तो दो भैंस या दो गाय से कोई यह सोचे की उसकी डेयरी चल जायेगी तो नहीं चलेगी उसके गले पर कर्ज और बंध जायेगा इसलिये इसको हम परिवर्तित करके 5,10 और 25 की यूनिट बना कर ऐसी डेयरी की इकाइयाँ स्थापित करने का काम करेंगे. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रयोग है, मैं नहीं कहता कि कितना सफल होगा, लेकिन फूड प्रोसेसिंग की छोटी-छोटी यूनिट, बड़ी इकाइयाँ भी फूड प्रोसेसिंग की आए, उस बात का भी हम प्रयास करेंगे. लेकिन फूड प्रोसेसिंग की छोटी छोटी इकाइयाँ भी आए, इस बात की आवश्यकता है और इसलिए इसके लिए बाहर से उद्योगपति हम नहीं बुलाएँगे. हमारे अपने बच्चे, जिनको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन और 10 लाख तक की सब्सीडी दी जाएगी और कोशिश यह करेंगे कि हर पंचायत में, वहाँ जो कच्चा माल उत्पादित होता है, जो वहाँ का कृषि उत्पाद है, उसके आधार पर, वह एक फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगाए. अगर 10 लाख की यूनिट भी लगती है तो वह वहाँ कम से कम 4 लोगों को रोजगार दे पाएगा और एक बच्चा अगर हमारा सफल हो गया तो 4 उसको देख कर सीखेंगे और ऐसे हम लघु और कुटीर उद्योगों की एक

श्रृंखला प्रारंभ करने में सफल हो पाएँगे और अगर कृषि उत्पाद वहीं के वहीं उसकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी, तो किसान को भी ठीक दाम मिल सकेगा, इस दिशा में भी हम कदम उठाना चाहते हैं. अध्यक्ष महोदय, अब जो आने वाला समय है वह ड्रिप और माइक्रो इरीगेशन का है. ड्रिप का है, स्प्रिंकलर का है इसलिए बड़ी सिंचाई की योजनाओं में भी हम ड्रिप और स्प्रिंकलर की तरफ जा रहे हैं. लेकिन हम किसानों को इस बात के लिए भी प्रेरित करेंगे कि कुँए और ट्यूबवेल से भी अगर सिंचाई करना है तो ड्रिप के जरिए और स्प्रिंकलर के जरिए सिंचाई करें. उसके लिए किसानों की संख्या अनुदान देने के लिए बढ़ाई जाएगी. इसको भी एक व्यापक पैमाने पर हम लेने की कोशिश करेंगे. एग्रो फॉरेस्ट्री की हम अलग नीति बनाएँगे. मैंने जैसे कहा है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट की स्थापना भी हम करेंगे ताकि वह टेक्नालॉजी देने का काम कर सकें और एक बात मैं और आप सब जानते हैं कि जब कृषि उत्पाद विशेषकर किसानों के फल और सब्जियाँ जब मंडी में आती हैं तो उसके रेट काफी कम मिल पाते हैं. 8 परसेंट आढ़त कट जाती है पता नहीं और कौन कौन सी चीजें कटती हैं इसलिए जो हमारी 51 मंडियाँ हैं उन सभी 51 मंडियों में, जिले की मंडी की मैं बात कर रहा हूँ. वहाँ फल और सब्जी के लिए अलग मंडियाँ बनाई जाएँगी और 2 परसेंट से ज्यादा कमीशन कोई भी नहीं काट सकेगा. अगर कोई काटेगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही करेंगे. ताकि उनको फलों और सब्जियों के ठीक दाम मिल सकें. खेती को फायदे का धंधा बनाने की दृष्टि से यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण होगा. एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ कि आपके जो जो भी सुझाव आए हैं उन सब सुझावों पर, उनमें से जो क्रियान्वित करने के लायक हैं, उनको क्रियान्वित करने में हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी. मैं फिर यह कहना चाहता हूँ कि आज का जो सत्र हमने बुलाया, वह इसलिए बुलाया कि आप सब से बातचीत करके, आपके सुझाव सामने आ ही गए, लेकिन उसके आधार पर फौरी तौर पर किसान को जो राहत की राशि देने की आवश्यकता है, वह राहत की राशि हम दे सकें. अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बार फिर यह आश्वस्त करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चिन्ता न करें, घबराएँ ना, सरकार उनके साथ है. हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे. यह साल सूखे का है. सरकार के सहयोग से किसान यह साल निकालेंगे.

"यह रैन अँधेरी बीतेगी, ऊषा यह मुकुट चढ़ाएगी,
पतवार चलाते जाएँगे. मंजिल आएगी, आएगी."

(मेजों की थपथपाहट)

इस सूखे के अँधेरे से हम किसान को निकाल कर बाहर ले जाएँगे और अगला साल और बेहतर आएगा और जो दीर्घकालीन योजना हमने बनाई है, उसके कारण खेती को हम निश्चित तौर पर लाभ का धंधा बनाएँगे, यह मेरा अपना विश्वास है. मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों को, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया उनको धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ. माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद. (मेजों की थपथपाहट) ...(व्यवधान)..

श्री जीतू पटवारी-- मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था कि आखरी में..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- क्या है बोलिए.

श्री जीतू पटवारी-- कोई राजनैतिक भाषा नहीं है. मुख्यमंत्री जी आप ही आदेश कर दें. मेरा अनुरोध यह है कि पूरे भाषण में मुआवजे को लेकर मुख्यमंत्री जी ने क्या बात कही वह स्पष्ट नहीं हो पाई, एक चीज. दूसरी, मुख्यमंत्री जी आप से अनुरोध करता हूँ कि आपने हॉर्टिकल्चर पर बात की...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- अब कृपया बैठ जाएँ. प्रश्नकाल नहीं है. अगले महीने फिर सत्र आ रहा है.

श्री जीतू पटवारी-- अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने मेरे को आज्ञा दे दी...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- अगले महीने फिर सत्र आ रहा है. अभी लंबा है हॉर्टिकल्चर आज नहीं आएगा. अगले महीने आएगा.

श्री जीतू पटवारी-- यह तो गलत बात है.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि-

"दिनाँक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 12, 13, 17, 22, 29 36, 41, 57, 58, 64 तथा 74 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर आठ हजार चार सौ सात करोड़, चौबीस लाख, इक्यासी हजार आठ सौ चालीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए."

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

समय 6.15 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 5) विधेयक, 2015 (क्रमांक 13 सन् 2015)

वित्तमंत्री(श्री जयंत मलैया)—अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश विनियोग(क्रमांक-5) विधेयक, 2015 का पुरःस्थापन करता हूं.

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक 2015 पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय--- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक 2015 पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय—प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक 2015 पर विचार किया जाय.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--- जब यह प्रस्ताव पास करें तो इसको सर्व सम्मति से पास कर दें .

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात तो कहने दें.विनियोग विधेयक पर हमेशा चर्चा होती है.

अध्यक्ष महोदय--- कभी भी इस पर चर्चा की परंपरा नहीं रही है . लेकिन आप जब इसका तृतीय वाचन होगा तब अपनी बात कह लें .

अध्यक्ष महोदय--- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2,3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2,3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया-- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश विनियोग(क्रमांक-5) विधेयक, 2015 पारित किया जाये.

अध्यक्ष महोदय--- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक , 2015 पारित किया जाय.

श्री रामनिवास रावत--- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सत्ता पक्ष द्वारा आपके द्वारा, विपक्ष के द्वारा और माननीय वित्तमंत्री जी द्वारा यह विशेष सत्र बुलाया गया आज प्रदेश में सूखे की भयावह स्थिति है प्रदेश का किसान संकट में है. आर्थिक विपन्नता है और किसान निरीह होकर के मारा-मारा घूम

रहा है बल्कि आत्महत्या की भी बात आई . माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी द्वारा आठ हजार चार, सौ सात करोड़,चौबीस लाख, इक्यासी हजार आठ सौ चालीस रुपये का संचित निधि में से प्रावधान किसानों के लिए मांगा है उसमें विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी लंबा एक घंटे 20 मिनट का लगभग भाषण दिया, दीर्घकालीन योजनाओं के बारे में तो बहुत कहा. मैं मुख्यमंत्री जी की ही एक बात करना चाहूंगा कृषि कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं माना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं माना है कि सूखे से 22 हजार करोड़ रुपये का नुकसान आंकलित किया है, प्रारम्भिक आकलन के अनुसार, यह आपने स्वयं इसकी स्वीकारोक्ति की है कि 22 हजार का नुकसान हुआ है और आज जो बजट की मांग की गयी है इसमें कुछ मत तो ऐसे हैं जो समायोजन के लिए हैं बाकी 7217 करोड़ लगभग केवल किसानों के लिए है अगर इसको देखें तो इसमें विधानसभा उपचुनाव का समायोजन करना है, कार्यालय भवनों की आकस्मिकता निधि का समायोजन होना है, भूअर्जन इसका समायोजन होना है. कुछ ही राशि है जो किसानों के हित में चाही गयी है. एक तरफ 22 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान कर रहे हैं और किस तरह से 7 हजार, 8 हजार करोड़ रुपये में किसान को आर्थिक मदद दिला पायेंगे, मैं इसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ.हमारी कोई आपत्ति नहीं है, हम सर्वसम्मति से चाहते हैं, अच्छा होता कि इस राशि को कहीं से भी किसी भी तरह से और बढ़ाते. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पिछले भाषणों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आयी तो उन्होंने अपने भाषण में लिखा है कि मैं गुना शिवपुरी के दौरे के बाद सीधे दिल्ली दौड़ा दौड़ा गया 5.3.2014 को,प्रधानमंत्री जी से मिला.

अध्यक्ष महोदय—आप कृपया विनियोग पर ही बोलिये.

श्री रामनिवास रावत—विनियोग पर ही बोल रहा हूँ, राशि की ही बात कर रहा हूँ, राशि की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ. माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला वह किस पर बोला?

अध्यक्ष महोदय-- वह तो आपने भी नहीं बोला. सब ने सूखे पर ही चर्चा की. अब आप विनियोग विधेयक को पास करने की स्थिति में आ गये हैं. वह अनुपूरक पर चर्चा थी,यह विनियोग पर चर्चा है, इसको जरा आप समझिये.

श्री रामनिवास रावत-- मध्यप्रदेश इस समय वित्तीय संकट की स्थिति में है, ऐसे संकट के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी पहले कहते थे कि क्या केन्द्र की ड्यूटी नहीं है, क्या केन्द्र का फर्ज नहीं है. मुझे यह कहते हुए तकलीफ होती है कि गोपाल जी ने बिलकुल ठीक कहा, पैसा न केन्द्र का है न राज्य का, पैसा जनता की जेब का है, इसमें कोई एहसान नहीं कर रहा कि जो किसानों को पैसा दे रहे हैं वह राज्य की जनता की जेब से आता है जो टैक्स के रुप में आता है, केन्द्र से खजाने में जाता है, वही राज्य के खजाने में जाता है. उस समय पैसे की जब कमी नहीं रहती थी तब केन्द्र सरकार जो दिल्ली में यूपीए की केन्द्र सरकार बैठी है वह लगातार हमारे साथ भेदभाव करने का काम कर रही है, यह वक्तव्य, यह टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी की है. माननीय मुख्यमंत्री जी, इस समय 22 हजार करोड़ रुपये का प्रारम्भिक आकलन आपने

किया है, क्या इस समय केन्द्र का दायित्व नहीं है, जब केन्द्र में यूपीए की सरकार थी उस समय कभी तो आप उपवास करते थे, कभी धरना देते थे, कभी साइकिल से चलते थे, सदैव आरोप लगाते थे.

डॉ. नरोत्तम मिश्र—अध्यक्ष महोदय, यह सारे विषय आ चुके हैं.

श्री रामनिवास रावत—आपने हमेशा केन्द्र पर आरोप लगाया. आपने बोनस देने की बात कही. आज आप पैसा मांगे, कौन मना कर रहा है. चलो मैं केन्द्र की बात नहीं करुंगा, आपको कष्ट हो रहा है(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—यह नहीं चलेगा.अब किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी.अब आप समाप्त करिये.

श्री रामनिवास रावत—मिनिमम सपोर्ट प्राइज पर धान खरीदने की, मक्का खरीदने की, ज्वार खरीदने की, बाजरा खरीदने की पूरे प्रदेश में कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे भाषण के दौरान एक शब्द नहीं बोला है कि जहां प्रदेश के किसानों का दाम 1410 रुपये प्रति क्विंटल बिकना था वह 1100 रुपये में बिक रहा है लेकिन इसकी सुध नहीं आयी. बुराई करना बहुत आसान है. मैं चाहता हूँ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइज पर आप धान खरीदी की बात करते. आप जनसम्पर्क विभाग का पूरा का पूरा बजट शून्य कर दो, कौन मना कर रहा है, पूरे विपक्ष की भी सहमति है, आपको भी सहमत होना चाहिए, क्यों छपाते हो अपने फोटो, क्यों देते हो विज्ञापन, पूरा शून्य कर दो, पूरा शून्य करके जितना भी जनसम्पर्क विभाग का बजट है पूरा का पूरा किसानों के लिए अंतरित कर दो, हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है. आपको ज्यादा दिक्कत हो, मध्यप्रदेश विधानसभा के सभी 230 विधायक को, विधायक विधानसभा क्षेत्र निधि देते हो, मैं तैयार हूँ विधानसभा विकास क्षेत्र निधि को, सबसे सहमति ले लो, इसको भी आप किसानों को आवंटित कर दो तो इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम पूरी तरह से तैयार हैं.अध्यक्ष महोदय, बात वहीं आकर के टिक जाती है,माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी राजनैतिक बातें बीच बीच में बोली हैं फिर रुक गये अभी तात्कालिक किसानों के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके संबंध में ज्यादा कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं बताया. माननीय मुख्यमंत्री जी आप मंथन करते हो, 2009 में भी मंथन किया, अभी भी मंथन करके आ रहे हो लेकिन आपने कभी भी विपक्ष का सहयोग लेने का या कभी भी प्रदेश के बुद्धिजीवियों का सहयोग लेने का या कभी भी प्रदेश के अच्छे किसानों का सहयोग लेने की कोशिश नहीं की कि आप इन सब लोगों की एक कमेटी बना करके किस तरह से हम कृषि को लाभ का धंधा बनाएं किस तरह से हम प्रदेश के विकास में सबका सहयोग लें. (व्यवधान...)

अध्यक्ष महोदय - अब कृपया समाप्त करें आप.

श्री रामनिवास रावत - माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी चिंता है बजट बढ़ाएं, हमें इसका जवाब चाहिए. (व्यवधान...)

अध्यक्ष महोदय - आपकी बात आ गई है कृपया समाप्त करें.

श्री रामनिवास रावत - माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि... (व्यवधान...) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा.

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया) - जो प्रस्तावित हैं उसको कृपया पारित कराने की कृपा करें. (व्यवधान...)

श्री रामनिवास रावत - माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और सत्ता पक्ष के पूरे सदस्यों से निवेदन है कि जितने भी प्रस्ताव प्रदेश के समस्त जिलों से विभिन्न तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित करने के शासन के पास आ चुके हैं उन्हें तुरंत सूखा प्रभावित घोषित करें. मेरा व्यक्तिगत रूप से निवेदन है और 22 हजार करोड़ रुपये की नुकसान की किसानों की भरपाई 7 हजार करोड़ से नहीं हो सकती, आप किस तरह से प्रदेश के पूरे किसानों को पैसा मुहैया कराओगे, ये जरा बता दें. विपक्ष का पूरा साथ आपके साथ है विपक्ष कहीं आपसे दूर नहीं जा रहा है, विपक्ष आपके साथ किसानों का साथ देने के लिए सदैव तैयार है. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद.

श्री बाला बच्चन (राजपुर) - माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी ने और पूरे सदन ने माननीय मुख्यमंत्री जी को शांतिपूर्ण तरीके से सुना है. इस विनियोग विधेयक का हम सब कांग्रेसी विधायक भी समर्थन करते हैं और हम यह चाहते हैं कि सर्वानुमति से यह पास हो. मेरा निवेदन है कि बजट बढ़ना चाहिए. मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब यूपीए की सरकार थी, डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय 73 हजार करोड़ रुपये के कर्ज माफ हुए थे.

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) - यूपीए सरकार ने एक पैसा नहीं दिया.

अध्यक्ष महोदय - प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -5) विधेयक, 2015 पारित किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

सर्वसम्मति से विधेयक पारित हुआ.

अध्यक्ष महोदय - अब राष्ट्रगान होगा.

(सदन में राष्ट्रगान का समूहगान हुआ.)

अध्यक्ष महोदय - विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित.

सायं 06.29 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई.

भोपाल
दिनांक : 5 नवंबर, 2015

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधानसभा